IUC ACADEMY

INCLUSIVE UNIVERSAL CAREERS ACADEMY

Learn. Prepare. Progress. • www.iucacademy.com

IUC अकादमी नोट्स

संपूर्ण
पाठ्यक्रम • विस्तृत व्याख्या • तुलनात्मक सारणियाँ • अभ्यास प्रश्न

भारतीय समाज, सामाजिक न्याय एवं अभिशासन (Governance) अध्ययन नोट्स

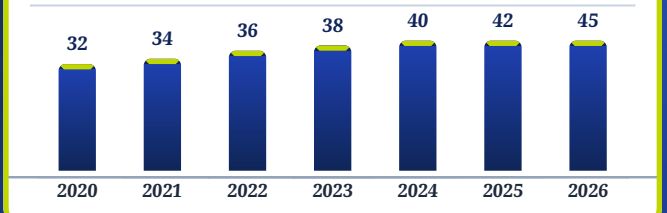
INDIAN SOCIETY, SOCIAL JUSTICE & GOVERNANCE Study Notes (GS-I & GS-II)

UPSC CSE (GS-I & GS-II), State PCS Mains, UGC-NET Sociology/PubAd एवं निबंध के लिए भारतीय समाज की विशेषताएँ, विविधता, महिला संगठन, जनसंख्या, शहरीकरण, भूमंडलीकरण, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, कल्याणकारी योजनाएँ, ई-गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर एवं सिविल सेवा की भूमिका

विषयवार परीक्षा प्रश्न भार विभाजन (%)



विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का रुझान



लक्षित प्रतियोगी, प्रवेश एवं विभागीय परीक्षाएँ (Target Exams Coverage)

UPSC CSE Mains (GS-I & GS-II) • UPPSC/BPSC/MPPSC/RAS Mains • CAPF Essay • UGC-NET • Social Welfare Officer

इस पुस्तक के प्रमुख खंड एवं परीक्षा प्रश्न भार (%)

- भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ, विविधता में एकता, जाति, परिवार एवं विवाह प्रणाली (24%)
- महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या मुद्दे, गरीबी एवं शहरीकरण की समस्याएँ (22%)
- भूमंडलीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद एवं धर्मनिरपेक्षता (18%)
- सामाजिक न्याय: संवेदनशील वर्गों (SC/ST/OBC/दिव्यांग/वृद्ध/बच्चे) हेतु कानून व योजनाएँ (18%)
- अभिशासन (Governance): पारदर्शिता, ई-गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, NGO/SHG एवं सिविल सेवा (18%)

संपूर्ण पाठ्यक्रम
NCERT एवं मानक स्रोत

तुलनात्मक सारणियाँ
प्रवाह आरेख व चार्ट

स्मृति सूत्र
त्वरित रिवीजन बिंदु

अभ्यास प्रश्न
व्याख्या सहित हल

आमुख, परीक्षा भार विश्लेषण एवं अध्ययन रणनीति — भारतीय समाज, सामाजिक न्याय एवं अभिशासन (Governance) अध्ययन नोट्स

IUC Academy (Inclusive Universal Careers Academy | www.iucacademy.com) • आधिकारिक अध्ययन नोट्स

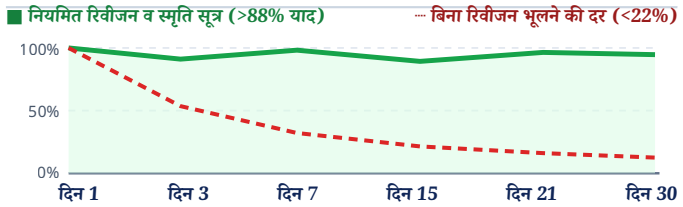
प्रिय अभ्यर्थियों,

अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं एवं विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं के नवीनतम पैटर्न में अवधारणात्मक स्पष्टता और सटीक तथ्यों का समन्वय अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से **IUC Academy (www.iucacademy.com)** द्वारा इन विस्तृत अध्ययन नोट्स का संकलन किया गया है। इसमें प्रत्येक अध्याय के साथ **तुलनात्मक सारणियाँ, प्रवाह आरेख, महत्वपूर्ण सूत्र, 'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स, 'परीक्षा सतर्कता (सामान्य गलतियाँ)', स्मृति सूत्र (Memory Tricks)** और **व्याख्या सहित हल प्रश्न** दिए गए हैं ताकि आपको पढ़ने और याद रखने में पूर्ण सुगमता रहे।

कठिनाई स्तर के अनुसार लक्ष्य सटीकता एवं कट-ऑफ (%)



नियमित रिवीजन (1-3-7-21 दिन नियम) एवं स्मृति धारण ग्राफ



अध्यायवार एवं खंडवार प्रश्न भार सूचकांक (Topic-wise Weightage %)



प्रामाणिक पाठ्यक्रम एवं आधिकारिक संदर्भ स्रोत (Verified Official Sources)

- नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट (https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2024-07/SDG_India_Index_2023-24.pdf)
- भारत की जनगणना (Census of India) (https://censusindia.gov.in/census.website/data/census-tables)
- IUC Academy GS-I & GS-II Syllabus (https://upsc.gov.in/)
- भारतीय संविधान (सामाजिक न्याय प्रावधान) (https://www.legislative.gov.in/constitution-of-india)

विस्तृत विषय-सूची एवं अध्याय संरचना (Table of Contents)

भारतीय समाज, सामाजिक न्याय एवं अभिशासन (Governance) अध्ययन नोट्स • संपूर्ण अध्याय, तुलनात्मक सारणियाँ, अभ्यास प्रश्न एवं त्वरित रिवीजन

1. पुस्तक क्रमांक 28: संपूर्ण भारतीय समाज, सामाजिक न्याय एवं शासन व्यवस्था

2. पुस्तक की संरचना एवं अध्याय सूची (Overview of Chapters)

3. अध्याय 1: भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ, विविधता में एकता, जाति व्यवस्था एवं परिवार-विवाह संस्था

4. 1.1 विस्तृत सैद्धांतिक एवं समाजशास्त्रीय व्याख्या

- (क) भारतीय समाज की मूलभूत विशेषताएँ एवं संरचनात्मक सातत्य
- (ख) विविधता में एकता (Unity in Diversity): बहुलता से राष्ट्रीय एकीकरण तक
- (ग) जाति व्यवस्था (Caste System): उत्पत्ति, विशेषताएँ एवं आधुनिक परिवर्तन
- (घ) परिवार एवं विवाह संस्था (Family and Marriage Institutions)

5. 1.2 परीक्षा जाल (Exam Trap)

6. 1.3 4-नोड फ्लोचार्ट: भारतीय सामाजिक संरचना का ऐतिहासिक रूपांतरण

7. 1.4 विस्तृत तुलनात्मक सारणी: वर्ण बनाम जाति तथा संयुक्त बनाम नाभिकीय परिवार

8. 1.5 चार्ट डेटा %: भारतीय सामाजिक एवं पारिवारिक संकेतकों का वितरण

9. 1.6 स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks)

10. 1.7 अभ्यास प्रश्नोत्तर (15 व्याख्यात्मक प्रश्न — अध्याय 1)

11. अध्याय 2: भारत में महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन एवं महिला सशक्तिकरण

12. 2.1 विस्तृत सैद्धांतिक एवं समाजशास्त्रीय व्याख्या

- (क) भारतीय इतिहास में महिलाओं की स्थिति का विकासात्मक अनुक्रम
- (ख) भारत में महिला संगठन: औपनिवेशिक काल से समकालीन नारीवादी आंदोलनों तक
- (ग) समकालीन महिला सशक्तिकरण: संवैधानिक प्रावधान, विधान एवं योजनाएँ
- (घ) महिलाओं के समक्ष प्रमुख सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ (Glass Ceiling & Pink Collarization)

13. 2.2 परीक्षा जाल (Exam Trap)

14. 2.3 4-नोड फ्लोचार्ट: भारत में महिला नीति के दृष्टिकोण का विकास

15. 2.4 विस्तृत तुलनात्मक सारणी: महिला सशक्तिकरण के प्रमुख विधान, आयोग एवं योजनाएँ

16. 2.5 चार्ट डेटा %: भारत में लैंगिक एवं महिला सशक्तिकरण संकेतक (2014 बनाम 2025-26)

17. 2.6 स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks)

18. 2.7 अभ्यास प्रश्नोत्तर (15 व्याख्यात्मक प्रश्न — अध्याय 2)

19. अध्याय 3: जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय

20. 3.1 विस्तृत सैद्धांतिक एवं समाजशास्त्रीय व्याख्या

- (क) भारत का जनसांख्यिकीय संक्रमण (Demographic Transition) एवं जनसंख्या गतिकी
- (ख) जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) बनाम जनसांख्यिकीय समय-बम
- (ग) भारत में गरीबी: मापन समितियाँ एवं बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI)
- (घ) विकासात्मक विषय एवं समावेशन की योजनाएँ

21. 3.2 परीक्षा जाल (Exam Trap)

22. 3.3 4-नोड फ्लोचार्ट: गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने का बहु-क्षेत्रीय मॉडल

23. 3.4 विस्तृत तुलनात्मक सारणी: भारत में गरीबी मापन समितियों एवं राष्ट्रीय MPI का विश्लेषण

24. 3.5 चार्ट डेटा %: राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी एवं बुनियादी सुविधा कवरेज

25. 3.6 स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks)

26. 3.7 अभ्यास प्रश्नोत्तर (15 व्याख्यात्मक प्रश्न — अध्याय 3)

27. अध्याय 4: शहरीकरण, उनकी समस्याएँ और उनके रक्षोपाय तथा प्रवासन (Migration)

28. 4.1 विस्तृत सैद्धांतिक एवं समाजशास्त्रीय व्याख्या

- (क) भारत में शहरीकरण (Urbanization): परिभाषा एवं जनगणना मानदंड
- (ख) भारत में शहरीकरण की विशेष प्रवृत्तियाँ: 'अति-शहरीकरण' एवं 'छद्म शहरीकरण'
- (ग) शहरीकरण की प्रमुख समस्याएँ एवं शासकीय रक्षोपाय (Urban Safeguards & Flagship Schemes)
- (घ) प्रवासन (Migration): धाराएँ, कारण (Push-Pull Factors) एवं 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड'

29. 4.2 परीक्षा जाल (Exam Trap)

30. 4.3 4-नोड फ्लोचार्ट: ग्रामीण-शहरी प्रवासन एवं एकीकृत नगरीय प्रबंधन चक्र

31. 4.4 विस्तृत तुलनात्मक सारणी: शहरी पुनरुद्धार एवं प्रवासी कल्याण की प्रमुख सरकारी पहलें

32. 4.5 चार्ट डेटा %: शहरी स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन एवं राशन पोर्टेबिलिटी प्रगति

33. 4.6 स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks)

34. 4.7 अभ्यास प्रश्नोत्तर (15 व्याख्यात्मक प्रश्न — अध्याय 4)

35. अध्याय 5: भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण (Globalization) का प्रभाव

36. 5.1 विस्तृत सैद्धांतिक एवं समाजशास्त्रीय व्याख्या

- (क) भूमंडलीकरण की अवधारणा एवं भारत में इसका विकास
- (ख) सांस्कृतिक प्रभाव: समरूपीकरण, ग्लोकलाइजेशन एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान
- (ग) विभिन्न सामाजिक वर्गों एवं संस्थाओं पर भूमंडलीकरण का प्रभाव

37. 5.2 परीक्षा जाल (Exam Trap)

38. 5.3 4-नोड फ्लोचार्ट: भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण के बहुआयामी प्रभाव का चक्र

39. 5.4 विस्तृत तुलनात्मक सारणी: भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों पर भूमंडलीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव

40. 5.5 चार्ट डेटा %: भूमंडलीकरण एवं डिजिटल-आर्थिक एकीकरण के प्रमुख संकेतक

41. 5.6 स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks)

42. 5.7 अभ्यास प्रश्नोत्तर (15 व्याख्यात्मक प्रश्न — अध्याय 5)

43. अध्याय 6: सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता

44. 6.1 विस्तृत सैद्धांतिक एवं समाजशास्त्रीय व्याख्या

- (क) सामाजिक सशक्तिकरण (Social Empowerment): अवधारणा एवं आयाम
- (ख) संप्रदायवाद (Communalism): उत्पत्ति, चरण एवं निराकरण

पुस्तक क्रमांक 28: संपूर्ण भारतीय समाज, सामाजिक न्याय एवं शासन व्यवस्था

उपशीर्षक: Complete Indian Society, Social Justice & Governance — मास्टर अध्ययन ग्रंथ

लक्षित परीक्षाएँ: UPSC CSE (GS Paper-I एवं GS Paper-II), UPPSC, BPSC, सभी राज्य सिविल सेवा परीक्षाएँ (State PCS), UGC-NET (समाजशास्त्र एवं लोक प्रशासन) तथा अन्य अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाएँ

संस्थापक एवं मुख्य मार्गदर्शक: सरोज मिश्रा, आईयूसी एकेडमी (Inclusive Universal Careers Academy — www.iucacademy.com)

संस्करण मानक: 100% शुद्ध देवनागरी हिंदी • नवीनतम शासकीय आँकड़े (NFHS, NITI Aayog MPI, DARPG, जनगणना एवं पीआईबी प्रतिवेदन) • परीक्षा जाल (Exam Trap) • 4-नोड फ्लोचार्ट • तुलनात्मक सारणियाँ • स्मृति सूत्र एवं 150 व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तर

पुस्तक की संरचना एवं अध्याय सूची (Overview of Chapters)

1. **अध्याय 1:** भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ, विविधता में एकता, जाति व्यवस्था एवं परिवार-विवाह संस्था
2. **अध्याय 2:** भारत में महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन एवं महिला सशक्तिकरण
3. **अध्याय 3:** जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय
4. **अध्याय 4:** शहरीकरण, उनकी समस्याएँ और उनके रक्षोपाय तथा प्रवासन (Migration)
5. **अध्याय 5:** भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण (Globalization) का प्रभाव
6. **अध्याय 6:** सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता
7. **अध्याय 7:** सामाजिक न्याय: स्वास्थ्य, शिक्षा व मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं का विकास
8. **अध्याय 8:** अति-संवेदनशील वर्गों (SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन, वृद्धजन, ट्रांसजेंडर) के लिए कल्याणकारी योजनाएँ, आयोग एवं संवैधानिक तंत्र
9. **अध्याय 9:** शासन व्यवस्था (Governance): सुशासन (Good Governance), ई-गवर्नेंस (डिजिटल इंडिया, DPI), नागरिक चार्टर (सेवोत्तम मॉडल), पारदर्शिता एवं जवाबदेही
10. **अध्याय 10:** लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, स्वयं सहायता समूह (SHGs), गैर-सरकारी संगठन (NGOs - FCRA) एवं दबाव समूह

अध्याय 1: भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ, विविधता में एकता, जाति व्यवस्था एवं परिवार-विवाह संस्था

1.1 विस्तृत सैद्धांतिक एवं समाजशास्त्रीय व्याख्या

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 1.1 विस्तृत सैद्धांतिक एवं समाजशास्त्रीय व्याख्या

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
(क) भारतीय समाज की मूलभूत विशेषताएँ एवं संरचनात्मक सातत्य	(ख) विविधता में एकता (Unity in Diversity): बहुलता से राष्ट्रीय एकीकरण तक	(ग) जाति व्यवस्था (Caste System): उत्पत्ति, विशेषताएँ एवं आधुनिक परिवर्तन	(घ) परिवार एवं विवाह संस्था (Family and Marriage Institutions)

(क) भारतीय समाज की मूलभूत विशेषताएँ एवं संरचनात्मक सातत्य

भारतीय समाज विश्व की प्राचीनतम एवं सर्वाधिक गतिशील सामाजिक संरचनाओं में से एक है, जिसकी मुख्य पहचान **'परंपरा और आधुनिकता का सह-अस्तित्व' (Co-existence of Tradition and Modernity)** है। समाजशास्त्री **योगेंद्र सिंह** ने अपनी प्रसिद्ध कृति *Modernization of Indian Tradition* में स्पष्ट किया है कि भारत में आधुनिकीकरण ने पारंपरिक संस्थाओं (जैसे—जाति, संयुक्त परिवार और धर्म) को पूर्णतः समाप्त नहीं किया, अपितु उनका **अनुकूली रूपांतरण (Adaptive Transformation)** किया है। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं में पदानुक्रमिक सामाजिक संरचना (Hierarchical Social Structure), सामूहिकता एवं सामुदायिक एकजुटता (Collectivism over Individualism), आध्यात्मिक एवं कर्म-पुनर्जन्म आधारित जीवन-दर्शन, बहुलतावादी सांस्कृतिक ताना-बाना (Pluralistic Cultural Fabric) तथा समन्वयवादी संस्कृति (Syncretic Culture या गंगा-जमुनी तहजीब) सम्मिलित हैं।

(ख) विविधता में एकता (Unity in Diversity): बहुलता से राष्ट्रीय एकीकरण तक

भारत में भौगोलिक, भाषाई, धार्मिक, नृजातीय (Ethnic) और सांस्कृतिक स्तर पर अद्वितीय विविधता विद्यमान है। **भारत की जनगणना एवं जनसंख्या प्रक्षेपण प्रतिवेदन** के अनुसार भारत की जनसांख्यिकीय और क्षेत्रीय संरचना अत्यंत विशाल एवं विविधतापूर्ण है, जहाँ संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएँ तथा सैकड़ों मातृभाषाएँ प्रचलित हैं। समाजशास्त्री **एम. एन. श्रीनिवास** ने 'विविधता में एकता' को भारतीय सभ्यता की अंतर्निहित शक्ति बताया है, जिसे निम्नलिखित चार स्तंभों से बल मिलता है:

- **भौगोलिक एवं सांस्कृतिक एकता:** उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक 'भारतवर्ष' की सांस्कृतिक चेतना और चार धाम तीर्थयात्रा परंपरा।
- **संवैधानिक एवं राजनीतिक एकता:** एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएँ और सर्वसमावेशी संसदीय लोकतंत्र।
- **भाषाई एवं साहित्यिक अंतर्संबंध:** संस्कृत, पाली, प्राकृत, फारसी और आधुनिक भारतीय भाषाओं के मध्य गहरा शब्दावली एवं वैचारिक आदान-प्रदान।
- **आर्थिक एवं प्रशासनिक अंतर-निर्भरता:** अंतर-राज्यीय व्यापार, श्रम गतिशीलता और राष्ट्रीय बाजार का एकीकरण।

(ग) जाति व्यवस्था (Caste System): उत्पत्ति, विशेषताएँ एवं आधुनिक परिवर्तन

प्रसिद्ध समाजशास्त्री **जी. एस. घुर्ये (G.S. Ghurye)** ने अपनी पुस्तक *Caste and Race in India* में जाति व्यवस्था की **6 मूलभूत विशेषताएँ** बताई हैं: (1) समाज का खंडात्मक विभाजन (Segmental Division of Society), (2) संस्तरण या पदानुक्रम (Hierarchy), (3) भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध (Restrictions on Feeding and Social Intercourse), (4) नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएँ तथा विशेषाधिकार (Civil and Religious Disabilities and Privileges), (5) पेशे के चुनाव का अभाव (Lack of Unrestricted Choice of Occupation), और (6) विवाह संबंधी प्रतिबंध या अंतर्विवाह (Endogamy)।

आधुनिक काल में शिक्षा, औद्योगीकरण, शहरीकरण, संवैधानिक आरक्षण एवं लोकतांत्रिक राजनीति के प्रभाव से जाति व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आए हैं:

- **संस्कृतिकरण (Sanskritization):** एम. एन. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित वह प्रक्रिया जिसमें निम्न जातियाँ उच्च जातियों (विशेषकर द्विज जातियों) के रीति-रिवाजों, कर्मकांडों और जीवन-शैली को अपनाकर सामाजिक सोपान में अपनी स्थिति ऊपर उठाने का प्रयास करती हैं। Notice कि यह केवल **'पदमुलक परिवर्तन' (Positional Change)** है, न कि **'संरचनात्मक परिवर्तन' (Structural Change)**।
- **प्रभुत्वशाली जाति (Dominant Caste):** एम. एन. श्रीनिवास के अनुसार वह जाति जो किसी ग्रामीण क्षेत्र में संख्याबल, भूमि स्वामित्व, राजनीतिक शक्ति और आधुनिक शिक्षा के आधार पर प्रभावशाली होती है।
- **जाति का राजनीतिकरण (Politicization of Caste): रजनी कोठारी** ने अपनी पुस्तक *Caste in Indian Politics* में स्पष्ट किया कि राजनीति ने जाति को समाप्त नहीं किया, बल्कि जाति और राजनीति दोनों ने एक-दूसरे को रूपांतरित कर दिया है।

(घ) परिवार एवं विवाह संस्था (Family and Marriage Institutions)

भारतीय समाज में **संयुक्त परिवार (Joint Family)** परंपरागत रूप से उत्पादन, उपभोग और समाजीकरण की प्राथमिक इकाई रहा है। **इरावती कर्वे** ने संयुक्त परिवार को ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया जो एक ही छत के नीचे रहता है, एक ही रसोई में पका भोजन करता है, सामान्य संपत्ति का स्वामी होता है और सामान्य पारिवारिक पूजा में भाग लेता है। वर्तमान में शहरीकरण और आजीविका गतिशीलता के कारण संरचनात्मक रूप से **नाभिकीय परिवार (Nuclear Family)** बढ़े हैं, किंतु **आई. पी. देसाई** और **के. एम. कपाड़िया** के अनुसार भारत में आज भी **'कार्यात्मक संयुक्तता' (Functional Jointness)** बनी

हुई है। विवाह संस्था में भी अंतर-जातीय विवाह (Inter-caste Marriage), विलंबित विवाह, सह-जीवन (Live-in Relationships) और वैवाहिक निर्णय में युवाओं की स्वायत्तता जैसी नई प्रवृत्तियाँ उभरी हैं।

समाजशास्त्रीय वैचारिक सूत्र (1D Conceptual Formula):

$$भारतीय सामाजिक आधुनिकता = संवैधानिक मूल्य (समानता + बंधुत्व) + कार्यात्मक परंपरा - जातीय एवं लैंगिक पदानुक्रम$$

1.2 परीक्षा जाल (Exam Trap)

परीक्षा जाल (Exam Trap): संस्कृतिकरण बनाम आधुनिकीकरण एवं परिवार का विघटन

1. **प्रथम भ्रम:** छात्र प्रायः परीक्षा में लिख देते हैं कि 'संस्कृतिकरण से जाति व्यवस्था की संरचना समाप्त हो जाती है'—यह **गलत** है। एम. एन. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण से केवल जाति पदानुक्रम के भीतर एक जाति की **स्थिति (Position)** बदलती है, स्वयं जाति प्रणाली की **संरचना (Structure)** अपरिवर्तित रहती है।
2. **द्वितीय भ्रम:** 'भारत में संयुक्त परिवार पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं'—यह कथन भी समाजशास्त्रीय रूप से अशुद्ध है। आवासीय रूप से नाभिकीय (Residentially Nuclear) होने के बावजूद भारतीय परिवार भावनात्मक, आर्थिक और संकटकालीन सहयोग में आज भी **कार्यात्मक रूप से संयुक्त (Functionally Joint)** हैं।
3. **तृतीय भ्रम: वर्ण (Varna)** और **जाति (Jati)** को एक मान लेना। वर्ण अखिल भारतीय स्तर पर 4 सैद्धांतिक श्रेणियाँ (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) हैं जो ग्रंथ-आधारित एवं अपेक्षाकृत लचीली थीं, जबकि जाति (Jati) जन्म-आधारित, क्षेत्रीय एवं अंतर्विवाही (Endogamous) इकाइयों की हजारों वास्तविक श्रेणियाँ हैं।

1.3 4-नोड फ्लोचार्ट: भारतीय सामाजिक संरचना का ऐतिहासिक रूपांतरण

[नोड 1: पारंपरिक समाज — वर्ण-जाति पदानुक्रम, जजमानी व्यवस्था एवं संयुक्त परिवार] **[नोड 2: औपनिवेशिक एवं सुधार काल — पश्चिमीकरण, सामाजिक-धार्मिक सुधार एवं विधिक हस्तक्षेप]** **[नोड 3: संवैधानिक लोकतंत्र — अनुच्छेद 14-18 समानता, सकारात्मक भेदभाव एवं संस्कृतिकरण]** **[नोड 4: समकालीन डिजिटल समाज — अंतर-जातीय गतिशीलता, कार्यात्मक संयुक्त परिवार एवं नागरिक पहचान]**

1.4 विस्तृत तुलनात्मक सारणी: वर्ण बनाम जाति तथा संयुक्त बनाम नाभिकीय परिवार

तुलना का आधार	पारंपरिक वर्ण एवं संयुक्त परिवार मॉडल	आधुनिक जाति एवं नाभिकीय/कार्यात्मक परिवार मॉडल	प्रमुख समाजशास्त्रीय संदर्भ एवं स्रोत
उत्पत्ति एवं आधार	ऋग्वैदिक पुरुषसूक्त एवं गुण-कर्म विभाजन; कृषि-आधारित सामूहिक अर्थव्यवस्था	जन्म-आधारित अंतर्विवाही (Endogamous) समूह; औद्योगिक एवं सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था	जी. एस. घुर्ये (*Caste and Race in India*)
संख्या एवं विस्तार	अखिल भारतीय स्तर पर 4 वर्ण; तीन या अधिक पीढ़ियों का साझा निवास	3,000 से अधिक जातियाँ एवं उप-जातियाँ; पति-पत्नी एवं अविवाहित बच्चों की इकाई	इरावती कर्वे (*Kinship Organization in India*)
सामाजिक गतिशीलता	उत्तर-वैदिक काल के बाद कठोर; व्यक्तिगत गतिशीलता सीमित	संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, शिक्षा एवं संवैधानिक आरक्षण से उच्च गतिशीलता	एम. एन. श्रीनिवास (*Social Change in Modern India*)
आर्थिक संबंध	**जजमानी व्यवस्था** (विलियम वाइजर)—अनाज के बदले सेवा का वंशानुगत आदान-प्रदान	बाजार एवं मुद्रा आधारित संविदात्मक संबंध (Contractual Market Relations)	योगेंद्र सिंह (*Modernization of Indian Tradition*)
निर्णय प्रक्रिया एवं सत्ता	पितृसत्तात्मक एवं वयोवृद्ध कर्ता (Karta) का सर्वोच्च प्राधिकार	लोकतांत्रिक एवं सहभागी निर्णय, महिलाओं व युवाओं की बढ़ती भूमिका	आई. पी. देसाई (महुआ अध्ययन) एवं के. एम. कपाड़िया
विवाह के नियम	कठोर जाति-अंतर्विवाह (Endogamy) एवं गोत्र-बहिर्विवाह (Exogamy)	विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत अंतर-जातीय एवं अंतर-धार्मिक विवाहों को मान्यता	नीति आयोग सामाजिक विकास प्रतिवेदन

1.5 चार्ट डेटा %: भारतीय सामाजिक एवं पारिवारिक संकेतकों का वितरण

निम्नलिखित आँकड़े भारत की जनगणना एवं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) तथा पीआईबी प्रतिवेदन के प्रमाणित रुझानों पर आधारित हैं:



1.6 स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks)

• **जी. एस. घुर्ये की जाति की 6 विशेषताएँ याद रखने का सूत्र — "खंड-पदानु-भोजन, नागरिक-पेशा-विवाह":**

1. **खंड** = खंडात्मक विभाजन (Segmental Division)
2. **पदानु** = पदानुक्रम/संस्तरण (Hierarchy)
3. **भोजन** = भोजन एवं सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध
4. **नागरिक** = नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएँ
5. **पेशा** = पेशे के चुनाव का अभाव
6. **विवाह** = अंतर्विवाह (Endogamy)

• **समाजशास्त्रियों और उनकी अवधारणाओं की ट्रिक — "श्रीनिवास का संस्कृत-प्रभुत्व, कोठारी की राजनीति, वाइजर का जजमान, सिंह की परंपरा":**

• **एम. एन. श्रीनिवास:** संस्कृतिकरण (Sanskritization), पश्चिमीकरण (Westernization), प्रभुत्वशाली जाति (Dominant Caste)

• **रजनी कोठारी:** जाति का राजनीतिकरण (Politicization of Caste)

• **विलियम वाइजर:** जजमानी व्यवस्था (Jajmani System — करीमपुर गाँव का अध्ययन)

• **योगेंद्र सिंह:** परंपरा का आधुनिकीकरण (Modernization of Indian Tradition)

1.7 अभ्यास प्रश्नोत्तर (15 व्याख्यात्मक प्रश्न — अध्याय 1)

अभ्यास प्रश्न #1 — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 1. 'संस्कृतिकरण' (Sanskritization) की अवधारणा का प्रतिपादन किस समाजशास्त्री ने किया था और इसका मूल अर्थ क्या है?

उत्तर एवं व्याख्या: इसका प्रतिपादन **एम. एन. श्रीनिवास** ने मैसूर के 'कुर्ग' (Coorgs) के अध्ययन के दौरान किया था। इसका अर्थ वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निम्न हिंदू जाति या जनजाति या कोई अन्य समूह अपने रीति-रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन-पद्धति को किसी उच्च और प्रायः 'द्विज' जाति की दिशा में बदलता है। यह केवल पदमुलक परिवर्तन (Positional Change) लाता है, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं।

अभ्यास प्रश्न #2 — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 2. जी. एस. घुर्ये के अनुसार जाति व्यवस्था की सबसे केंद्रीय विशेषता कौन-सी है?

उत्तर एवं व्याख्या: घुर्ये एवं डॉ. बी. आर. अम्बेडकर दोनों के अनुसार **'अंतर्विवाह' (Endogamy)** अर्थात् अपनी ही जाति या उप-जाति के भीतर विवाह करना जाति व्यवस्था का मूल आधार और उसकी निरंतरता का सबसे बड़ा कारण है।

अभ्यास प्रश्न #3 — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 3. भारत में 'जजमानी व्यवस्था' (Jajmani System) का सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन किसने किया?

उत्तर एवं व्याख्या: अमेरिकी मानवशास्त्री **विलियम एच. वाइजर (William H. Wiser)** ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के 'करीमपुर' गाँव के अध्ययन के आधार पर अपनी पुस्तक *The Hindu Jajmani System* (1936) में इसका वर्णन किया। इसमें भूमिधर परिवार ('जजमान') और सेवा प्रदान करने वाली जातियों ('कमीन' या 'पुरजन') के बीच वस्तु-विनिमय आधारित वंशानुगत संबंध होते थे।

अभ्यास प्रश्न #4 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 4. 'प्रभुत्वशाली जाति' (Dominant Caste) के निर्धारण के प्रमुख मानदंड क्या हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: एम. एन. श्रीनिवास के अनुसार इसके 4 प्रमुख मानदंड हैं: (1) कृषि योग्य भूमि के बड़े हिस्से पर स्वामित्व, (2) संख्यात्मक शक्ति, (3) स्थानीय पदानुक्रम में अपेक्षाकृत उच्च स्थान, तथा (4) आधुनिक शिक्षा एवं प्रशासनिक/राजनीतिक पदों तक पहुँच।

अभ्यास प्रश्न #5 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 5. इरावती कर्वे ने भारत की नातेदारी व्यवस्था (Kinship System) को कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया है?

उत्तर एवं व्याख्या: इरावती कर्वे ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक *Kinship Organization in India* (1953) में भाषाई, भौगोलिक और वैवाहिक नियमों के आधार पर भारत को **4 नातेदारी क्षेत्रों** में बाँटा है: उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र।

अभ्यास प्रश्न #6 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 6. भारतीय परिवारों के संदर्भ में 'कार्यात्मक संयुक्तता' (Functional Jointness) का सिद्धांत किसने दिया?

उत्तर एवं व्याख्या: समाजशास्त्री **आई. पी. देसाई** ने गुजरात के 'महुआ' नगर के अध्ययन में स्पष्ट किया कि भले ही शहरीकरण के कारण लोग अलग-अलग घरों (नाभिकीय इकाइयों) में रहते हों, किंतु संपत्ति, पर्व-त्योहार, संकटकालीन सहायता और पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन में वे आज भी संयुक्त परिवार की तरह कार्य करते हैं।

अभ्यास प्रश्न #7 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 7. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद 'अस्पृश्यता' (Untouchability) का पूर्ण उन्मूलन करता है?

उत्तर एवं व्याख्या: अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को दंडनीय अपराध घोषित करता है। इसे लागू करने के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 बनाए गए हैं।

अभ्यास प्रश्न #8 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 8. 'जाति का राजनीतिकरण' (Politicization of Caste) से क्या तात्पर्य है?

उत्तर एवं व्याख्या: राजनीतिक वैज्ञानिक **रजनी कोठारी** के अनुसार लोकतांत्रिक राजनीति में सत्ता प्राप्ति के लिए जब राजनीतिक दल जातीय पहचान का उपयोग करते हैं और जातियाँ भी अपने हितों की पूर्ति के लिए जातीय संघों व दबाव समूहों के रूप में संगठित होती हैं, तो इसे जाति का राजनीतिकरण कहा जाता है।

अभ्यास प्रश्न #9 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 9. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में मुख्य अंतर क्या है?

उत्तर एवं व्याख्या: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 हिंदुओं (बौद्ध, जैन और सिख सहित) के मध्य संस्कार-आधारित विवाहों को विनियमित करता है, जबकि **विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act, 1954)** किसी भी धर्म या जाति के नागरिकों को बिना धर्म परिवर्तन किए सिविल अनुबंध के रूप में अंतर-धार्मिक और अंतर-जातीय विवाह करने का वैधानिक अधिकार देता है।

अभ्यास प्रश्न #10 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 10. लुई ड्यूमोंट (Louis Dumont) की पुस्तक 'Homo Hierarchicus' का मुख्य तर्क क्या है?

उत्तर एवं व्याख्या: फ्रांसीसी समाजशास्त्री लुई ड्यूमोंट ने भारतीय जाति व्यवस्था को **'शुद्धता और अशुद्धता' (Purity and Pollution)** के वैचारिक द्विभाजन पर आधारित एक अद्वितीय पदानुक्रमिक व्यवस्था बताया, जो पश्चिमी समतावादी समाज (Homo Aequalis) से भिन्न है।

अभ्यास प्रश्न #11 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 11. 'अलोम' (Hypergamy) और 'प्रतिलोम' (Hypogamy) विवाह में क्या अंतर है?

उत्तर एवं व्याख्या: जब उच्च वर्ण/जाति के पुरुष का विवाह निम्न वर्ण/जाति की कन्या से होता है, तो उसे **अनुलोम विवाह** कहते हैं। इसके विपरीत, जब उच्च वर्ण/जाति की कन्या का विवाह निम्न वर्ण/जाति के पुरुष से होता है, तो उसे **प्रतिलोम विवाह** कहा जाता है।

अभ्यास प्रश्न #12 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 12. भारत में मातृवंशीय (Matrilineal) परिवार प्रणाली किन समुदायों में पाई जाती है?

उत्तर एवं व्याख्या: मेघालय की **खासी, गारो और जयंतिया** जनजातियों तथा केरल के **नायर** और लक्षद्वीप के कुछ समुदायों में मातृवंशीय व्यवस्था पाई जाती है, जहाँ वंश और संपत्ति का उत्तराधिकार माता से पुत्री को प्राप्त होता है।

अभ्यास प्रश्न #13 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 13. योगेंद्र सिंह के अनुसार भारतीय परंपरा के आधुनिकीकरण के दो प्रमुख स्रोत कौन-से हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: योगेंद्र सिंह ने परिवर्तन के दो स्रोत बताए हैं: **अंतर्जात (Orthogenetic)** स्रोत (जैसे—बौद्ध, जैन, भक्ति और सूफी आंदोलन जो समाज के भीतर से उभरे) तथा **बहिर्जात (Heterogenetic)** स्रोत (जैसे—इस्लामी संपर्क और ब्रिटिश औपनिवेशिक आधुनिकता जो बाहर से आए)।

अभ्यास प्रश्न #14 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 14. 'विविधता' (Diversity) और 'बहुलवाद' (Pluralism) में क्या सूक्ष्म अंतर है?

उत्तर एवं व्याख्या: 'विविधता' एक वर्णनात्मक तथ्य (Descriptive Fact) है जो बताता है कि समाज में विभिन्न धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग मौजूद हैं; जबकि 'बहुलवाद' एक मूल्यपरक दर्शन (Normative Philosophy) है जो इन सभी विविध समूहों के समान सम्मान, सह-अस्तित्व और अधिकारों की सक्रिय स्वीकृति देता है।

अभ्यास प्रश्न #15 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 15. मुख्य परीक्षा (Mains) दृष्टिकोण: क्या आधुनिक भारत में जाति अपनी प्रासंगिकता खो रही है?

उत्तर एवं व्याख्या: जाति के **कर्मकांडीय एवं सहभोज संबंधी प्रतिबंध (Ritual & Commensal Aspects)** शहरीकरण, शिक्षा और कानूनों के कारण कमजोर पड़े हैं, किंतु **वैवाहिक (Endogamy) और राजनीतिक-आर्थिक (Vote-bank & Reservation)** क्षेत्रों में जाति की पहचान ने नया रूप (Caste Associations) धारण कर लिया है। अतः जाति समाप्त होने के बजाय 'रूपांतरित' हो रही है।

अध्याय 2: भारत में महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन एवं महिला सशक्तिकरण

2.1 विस्तृत सैद्धांतिक एवं समाजशास्त्रीय व्याख्या

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 2.1 विस्तृत सैद्धांतिक एवं समाजशास्त्रीय व्याख्या

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
(क) भारतीय इतिहास में महिलाओं की स्थिति का विकासात्मक अनुक्रम	(ख) भारत में महिला संगठन: औपनिवेशिक काल से समकालीन नारीवादी आंदोलनों तक	(ग) समकालीन महिला सशक्तिकरण: संवैधानिक प्रावधान, विधान एवं योजनाएँ	(घ) महिलाओं के समक्ष प्रमुख सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ (Glass Ceiling & Pink Collarization)

(क) भारतीय इतिहास में महिलाओं की स्थिति का विकासात्मक अनुक्रम

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से उतार-चढ़ाव भरी रही है। **ऋग्वैदिक काल** में महिलाओं को उच्च सम्मान, शिक्षा (उपनयन संस्कार) और सभा-समिति जैसी राजनीतिक संस्थाओं में भागीदारी का अधिकार प्राप्त था; **लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्ववारा और मैत्रेयी** जैसी विदुषी महिलाओं ने वैदिक ऋचाओं की रचना की। किंतु उत्तर-वैदिक और स्मृति काल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा और संपत्ति के अधिकार से वंचना के कारण महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई।

19वीं शताब्दी के सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों ने महिला मुक्ति की नींव रखी:

- **राजा राममोहन राय** के प्रयासों से **सती प्रथा उन्मूलन विनियम, 1829** (लॉर्ड विलियम बेंटिंक) पारित हुआ।
- **ईश्वरचंद्र विद्यासागर** के संघर्ष से **हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856** लागू हुआ।
- **सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले** ने 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में बालिकाओं के लिए भारत का प्रथम स्वदेशी विद्यालय खोला।
- **पंडिता रमाबाई** ने 'आर्य महिला समाज' और 'शारदा सदन' की स्थापना की।

(ख) भारत में महिला संगठन: औपनिवेशिक काल से समकालीन नारीवादी आंदोलनों तक

भारत में संगठित महिला आंदोलन का विकास तीन प्रमुख चरणों में हुआ:

1. **प्रथम चरण (1910–1947 — मताधिकार एवं स्वतंत्रता संग्राम):**

- **भारत स्त्री महामंडल (1910):** सरला देवी चौधरानी द्वारा इलाहाबाद में स्थापित (महिला द्वारा स्थापित प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन)।
- **विमेंस इंडियन एसोसिएशन (WIA, 1917):** एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स और डोरोथी जिनराजदासा द्वारा मद्रास (अड्यार) में स्थापित।
- **नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन इन इंडिया (NCWI, 1925):** लेडी मेहरबाई टाटा द्वारा स्थापित।
- **ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस (AIWC, 1927):** मार्गरेट कजिन्स द्वारा पुणे में स्थापित (प्रथम अध्यक्ष: महारानी चिमनाबाई गायकवाड़), जिसने बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 (शारदा एक्ट) पारित कराने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई।

2. **द्वितीय चरण (1947–1990 — कल्याण से विकास की ओर):**

- **सेवा (SEWA - Self Employed Women's Association, 1972):** इला भट्ट द्वारा अहमदाबाद में असंगठित क्षेत्र की कामगार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु स्थापित।
- **Towards Equality Report (1974):** भारत सरकार द्वारा गठित 'कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया' (CSWI — वीणा मजूमदार एवं फुलरेणु गुहा) की इस ऐतिहासिक रिपोर्ट ने छठी पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को 'कल्याण' (Welfare) से बदलकर 'विकास' (Development) और बाद में 'सशक्तिकरण' (Empowerment) कर दिया।

3. **तृतीय चरण (1990 से वर्तमान — अधिकार, सुरक्षा एवं महिला-नेतृत्व विकास):**

- **राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990** के तहत जनवरी 1992 में वैधानिक आयोग (NCW) का गठन (प्रथम अध्यक्ष: जयंती पटनायक)।
- कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा हेतु **विशाखा दिशा-निर्देश (1997)** एवं **POSH अधिनियम, 2013**।

(ग) समकालीन महिला सशक्तिकरण: संवैधानिक प्रावधान, विधान एवं योजनाएँ

पीआईबी के समावेशी परिवर्तन प्रतिवेदन (जून 2026) तथा लखपति दीदी पहल प्रतिवेदन (नवंबर 2026) के अनुसार भारत आज **'महिलाओं के विकास' (Development of Women)** से आगे बढ़कर **'महिला-नेतृत्व वाले विकास' (Women-Led Development)** के प्रतिमान पर कार्य कर रहा है:

- **106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम):** इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 330A, 332A और 334A जोड़े गए, जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए **33% आरक्षण** सुनिश्चित करते हैं।

• **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV):** पीआईबी प्रतिवेदन (2026) के अनुसार देश में लिंगानुपात 943 (जनगणना 2011) से बढ़कर **1,020 महिलाएँ प्रति 1,000 पुरुष (NFHS-5)** हो गया है और माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का नामांकन 2014-15 के 75.51% से बढ़कर 2024-25 में **80.2%** हो गया है।

• **लखपति दीदी एवं DAY-NRLM:** पीआईबी तथ्य-पत्रक (15 नवंबर 2026) के अनुसार 12 नवंबर 2026 तक दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ने **10.13 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को 94.40 लाख स्वयं सहायता समूहों (SHGs)** में संगठित किया है।

• **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY):** पीआईबी आँकड़ों (मई 2026) के अनुसार बीपीएल परिवारों की महिलाओं को **10.57 करोड़ से अधिक नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन** प्रदान किए गए हैं।

(घ) महिलाओं के समक्ष प्रमुख सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ (Glass Ceiling & Pink Collarization)

महिला सशक्तिकरण के मार्ग में प्रमुख बाधाओं में **पितृसत्तात्मक मानसिकता, अवैतनिक देखभाल कार्य (Unpaid Care Work — Time Use Survey)**, कॉर्पोरेट एवं उच्च पदों पर अदृश्य अवरोध अर्थात् **'ग्लास सीलिंग' (Glass Ceiling)**, कृषि का नारीकरण (**Feminization of Agriculture**—जहाँ पुरुष शहरों की ओर प्रवास करते हैं और महिलाएँ बिना भूमि स्वामित्व के कृषि श्रम करती हैं), और रोजगार का **'पिंक कॉलराइजेशन' (Pink Collarization)** (महिलाओं का केवल नर्सिंग, शिक्षण, रिसेप्शन जैसे कम वेतन वाले पारंपरिक क्षेत्रों में सिमटना) शामिल हैं।

महिला सशक्तिकरण सूचकांक सूत्र (1D Conceptual Formula):

$$महिला सशक्तिकरण (WE) = शिक्षा एवं स्वास्थ्य (KGBV + PMMVY) + आर्थिक स्वायत्तता (SHG + लखपति दीदी) + राजनीतिक प्रतिनिधित्व (106वाँ संशोधन)$$

2.2 परीक्षा जाल (Exam Trap)

परीक्षा जाल (Exam Trap): संवैधानिक संशोधन, आयोग एवं ऐतिहासिक संगठन

1. **प्रथम भ्रम:** छात्र प्राय: 'भारत स्त्री महामंडल (1910)' और 'विमेंस इंडियन एसोसिएशन (1917)' के संस्थापकों में भ्रमित हो जाते हैं। याद रखें: **भारत स्त्री महामंडल (1910)** की स्थापना **सरला देवी चौधरानी** ने इलाहाबाद में की थी, जबकि **WIA (1917)** की स्थापना **एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स और डोरोथी जिनराजदासा** ने मद्रास में की थी।
2. **द्वितीय भ्रम: राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)** को 'संवैधानिक निकाय' समझ लेना—यह **गलत** है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक **वैधानिक निकाय (Statutory Body)** है जिसकी स्थापना संसद द्वारा पारित 'राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990' के तहत जनवरी 1992 में की गई थी।
3. **तृतीय भ्रम: 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम)** के तहत राज्यसभा और विधान परिषदों में भी 33% आरक्षण मानना—यह **गलत** है। यह आरक्षण केवल **लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा** में लागू है (राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं), तथा यह परिसीमन (Delimitation) के पश्चात 15 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए प्रभावी होगा।

2.3 4-नोड फ्लोचार्ट: भारत में महिला नीति के दृष्टिकोण का विकास

[नोड 1: कल्याणकारी दृष्टिकोण (1950–70) — महिलाओं को केवल लाभार्थी एवं आश्रित के रूप में देखना] **[नोड 2: विकासात्मक दृष्टिकोण (1974–85) — 'Towards Equality' रिपोर्ट एवं छठी योजना में उत्पादक भूमिका]** **[नोड 3: अधिकार एवं सशक्तिकरण दृष्टिकोण (1990–2014) — 73वाँ/74वाँ संशोधन, NCW एवं घरेलू हिंसा कानून]** **[नोड 4: महिला-नेतृत्व विकास (2015–2026) — मिशन शक्ति, लखपति दीदी एवं 106वाँ संविधान संशोधन]**

2.4 विस्तृत तुलनात्मक सारणी: महिला सशक्तिकरण के प्रमुख विधान, आयोग एवं योजनाएँ

पहल / अधिनियम / संगठन	स्थापना वर्ष / अनुच्छेद	मुख्य उद्देश्य एवं विधिक/नीतिगत प्रावधान	प्रमाणित उपलब्धि / आधिकारिक स्रोत
पंचायती राज एवं नगरपालिका आरक्षण	73वाँ एवं 74वाँ संशोधन (1992)	अनुच्छेद 243D एवं 243T के तहत स्थानीय निकायों में कम से कम 1/3 (कई राज्यों में 50%) सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित	14 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (पंचायत स्तर पर)

पहल / अधिनियम / संगठन	स्थापना वर्ष / अनुच्छेद	मुख्य उद्देश्य एवं विधिक/नीतिगत प्रावधान	प्रमाणित उपलब्धि / आधिकारिक स्रोत
नारी शक्ति वंदन अधिनियम	106वाँ संशोधन अधिनियम, 2023	लोकसभा (अनु. 330A), विधानसभाओं (अनु. 332A) व दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण	राजनीतिक सशक्तिकरण में ऐतिहासिक मील का पत्थर
घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम	अधिनियम संख्या 43, वर्ष 2005	शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक, यौन एवं आर्थिक दुर्व्यवहार से सुरक्षा; निवास का अधिकार व संरक्षण अधिकारी	दीवानी प्रकृति का त्वरित राहत कानून
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण (POSH)	वर्ष 2013 (विशाखा केस 1997)	10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संस्थान में 'आंतरिक शिकायत समिति' (ICC) का अनिवार्य गठन	सुरक्षित कार्य-परिवेश एवं SHe-Box ऑनलाइन पोर्टल
मिशन शक्ति (संबल + सामर्थ्य)	15वाँ वित्त आयोग चक्र	**संबल:** सुरक्षा (वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ); **सामर्थ्य:** सशक्तिकरण (PMMVY, शक्ति सदन, पालना)	पीआईबी महिला एवं बाल विकास प्रतिवेदन
लखपति दीदी पहल (DAY-NRLM)	2023–2026 (विस्तारित लक्ष्य)	स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय कम से कम ₹1,00,000 सुनिश्चित करना	10.13 करोड़ महिलाएँ 94.40 लाख SHGs से जुड़ीं (PIB, नवंबर 2026)

2.5 चार्ट डेटा %: भारत में लैंगिक एवं महिला सशक्तिकरण संकेतक (2014 बनाम 2025-26)

निम्नलिखित आँकड़े पीआईबी के दशकीय समावेशी परिवर्तन प्रतिवेदन (जून 2026) तथा एनएफएचएस-6 विज्ञप्ति (मई 2026) पर आधारित हैं:



2.6 स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks)

- **स्वतंत्रता-पूर्व के 4 प्रमुख महिला संगठनों का कालक्रम सूत्र — "सरला का महामंडल (1910), एनी का WIA (1917), मेहरबाई की काउंसिल (1925), कजिन्स की AIWC (1927)":**
- **1910:** भारत स्त्री महामंडल (सरला देवी चौधरानी)
- **1917:** विमेंस इंडियन एसोसिएशन - WIA (एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स)
- **1925:** नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन इन इंडिया - NCWI (लेडी मेहरबाई टाटा)
- **1927:** ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस - AIWC (मार्गरेट कजिन्स)
- **मिशन शक्ति के दो उप-घटक याद रखने की ट्रिक — "संबल से सुरक्षा, सामर्थ्य से सशक्तिकरण":**
- **संबल (Sambal = Safety & Security):** वन स्टॉप सेंटर (OSC), महिला हेल्पलाइन (181), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP), नारी अदालत।
- **सामर्थ्य (Samarthya = Empowerment):** प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY), शक्ति सदन (स्वाधार गृह + उज्ज्वला का विलय), सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास), पालना (राष्ट्रीय क्रेच योजना)।

2.7 अभ्यास प्रश्नोत्तर (15 व्याख्यात्मक प्रश्न — अध्याय 2)

अभ्यास प्रश्न #16 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 1. 1910 में इलाहाबाद में 'भारत स्त्री महामंडल' की स्थापना किसने की थी?

उत्तर एवं व्याख्या: सरला देवी चौधरानी ने 1910 में इलाहाबाद (प्रयागराज) में 'भारत स्त्री महामंडल' की स्थापना की थी। यह किसी भारतीय महिला द्वारा स्थापित प्रथम अखिल भारतीय स्तर का महिला संगठन था, जिसका उद्देश्य महिला शिक्षा का प्रसार और पर्दा प्रथा का उन्मूलन था।

अभ्यास प्रश्न #17 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 2. 1974 की किस ऐतिहासिक सरकारी रिपोर्ट ने भारत में महिला अध्ययन और महिला नीतियों की दिशा बदल दी?

उत्तर एवं व्याख्या: 'टुवर्ड्स इक्वालिटी' (Towards Equality, 1974) रिपोर्ट, जिसे 'कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया' (CSWI) ने तैयार किया था। इसमें डॉ. फुलरेणु गुहा (अध्यक्ष) और डॉ. वीणा मजूमदार (सदस्य-सचिव) की प्रमुख भूमिका थी। इसने घटते लिंगानुपात और महिलाओं की आर्थिक हाशियाकरण को उजागर किया।

अभ्यास प्रश्न #18 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 3. भारतीय संविधान के कौन-से अनुच्छेद प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक समानता और महिलाओं के कल्याण से संबंधित हैं?

उत्तर एवं व्याख्या:

- **अनुच्छेद 14:** विधि के समक्ष समता।
- **अनुच्छेद 15(1):** लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध।
- **अनुच्छेद 15(3):** राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति।
- **अनुच्छेद 39(a) एवं 39(d):** आजीविका के पर्याप्त साधन और पुरुषों व स्त्रियों दोनों के लिए **समान कार्य के लिए समान वेतन**।
- **अनुच्छेद 42:** काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा **प्रसूति सहायता (Maternity Relief)** का उपबंध।
- **अनुच्छेद 51A(e):** स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना (मौलिक कर्तव्य)।

अभ्यास प्रश्न #19 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 4. मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत कामकाजी महिलाओं को कितने सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश मिलता है?

उत्तर एवं व्याख्या: प्रथम दो जीवित बच्चों के लिए वैतनिक मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर **26 सप्ताह** कर दिया गया है। दो से अधिक बच्चों वाली महिलाओं तथा दत्तक माता (Adoptive Mother) या कमीशनिंग माता के लिए यह अवधि **12 सप्ताह** है। साथ ही 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रेच (पालनाघर) की सुविधा अनिवार्य है।

अभ्यास प्रश्न #20 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 5. पीआईबी प्रतिवेदन (जून 2026) के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) में कितनी कमी आई है?

उत्तर एवं व्याख्या: भारत का मातृ मृत्यु अनुपात (Maternal Mortality Ratio - MMR) 2014–16 के **130 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म** से घटकर 2021–23 में **88 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म** रह गया है, जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG 3.1 — 2030 तक MMR को 70 से नीचे लाना) की दिशा में बड़ी उपलब्धि है।

अभ्यास प्रश्न #21 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 6. 'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय' (KGBV) योजना किस वर्ग की बालिकाओं को लक्षित करती है और इसकी नवीनतम स्थिति क्या है?

उत्तर एवं व्याख्या: KGBV योजना अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों की बालिकाओं को कक्षा 6 से 12 तक आवासीय विद्यालयी शिक्षा प्रदान करती है। **पीआईबी आँकड़ों (2026)** के अनुसार 2024–25 में स्वीकृत KGBVs की संख्या बढ़कर **5,639** (नामांकन **7.11 लाख** बालिकाएँ) हो गई है।

अभ्यास प्रश्न #22 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 7. 'कृषि का नारीकरण' (Feminization of Agriculture) से क्या आशय है?

उत्तर एवं व्याख्या: जब ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुष बेहतर रोजगार की तलाश में शहरों की ओर प्रवास (Male Out-migration) करते हैं, तो खेती की बुवाई, निराई, कटाई और पशुपालन का संपूर्ण भार ग्रामीण महिलाओं के कंधों पर आ जाता है। इसे 'कृषि का नारीकरण' कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि 70% से अधिक कृषि कार्य करने के बावजूद केवल लगभग 13–14% महिलाओं के पास ही भूमि का वैधानिक स्वामित्व (Land Title) है।

अभ्यास प्रश्न #23 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 8. 'ग्लास सीलिंग' (Glass Ceiling) और 'ग्लास क्लिफ' (Glass Cliff) में क्या अंतर है?

उत्तर एवं व्याख्या: ग्लास सीलिंग वह अदृश्य संस्थागत एवं सांस्कृतिक अवरोध है जो योग्य महिलाओं को कॉर्पोरेट, प्रशासन या राजनीति के सर्वोच्च नेतृत्व पदों तक पहुँचने से रोकता है। इसके विपरीत, **ग्लास क्लिफ** वह स्थिति है जहाँ किसी संगठन के गंभीर संकट या विफलता के समय महिला को नेतृत्व पद सौंपा जाता है, जिससे विफलता का जोखिम और दोषारोपण अधिक होता है।

अभ्यास प्रश्न #24 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 9. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH Act) किस सर्वोच्च न्यायालय निर्णय पर आधारित है?

उत्तर एवं व्याख्या: यह वर्ष 1997 के ऐतिहासिक **विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (Vishaka vs State of Rajasthan, 1997)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए 'विशाखा दिशा-निर्देशों' पर आधारित है। इसमें भंवरी देवी (राजस्थान की साथिन कार्यकर्ता) के मामले से उत्पन्न जनहित याचिका पर न्यायालय ने अनुच्छेद 14, 19(1)(g) और 21 के तहत सुरक्षित कार्यस्थल को मौलिक अधिकार माना।

अभ्यास प्रश्न #25 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 10. 'लखपति दीदी' योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है और इसकी पात्रता क्या है?

उत्तर एवं व्याख्या: **पीआईबी विज्ञप्ति (नवंबर 2026)** के अनुसार लखपति दीदी पहल **ग्रामीण विकास मंत्रालय** के अधीन **DAY-NRLM** का परिणाम है। इसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूह (SHG) की ऐसी महिला सदस्य को 'लखपति दीदी' कहा जाता है जिसकी स्थायी आजीविका गतिविधियों (कृषि, पशुपालन, सूक्ष्म उद्यम, नमो ड्रोन दीदी आदि) से वार्षिक पारिवारिक आय कम से कम **₹1,00,000** हो।

अभ्यास प्रश्न #26 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 11. 'पंचायत पति' या 'सरपंच पति' सिंड्रोम क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है?

उत्तर एवं व्याख्या: पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण (अनुच्छेद 243D) के तहत निर्वाचित महिला सरपंचों के स्थान पर जब उनके पति या पुरुष रिश्तेदार अनौपचारिक रूप से वास्तविक प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो इसे 'सरपंच पति' या 'प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व' (Proxy Representation) कहा जाता है। इसे क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, महिला ग्राम सभाओं के सुदृढ़ीकरण और वित्तीय स्वायत्तता से दूर किया जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न #27 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 12. 'समय उपयोग सर्वेक्षण' (Time Use Survey - NSO) महिला सशक्तिकरण की किस समस्या को उजागर करता है?

उत्तर एवं व्याख्या: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) का 'समय उपयोग सर्वेक्षण' यह उजागर करता है कि भारतीय महिलाएँ प्रतिदिन औसतन 5 से 6 घंटे **अवैतनिक घरेलू एवं देखभाल कार्यों (Unpaid Domestic and Caregiving Services)** में लगाती हैं, जबकि पुरुषों का योगदान इसमें अत्यंत कम है। इस 'केयर इकोनॉमी' के बोझ के कारण भारत में महिला श्रमबल भागीदारी दर (FLFPR) प्रभावित होती है।

अभ्यास प्रश्न #28 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 13. 'शक्ति सदन' और 'सखी निवास' क्या हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के 'मिशन शक्ति' (सामर्थ्य उप-योजना) के अंतर्गत पूर्ववर्ती 'स्वाधार गृह' और 'उज्ज्वला' योजनाओं को मिलाकर **'शक्ति सदन'** (संकटग्रस्त एवं तस्करी से बचाई गई महिलाओं हेतु एकीकृत राहत व पुनर्वास गृह) बनाया गया है, जबकि कामकाजी महिलाओं के सुरक्षित आवास हेतु हॉस्टल योजना को **'सखी निवास'** नाम दिया गया है।

अभ्यास प्रश्न #29 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 14. 'नमो ड्रोन दीदी' योजना किस प्रकार ग्रामीण महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदल रही है?

उत्तर एवं व्याख्या: 'नमो ड्रोन दीदी' योजना महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को कृषि उद्देश्यों (तरल उर्वरक जैसे नैनो यूरिया और कीटनाशक छिड़काव) के लिए ड्रोन प्रदान करती है और महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित करती है। यह ग्रामीण महिलाओं को पारंपरिक शारीरिक श्रम से निकालकर **उच्च-प्रौद्योगिकी (High-Tech Agri-Entrepreneurship)** के केंद्र में स्थापित करती है।

अभ्यास प्रश्न #30 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 15. मुख्य परीक्षा (Mains) दृष्टिकोण: 'महिलाओं के विकास' (Women's Development) और 'महिला-नेतृत्व वाले विकास' (Women-Led Development) में क्या मूलभूत अंतर है?

उत्तर एवं व्याख्या: 'महिलाओं के विकास' में महिलाओं को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के निष्क्रिय लाभार्थी (Passive Recipients) के रूप में देखा जाता है; जबकि 'महिला-नेतृत्व वाले विकास' में महिलाओं को नीति-निर्माण, शासन, नवाचार, उद्यमिता और राष्ट्रीय विकास के **सक्रिय परिवर्तनकर्ता एवं नेतृत्वकर्ता (Active Architects and Leaders of Growth)** के रूप में स्थापित किया जाता है।

अध्याय 3: जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय

3.1 विस्तृत सैद्धांतिक एवं समाजशास्त्रीय व्याख्या

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 3.1 विस्तृत सैद्धांतिक एवं समाजशास्त्रीय व्याख्या

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
(क) भारत का जनसांख्यिकीय संक्रमण (Demographic Transition) एवं जनसंख्या गतिकी	(ख) जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) बनाम जनसांख्यिकीय समय-बम	(ग) भारत में गरीबी: मापन समितियाँ एवं बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI)	(घ) विकासात्मक विषय एवं समावेशन की योजनाएँ

(क) भारत का जनसांख्यिकीय संक्रमण (Demographic Transition) एवं जनसंख्या गतिकी

जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत (फ्रैंक नोटस्टीन एवं डब्ल्यू. एस. थॉम्पसन) के अनुसार कोई भी समाज उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की अवस्था से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की अवस्था की ओर गुजरता है। भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास को चार प्रमुख चरणों में बाँटा जाता है:

1. **प्रथम चरण (1901–1921 — स्थिर जनसंख्या का काल):** उच्च जन्म दर और महामारी/अकाल के कारण उच्च मृत्यु दर। **वर्ष 1921 को 'महान विभाजक वर्ष' (Year of Great Divide)** कहा जाता है क्योंकि 1911–1921 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक (-0.31%) रही थी।
2. **द्वितीय चरण (1921–1951 — स्थिर एवं मंद वृद्धि का काल):** स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार से मृत्यु दर में गिरावट प्रारंभ हुई।
3. **तृतीय चरण (1951–1981 — जनसंख्या विस्फोट का काल):** मृत्यु दर में तीव्र गिरावट किंतु जन्म दर उच्च बनी रही; 1961–1971 के दशक में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि (24.80%) दर्ज की गई।

4. **चतुर्थ चरण (1981 से वर्तमान — घटती वृद्धि दर एवं जनसांख्यिकीय लाभांश का काल):** कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate - TFR) में निरंतर गिरावट आई है और भारत ने प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर (**Replacement Level Fertility = 2.1**, NFHS-5 में **2.0**) प्राप्त कर ली है।

(ख) जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) बनाम जनसांख्यिकीय समय-बम

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के अनुसार जब किसी देश की कुल जनसंख्या में कार्यशील आयु वर्ग (**15 से 59 वर्ष** या अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार **15 से 64 वर्ष**) का अनुपात आश्रित जनसंख्या (0–14 वर्ष के बच्चे और 60+ वर्ष के वृद्ध) की तुलना में अधिक होता है, तो उससे प्राप्त होने वाली आर्थिक वृद्धि की क्षमता को **'जनसांख्यिकीय लाभांश' (Demographic Dividend)** कहते हैं। भारत की औसत आयु (Median Age) लगभग 28–29 वर्ष है, जो विश्व के प्रमुख देशों में सबसे युवा है।

किंतु अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों की चेतावनी है कि जनसांख्यिकीय लाभांश स्वतः प्राप्त नहीं होता—यदि कार्यशील युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (NEP 2020), कौशल विकास (Skill India), उत्तम स्वास्थ्य (Ayushman Bharat) और औपचारिक रोजगार न मिले, तो यही युवा आबादी बेरोजगारी और सामाजिक असंतोष के कारण **'जनसांख्यिकीय आपदा' (Demographic Disaster)** में बदल सकती है। साथ ही, दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में प्रजनन दर 1.6–1.7 के नीचे जाने से अब भारत में **'जनसंख्या का वृद्धीकरण' (Ageing of Population — Silver Economy)** भी एक उभरता हुआ विषय है।

(ग) भारत में गरीबी: मापन समितियाँ एवं बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI)

गरीबी केवल आय या उपभोग का अभाव नहीं है, अपितु यह **अमर्त्य सेन** के शब्दों में **'क्षमता का अभाव' (Capability Deprivation)** है। स्वतंत्रता के बाद भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु कई समितियाँ गठित की गईं:

- **दांडेकर एवं रथ समिति (1971):** सर्वप्रथम 2,250 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के पोषण मानक का उपयोग किया।
- **वाई. के. अलघ समिति (1979):** ग्रामीण क्षेत्र हेतु **2,400 कैलोरी** और शहरी क्षेत्र हेतु **2,100 कैलोरी** प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का मानक निर्धारित किया।
- **लकड़ावाला समिति (1993):** राज्य-विशिष्ट गरीबी रेखाओं और CPI-AL / CPI-IW सूचकांकों की सिफारिश की।
- **सुरेश तेंदुलकर समिति (2009):** कैलोरी मानक को छोड़कर स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को शामिल किया तथा मिश्रित संदर्भ अवधि (MRP) अपनाई (2011-12 में गरीबी 21.9% आंकी गई)।
- **सी. रंगराजन समिति (2014):** पोषण के साथ प्रोटीन व वसा तथा गैर-खाद्य व्यय को जोड़ा (2011-12 में गरीबी 29.5% आंकी गई)।

राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (National Multidimensional Poverty Index - MPI):

नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रतिवेदन तथा नीति आयोग एमपीआई नोड के अनुसार भारत का राष्ट्रीय एमपीआई **3 आयामों (स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-स्तर — प्रत्येक का 1/3 भार)** और **12 संकेतकों** पर आधारित है (वैश्विक OPHI-UNDP MPI के 10 संकेतकों में भारत ने **'मातृ स्वास्थ्य' (Maternal Health)** और **'बैंक खाता' (Bank Account)** नामक 2 नए संकेतक जोड़े हैं)। इस प्रतिवेदन के अनुसार NFHS-4 (2015–16) और NFHS-5 (2019–21) के बीच भारत में बहुआयामी गरीबी **24.85% से घटकर 14.96%** रह गई है और **13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर** निकले हैं।

(घ) विकासात्मक विषय एवं समावेशन की योजनाएँ

पीआईबी के दशकीय समावेशी परिवर्तन प्रतिवेदन (जून 2026) के अनुसार गरीबी उन्मूलन और बुनियादी सेवाओं के संतृप्तिकरण (Saturation Approach) ने विकासात्मक परिदृश्य को बदल दिया है:

- **प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY):** 2015 से 2026 के बीच **PMAY-Urban** के तहत **98.10 लाख से अधिक आवास** पूरे किए गए और बजट आवंटन 2015-16 के ₹4,175 करोड़ से 346.1% बढ़कर 2026-27 में **₹18,625.05 करोड़** हो गया; वहीं **PMAY-Gramin** का बजट आवंटन 2026-27 में **₹54,916.70 करोड़** पहुँच गया है।
- **जल जीवन मिशन (हर घर जल):** आकांक्षी जिलों (Aspirational Districts) में नल जल कनेक्शन अगस्त 2019 के 23.62 लाख से बढ़कर मई 2026 तक **2.20 करोड़ परिवारों** तक पहुँच गए हैं, तथा **9.23 लाख विद्यालयों** और **9.66 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों** को नल जल से जोड़ा जा चुका है।
- **सौभाग्य योजना (SAUBHAGYA, 2017):** सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण सुनिश्चित करते हुए सभी इच्छुक परिवारों का विद्युतीकरण किया गया।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक सूत्र (1D Mathematical Formula):

$$MPI = H \times A \text{ (जहाँ H = Headcount Ratio / गरीबों का अनुपात, ; A = Intensity of Poverty / वंचना की तीव्रता)}$$

3.2 परीक्षा जाल (Exam Trap)

परीक्षा जाल (Exam Trap): वैश्विक MPI बनाम राष्ट्रीय MPI तथा प्रजनन दर मानक

1. **प्रथम भ्रम:** छात्र प्राय: लिख देते हैं कि 'वैश्विक *MPI* और नीति आयोग के राष्ट्रीय *MPI* दोनों में 10 संकेतक होते हैं'—यह **गलत** है। UNDP और OPHI के वैश्विक MPI में **10 संकेतक** होते हैं, जबकि नीति आयोग के राष्ट्रीय MPI में **12 संकेतक** शामिल हैं (भारत ने स्वास्थ्य आयाम में **'मातृ स्वास्थ्य'** और जीवन-स्तर आयाम में **'बैंक खाता'** जोड़ा है)।
2. **द्वितीय भ्रम:** 'कुल प्रजनन दर (*TFR*) 2.1 होने का अर्थ है कि जनसंख्या तुरंत स्थिर हो जाएगी'—यह **गलत** है। TFR के प्रतिस्थापन स्तर (2.1) पर पहुँचने के बाद भी **'पापुलेशन मोमेंटम' (Population Momentum)** के कारण (क्योंकि प्रजनन आयु वर्ग में पहले से ही बड़ी युवा आबादी मौजूद होती है) जनसंख्या आगामी कुछ दशकों तक बढ़ती रहती है और फिर स्थिर होती है।
3. **तृतीय भ्रम:** जनसंख्या के इतिहास में **1921** को 'जनसंख्या विस्फोट का वर्ष' समझना। वास्तव में **1921** को **'महान विभाजक वर्ष' (Year of Great Divide)** इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे पहले जनसंख्या वृद्धि अनियमित/ऋणात्मक थी और 1921 के बाद से भारत की जनसंख्या निरंतर बढ़ी है।

3.3 4-नोड फ्लोचार्ट: गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने का बहु-क्षेत्रीय मॉडल

[नोड 1: बहुआयामी वंचना — कुपोषण, अशिक्षा, कच्चा आवास एवं असंगठित श्रम] **[नोड 2: बुनियादी सेवा संतृप्तिकरण — हर घर जल, उज्ज्वला, सौभाग्य, PMAY एवं स्वच्छ भारत]** **[नोड 3: मानव पूंजी एवं सुरक्षा जाल — PMGKAY खाद्य सुरक्षा, आयुष्मान भारत एवं समग्र शिक्षा]** **[नोड 4: आजीविका एवं क्षमता सृजन — DAY-NRLM, कौशल विकास एवं MPI में 24.85% से 14.96% की गिरावट]**

3.4 विस्तृत तुलनात्मक सारणी: भारत में गरीबी मापन समितियों एवं राष्ट्रीय MPI का विश्लेषण

समिति / सूचकांक	वर्ष	मुख्य कार्यप्रणाली एवं मानक आधार	प्रमुख निष्कर्ष / आधिकारिक आँकड़े
वाई. के. अलघ समिति	1979	कैलोरी उपभोग आधारित: ग्रामीण **2,400 कैलोरी/दिन**, शहरी **2,100 कैलोरी/दिन**	पोषण ऊर्जा को गरीबी रेखा का सीधा मानक बनाया
लकड़ावाला समिति	1993	कैलोरी मानक बनाए रखा; राज्यों के लिए CPI-AL (ग्रामीण) एवं CPI-IW (शहरी) से मूल्य अद्यतन	प्रत्येक राज्य के लिए अलग गरीबी रेखा की गणना
सुरेश तेंदुलकर समिति	2009	कैलोरी मानक का त्याग; भोजन + शिक्षा + स्वास्थ्य व्यय; मिश्रित संदर्भ अवधि (MRP)	2011–12 में भारत में गरीबी का अनुपात **21.9%** बताया
सी. रंगराजन समिति	2014	संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि (MMRP); कैलोरी + प्रोटीन + वसा + व्यवहार्य गैर-खाद्य व्यय	2011–12 में गरीबी **29.5%** आंकी (ग्रामीण ₹972/माह, शहरी ₹1407/माह)
नीति आयोग राष्ट्रीय MPI	2023	3 आयाम (स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन-स्तर) और **12 संकेतक** (NFHS डेटा पर आधारित)	बहुआयामी गरीबी 24.85% (2015-16) से घटकर 14.96% (2019-21) हुई

3.5 चार्ट डेटा %: राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी एवं बुनियादी सुविधा कवरेज

निम्नलिखित आँकड़े नीति आयोग राष्ट्रीय MPI प्रतिवेदन तथा पीआईबी के जून 2026 प्रतिवेदन पर आधारित हैं:



3.6 स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks)

• **गरीबी मापन समितियों का कालानुक्रमिक सूत्र — "दांडेकर के अलग लकड़ी से तेंदुलकर ने रंग जमाया":**

1. **दांडेकर** = दांडेकर एवं रथ समिति (1971)
2. **अलग** = वाई. के. अलघ समिति (1979)
3. **लकड़ी** = डी. टी. लकड़ावाला समिति (1993)
4. **तेंदुलकर** = सुरेश तेंदुलकर समिति (2009)
5. **रंग** = सी. रंगराजन समिति (2014)

• **राष्ट्रीय MPI के 3 आयाम और 12 संकेतक याद रखने का सूत्र — "स्वास्थ्य के 3, शिक्षा के 2, जीवन-स्तर के 7 (3 + 2 + 7 = 12)":**

• **स्वास्थ्य (3):** पोषण (Nutrition), बाल एवं किशोर मृत्यु दर (Child & Adolescent Mortality), **मातृ स्वास्थ्य (Maternal Health — भारतीय अतिरिक्त संकेतक)**।

• **शिक्षा (2):** स्कूली शिक्षा के वर्ष (Years of Schooling), स्कूल में उपस्थिति (School Attendance)।

• **जीवन-स्तर (7):** खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, आवास, परिसंपत्तियाँ, **बैंक खाता (Bank Account — भारतीय अतिरिक्त संकेतक)**।

3.7 अभ्यास प्रश्नोत्तर (15 व्याख्यात्मक प्रश्न — अध्याय 3)

अभ्यास प्रश्न #31 — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 1. भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में वर्ष 1921 को 'महान विभाजक वर्ष' (Year of Great Divide) क्यों कहा जाता है?

उत्तर एवं व्याख्या: 1911–1921 के दशक में प्लेग, इन्फ्लुएंजा महामारी और अकाल के कारण भारत की जनसंख्या में **-0.31% की ऋणात्मक वृद्धि** हुई थी। 1921 के पश्चात मृत्यु दर पर नियंत्रण होने से भारत की जनसंख्या में निरंतर धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई, इसलिए इसे 'महान विभाजक वर्ष' कहा जाता है।

अभ्यास प्रश्न #32 — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 2. 'प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर' (Replacement Level Fertility) क्या है और इसका मानक मान कितना होता है?

उत्तर एवं व्याख्या: यह कुल प्रजनन दर (TFR) का वह स्तर है जिस पर एक पीढ़ी की महिलाएँ ठीक उतनी ही संतानों को जन्म देती हैं जितनी अगली पीढ़ी में उनकी संख्या को प्रतिस्थापित करने के लिए आवश्यक हैं। शिशु मृत्यु दर को समायोजित करने के कारण इसका मानक मान **2.1 बच्चे प्रति महिला** माना जाता है।

अभ्यास प्रश्न #33 — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 3. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 (NPP 2000) का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या था?

उत्तर एवं व्याख्या: एम. एस. स्वामीनाथन समिति की अनुशंसाओं पर आधारित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 का तात्कालिक उद्देश्य गर्भनिरोधक व स्वास्थ्य अवसंरचना की आपूर्ति करना, मध्यकालिक उद्देश्य TFR को 2.1 पर लाना तथा दीर्घकालिक उद्देश्य **वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण** प्राप्त करना था (जिसे बाद में संशोधित कर 2070 तक लक्षित किया गया)।

अभ्यास प्रश्न #34 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 4. नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) में कौन-से दो संकेतक वैश्विक MPI के अतिरिक्त जोड़े गए हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: वैश्विक MPI (OPHI और UNDP) में 10 संकेतक होते हैं, जबकि नीति आयोग ने भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप इसमें 2 नए संकेतक जोड़े हैं: स्वास्थ्य आयाम में **'मातृ स्वास्थ्य' (Maternal Health)** और जीवन-स्तर आयाम में **'बैंक खाता' (Bank Account)**, जिससे कुल संकेतकों की संख्या **12** हो जाती है।

अभ्यास प्रश्न #35 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 5. किसी परिवार को बहुआयामी रूप से गरीब (Multidimensionally Poor) कब घोषित किया जाता है?

उत्तर एवं व्याख्या: जब किसी परिवार का भारित वंचना स्कोर (Weighted Deprivation Score) सभी 12 संकेतकों के कुल भार में से **एक-तिहाई (1/3 अर्थात् 33.33%) या उससे अधिक** होता है, तो उस परिवार को बहुआयामी रूप से गरीब माना जाता है।

अभ्यास प्रश्न #36 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 6. लोरेन्ज वक्र (Lorenz Curve) और गिनी गुणांक (Gini Coefficient) क्या मापते हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: दोनों अर्थव्यवस्था में **आय या संपत्ति की असमानता (Income/Wealth Inequality)** को मापते हैं। गिनी गुणांक का मान **0 से 1** के बीच होता है: **0** पूर्ण समानता (Perfect Equality) को दर्शाता है और **1** पूर्ण असमानता (Perfect Inequality) को दर्शाता है।

अभ्यास प्रश्न #37 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 7. 'पापुलेशन मोमेंटम' (Population Momentum) से क्या तात्पर्य है?

उत्तर एवं व्याख्या: जब किसी देश की प्रजनन दर (TFR) प्रतिस्थापन स्तर (2.1) या उससे नीचे आ जाती है, तब भी पूर्व के दशकों की उच्च जन्म दर के कारण प्रजनन योग्य आयु वर्ग (15–49 वर्ष) में युवाओं की विशाल संख्या मौजूद रहती है। इस कारण कुल जनसंख्या कुछ दशकों तक बढ़ती रहती है; इसी प्रवृत्ति को 'पापुलेशन मोमेंटम' कहते हैं।

अभ्यास प्रश्न #38 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 8. अमर्त्य सेन का 'क्षमता दृष्टिकोण' (Capability Approach) गरीबी को किस प्रकार परिभाषित करता है?

उत्तर एवं व्याख्या: नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के अनुसार गरीबी केवल कम आय (Low Income) होना नहीं है, बल्कि यह उन बुनियादी क्षमताओं (Capabilities—जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान) से वंचना है जो व्यक्ति को एक मूल्यवान जीवन जीने में सक्षम बनाती हैं।

अभ्यास प्रश्न #39 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 9. पीआईबी के जून 2026 प्रतिवेदन के अनुसार आकांक्षी जिलों और विद्यालयों में 'जल जीवन मिशन' की क्या उपलब्धि रही है?

उत्तर एवं व्याख्या: आकांक्षी जिलों (Aspirational Districts) में घरेलू नल जल कनेक्शन अगस्त 2019 के 23.62 लाख से बढ़कर मई 2026 तक **2.20 करोड़** हो गए हैं, तथा देश के **9.23 लाख विद्यालयों** और **9.66 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों** में नल से शुद्ध पेयजल पहुँचाया जा चुका है।

अभ्यास प्रश्न #40 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 10. भारत में 'सिल्वर इकोनॉमी' (Silver Economy) की अवधारणा क्यों महत्वपूर्ण हो रही है?

उत्तर एवं व्याख्या: जीवन प्रत्याशा बढ़ने और प्रजनन दर घटने के कारण भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की आबादी तेजी से बढ़ रही है (2050 तक कुल जनसंख्या का लगभग 20% होने का अनुमान)। वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य देखभाल (आयुष्मान वय वंदना), पेंशन, सहायक उपकरण और वृद्धाश्रम से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को 'सिल्वर इकोनॉमी' कहा जाता है।

अभ्यास प्रश्न #41 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 11. 'छिपी हुई भूख' (Hidden Hunger) क्या है और इसके समाधान के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर एवं व्याख्या: पर्याप्त कैलोरी युक्त भोजन मिलने के बावजूद जब शरीर में आवश्यक **सूक्ष्म पोषक तत्वों (Micronutrients — जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन-A, फोलिक एसिड)** की कमी हो जाती है, तो उसे 'छिपी हुई भूख' कहते हैं। इसके समाधान हेतु सरकार **'फूड फोर्टिफिकेशन' (चावल का पोषण संवर्धन)**, पोषण अभियान 2.0 और एनीमिया मुक्त भारत चला रही है।

अभ्यास प्रश्न #42 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 12. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार योगदान देती है?

उत्तर एवं व्याख्या: आर्थिक सर्वेक्षण एवं पीआईबी प्रतिवेदन के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA, 2013) के तहत लगभग **81.4 करोड़ लाभार्थियों** (अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किग्रा प्रति परिवार तथा प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 किग्रा प्रति व्यक्ति प्रतिमाह) को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

अभ्यास प्रश्न #43 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 13. सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी मापन में कौन-सा प्रमुख पद्धतिगत परिवर्तन किया था?

उत्तर एवं व्याख्या: तेंदुलकर समिति (2009) ने तीन बड़े बदलाव किए: (1) कैलोरी-आधारित मानक को छोड़ दिया, (2) शहरी गरीबी रेखा की उपभोग टोकरी को ही ग्रामीण व शहरी दोनों के लिए आधार बनाया, और (3) स्वास्थ्य व शिक्षा पर होने वाले निजी खर्च को गरीबी रेखा के आकलन में शामिल किया।

अभ्यास प्रश्न #44 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 14. 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' (Aspirational Districts Programme - ADP) और 'आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम' (ABP) का उद्देश्य क्या है?

उत्तर एवं व्याख्या: नीति आयोग द्वारा जनवरी 2018 में प्रारंभ किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम (112 जिले) और बाद में प्रारंभ आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (500 ब्लॉक) का उद्देश्य **अभिसरण (Convergence), सहयोग (Collaboration) और प्रतिस्पर्धा (Competition)** के माध्यम से देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और बुनियादी ढाँचे का तीव्र विकास करना है।

अभ्यास प्रश्न #45 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 15. मुख्य परीक्षा (Mains) दृष्टिकोण: भारत में उत्तर और दक्षिण के राज्यों के मध्य उभरते जनसांख्यिकीय अंतराल (Demographic Divide) के क्या निहितार्थ हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: दक्षिणी राज्यों (केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश) में प्रजनन दर पहले ही कम होने से वहाँ कार्यशील आबादी स्थिर/वृद्ध हो रही है, जबकि उत्तर-मध्य राज्यों (बिहार, उत्तर प्रदेश) में युवा कार्यबल का अनुपात अधिक है। इसके तीन प्रमुख निहितार्थ हैं: (1) उत्तर से दक्षिण की ओर आंतरिक श्रम प्रवासन में वृद्धि, (2) वित्त आयोग के कर हस्तांतरण (जनसांख्यिकीय प्रदर्शन मानदंड) पर बहस, और (3) भविष्य के संसदीय परिसीमन में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व संतुलन की आवश्यकता।

अध्याय 4: शहरीकरण, उनकी समस्याएँ और उनके रक्षोपाय तथा प्रवासन (Migration)

4.1 विस्तृत सैद्धांतिक एवं समाजशास्त्रीय व्याख्या

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 4.1 विस्तृत सैद्धांतिक एवं समाजशास्त्रीय व्याख्या

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
(क) भारत में शहरीकरण (Urbanization): परिभाषा एवं जनगणना मानदंड	(ख) भारत में शहरीकरण की विशेष प्रवृत्तियाँ: 'अति-शहरीकरण' एवं 'छद्म शहरीकरण'	(ग) शहरीकरण की प्रमुख समस्याएँ एवं शासकीय रक्षोपाय (Urban Safeguards & Flagship Schemes)	(घ) प्रवासन (Migration): धाराएँ, कारण (Push-Pull Factors) एवं 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड'

(क) भारत में शहरीकरण (Urbanization): परिभाषा एवं जनगणना मानदंड

शहरीकरण केवल जनसंख्या का गाँवों से शहरों में स्थानांतरण नहीं है, अपितु यह कृषि-आधारित ग्रामीण समाज का गैर-कृषि (उद्योग, व्यापार एवं सेवा) आधारित नगरीय समाज और जीवन-शैली (**Urbanism as a Way of Life — लुई वर्थ**) में रूपांतरण है। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के अनुसार नगरीय क्षेत्रों को दो श्रेणियों में परिभाषित किया जाता है:

1. **वैधानिक नगर (Statutory Towns):** वे सभी स्थान जहाँ नगरपालिका (Municipality), नगर निगम (Municipal Corporation), छावनी बोर्ड (Cantonment Board) या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति विद्यमान हो।
2. **जनगणना नगर (Census Towns):** वे स्थान जो निम्नलिखित **तीनों मानदंड** एक साथ पूरे करते हैं:

- न्यूनतम जनसंख्या **5,000** हो;
- कार्यशील पुरुष जनसंख्या का कम से कम **75% गैर-कृषि कार्यों (Non-agricultural pursuits)** में संलग्न हो; तथा
- जनसंख्या घनत्व कम से कम **400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर** हो।

- **नगरीय संकुल (Urban Agglomeration - UA):** एक मुख्य नगर और उसके निरंतर शहरी फैलाव (Outgrowths) का समूह। 10 लाख (1 Million) से अधिक आबादी वाले शहरों को **'मिलियन प्लस सिटी'** और 1 करोड़ (10 Million) से अधिक आबादी वाले नगरीय संकुलों को **'मेगा सिटी' (Mega Cities — जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता)** कहा जाता है।

(ख) भारत में शहरीकरण की विशेष प्रवृत्तियाँ: 'अति-शहरीकरण' एवं 'छद्म शहरीकरण'

भारतीय शहरीकरण पश्चिमी देशों के औद्योगिक शहरीकरण से भिन्न है:

- **प्रथम-नगरीय संकेंद्रण (Top-Heavy / Lopsided Urbanization):** भारत की कुल शहरी आबादी का 70% से अधिक हिस्सा केवल **प्रथम श्रेणी के नगरों (Class-I Towns — जनसंख्या 1,00,000 या अधिक)** में केंद्रित है, जबकि छोटे और मध्यम कस्बों का विकास अपेक्षाकृत धीमा रहा है।
- **बिना औद्योगीकरण के शहरीकरण (Over-urbanization / Pseudo-urbanization):** ग्रामीण संकट (Agrarian Distress) के कारण लोग शहरों में आते हैं, किंतु विनिर्माण क्षेत्र के बजाय अनौपचारिक सेवा क्षेत्र (रेहड़ी-पटरी, गिग वर्क, निर्माण श्रम) में जुड़ते हैं, जिससे मलिन बस्तियों (Slums) का विस्तार होता है।
- **सब-अर्बनाइजेशन एवं रर्बनाइजेशन (Sub-urbanization & Rurbanization):** महानगरों के बाहरी घेरे (Peri-urban areas) का तेजी से विकास होना और ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का विस्तार होना।

(ग) शहरीकरण की प्रमुख समस्याएँ एवं शासकीय रक्षोपाय (Urban Safeguards & Flagship Schemes)

तीव्र और अनियोजित शहरीकरण से आवास की कमी, मलिन बस्ती विस्तार, शहरी बाढ़ (Urban Flooding — ड्रेनेज अतिक्रमण एवं कंक्रीटीकरण), ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संकट, वायु प्रदूषण, शहरी ताप द्वीप (**Urban Heat Island Effect**) और जल संकट जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इनके समाधान हेतु भारत सरकार ने व्यापक मिशन चलाए हैं:

- **स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 (SBM-U 2.0):** पीआईबी प्रतिवेदन (जून 2026) के अनुसार SBM-U का बजट परिव्यय चरण-1 (2014–21) के ₹62,009 करोड़ से 128.3% बढ़कर SBM-U 2.0 (2021–26) में **₹1.41 लाख करोड़** किया गया। इसके परिणामस्वरूप घर-घर कचरा संग्रहण (Door-to-door waste collection) 2014 के 43% से बढ़कर 2026 में **98%** और कचरा प्रसंस्करण (Waste Processing) 2014 के 16% से बढ़कर 2026 में **82%** हो गया है।
- **अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (AMRUT 2.0):** पीआईबी विज्ञप्ति के अनुसार 1 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ इस मिशन का उद्देश्य शहरों को **'जल सुरक्षित' (Water Secure) और 'आत्मनिर्भर'** बनाना तथा सभी वैधानिक नगरों में 100% कार्यात्मक नल कनेक्शन और 500 अमृत शहरों में 100% सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U):** पीआईबी आँकड़ों (2026) के अनुसार 2015 से 2026 के मध्य शहरी गरीबों के लिए **98.10 लाख से अधिक पक्के मकान** निर्मित किए गए हैं।

(घ) प्रवासन (Migration): धाराएँ, कारण (Push-Pull Factors) एवं 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड'

प्रवासन की चार प्रमुख आंतरिक धाराएँ हैं: (1) **ग्रामीण से ग्रामीण (Rural-to-Rural — सर्वाधिक संख्या, मुख्यतः विवाह के कारण महिलाओं का प्रवासन)**, (2) **ग्रामीण से शहरी (Rural-to-Urban — मुख्यतः रोजगार के कारण पुरुषों का प्रवासन)**, (3) शहरी से शहरी, और (4) शहरी से ग्रामीण।

- **प्रतिकर्ष कारक (Push Factors):** ग्रामीण बेरोजगारी, कृषि संकट, भूमिहीनता, बाढ़/सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएँ और जातीय भेदभाव।
- **अपकर्ष कारक (Pull Factors):** शहरों में उच्च मजदूरी, बेहतर शिक्षा व चिकित्सा सुविधाएँ, औद्योगिक रोजगार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता।
- **प्रवासी श्रमिकों हेतु पोर्टेबिलिटी सुधार — 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' (ONORC):** पीआईबी तथ्य-पत्रक (12 नवंबर 2026) के अनुसार ONORC सभी **36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 100% PMGKAY लाभार्थियों** को कवर करता है। यह प्रतिमाह लगभग **3.27 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन** सुगम बनाता है और अपने प्रारंभ से अब तक **233 करोड़ से अधिक अंतर-राज्यीय एवं अंतः-राज्यीय लेनदेन** के माध्यम से **614 लाख मीट्रिक टन (LMT) से अधिक खाद्यान्न** प्रवासी परिवारों को वितरित कर चुका है।

नगरीय संधारणीयता एवं प्रवासन सूत्र (1D Conceptual Formula):

$$संधारणीय शहरीकरण = 74वाँ संशोधन (ULB सशक्तिकरण) + चक्रीय अपशिष्ट-जल प्रबंधन (SBM 2.0 + AMRUT 2.0) + प्रवासी सामाजिक सुरक्षा (ONORC + ई-श्रम)$$

4.2 परीक्षा जाल (Exam Trap)

परीक्षा जाल (Exam Trap): जनगणना नगर मानदंड एवं भारत में प्रवासन की सबसे बड़ी धारा

1. **प्रथम भ्रम:** छात्र प्रायः परीक्षा में टिक कर देते हैं कि 'भारत में आंतरिक प्रवासन की सबसे बड़ी धारा ग्रामीण से शहरी (*Rural to Urban*) है'—यह **गलत** है। जनगणना के आँकड़ों के अनुसार भारत में कुल आंतरिक प्रवासन में **ग्रामीण से ग्रामीण (Rural-to-Rural)** धारा का हिस्सा सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें विवाह के पश्चात महिलाओं का ससुराल जाना शामिल होता है। हाँ, यदि केवल **पुरुष आर्थिक/रोजगार प्रवासन** पूछा जाए, तब 'ग्रामीण से शहरी' धारा प्रमुख होती है।
2. **द्वितीय भ्रम: जनगणना नगर (Census Town)** के दूसरे मानदंड में 'कुल जनसंख्या का 75% गैर-कृषि कार्यों में संलग्न होना' मान लेना—यह भी **गलत** है। सटीक मानदंड **'मुख्य कार्यशील पुरुष जनसंख्या (Male Main Working Population) का कम से कम 75% गैर-कृषि कार्यों में संलग्न होना'** है।
3. **तृतीय भ्रम:** जनगणना नगरों में स्वतः नगरपालिका (Municipality) का होना मान लेना। जनगणना नगर शहरी मानदंड तो पूरे करते हैं किंतु जब तक राज्य सरकार उन्हें वैधानिक नगर (Statutory Town) अधिसूचित नहीं करती, तब तक वे प्रशासनिक रूप से ग्राम पंचायत के अधीन ही रहते हैं।

4.3 4-नोड फ्लोचार्ट: ग्रामीण-शहरी प्रवासन एवं एकीकृत नगरीय प्रबंधन चक्र

[नोड 1: ग्रामीण प्रतिकर्ष (Push) एवं शहरी अपकर्ष (Pull) — कृषि संकट व बेहतर रोजगार की खोज] **[नोड 2: अनौपचारिक नगरीय दबाव — मलिन बस्तियाँ, आवास संकट एवं अपशिष्ट-जल प्रबंधन चुनौती]** **[नोड 3: मिशन-मोड नगरीय रक्षोपाय — PMAY-U (98.1 लाख आवास), SBM-U 2.0 (82% कचरा प्रसंस्करण) व AMRUT 2.0]** **[नोड 4: समावेशी प्रवासी कल्याण — ONORC (233 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन), ई-श्रम एवं PM स्वनिधि]**

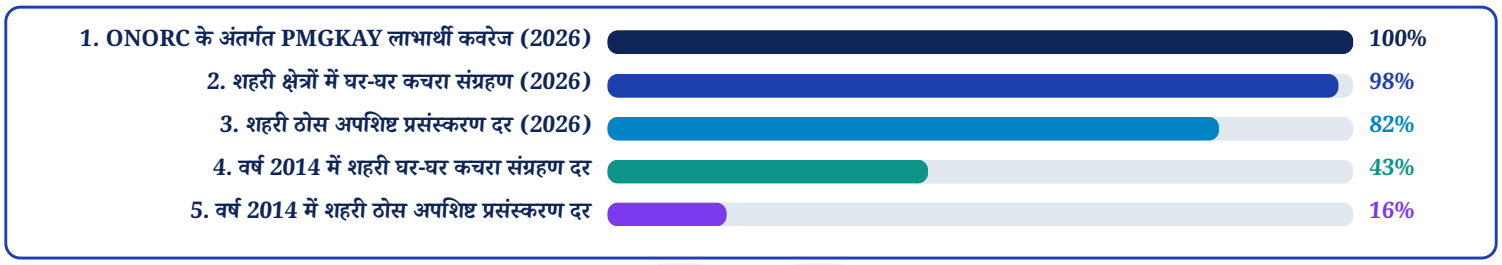
4.4 विस्तृत तुलनात्मक सारणी: शहरी पुनरुद्धार एवं प्रवासी कल्याण की प्रमुख सरकारी पहलें

योजना / सुधार मिशन	नोडल मंत्रालय / संवैधानिक आधार	मुख्य उद्देश्य एवं लक्षित घटक	प्रमाणित उपलब्धि (2026 अद्यतन) / स्रोत
74वाँ संविधान संशोधन (1992)	भाग IX-A (अनुच्छेद 243P–243ZG), 12वीं अनुसूची	शहरी स्थानीय निकायों (नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद, नगर निगम) को संवैधानिक दर्जा व **18 विषय**	जिला योजना समिति (अनु. 243ZD) एवं महानगर योजना समिति (अनु. 243ZE)
स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)	कचरा मुक्त शहर (Garbage Free Cities), लेगेसी डंपसाइट रेमेडिएशन एवं मटेरियल रिकवरी	घर-घर कचरा संग्रहण 98% एवं अपशिष्ट प्रसंस्करण 82% पहुँचा (PIB, जून 2026)
अमृत 2.0 (AMRUT 2.0)	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (2021–2026)	सभी वैधानिक शहरों में 100% नल जल आपूर्ति, जल निकायों का कायाकल्प एवं चक्रीय जल अर्थव्यवस्था	500 शहरों से विस्तार कर सभी वैधानिक नगरों को जल-सुरक्षित बनाना

योजना / सुधार मिशन	नोडल मंत्रालय / संवैधानिक आधार	मुख्य उद्देश्य एवं लक्षित घटक	प्रमाणित उपलब्धि (2026 अद्यतन) / स्रोत
प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (2015 से)	मलिन बस्ती पुनर्विकास (ISSR), ऋण आधारित सब्सिडी (CLSS), किफायती आवास (AHP) व लाभार्थी निर्माण (BLC)	98.10 लाख से अधिक शहरी आवास पूर्ण; 2026-27 बजट ₹18,625.05 करोड़
एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC)	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से देश की किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से राशन प्राप्त करने की सुविधा	36 राज्यों/UTs में 100% कवरेज; 233 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन (PIB, नवंबर 2026)

4.5 चार्ट डेटा %: शहरी स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन एवं राशन पोर्टेबिलिटी प्रगति

निम्नलिखित आँकड़े पीआईबी के जून 2026 प्रतिवेदन और ONORC नवंबर 2026 तथ्य-पत्रक पर आधारित हैं:



4.6 स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks)

• **जनगणना नगर (Census Town) के 3 मानदंड याद रखने का सूत्र — "5 हजार लोग, 75 पुरुष गैर-कृषि, 400 घनत्व":**

1. **5,000:** न्यूनतम जनसंख्या
2. **75%:** मुख्य कार्यशील पुरुष आबादी गैर-कृषि कार्यों में
3. **400:** व्यक्ति प्रति वर्ग किमी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व

• **शहरी समस्याओं के 5 समाधान स्तंभ (5S of Urban Safeguards):**

• **S1 - Sanitation:** SBM-Urban 2.0 (कचरा मुक्त शहर)

• **S2 - Supply of Water:** AMRUT 2.0 (जल सुरक्षित शहर)

• **S3 - Shelter:** PMAY-Urban (सबके लिए पक्का आवास)

• **S4 - Street Vendors & Migrants:** PM SVANidhi + ONORC + e-Shram

• **S5 - Smart Governance:** Smart Cities Mission (ICCC - Integrated Command and Control Centres)

4.7 अभ्यास प्रश्नोत्तर (15 व्याख्यात्मक प्रश्न — अध्याय 4)

अभ्यास प्रश्न #46 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 1. भारत में किसी बस्ती को 'जनगणना नगर' (Census Town) घोषित करने के लिए कौन-सी तीन शर्तें आवश्यक हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: (1) न्यूनतम जनसंख्या 5,000 हो, (2) मुख्य कार्यशील पुरुष जनसंख्या का कम से कम 75% गैर-कृषि गतिविधियों में संलग्न हो, और (3) जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो।

अभ्यास प्रश्न #47 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 2. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में कौन-सी अनुसूची जोड़ी गई और इसमें कितने विषय हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: इसके द्वारा संविधान में **भाग IX-A** और **बारहवीं अनुसूची (12th Schedule)** जोड़ी गई, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के कार्यक्षेत्र से संबंधित **18 कार्यात्मक विषय** (जैसे—नगरीय नियोजन, जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मलिन बस्ती सुधार आदि) शामिल हैं।

अभ्यास प्रश्न #48 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 3. 'शहरी ताप द्वीप प्रभाव' (Urban Heat Island Effect - UHI) क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: जब किसी महानगर या शहरी क्षेत्र का तापमान उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक (2°C से 5°C तक अधिक) हो जाता है, तो इसे 'शहरी ताप द्वीप प्रभाव' कहते हैं। इसके मुख्य कारण हरित क्षेत्रों व जल निकायों का विनाश, कंक्रीट और डामर (Asphalt) द्वारा सौर विकिरण का अवशोषण, काँच की गगनचुंबी इमारतें और वाहनों व एयर-कंडीशनर से निकलने वाली अपशिष्ट ऊष्मा हैं।

अभ्यास प्रश्न #49 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 4. 'रर्बनाइजेशन' (Rurbanization) की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया और भारत में इससे जुड़ी योजना कौन-सी है?

उत्तर एवं व्याख्या: समाजशास्त्रीय रूप से भारत में **जी. एस. घुर्ये** और वैश्विक स्तर पर सी. जे. गैलपिन ने इसका प्रयोग किया। भारत सरकार का **श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन (SPMRM)** इसी अवधारणा पर आधारित है, जिसका मूल मंत्र है—"ग्रामीण आत्मा का संरक्षण, किंतु शहरी सुविधाओं की उपलब्धता" (Soul of a village, facilities of a city)।

अभ्यास प्रश्न #50 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 5. पीआईबी के नवंबर 2026 तथ्य-पत्रक के अनुसार 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' (ONORC) ने प्रवासी श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा में क्या उपलब्धि हासिल की है?

उत्तर एवं व्याख्या: ONORC देश के सभी **36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों** में लागू है तथा 100% PMGKAY लाभार्थियों को कवर करता है। यह प्रतिमाह औसतन **3.27 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन** संपन्न करता है और प्रारंभ से नवंबर 2026 तक **233 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन** के माध्यम से **614 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न** वितरित कर चुका है।

अभ्यास प्रश्न #51 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 6. शहरी बाढ़ (Urban Flooding) ग्रामीण बाढ़ से किस प्रकार भिन्न है?

उत्तर एवं व्याख्या: ग्रामीण बाढ़ मुख्यतः नदियों के अपने तटबंध तोड़ने और विस्तृत मैदानों में फैलने से आती है, जबकि **शहरी बाढ़** मुख्यतः मानव-जनित कारकों—जैसे प्राकृतिक जल निकासी नालों व आर्द्रभूमियों (Wetlands) पर अवैध निर्माण, कंक्रीटीकरण के कारण वर्षा जल का भूमि में रिसाव न हो पाना (Zero Percolation) और प्लास्टिक कचरे से स्टॉर्म-वाटर ड्रेन के जाम होने—के कारण कुछ ही घंटों की तीव्र वर्षा में उत्पन्न हो जाती है।

अभ्यास प्रश्न #52 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 7. पीआईबी के जून 2026 प्रतिवेदन के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (SBM-U 2.0) के तहत कचरा संग्रहण और प्रसंस्करण में कितना सुधार हुआ है?

उत्तर एवं व्याख्या: घर-घर से कचरा संग्रहण (Door-to-door waste collection) वर्ष 2014 के 43% से बढ़कर 2026 में **98%** हो गया है, जबकि संग्रहण एवं मटेरियल रिकवरी केंद्रों पर अपशिष्ट प्रसंस्करण (Waste Processing) वर्ष 2014 के मात्र 16% से बढ़कर 2026 में **82%** तक पहुँच गया है।

अभ्यास प्रश्न #53 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 8. 'चक्रीय प्रवासन' (Circular Migration) या 'मौसमी प्रवासन' (Seasonal Migration) क्या है?

उत्तर एवं व्याख्या: जब ग्रामीण श्रमिक कृषि के खाली महीनों (Off-season) में रोजगार के लिए शहरों या ईंट-भट्ठों, निर्माण स्थलों व अन्य राज्यों के खेतों में जाते हैं और बुवाई या कटाई के समय वापस अपने गाँव लौट आते हैं, तो इस आवर्ती आवागमन को 'चक्रीय प्रवासन' कहते हैं।

अभ्यास प्रश्न #54 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 9. विश्व बैंक के अनुसार प्रेषित धन (Remittances) प्राप्त करने के मामले में भारत का विश्व में कौन-सा स्थान है?

उत्तर एवं व्याख्या: आर्थिक सर्वेक्षण एवं पीआईबी प्रतिवेदन के अनुसार भारत विश्व में प्रेषित धन (Remittances) प्राप्त करने वाला **शीर्ष (प्रथम) देश** है, जिसने 2022 में ही 100 अरब अमेरिकी डॉलर का ऐतिहासिक आँकड़ा पार कर लिया था और यह भारत के चालू खाता घाटे (CAD) को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अभ्यास प्रश्न #55 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 10. 'पीएम स्वनिधि' (PM SVANidhi) योजना शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को कैसे सशक्त करती है?

उत्तर एवं व्याख्या: प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) रेहड़ी-पटरी वालों (Street Vendors) को बिना किसी गारंटी (Collateral-free) के चरणबद्ध कार्यशील पूंजी ऋण (₹10,000, ₹20,000 और ₹50,000), समय पर भुगतान पर 7% ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेनदेन पर कैशबैक प्रदान कर उन्हें साहूकारों के चंगुल से मुक्त करती है।

अभ्यास प्रश्न #56 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 11. 'मेगा सिटी' (Mega City) और 'प्राइमेट सिटी' (Primate City) में क्या अंतर है?

उत्तर एवं व्याख्या: मेगा सिटी वह नगरीय संकुल है जिसकी कुल जनसंख्या **1 करोड़ (10 Million) या उससे अधिक** हो। जबकि **प्राइमेट सिटी** (मार्क जेफरसन द्वारा प्रतिपादित) किसी देश या राज्य का वह सर्वोच्च शहर होता है जो जनसंख्या और आर्थिक-राजनीतिक प्रभाव में अपने ही क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े शहर से कई गुना बड़ा होता है (जैसे—पश्चिम बंगाल में कोलकाता या महाराष्ट्र में मुंबई)।

अभ्यास प्रश्न #57 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 12. 74वें संविधान संशोधन के बावजूद भारतीय नगर निगमों (Municipal Corporations) की वित्तीय कमजोरी के मुख्य कारण क्या हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: इसे **'3Fs की कमी' (Lack of Funds, Functions and Functionaries)** कहा जाता है: (1) राज्य सरकारों द्वारा 12वीं अनुसूची के सभी 18 विषयों का पूर्ण हस्तांतरण न करना, (2) संपत्ति कर (Property Tax) का कम संग्रहण, (3) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन में देरी, और (4) म्युनिसिपल बॉन्ड बाजार में सीमित भागीदारी।

अभ्यास प्रश्न #58 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 13. 'जिला योजना समिति' (District Planning Committee - DPC) का संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

उत्तर एवं व्याख्या: भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 243ZD** के तहत प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने हेतु 'जिला योजना समिति' के गठन का प्रावधान है।

अभ्यास प्रश्न #59 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 14. 'ई-श्रम पोर्टल' (e-Shram Portal) प्रवासी और असंगठित श्रमिकों के लिए क्यों बनाया गया है?

उत्तर एवं व्याख्या: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ 'ई-श्रम पोर्टल' असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों (निर्माण मजदूर, प्रवासी श्रमिक, गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स, घरेलू कामगार) का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है, जो प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को 12 अंकों का सार्वभौमिक खाता संख्या (UAN) कार्ड और दुर्घटना बीमा व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पोर्टेबिलिटी प्रदान करता है।

अभ्यास प्रश्न #60 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 15. मुख्य परीक्षा (Mains) दृष्टिकोण: भारत में ग्रामीण से शहरी प्रवासन के दबाव को कम करने के लिए 'PURA' और 'Tier-2/Tier-3 शहरों' का विकास क्यों आवश्यक है?

उत्तर एवं व्याख्या: डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तुत **PURA (Provision of Urban Amenities to Rural Areas)** मॉडल के अनुसार यदि ग्रामीण क्लस्टरों और टियर-2/टियर-3 कस्बों में भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक और ज्ञान कनेक्टिविटी विकसित कर कृषि-प्रसंस्करण व एमएसएमई उद्योग लगाए जाएँ, तो महानगरों पर अत्यधिक जनसंख्या दबाव घटेगा और संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित होगा।

अध्याय 5: भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण (Globalization) का प्रभाव

5.1 विस्तृत सैद्धांतिक एवं समाजशास्त्रीय व्याख्या

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 5.1 विस्तृत सैद्धांतिक एवं समाजशास्त्रीय व्याख्या

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
(क) भूमंडलीकरण की अवधारणा एवं भारत में इसका विकास	**(ख) सांस्कृतिक प्रभाव: समरूपीकरण, ग्लोकलाइजेशन एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान**	**(ग) विभिन्न सामाजिक वर्गों एवं संस्थाओं पर भूमंडलीकरण का प्रभाव**

(क) भूमंडलीकरण की अवधारणा एवं भारत में इसका विकास

भूमंडलीकरण (Globalization) वह बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विश्व के विभिन्न समाज, अर्थव्यवस्थाएँ और संस्कृतियाँ वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी, सूचना और विचारों के मुक्त प्रवाह द्वारा परस्पर एकीकृत और अंतर-निर्भर हो जाती हैं। समाजशास्त्री **एंथोनी गिडेंस (Anthony Giddens)** ने इसे 'समय और स्थान के संपीड़न' (*Time-Space Compression*) तथा विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों के सघनीकरण के रूप में परिभाषित किया है।

भारत में सांस्कृतिक और व्यापारिक वैश्वीकरण सिंधु घाटी सभ्यता और रेशम मार्ग के काल से ही विद्यमान रहा ('वसुधैव कुटुम्बकम्'), किंतु आधुनिक आर्थिक एवं संरचनात्मक भूमंडलीकरण वर्ष **1991 के आर्थिक सुधारों (LPG — Liberalization, Privatization, Globalization)** के पश्चात तीव्र हुआ।

(ख) सांस्कृतिक प्रभाव: समरूपीकरण, ग्लोकलाइजेशन एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान

भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को तीन समाजशास्त्रीय प्रतिमानों में समझा जाता है:

1. **सांस्कृतिक समरूपीकरण (Cultural Homogenization / McDonaldization):** समाजशास्त्री **जॉर्ज रित्ज़र (George Ritzer)** ने इसे 'मैकडोनाल्डाइजेशन' कहा है, जहाँ पश्चिमी उपभोक्तावाद, फास्ट-फूड संस्कृति, जींस-टीशर्ट, अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व और ओटीटी/हॉलीवुड मीडिया वैश्विक स्तर पर एक जैसी जीवन-शैली थोपते हैं।

2. **ग्लोकलाइजेशन (Glocalization = Global + Local):** समाजशास्त्री **रोलैंड रॉबर्टसन (Roland Robertson)** द्वारा प्रतिपादित इस अवधारणा के अनुसार वैश्विक उत्पाद और विचार जब भारत में आते हैं, तो वे भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप ढल जाते हैं। उदाहरणार्थ—मैकडोनाल्ड द्वारा भारत में बीफ/पोर्क हटाकर 'मैकआलू टिक्की' और नवरात्रि व्रत मेनू परोसना, या अंतरराष्ट्रीय चैनलों का हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण करना।

3. **सांस्कृतिक पुनरुत्थान एवं सॉफ्ट पावर (Cultural Revivalism & Indian Soft Power):** भूमंडलीकरण एकतरफा नहीं है; भारत ने भी योग (21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस), आयुर्वेद, शास्त्रीय संगीत, बॉलीवुड, भारतीय व्यंजन, आध्यात्मिकता और अंतरराष्ट्रीय श्री अन्न (Millets) वर्ष के माध्यम से अपनी वैश्विक 'सॉफ्ट पावर' का विस्तार किया है।

(ग) विभिन्न सामाजिक वर्गों एवं संस्थाओं पर भूमंडलीकरण का प्रभाव

• **परिवार एवं विवाह पर प्रभाव:** बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) और आईटी सेक्टर में रोजगार से युवाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ी है, जिससे प्रेम विवाह, अंतर-जातीय विवाह, मैट्रिमोनियल वेबसाइटों का चलन और DINK (Double Income No Kids) या नाभिकीय परिवारों की प्रवृत्ति बढ़ी है। साथ ही, कार्य-दबाव के कारण वृद्ध माता-पिता में **'एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम' (Empty Nest Syndrome)** की चुनौती भी उभरी है।

• **महिलाओं पर प्रभाव:** बीपीओ, आईटी, बैंकिंग, विमानन, ई-कॉमर्स और स्टार्टअप क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुले हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया में उनकी स्वायत्तता बढ़ी है। किंतु दूसरी ओर, असंगठित निर्यात उद्योगों (गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली) में कम मजदूरी पर महिला श्रम का शोषण, कार्य और

घर का दोहरा बोझ (**Double Burden**) तथा विज्ञापनों में महिलाओं का वस्तुकरण (**Commodification of Women**) जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियाँ भी देखी गई हैं।

• **युवाओं एवं शिक्षा पर प्रभाव:** वैश्विक ज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), कोडिंग और विदेशी विश्वविद्यालयों तक पहुँच बढ़ी है, किंतु सोशल मीडिया की लत, उपभोक्तावादी तनाव, गिग इकॉनमी की असुरक्षा और पारंपरिक सामुदायिक संबंधों से अलगाव भी बढ़ा है।

• **कृषि, जनजातीय समाज एवं अनौपचारिक क्षेत्र पर प्रभाव:** नकदी फसलों, अनुबंध कृषि (Contract Farming) और कृषि-निर्यात से प्रगतिशील किसानों को लाभ हुआ है, किंतु **आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन** में रेखांकित वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं, महँगे आदानों (बीज, उर्वरक) और मूल्य उतार-चढ़ाव से सीमांत किसानों की संवेदनशीलता बढ़ी है। जनजातीय क्षेत्रों में खनन एवं औद्योगिक परियोजनाओं से विस्थापन और पारंपरिक वनोपज ज्ञान के पेटेंट (Biopiracy) का खतरा उत्पन्न हुआ है।

ग्लोकलाइजेशन संतुलन सूत्र (1D Conceptual Formula):

$$संतुलित भूमंडलीकरण (Glocalization) = वैश्विक प्रौद्योगिकी एवं बाजार पहुँच × स्वदेशी सांस्कृतिक मूल्य एवं सामाजिक सुरक्षा$$

5.2 परीक्षा जाल (Exam Trap)

परीक्षा जाल (Exam Trap): भूमंडलीकरण बनाम पश्चिमीकरण तथा ग्लोकलाइजेशन

1. **प्रथम भ्रम:** छात्र प्रायः 'भूमंडलीकरण' (*Globalization*) और 'पश्चिमीकरण' (*Westernization*) को पर्यायवाची मान लेते हैं—यह **गलत** है। एम. एन. श्रीनिवास के अनुसार 'पश्चिमीकरण' मुख्यतः 150 वर्षों के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान पश्चिमी शिक्षा व जीवन-शैली का एकतरफा प्रभाव था; जबकि 'भूमंडलीकरण' बहु-दिशात्मक (Multi-directional) वैश्विक अंतर्संबंध है जिसमें भारत की योग, आयुर्वेद, यूपीआई (DPI) और श्री अन्न जैसी परंपराएँ भी विश्व को प्रभावित कर रही हैं।
2. **द्वितीय भ्रम:** मुख्य परीक्षा में भूमंडलीकरण के प्रभाव को केवल सकारात्मक या केवल नकारात्मक लिख देना। यूपीएससी और राज्य पीसीएस में सदैव **द्वैत प्रभाव (Dual Impact — एक ओर अवसर व सशक्तिकरण, दूसरी ओर असमानता व सांस्कृतिक तनाव)** का संतुलित विश्लेषण अपेक्षित होता है।
3. **तृतीय भ्रम: 'ग्लोकलाइजेशन' (Glocalization)** शब्द का जनक जॉर्ज रित्ज़र को मान लेना। याद रखें: **जॉर्ज रित्ज़र** ने **'मैकडोनाल्डाइजेशन' (McDonaldization)** शब्द दिया था, जबकि **'ग्लोकलाइजेशन'** की समाजशास्त्रीय अवधारणा **रोलैंड रॉबर्टसन (Roland Robertson)** ने प्रतिपादित की थी।

5.3 4-नोड फ्लोचार्ट: भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण के बहुआयामी प्रभाव का चक्र

[नोड 1: 1991 के LPG सुधार एवं डिजिटल क्रांति — पूंजी, प्रौद्योगिकी, मीडिया व बहुराष्ट्रीय उद्यमों का प्रवेश] **[नोड 2: आर्थिक एवं व्यावसायिक रूपांतरण — सेवा क्षेत्र उछाल, प्रेषित धन ($100B+) एवं गिग इकॉनमी का उदय]** **[नोड 3: सामाजिक-सांस्कृतिक द्वंद्व — नाभिकीय परिवार, महिला स्वायत्तता बनाम उपभोक्तावाद व दोहरा बोझ]** **[नोड 4: ग्लोकलाइजेशन एवं भारतीय सॉफ्ट पावर — स्थानीय अनुकूलन, योग, आयुर्वेद व स्वदेशी डिजिटल स्टैक (DPI)]**

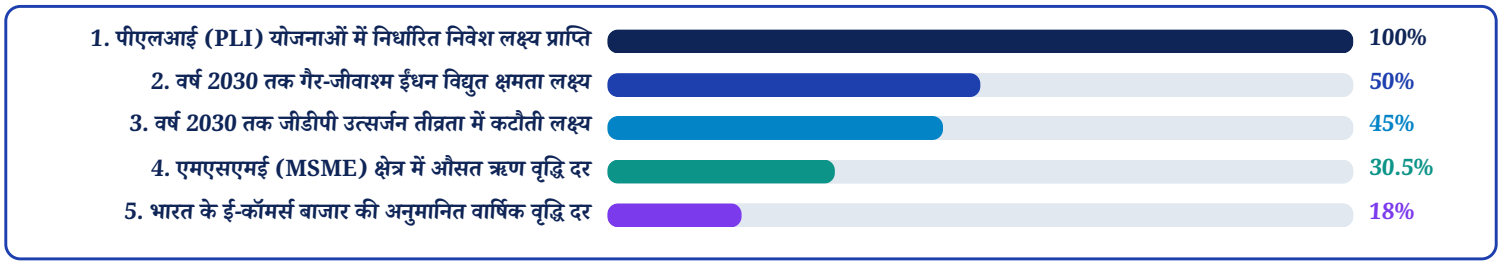
5.4 विस्तृत तुलनात्मक सारणी: भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों पर भूमंडलीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव

सामाजिक वर्ग / संस्था	सकारात्मक प्रभाव (अवसर एवं सशक्तिकरण)	नकारात्मक प्रभाव (चुनौतियाँ एवं असुरक्षा)	नीतिगत समाधान एवं अनुकूलन
महिलाएँ	आईटी, बीपीओ, बैंकिंग व ई-कॉमर्स में रोजगार; आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं निर्णय क्षमता में वृद्धि	असंगठित क्षेत्र में कम वेतन; घर व दफ्तर का 'दोहरा बोझ'; विज्ञापनों में वस्तुकरण	मातृत्व लाभ अधिनियम, POSH कानून, लखपति दीदी एवं क्रेच (पालना) सुविधा
युवा वर्ग	वैश्विक रोजगार, स्टार्टअप इकोसिस्टम, उच्च शिक्षा एवं डिजिटल कौशल तक सीधी पहुँच	'गिग इकॉनमी' में सामाजिक सुरक्षा का अभाव; मानसिक तनाव, उपभोक्तावाद व साइबर अलगाव	स्किल इंडिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एवं सामाजिक सुरक्षा संहिता
परिवार एवं वृद्धजन	जीवन-स्तर में सुधार, टेलीमेडिसिन एवं डिजिटल भुगतान से वित्तीय सुगमता	संयुक्त परिवारों का आवासीय बिखराव; वृद्धों में 'एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम' व अकेलापन	माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम, 2007 एवं आयुष्मान वय वंदना
कृषि एवं ग्रामीण समाज	कृषि निर्यात, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन एवं अनुबंध कृषि से बाजार विस्तार	वैश्विक कीमतों के उतार-चढ़ाव का जोखिम; महँगे संकर बीज व रासायनिक आदानों पर निर्भरता	पीएम-किसान, ई-नाम (e-NAM), एफपीओ (FPOs) एवं **श्री अन्न (Millets) प्रोत्साहन**

सामाजिक वर्ग / संस्था	सकारात्मक प्रभाव (अवसर एवं सशक्तिकरण)	नकारात्मक प्रभाव (चुनौतियाँ एवं असुरक्षा)	नीतिगत समाधान एवं अनुकूलन
जनजातीय एवं हस्तशिल्प समुदाय	जीआई टैग (GI Tag), ट्राइफेड (TRIFED) और ई-कॉमर्स से जनजातीय कला को वैश्विक बाजार	सस्ते मशीन-निर्मित आयातित सामानों से पारंपरिक कारीगरों को प्रतिस्पर्धा; विस्थापन	पीएम विश्वकर्मा योजना, वन धन विकास केंद्र एवं पेसा (PESA) अधिनियम

5.5 चार्ट डेटा %: भूमंडलीकरण एवं डिजिटल-आर्थिक एकीकरण के प्रमुख संकेतक

निम्नलिखित आँकड़े आर्थिक सर्वेक्षण पीआईबी प्रतिवेदन और एनएफएचएस-6/पीआईबी प्रतिवेदन (2026) पर आधारित हैं:



5.6 स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks)

- **भूमंडलीकरण के सांस्कृतिक सिद्धांतकारों की ट्रिक — "गिडेंस का संपीड़न, रित्ज़र का मैकडोनाल्ड, रॉबर्टसन का ग्लोकल, ऐपदुराई के 5 स्केप्स":**

1. **एंथोनी गिडेंस:** समय-स्थान संपीड़न (Time-Space Compression)
2. **जॉर्ज रित्ज़र:** समाज का मैकडोनाल्डाइजेशन (McDonaldization of Society)
3. **रोलैंड रॉबर्टसन:** ग्लोकलाइजेशन (Glocalization)
4. **अर्जुन ऐपदुराई:** वैश्विक सांस्कृतिक प्रवाह के 5 आयाम (Ethnoscapes, Mediascapes, Technoscapes, Financescapes, Ideoscapes)

- **भारतीय समाज के 6 वर्गों पर भूमंडलीकरण का प्रभाव याद रखने का सूत्र — "म-यु-व-कि-ज-भा" (महिला, युवा, वृद्ध, किसान, जनजाति, भाषा-संस्कृति)।**

5.7 अभ्यास प्रश्नोत्तर (15 व्याख्यात्मक प्रश्न — अध्याय 5)

अभ्यास प्रश्न #61 — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 1. समाजशास्त्र में 'ग्लोकलाइजेशन' (Glocalization) शब्द का प्रतिपादन किसने किया और इसका अर्थ क्या है?

उत्तर एवं व्याख्या: समाजशास्त्री **रोलैंड रॉबर्टसन (Roland Robertson)** ने जापानी व्यापारिक शब्द 'दोचाकुका' से प्रेरित होकर 'ग्लोकलाइजेशन' (Global + Local) की अवधारणा दी। इसका अर्थ वैश्विक उत्पादों, सेवाओं या विचारों का किसी स्थानीय संस्कृति और परंपरा के अनुरूप अनुकूलन (Local Adaptation of Global Products) है—जैसे भारत में बहुराष्ट्रीय फास्ट-फूड कंपनियों द्वारा शाकाहारी और स्थानीय मसालों वाले व्यंजन परोसना।

अभ्यास प्रश्न #62 — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 2. अर्जुन ऐपदुराई (Arjun Appadurai) ने भूमंडलीकरण के सांस्कृतिक प्रवाह को समझाने के लिए किन '5 स्केप्स' (Five Scapes) की चर्चा की है?

उत्तर एवं व्याख्या: भारतीय-अमेरिकी मानवशास्त्री अर्जुन ऐपदुराई ने अपनी पुस्तक *Modernity at Large* में वैश्विक प्रवाह के 5 आयाम बताए हैं:

1. **एथनोस्केप (Ethnoscape):** पर्यटकों, प्रवासियों, शरणार्थियों और श्रमिकों का प्रवाह।

2. **टेक्नोस्केप (Technoscape):** प्रौद्योगिकी का तीव्र सीमा-पार प्रवाह।
3. **फाइनेंसस्केप (Financescape):** वैश्विक पूंजी, शेयर बाजार और मुद्रा का प्रवाह।
4. **मीडियास्केप (Mediascape):** डिजिटल मीडिया, सिनेमा और समाचार चैनलों का प्रवाह।
5. **आइडियोस्केप (Ideoscape):** लोकतंत्र, मानवाधिकार, पर्यावरणवाद और संप्रभुता जैसी विचारधाराओं का प्रवाह।

अभ्यास प्रश्न #63 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 3. 'समाज का मैकडोनाल्डाइजेशन' (McDonaldization of Society) किसकी अवधारणा है?

उत्तर एवं व्याख्या: अमेरिकी समाजशास्त्री **जॉर्ज रित्ज़र (George Ritzer)** ने 1993 में यह अवधारणा दी। उनके अनुसार आधुनिक भूमंडलीकृत समाज फास्ट-फूड रेस्तरां के चार सिद्धांतों—दक्षता (Efficiency), गणनीयता (Calculability), पूर्वानुमेयता (Predictability) और नियंत्रण (Control)—को शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन में अपना रहा है, जिससे मानवीय संवेदनाओं का यांत्रिकीकरण हो रहा है।

अभ्यास प्रश्न #64 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 4. भूमंडलीकरण के युग में वृद्धजनों में देखी जाने वाली 'एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम' (Empty Nest Syndrome) क्या है?

उत्तर एवं व्याख्या: जब परिवार के युवा बच्चे उच्च शिक्षा या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार के लिए महानगरों या विदेशों में बस जाते हैं और घर में केवल वृद्ध माता-पिता अकेले रह जाते हैं, तो उनमें उत्पन्न होने वाले भावनात्मक अकेलेपन, अवसाद और असुरक्षा की स्थिति को 'एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम' कहा जाता है।

अभ्यास प्रश्न #65 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 5. 'बायोपायरेसी' (Biopiracy) क्या है और भारत ने इससे अपने पारंपरिक ज्ञान की रक्षा कैसे की है?

उत्तर एवं व्याख्या: जब बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ किसी देश के स्वदेशी समुदायों के पारंपरिक जैविक संसाधनों और औषधीय ज्ञान (जैसे—हल्दी, नीम, बासमती चावल) पर बिना अनुमति या लाभ-साझाकरण के पेटेंट प्राप्त करने का प्रयास करती हैं, तो इसे 'बायोपायरेसी' कहते हैं। भारत ने इसकी रोकथाम के लिए **'पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय' (TKDL - Traditional Knowledge Digital Library)** और जैव विविधता अधिनियम, 2002 का निर्माण किया है।

अभ्यास प्रश्न #66 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 6. भूमंडलीकरण ने भारत की जाति व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया है?

उत्तर एवं व्याख्या: भूमंडलीकरण और बाजार अर्थव्यवस्था ने कॉर्पोरेट कार्यस्थलों, सार्वजनिक परिवहन, होटलों और महानगरों में जातिगत छुआछूत व खान-पान के प्रतिबंधों को कमजोर किया है तथा कौशल-आधारित रोजगार (Meritocracy) को बढ़ावा दिया है। किंतु वैवाहिक क्षेत्र में ऑनलाइन मैट्रिमोनियल पोर्टलों के माध्यम से जातिगत अंतर्विवाह (Cyber-Endogamy) आज भी बना हुआ है।

अभ्यास प्रश्न #67 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 7. 'सांस्कृतिक साम्राज्यवाद' (Cultural Imperialism) या 'सांस्कृतिक समरूपीकरण' से क्या आशय है?

उत्तर एवं व्याख्या: जब आर्थिक और तकनीकी रूप से संपन्न पश्चिमी देशों की भाषा (अंग्रेजी), खान-पान, पहनावा और उपभोक्तावादी जीवन-शैली मीडिया व बाजार के माध्यम से विकासशील देशों की स्थानीय भाषाओं, लोक कलाओं और जीवन-मूल्यों पर हावी होकर उन्हें एकरूप बनाने लगती है, तो इसे सांस्कृतिक समरूपीकरण या सांस्कृतिक साम्राज्यवाद कहा जाता है।

अभ्यास प्रश्न #68 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 8. 'सॉफ्ट पावर' (Soft Power) क्या है और भूमंडलीकरण में भारत के प्रमुख सॉफ्ट पावर स्तंभ कौन-से हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: जोसेफ नाई (Joseph Nye) द्वारा प्रतिपादित 'सॉफ्ट पावर' किसी देश की सैन्य या आर्थिक बल प्रयोग के बजाय अपनी संस्कृति, राजनीतिक मूल्यों और विदेश नीति के आकर्षण से अन्य देशों को प्रभावित करने की क्षमता है। भारत के प्रमुख सॉफ्ट पावर स्तंभों में **योग, आयुर्वेद, बौद्ध विरासत, भारतीय सिनेमा, प्रवासी भारतीय (Diaspora), वैक्सीन मैत्री और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (UPI)** शामिल हैं।

अभ्यास प्रश्न #69 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 9. भूमंडलीकरण ने भारतीय महिलाओं के लिए 'दोहरे बोझ' (Dual Burden / Second Shift) की समस्या कैसे उत्पन्न की है?

उत्तर एवं व्याख्या: समाजशास्त्री अर्ली होचशिल्ड के अनुसार भूमंडलीकरण ने महिलाओं को घर से बाहर संगठित व कॉर्पोरेट क्षेत्र में वेतनभोगी रोजगार के अवसर तो दिए, किंतु परिवार के भीतर पितृसत्तात्मक श्रम-विभाजन में अपेक्षित बदलाव नहीं आया। फलस्वरूप कामकाजी महिलाओं को दफ्तर की 8–10 घंटे की ड्यूटी के बाद घर लौटकर रसोई और बच्चों/बुजुर्गों की देखभाल की 'दूसरी पाली' (Second Shift) भी निभानी पड़ती है।

अभ्यास प्रश्न #70 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 10. भारत के कुटीर और हस्तशिल्प उद्योगों पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर एवं व्याख्या: एक ओर सस्ते मशीन-निर्मित आयातित उत्पादों ने पारंपरिक कुम्हारों, बुनकरों और खिलौना कारीगरों की आजीविका को कड़ी चुनौती दी है; वहीं दूसरी ओर जीआई टैग (GI Tag), ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (GeM, ONDC, TRIFED) और 'वोकल फॉर लोकल' अभियान ने बनारसी साड़ी, मधुबनी पेंटिंग, भदोही कालीन और चन्नपटना खिलौनों को वैश्विक निर्यात बाजार से जोड़ा है।

अभ्यास प्रश्न #71 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 11. 'गिग और प्लेटफॉर्म इकॉनमी' (Gig & Platform Economy) भूमंडलीकरण की देन कैसे है?

उत्तर एवं व्याख्या: वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप-आधारित सेवा कंपनियों (राइड-शेयरिंग, फूड डिलीवरी, फ्रीलांस कोडिंग) ने स्थायी नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के स्थान पर लचीले, कार्य-आधारित (Task-based) रोजगार मॉडल को जन्म दिया है। नीति आयोग के अनुसार भारत में गिग वर्कर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिनके कल्याण हेतु 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' में पहली बार कानूनी प्रावधान किए गए हैं।

अभ्यास प्रश्न #72 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 12. भारतीय भाषाओं पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर एवं व्याख्या: प्रारंभिक चरण में कॉर्पोरेट रोजगार और इंटरनेट पर अंग्रेजी के प्रभुत्व से क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के हाशियाकरण का संकट उत्पन्न हुआ; किंतु हाल के वर्षों में स्थानीय भाषा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की वृद्धि, वॉयस सर्च, एआई अनुवाद (भाषिणी मिशन) और ओटीटी प्लेटफॉर्मों के क्षेत्रीय विस्तार ने भारतीय भाषाओं को नया डिजिटल बाज़ार प्रदान किया है।

अभ्यास प्रश्न #73 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 13. 'चिकित्सा पर्यटन' (Medical Tourism) क्या है और भारत इसका वैश्विक केंद्र क्यों बन रहा है?

उत्तर एवं व्याख्या: जब विदेशी नागरिक उन्नत और किफायती चिकित्सा उपचार (जैसे—हृदय शल्य चिकित्सा, अंग प्रत्यारोपण, ऑर्थोपेडिक सर्जरी) तथा पारंपरिक आयुष उपचार (आयुर्वेद एवं योग वेलनेस) के लिए भारत आते हैं, तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। विश्वस्तरीय चिकित्सक, पश्चिमी देशों की तुलना में 60–80% कम लागत और 'हील इन इंडिया' (Heal in India) पहल इसके प्रमुख कारक हैं।

अभ्यास प्रश्न #74 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 14. 'वि-भूमंडलीकरण' (De-globalization) और 'फ्रेंड-शोरिंग' (Friend-shoring) क्या हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: कोविड-19 महामारी और भू-राजनीतिक संघर्षों के बाद जब देश अत्यधिक वैश्विक निर्भरता को घटाकर संरक्षणवाद, आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला और भरोसेमंद मित्र देशों के साथ ही विनिर्माण साझेदारी (Friend-shoring / China Plus One) को प्राथमिकता देते हैं, तो इसे वि-भूमंडलीकरण की प्रवृत्ति कहा जाता है। भारत ने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ** प्रारंभ की हैं।

अभ्यास प्रश्न #75 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 15. मुख्य परीक्षा (Mains) दृष्टिकोण: क्या भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज में सामाजिक असमानता को बढ़ाया है या घटाया है?

उत्तर एवं व्याख्या: भूमंडलीकरण ने उच्च-कौशल युक्त शहरी मध्यम वर्ग के विस्तार और **बहुआयामी गरीबी में कमी (14.96%)** में योगदान देकर निरपेक्ष गरीबी (Absolute Poverty) को घटाया है; किंतु पूंजी-गहन और कौशल-गहन क्षेत्रों को अधिक लाभ मिलने के कारण ग्रामीण बनाम शहरी, संगठित बनाम असंगठित

और डिजिटल रूप से साक्षर बनाम वंचित वर्गों के बीच सापेक्षिक असमानता (Relative Inequality) की खाई को चौड़ा भी किया है, जिसे डीबीटी और समावेशन योजनाओं से पाटा जा रहा है।

अध्याय 6: सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता

6.1 विस्तृत सैद्धांतिक एवं समाजशास्त्रीय व्याख्या

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 6.1 विस्तृत सैद्धांतिक एवं समाजशास्त्रीय व्याख्या

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
(क) सामाजिक सशक्तिकरण (Social Empowerment): अवधारणा एवं आयाम	(ख) संप्रदायवाद (Communalism): उत्पत्ति, चरण एवं निराकरण	(ग) क्षेत्रवाद (Regionalism): रूप, कारण एवं 'धरती पुत्र' सिद्धांत	(घ) धर्मनिरपेक्षता (Secularism): भारतीय मॉडल बनाम पश्चिमी मॉडल

(क) सामाजिक सशक्तिकरण (Social Empowerment): अवधारणा एवं आयाम

सामाजिक सशक्तिकरण वह बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ऐतिहासिक रूप से वंचित, हाशियाकृत और बहिष्कृत समूहों (महिलाएँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन एवं ट्रांसजेंडर) में आत्म-सम्मान, निर्णय लेने की स्वायत्तता, संसाधनों तक समान पहुँच और संस्थागत सत्ता में भागीदारी की क्षमता विकसित की जाती है। समाजशास्त्री **पाउलो फ्रेरे (Paulo Freire)** की 'चेतनाकरण' (Conscientization) और **अमर्त्य सेन** के 'क्षमता दृष्टिकोण' (Capability Approach) के अनुसार सशक्तिकरण के तीन प्रमुख स्तंभ हैं: **शैक्षिक सशक्तिकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता और राजनीतिक-संवैधानिक प्रतिनिधित्व**।

(ख) संप्रदायवाद (Communalism): उत्पत्ति, चरण एवं निराकरण

संप्रदायवाद एक ऐसी विचारधारा है जो यह मानती है कि एक धर्म के अनुयायियों के केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हित भी एक समान होते हैं और वे अन्य धर्मों के अनुयायियों के हितों से भिन्न या विरोधी होते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार **बिपिन चंद्र** ने अपनी पुस्तक *Communalism in Modern India* में संप्रदायवाद के विकास के **3 क्रमिक चरण** बताए हैं:

1. **उदारवादी या प्रथम चरण (Communal Nationalism):** यह विश्वास कि एक ही धर्म के लोगों के धर्मनिरपेक्ष (सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक) हित समान होते हैं।
2. **मध्यमार्गी या द्वितीय चरण (Liberal Communalism):** यह मान्यता कि भारत जैसे बहु-धार्मिक देश में विभिन्न धर्मों के लोगों के धर्मनिरपेक्ष हित एक-दूसरे से भिन्न (Different) होते हैं।
3. **उग्र या तृतीय चरण (Extreme/Fascist Communalism):** यह धारणा कि विभिन्न धार्मिक समुदायों के हित न केवल भिन्न हैं, अपितु एक-दूसरे के शत्रुतापूर्ण और असंगत (Mutually Hostile & Antagonistic) हैं और वे एक साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते।

• **ऐतिहासिक एवं समकालीन कारण:** ब्रिटिश औपनिवेशिक 'फूट डालो और राज करो' की नीति (1905 बंगाल विभाजन, 1909 मार्ले-मिंटो सुधार का पृथक निर्वाचक मंडल), वोट-बैंक की राजनीति, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज व हेट स्पीच तथा आर्थिक-शैक्षिक पिछड़ापन।

(ग) क्षेत्रवाद (Regionalism): रूप, कारण एवं 'धरती पुत्र' सिद्धांत

क्षेत्रवाद किसी भौगोलिक या भाषाई क्षेत्र के प्रति निवासियों का वह अत्यधिक लगाव है जो कभी-कभी राष्ट्रीय हितों के मुकाबले क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता देने लगता है। राजनीतिक वैज्ञानिक **इकबाल नारायण** के अनुसार क्षेत्रवाद के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं:

• **सकारात्मक क्षेत्रवाद:** जब क्षेत्रीय आकांक्षाएँ संवैधानिक ढाँचे के भीतर अपनी भाषा, संस्कृति के संरक्षण और संतुलित आर्थिक विकास व सुशासन (जैसे— छोटे राज्यों का गठन: उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़) की माँग करती हैं, तो यह सहकारी संघवाद को मजबूत करता है।

• **नकारात्मक क्षेत्रवाद:**

1. **अलगाववाद (Secessionism):** भारतीय संघ से अलग होने की उग्रवादी माँग।

2. **'धरती पुत्र' का सिद्धांत (Sons of the Soil Doctrine — मायरन वीनर):** यह मान्यता कि किसी राज्य के संसाधनों और रोजगारों पर केवल वहाँ के मूल निवासियों व स्थानीय भाषा-भाषियों का ही एकाधिकार होना चाहिए, जिससे अंतर-राज्यीय प्रवासियों के विरुद्ध भेदभाव उत्पन्न होता है।

3. **अंतर-राज्यीय विवाद:** नदी जल विवाद (अनुच्छेद 262 — जैसे कावेरी, कृष्णा, सतलज-यमुना लिंक) और सीमा विवाद (जैसे महाराष्ट्र-कर्नाटक बेलगावी विवाद या असम-मिजोरम सीमा विवाद)।

(घ) धर्मनिरपेक्षता (Secularism): भारतीय मॉडल बनाम पश्चिमी मॉडल

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में **'पंथनिरपेक्ष' (Secular)** शब्द जोड़ा गया, यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने **एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)** मामले में स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के जन्म से ही उसके **'मूल ढाँचे' (Basic Structure)** का अभिन्न अंग रही है। राजनीतिक दार्शनिक **राजीव भार्गव** ने भारतीय धर्मनिरपेक्षता को **'सैद्धांतिक दूरी' (Principled Distance)** का मॉडल कहा है:

- **पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता (नकारात्मक अवधारणा):** चर्च और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव (Strict Wall of Separation — जैसे फ्रांस की *Laïcité*), जहाँ राज्य धर्म के मामले में पूर्णतः अहस्तक्षेप करता है।

- **भारतीय धर्मनिरपेक्षता (सकारात्मक अवधारणा — सर्वधर्म समभाव):** भारत में राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है, किंतु वह धर्म-विरोधी या धर्म के प्रति उदासीन नहीं है। राज्य सभी धर्मों का समान सम्मान करता है और साथ ही सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकारों की रक्षा के लिए धार्मिक कुरीतियों (जैसे— अनुच्छेद 25(2) के तहत मंदिर प्रवेश, अस्पृश्यता उन्मूलन या तीन तलाक समाप्ति) में **सकारात्मक सुधारात्मक हस्तक्षेप** भी करता है।

राष्ट्रीय अखंडता संतुलन सूत्र (1D Conceptual Formula):

$$राष्ट्रीय एकीकरण = सर्वधर्म समभाव (अनुच्छेद 25-28) + सहकारी संघवाद (संतुलित क्षेत्रीय विकास) - (उग्र संप्रदायवाद + धरती पुत्र संकीर्णता)$$

6.2 परीक्षा जाल (Exam Trap)

परीक्षा जाल (Exam Trap): भारतीय बनाम पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता तथा क्षेत्रवाद की प्रकृति

1. **प्रथम भ्रम:** छात्र प्रायः लिख देते हैं कि 'भारतीय संविधान राज्य और धर्म के बीच पूर्ण अलगाव (*Strict Separation of Church and State*) की स्थापना करता है'—यह **गलत** है। पूर्ण अलगाव पश्चिमी/फ्रांसीसी मॉडल है। भारत में **'सैद्धांतिक दूरी' (Principled Distance)** और **'सर्वधर्म समभाव'** का मॉडल है, जहाँ राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अनुदान (अनुच्छेद 30) दे सकता है और सामाजिक सुधार हेतु धार्मिक प्रथाओं को विनियमित (अनुच्छेद 25(2)) भी कर सकता है।
2. **द्वितीय भ्रम:** 'क्षेत्रवाद सदैव राष्ट्र-विरोधी (*Anti-National*) होता है'—यह कथन **अशुद्ध** है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन (1956) और विकास के आधार पर नए राज्यों के गठन ने वास्तव में अलगाववादी प्रवृत्तियों को शांत कर भारत की राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत किया है।
3. **तृतीय भ्रम:** संविधान की प्रस्तावना में 'पंथनिरपेक्ष' शब्द 1976 में जुड़ने का अर्थ यह समझना कि 1976 से पहले भारत पंथनिरपेक्ष राज्य नहीं था। अनुच्छेद 14, 15, 16, 25–28 और 29–30 मूल संविधान (1950) से ही भारत को एक पंथनिरपेक्ष गणराज्य बनाते हैं।

6.3 4-नोड फ्लोचार्ट: सामाजिक वैमनस्य से संवैधानिक राष्ट्र-निर्माण का पथ

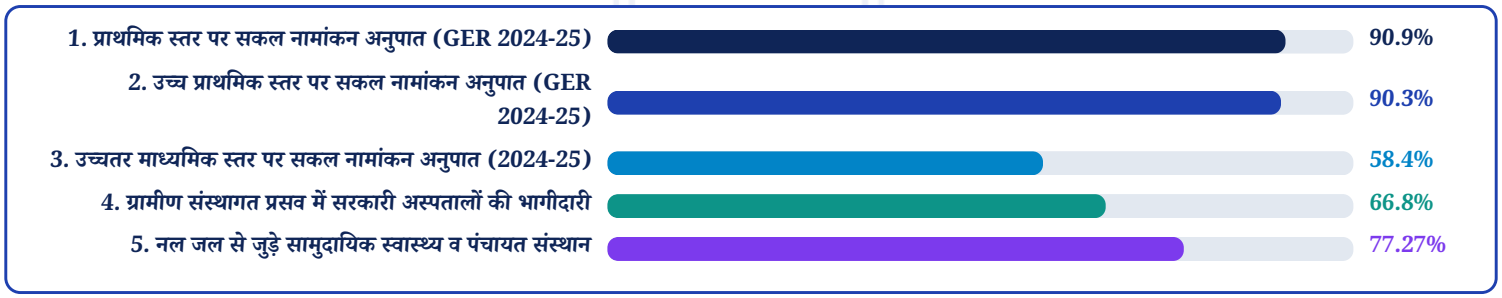
[नोड 1: ऐतिहासिक एवं संरचनात्मक चुनौतियाँ — औपनिवेशिक विभाजनकारी नीति, क्षेत्रीय असंतुलन एवं जातीय-धार्मिक ध्रुवीकरण] [नोड 2: संवैधानिक सुरक्षा कवच — प्रस्तावना, मौलिक अधिकार (अनु. 14-30) एवं एस. आर. बोम्मई निर्णय] [नोड 3: संस्थागत एवं विकासात्मक समन्वय — अंतर-राज्यीय परिषद (अनु. 263), नीति आयोग एवं आकांक्षी जिला/ब्लॉक कार्यक्रम] [नोड 4: सशक्त एवं एकीकृत भारत — सर्वधर्म समभाव, एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं समावेशी नागरिक राष्ट्रवाद]

6.4 विस्तृत तुलनात्मक सारणी: धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल बनाम भारतीय मॉडल

तुलना का आयाम	पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता (Western Secularism)	भारतीय धर्मनिरपेक्षता (Indian Secularism)	संवैधानिक / सैद्धांतिक संदर्भ
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	यूरोप में चर्च (पोप) और राजसत्ता के संघर्ष तथा पुनर्जागरण से उदय (अंत:-धार्मिक संघर्ष)	बहु-धार्मिक समाज में विभिन्न धर्मों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और सामाजिक सुधार से उदय	राजीव भार्गव (*Secularism and its Critics*)
राज्य एवं धर्म का संबंध	धर्म और राज्य के मध्य कठोर दीवार (Strict Wall of Separation); पारस्परिक बहिष्कार	**सर्वधर्म समभाव** एवं **सैद्धांतिक दूरी (Principled Distance)**; राज्य की सकारात्मक तटस्थता	एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)
धार्मिक सुधार में राज्य की भूमिका	राज्य धार्मिक मामलों में सामान्यत: हस्तक्षेप नहीं करता; धर्म पूर्णत: निजी विषय	राज्य अस्पृश्यता उन्मूलन (अनु. 17) व सभी वर्गों के लिए हिंदू धार्मिक संस्थान खोलने (अनु. 25(2)(b)) हेतु हस्तक्षेप कर सकता है	अनुच्छेद 17 एवं अनुच्छेद 25(2)
समुदाय-आधारित अधिकार	मुख्यत: व्यक्ति-केंद्रित अधिकार (Individual Rights); अल्पसंख्यक समूह अधिकारों को कम मान्यता	व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता (अनु. 25) के साथ धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों के सामूहिक सांस्कृतिक-शैक्षिक अधिकार (अनु. 29-30)	अनुच्छेद 25 से 30
सार्वजनिक प्रकटीकरण	फ्रांस जैसे देशों में सार्वजनिक स्कूलों व दफ्तरों में धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध	सार्वजनिक जीवन में सभी धर्मों के सांस्कृतिक-धार्मिक प्रतीकों व पर्वों का सम्मानजनक सह-अस्तित्व	उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक प्रतिवेदन

6.5 चार्ट डेटा %: सामाजिक सशक्तिकरण एवं क्षेत्रीय समावेशन के प्रमुख सूचकांक

निम्नलिखित आँकड़े पीआईबी के जून 2026 समावेशी परिवर्तन प्रतिवेदन और नीति आयोग VNR प्रतिवेदन पर आधारित हैं:



6.6 स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks)

- **धार्मिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद (25 से 28) याद रखने का सूत्र — "अंत:करण (25), प्रबंधन (26), कर-मुक्ति (27), शिक्षण-संस्थान (28)":**
- **अनुच्छेद 25:** अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
- **अनुच्छेद 26:** धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता।
- **अनुच्छेद 27:** किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता।
- **अनुच्छेद 28:** कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता।
- **क्षेत्रवाद के समाधान के 4C सूत्र — "Constitution (अनु. 263 अंतर-राज्यीय परिषद), Co-operative Federalism (नीति आयोग), Connectivity (पीएम गतिशक्ति), Cultural Integration (एक भारत श्रेष्ठ भारत)"।**

6.7 अभ्यास प्रश्नोत्तर (15 व्याख्यात्मक प्रश्न — अध्याय 6)

अभ्यास प्रश्न #76 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 1. बिपिन चंद्र के अनुसार संप्रदायवाद (Communalism) के तीन चरण कौन-से हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: (1) **प्रथम चरण (सांप्रदायिक राष्ट्रवाद):** एक धर्म के अनुयायियों के धर्मनिरपेक्ष हित समान होते हैं; (2) **द्वितीय चरण (उदार संप्रदायवाद):** विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के धर्मनिरपेक्ष हित एक-दूसरे से भिन्न होते हैं; तथा (3) **तृतीय चरण (उग्र संप्रदायवाद):** विभिन्न धर्मों के हित एक-दूसरे के विरोधी और शत्रुतापूर्ण होते हैं।

अभ्यास प्रश्न #77 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 2. भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में 'सैद्धांतिक दूरी' (Principled Distance) की अवधारणा किसने दी है?

उत्तर एवं व्याख्या: राजनीतिक दार्शनिक **राजीव भार्गव** ने यह अवधारणा दी। इसका अर्थ है कि भारतीय राज्य धर्म से न तो पूर्णतः कटा हुआ है और न ही किसी एक धर्म से जुड़ा है; राज्य संवैधानिक मूल्यों (समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय) को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकतानुसार धर्म में सकारात्मक हस्तक्षेप या अहस्तक्षेप का निर्णय लेता है।

अभ्यास प्रश्न #78 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 3. सर्वोच्च न्यायालय के किस ऐतिहासिक निर्णय में 'धर्मनिरपेक्षता' को संविधान के मूल ढाँचे (Basic Structure) का भाग घोषित किया गया?

उत्तर एवं व्याख्या: एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) (तथा केशवानंद भारती वाद, 1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढाँचे का अभिन्न हिस्सा है और यदि कोई राज्य सरकार धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध कार्य करती है, तो अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई वैध हो सकती है।

अभ्यास प्रश्न #79 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 4. 'धरती पुत्र का सिद्धांत' (Sons of the Soil Doctrine) क्या है और इसका समाजशास्त्रीय अध्ययन किसने किया?

उत्तर एवं व्याख्या: राजनीतिक वैज्ञानिक **मायरन वीनर (Myron Weiner)** ने अपनी पुस्तक *Sons of the Soil: Migration and Ethnic Conflict in India* में इसका विश्लेषण किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी राज्य के भूमि, संसाधनों और नौकरियों पर केवल वहाँ के मूल भाषाई/नृजातीय निवासियों का ही अधिकार माना जाता है, जो संविधान के **अनुच्छेद 19(1)(d), 19(1)(e) और 16** की भावना के प्रतिकूल है।

अभ्यास प्रश्न #80 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 5. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता पर किन तीन आधारों पर निर्बंधन (Restrictions) लगाता है?

उत्तर एवं व्याख्या: अनुच्छेद 25(1) के अनुसार अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता तीन प्रमुख आधारों के अधीन है: **(1) लोक व्यवस्था (Public Order), (2) सदाचार/नैतिकता (Morality), और (3) स्वास्थ्य (Health)** तथा भाग-III के अन्य मौलिक अधिकारों के उपबंध।

अभ्यास प्रश्न #81 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 6. भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु गठित 'फजल अली आयोग' (1953) के अन्य दो सदस्य कौन थे?

उत्तर एवं व्याख्या: दिसंबर 1953 में गठित तीन-सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष **न्यायमूर्ति फजल अली** थे और अन्य दो सदस्य **के. एम. पणिक्कर** तथा **एच. एन. कुंजरू** थे। आयोग ने 'एक भाषा-एक राज्य' के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक दक्षता और भाषाई-सांस्कृतिक एकरूपता के संतुलित आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की (7वाँ संविधान संशोधन एवं राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956)।

अभ्यास प्रश्न #82 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 7. अंतर-राज्यीय जल विवादों के न्यायनिर्णयन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

उत्तर एवं व्याख्या: **अनुच्छेद 262** संसद को अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए विधि बनाने तथा सर्वोच्च न्यायालय व अन्य न्यायालयों की अधिकारिता को अपवर्जित करने की शक्ति देता है (जिसके तहत अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 पारित हुआ)।

अभ्यास प्रश्न #83 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 8. 'क्षेत्रीय परिषदें' (Zonal Councils) संवैधानिक निकाय हैं या वैधानिक निकाय?

उत्तर एवं व्याख्या: क्षेत्रीय परिषदें **वैधानिक निकाय (Statutory Bodies)** हैं, संवैधानिक निकाय नहीं। इनका गठन संसद द्वारा पारित **राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956** के तहत देश को 5 क्षेत्रों (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी) में बाँटकर किया गया था, जबकि **पूर्वोत्तर परिषद (North Eastern Council)** का गठन एक पृथक अधिनियम (पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971) द्वारा किया गया। सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष **केंद्रीय गृह मंत्री** होते हैं।

अभ्यास प्रश्न #84 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 9. 'अंतर-राज्यीय परिषद' (Inter-State Council) का प्रावधान किस अनुच्छेद में है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: यह एक **संवैधानिक निकाय** है जिसका प्रावधान **अनुच्छेद 263** में है। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से इसका गठन किया गया और इसके पदेन अध्यक्ष **प्रधानमंत्री** होते हैं।

अभ्यास प्रश्न #85 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 10. संप्रदायवाद से निपटने के लिए 'राष्ट्रीय एकता परिषद' (National Integration Council - NIC) का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था?

उत्तर एवं व्याख्या: संप्रदायवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं से निपटने के लिए वर्ष **1961** में तत्कालीन प्रधानमंत्री **पंडित जवाहरलाल नेहरू** द्वारा एक संविधान-इतर सलाहकार निकाय के रूप में 'राष्ट्रीय एकता परिषद' का गठन किया गया था।

अभ्यास प्रश्न #86 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 11. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता - UCC) धर्मनिरपेक्षता और लैंगिक न्याय से कैसे जुड़ा है?

उत्तर एवं व्याख्या: राज्य के नीति निदेशक तत्वों के **अनुच्छेद 44** में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यह विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे दीवानी मामलों में धर्म-आधारित भेदभाव को समाप्त कर लैंगिक समानता (अनुच्छेद 14 व 15) को सुदृढ़ करता है (उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में UCC अधिनियम लागू करने वाला प्रमुख राज्य बना)।

अभ्यास प्रश्न #87 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 12. 'दबाव की राजनीति' (Politics of Accommodation) ने भारत में भाषाई क्षेत्रवाद को अलगाववाद बनने से कैसे रोका?

उत्तर एवं व्याख्या: भारत ने किसी एक भाषा को बलात् थोपने के बजाय त्रि-भाषा सूत्र (Three-Language Formula), आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को संवैधानिक सम्मान, राजभाषा अधिनियम, 1963 और भाषाई राज्यों के गठन की लचीली व समावेशी नीति अपनाई, जिसने भाषाई आंदोलनों को लोकतांत्रिक मुख्यधारा में समाहित कर लिया।

अभ्यास प्रश्न #88 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 13. 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान राष्ट्रीय एकीकरण को कैसे बढ़ावा देता है?

उत्तर एवं व्याख्या: सरदार वल्लभभाई पटेल की 140वीं जयंती (31 अक्टूबर 2015) पर घोषित इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के जोड़े (Paired States) बनाए जाते हैं, जो भाषा, साहित्य, व्यंजन, पर्यटन, त्योहार और युवा आदान-प्रदान के माध्यम से भावनात्मक एकता को मजबूत करते हैं।

अभ्यास प्रश्न #89 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 14. 'अल्पसंख्यक' (Minority) शब्द के संबंध में भारतीय संविधान में क्या स्थिति है?

उत्तर एवं व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में 'अल्पसंख्यक' शब्द का उल्लेख तो है (धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के रूप में), किंतु संविधान में कहीं भी 'अल्पसंख्यक' शब्द को **परिभाषित नहीं** किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत केंद्र सरकार ने 6 धार्मिक समुदायों—मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी (जोरास्ट्रियन) और जैन (2014 में अधिसूचित)—को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया है।

अभ्यास प्रश्न #90 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 15. मुख्य परीक्षा (Mains) दृष्टिकोण: क्या भारत में आर्थिक असमानता क्षेत्रवाद की जननी है?

उत्तर एवं व्याख्या: आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों (जैसे—विदर्भ, बुंदेलखंड, पूर्वांचल या पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से) में जब संसाधनों के दोहन के बावजूद बुनियादी अवसंरचना और रोजगार का अभाव रहता है, तो वहाँ **'आंतरिक उपनिवेशवाद' (Internal Colonialism)** की भावना पनपती है जो क्षेत्रवाद को जन्म देती है। किंतु महाराष्ट्र, पंजाब या तमिलनाडु जैसे समृद्ध राज्यों में भी सांस्कृतिक-भाषाई गर्व और संसाधनों के संरक्षण हेतु क्षेत्रवाद देखा गया है; अतः क्षेत्रवाद केवल आर्थिक अभाव ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक महत्वाकांक्षा का भी परिणाम है।

अध्याय 7: सामाजिक न्याय: स्वास्थ्य, शिक्षा व मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र /सेवाओं का विकास

7.1 विस्तृत सैद्धांतिक एवं समाजशास्त्रीय व्याख्या

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 7.1 विस्तृत सैद्धांतिक एवं समाजशास्त्रीय व्याख्या

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
(क) सामाजिक न्याय (Social Justice) का दार्शनिक एवं संवैधानिक आधार	(ख) स्वास्थ्य क्षेत्र का विकास एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/आयुष्मान भारत	(ग) शिक्षा क्षेत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (NEP 2020)	(घ) मानव संसाधन विकास एवं कौशल निर्माण

(क) सामाजिक न्याय (Social Justice) का दार्शनिक एवं संवैधानिक आधार

सामाजिक न्याय का तात्पर्य समाज के सभी सदस्यों के मध्य बिना किसी जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थान के भेदभाव के संसाधनों, अवसरों और विशेषाधिकारों के न्यायपूर्ण वितरण से है। अमेरिकी दार्शनिक **जॉन रॉल्स (John Rawls)** ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक *A Theory of Justice* (1971) में **'अज्ञानता के पर्दे' (Veil of Ignorance)** और **'अंतर सिद्धांत' (Difference Principle)** का प्रतिपादन करते हुए कहा कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को केवल तभी न्यायसंगत माना जा सकता है जब वे **'समाज के सबसे कम सुविधा-संपन्न व्यक्ति को अधिकतम लाभ' (Greatest benefit of the least advantaged)** पहुँचाती हों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में **सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय** को सर्वोच्च स्थान दिया गया है तथा भाग-III (मौलिक अधिकार) और भाग-IV (राज्य के नीति निदेशक तत्व — विशेषतः अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46 और 47) इसके संस्थागत वाहक हैं।

(ख) स्वास्थ्य क्षेत्र का विकास एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन /आयुष्मान भारत

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 एवं पीआईबी के जून 2026 प्रतिवेदन के अनुसार भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य को तीन-स्तरीय (प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक) ढाँचे में सुदृढ़ किया गया है:

- **आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY):** सितंबर 2018 में प्रारंभ यह विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जो देश के निचले 40% आर्थिक रूप से संवेदनशील परिवारों (लगभग 12.37 करोड़ परिवार तथा मार्च 2024 से 37 लाख आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवार) को प्रति परिवार प्रतिवर्ष **₹5 लाख** का कैशलेस द्वितीयक व तृतीयक उपचार कवरेज देती है। पीआईबी के मई 2026 आँकड़ों के अनुसार अब तक **43.93 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड** जारी किए जा चुके हैं और ₹1.80 लाख करोड़ की लागत से **12.03 करोड़ अस्पताल भर्तियाँ** संपन्न हुई हैं।
- **आयुष्मान भारत वय वंदना योजना:** 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों (आय की परवाह किए बिना) को ₹5 लाख का स्वास्थ्य कवर; मई 2026 तक 1.20 करोड़ से अधिक वरिष्ठ नागरिक नामांकित और ₹3,000 करोड़ से अधिक के 13.84 लाख उपचार संपन्न।

• **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM):** 14 अंकों की विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य पहचान **ABHA (Ayushman Bharat Health Account)** के माध्यम से मई 2026 तक **88.33 करोड़ आभा खाते** बनाए गए हैं और **97.81 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड** जोड़े जा चुके हैं।

• **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) एवं जन औषधि/अमृत विस्तार:** पीआईबी प्रतिवेदन (2026) के अनुसार स्वीकृत व परिचालित एम्स की संख्या 8 (1947–2014) से बढ़कर 2014–2026 में **15 (लगभग दोगुनी)** हो गई है तथा **7.41 करोड़ नागरिक किफायती AMRIT आउटलेट्स** से लाभान्वित हुए हैं।

• **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6, मई 2026):** पीआईबी की एनएफएचएस-6 विज्ञप्ति (29 मई 2026) के अनुसार परिवार स्तर पर स्वास्थ्य बीमा/वित्तपोषण योजना का कवरेज **41.0% से बढ़कर 60.2%** हो गया है, जबकि प्रथम तिमाही प्रसवपूर्व देखभाल (ANC) **59% से बढ़कर 76.2%** हो गई है। साथ ही एनएफएचएस-6 ने **'कुपोषण और वयस्कों में बढ़ते मोटापे/गैर-संचारी रोगों (NCDs) के दोहरे बोझ' (Dual Burden of Malnutrition)** की ओर भी नीतिगत ध्यान आकर्षित किया है।

(ग) शिक्षा क्षेत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (NEP 2020)

86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा **अनुच्छेद 21A** जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया (शिक्षा का अधिकार अधिनियम - RTE, 2009)।

• **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (कस्तूरीरंगन समिति):** इसने 1986 की शिक्षा नीति का स्थान लिया और पुरानी `10+2` संरचना को बदलकर `5+3+3+4` **शैक्षणिक एवं पाठ्यचर्या संरचना** लागू की:

1. **फाउंडेशनल स्टेज (5 वर्ष):** 3 वर्ष आंगनवाड़ी/प्री-स्कूल + कक्षा 1 और 2 (आयु 3–8 वर्ष)।
2. **प्रिपरेटरी स्टेज (3 वर्ष):** कक्षा 3 से 5 (आयु 8–11 वर्ष)।
3. **मिडिल स्टेज (3 वर्ष):** कक्षा 6 से 8 (आयु 11–14 वर्ष — व्यावसायिक कौशल एवं कोडिंग का प्रारंभ)।
4. **सेकेंडरी स्टेज (4 वर्ष):** कक्षा 9 से 12 (आयु 14–18 वर्ष — बहु-विषयक अध्ययन)।

• **नामांकन एवं ड्रॉप-आउट में सुधार:** पीआईबी के जून 2026 प्रतिवेदन के अनुसार 2024–25 में प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (GER) **90.9%**, उच्च प्राथमिक पर **90.3%** और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 2014–15 के 46.4% से बढ़कर **58.4%** हो गया है। प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं का ड्रॉप-आउट 4.6% से घटकर मात्र **0.3%** रह गया है।

(घ) मानव संसाधन विकास एवं कौशल निर्माण

मानव संसाधन को उत्पादक 'मानव पूंजी' (Human Capital) में बदलने के लिए **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY 4.0)**, **पीएम श्री स्कूल (PM SHRI Schools)**, **निपुण भारत मिशन (NIPUN Bharat — मूलभूत साक्षरता एवं संख्याज्ञान)** और **पीएम पोषण (PM POSHAN — पूर्ववर्ती मिड-डे मील)** संचालित किए जा रहे हैं।

मानव पूंजी एवं सामाजिक न्याय सूत्र (1D Conceptual Formula):

$$मानव पूंजी निर्माण = सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा (PM-JAY + ABDM) + गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (NEP 5+3+3+4) + भविष्य-उन्मुख कौशल (PMKVY 4.0)$$

7.2 परीक्षा जाल (Exam Trap)

परीक्षा जाल (Exam Trap): आयुष्मान भारत के घटक, NEP 2020 संरचना एवं स्वास्थ्य व्यय

1. **प्रथम भ्रम:** छात्र प्रायः 'आयुष्मान भारत' का अर्थ केवल '₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा (*PM-JAY*)' समझ लेते हैं—यह **अधूरा** है। आयुष्मान भारत के **4 स्तंभ** हैं: (1) आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पूर्ववर्ती 1.5 लाख+ Health & Wellness Centres — प्राथमिक देखभाल), (2) PM-JAY (द्वितीयक व तृतीयक देखभाल), (3) आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM - ABHA ID), और (4) प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM)।
2. **द्वितीय भ्रम:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की **5+3+3+4** संरचना में प्रथम '5' का अर्थ कक्षा 1 से 5 मान लेना—यह **गलत** है। प्रथम **5 वर्ष (Foundational Stage)** में **3 वर्ष प्री-स्कूल/आंगनवाड़ी/बालवाटिका (आयु 3–6 वर्ष) और 2 वर्ष कक्षा 1 व 2 (आयु 6–8 वर्ष)** शामिल हैं।
3. **तृतीय भ्रम:** संविधान में 'स्वास्थ्य' को संघ सूची का विषय मानना। मूलतः **'लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा अस्पताल और औषधालय' राज्य सूची (State List — प्रविष्टि 6)** का विषय है, जबकि 'शिक्षा' को 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा राज्य सूची से हटाकर **समवर्ती सूची (Concurrent List — प्रविष्टि 25)** में शामिल किया गया है।

7.3 4-नोड फ्लोचार्ट: भारत का एकीकृत मानव संसाधन एवं सामाजिक क्षेत्र विकास मॉडल

[नोड 1: प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं पोषण — मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0, निपुण भारत व पीएम पोषण] **[नोड 2: समग्र शिक्षा एवं NEP 2020 — 5+3+3+4 ढाँचा, पीएम श्री स्कूल एवं उच्चतर शिक्षा में बहु-विषयकता]** **[नोड 3: सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवच — आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PM-JAY (43.93 करोड़ कार्ड) एवं ABHA (88.33 करोड़ खाते)]** **[नोड 4: उत्पादक मानव पूंजी — कौशल भारत (PMKVY 4.0), AI प्रशिक्षण एवं विकसित भारत @2047 कार्यबल]**

7.4 विस्तृत तुलनात्मक सारणी: स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र के प्रमुख कार्यक्रम और प्रमाणित परिणाम (2026)

सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रम	प्रारंभ वर्ष / मंत्रालय	मुख्य प्रावधान एवं संरचनात्मक विशेषताएँ	प्रमाणित उपलब्धि (मई–जून 2026) / आधिकारिक स्रोत
आयुष्मान भारत (AB PM-JAY)	सितंबर 2018 (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)	प्रति परिवार प्रतिवर्ष ₹5 लाख का कैशलेस द्वितीयक व तृतीयक उपचार; 70+ वर्ष के सभी बुजुर्ग (वय वंदना) शामिल	43.93 करोड़ आयुष्मान कार्ड; 12.03 करोड़ अस्पताल भर्तियाँ; 60.2% परिवार स्वास्थ्य बीमा कवरेज (NFHS-6)
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)	सितंबर 2021 (राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण - NHA)	14 अंकों की ABHA ID, स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री (HPR) एवं डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड लिंकिंग	मई 2026 तक 88.33 करोड़ ABHA खाते और 97.81 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड लिंक (PIB)
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) एवं समग्र शिक्षा	2020 (शिक्षा मंत्रालय)	**5+3+3+4** संरचना, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) एवं PARAKH मूल्यांकन केंद्र	प्राथमिक GER 90.9%, उच्च प्राथमिक GER 90.3%, उच्चतर माध्यमिक GER 58.4% (2024-25)
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा (NHM + NFHS-6)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	जननी सुरक्षा योजना (JSY), जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान	MMR 130 से घटकर 88 हुआ; प्रथम तिमाही ANC 59% से बढ़कर 76.2% (NFHS-6, 2026)
ग्रामीण सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना (NSO 80वाँ दौर)	स्वास्थ्य मंत्रालय / NSO	आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं ग्रामीण सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव व ओपीडी सेवा विस्तार	ग्रामीण संस्थागत प्रसव का 66.8% सरकारी अस्पतालों में; ग्रामीण ओपीडी उपयोग 28% से बढ़कर 35% (2025)

7.5 चार्ट डेटा %: स्वास्थ्य बीमा, मातृ देखभाल एवं विद्यालयी नामांकन (NFHS-6 एवं PIB 2026)

निम्नलिखित आँकड़े पीआईबी की एनएफएचएस-6 विज्ञप्ति (29 मई 2026) तथा पीआईबी के जून 2026 प्रतिवेदन से लिए गए हैं:



7.6 स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks)

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के `5+3+3+4` चरणों और आयु वर्ग की ट्रिक — "फाउंडेशन 5 (3-8), प्रिपरेटरी 3 (8-11), मिडिल 3 (11-14), सेकेंडरी 4 (14-18)":**
- **5 (Foundational):** 3 वर्ष आंगनवाड़ी + कक्षा 1–2 (आयु 3 से 8 वर्ष)
- **3 (Preparatory):** कक्षा 3 से 5 (आयु 8 से 11 वर्ष)
- **3 (Middle):** कक्षा 6 से 8 (आयु 11 से 14 वर्ष)
- **4 (Secondary):** कक्षा 9 से 12 (आयु 14 से 18 वर्ष)
- **NEP 2020 की प्रमुख संस्थाओं का सूत्र — "PARAKH से परीक्षा मूल्यांकन, ABC से क्रेडिट बैंक, HECI के 4 स्तंभ (NHERC, NAC, HEGC, GEC)"।**

7.7 अभ्यास प्रश्नोत्तर (15 व्याख्यात्मक प्रश्न — अध्याय 7)

अभ्यास प्रश्न #91 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 1. जॉन रॉल्स (John Rawls) का 'अंतर सिद्धांत' (Difference Principle) सामाजिक न्याय को कैसे परिभाषित करता है?

उत्तर एवं व्याख्या: जॉन रॉल्स के अनुसार समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी स्वतंत्रताओं का समान अधिकार होना चाहिए, और यदि समाज में कोई सामाजिक या आर्थिक असमानता रखी जाती है (जैसे सकारात्मक भेदभाव/आरक्षण या प्रगतिशील कराधान), तो वह केवल तभी न्यायपूर्ण है जब उससे **समाज के सबसे वंचित और कमजोर व्यक्ति का अधिकतम कल्याण (Maximin Rule)** होता हो।

अभ्यास प्रश्न #92 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 2. एनएफएचएस-6 (मई 2026) के अनुसार भारत में परिवार स्तर पर स्वास्थ्य बीमा/वित्तपोषण कवरेज बढ़कर कितना हो गया है?

उत्तर एवं व्याख्या: एनएफएचएस-6 के आँकड़ों के अनुसार भारत में परिवार स्तर पर स्वास्थ्य बीमा/वित्तपोषण योजना का कवरेज **41.0% से बढ़कर 60.2%** हो गया है, जिसमें आयुष्मान भारत (PM-JAY) और राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की केंद्रीय भूमिका रही है।

अभ्यास प्रश्न #93 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 3. पीआईबी प्रतिवेदन (जून 2026) के अनुसार 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' (ABDM) के तहत कितने ABHA खाते और स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े जा चुके हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: मई 2026 तक देश में **88.33 करोड़ आभा (ABHA — 14 अंकों की विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य आईडी) खाते** बनाए जा चुके हैं और इनके साथ **97.81 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड** जोड़े गए हैं, जिससे पेपरलेस स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ है।

अभ्यास प्रश्न #94 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 4. 'जेब से होने वाले स्वास्थ्य व्यय' (Out-of-Pocket Expenditure - OOPE) का क्या अर्थ है और यह गरीबी से कैसे जुड़ा है?

उत्तर एवं व्याख्या: जब किसी परिवार को बीमारी के इलाज, दवाइयों और जांच का खर्च बीमा या सरकारी मुफ्त सेवा के बजाय सीधे अपनी निजी बचत या कर्ज लेकर चुकाना पड़ता है, तो उसे OOPE कहते हैं। उच्च OOPE के कारण भारत में प्रतिवर्ष लाखों परिवार गरीबी रेखा के नीचे चले जाते थे; PM-JAY, जन औषधि केंद्रों और AMRIT आउटलेट्स ने OOPE को कम करने में बड़ा योगदान दिया है।

अभ्यास प्रश्न #95 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 5. एनएफएचएस-6 (2026) में रेखांकित 'कुपोषण का दोहरा बोझ' (Dual Burden of Malnutrition) क्या है?

उत्तर एवं व्याख्या: जब किसी देश या परिवार में एक ही समय पर **अल्प-पोषण (Undernutrition — जैसे बच्चों में ठिगनापन/Stunting, दुबलापन/Wasting व एनीमिया)** और **अति-पोषण (Overnutrition — वयस्कों व शहरी आबादी में बढ़ता मोटापा/Obesity, मधुमेह व उच्च रक्तचाप जैसे गैर-संचारी रोग)** दोनों सह-अस्तित्व में होते हैं, तो इसे 'कुपोषण का दोहरा बोझ' कहा जाता है।

अभ्यास प्रश्न #96 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 6. बच्चों में 'स्टंटिंग' (Stunting) और 'वेस्टिंग' (Wasting) में क्या अंतर है?

उत्तर एवं व्याख्या: स्टंटिंग (ठिगनापन): आयु के अनुपात में कम लंबाई (Low Height-for-Age), जो **दीर्घकालिक (Chronic) कुपोषण** को दर्शाती है। **वेस्टिंग (दुबलापन):** लंबाई के अनुपात में कम वजन (Low Weight-for-Height), जो **तीव्र या तात्कालिक (Acute) कुपोषण** एवं संक्रमण को दर्शाता है।

अभ्यास प्रश्न #97 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 7. 'निपुण भारत मिशन' (NIPUN Bharat Mission) का मुख्य लक्ष्य क्या है?

उत्तर एवं व्याख्या: शिक्षा मंत्रालय द्वारा जुलाई 2021 में प्रारंभ 'नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी' (NIPUN Bharat) का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का प्रत्येक बच्चा **कक्षा 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy - FLN)** प्राप्त कर ले।

अभ्यास प्रश्न #98 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्थापित 'परख' (PARAKH) क्या है?

उत्तर एवं व्याख्या: PARAKH (Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development) एनसीईआरटी (NCERT) के अधीन एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, जिसका कार्य देश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन के मानक, मानदंड और दिशा-निर्देश तय करना तथा रटने की प्रवृत्ति के स्थान पर दक्षता-आधारित मूल्यांकन को बढ़ावा देना है।

अभ्यास प्रश्न #99 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 9. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) की धारा 12(1)(c) का क्या महत्व है?

उत्तर एवं व्याख्या: RTE अधिनियम की **धारा 12(1)(c)** के तहत सभी गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) के लिए प्रवेश स्तर (कक्षा 1 या प्री-प्राइमरी) पर कम से कम **25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूहों के बच्चों** के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है, जिसकी शुल्क प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाती है।

अभ्यास प्रश्न #100 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 10. उच्च शिक्षा में 'अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (Academic Bank of Credits - ABC) कैसे कार्य करता है?

उत्तर एवं व्याख्या: NEP 2020 के तहत ABC एक डिजिटल रिपॉजिटरी है जो उच्च शिक्षा के छात्रों द्वारा विभिन्न संस्थानों या ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (SWAYAM) से अर्जित किए गए अकादमिक क्रेडिट्स को संग्रहीत करता है। यह **'मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट' (Multiple Entry and Exit)** की सुविधा देता है—1 वर्ष पर सर्टिफिकेट, 2 वर्ष पर डिप्लोमा, 3 वर्ष पर डिग्री और 4 वर्ष पर शोध सहित स्नातक डिग्री।

अभ्यास प्रश्न #101 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 11. 'पीएम पोषण' (PM POSHAN) योजना में 'तिथि भोजन' और 'पोषण उद्यान' क्या हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: 'तिथि भोजन' एक सामुदायिक भागीदारी पहल है जिसमें स्थानीय नागरिक जन्मदिन, त्योहार या वर्षगांठ जैसे विशेष अवसरों पर सरकारी विद्यालयों के बच्चों को पौष्टिक भोजन या फल प्रदान करते हैं। 'स्कूल पोषण उद्यान' (School Nutrition Gardens) विद्यालय परिसर में ही ताजी सब्जियाँ और फल उगाने की पहल है।

अभ्यास प्रश्न #102 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 12. NSO के 80वें दौर के सर्वेक्षण (PIB 2026) के अनुसार ग्रामीण भारत में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग में क्या बदलाव आया है?

उत्तर एवं व्याख्या: ग्रामीण क्षेत्रों में कुल संस्थागत प्रसवों का लगभग **दो-तिहाई (66.8%)** सरकारी अस्पतालों में हो रहा है (शहरी क्षेत्रों में 47%), तथा बाह्य रोगी सेवाओं (OPD) के लिए ग्रामीण आबादी में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों का उपयोग 2014 के 28% से बढ़कर 2025 में **35%** हो गया है।

अभ्यास प्रश्न #103 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 13. 'आयुष्मान भारत वय वंदना योजना' की सबसे बड़ी विशेषता क्या है?

उत्तर एवं व्याख्या: इसके अंतर्गत **70 वर्ष और उससे अधिक आयु के देश के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक** को—चाहे उनकी पारिवारिक आय कुछ भी हो (अमीर या गरीब दोनों)—आयुष्मान भारत PM-JAY के तहत प्रतिवर्ष ₹5 लाख का निःशुल्क स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया गया है। **मई 2026 तक इसमें 1.20 करोड़ से अधिक वरिष्ठ नागरिक जुड़ चुके हैं**।

अभ्यास प्रश्न #104 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 14. भारत में 'शैक्षणिक मुद्रास्फीति' (Educational Inflation) और 'कौशल अंतराल' (Skill Gap) का क्या संबंध है?

उत्तर एवं व्याख्या: महाविद्यालयों से प्रतिवर्ष लाखों स्नातक और इंजीनियर निकलने के बावजूद जब उनकी पाठ्यचर्या उद्योग की व्यावहारिक आवश्यकताओं (AI, डेटा एनालिटिक्स, आधुनिक विनिर्माण, सॉफ्ट स्किल्स) से मेल नहीं खाती, तो डिग्री होने के बावजूद रोजगार योग्यता (Employability) कम रहती है। इसी अंतर को पाटने के लिए PMKVY 4.0, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (NAPS) और इंटर्नशिप योजनाओं को जोड़ा गया है।

अभ्यास प्रश्न #105 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 15. मुख्य परीक्षा (Mains) दृष्टिकोण: स्वास्थ्य और शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को 'सामाजिक खर्च' के बजाय 'पूंजीगत निवेश' क्यों माना जाना चाहिए?

उत्तर एवं व्याख्या: अर्थशास्त्री थियोडोर शुल्ट्ज और गैरी बेकर के मानव पूंजी सिद्धांत के अनुसार एक स्वस्थ और शिक्षित नागरिक की श्रम उत्पादकता, नवाचार क्षमता और कर योगदान कई गुना बढ़ जाता है तथा बीमारी से होने वाली कार्य-दिवसों की हानि रुकती है। अतः स्वास्थ्य (जीडीपी का 2.5% लक्ष्य) और शिक्षा (जीडीपी का 6% लक्ष्य) पर किया गया व्यय दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि का सबसे उच्च-प्रतिफल वाला निवेश है।

अध्याय 8: अति-संवेदनशील वर्गों (SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन, वृद्धजन, ट्रांसजेंडर) के लिए कल्याणकारी योजनाएँ, आयोग एवं संवैधानिक तंत्र

8.1 विस्तृत सैद्धांतिक एवं समाजशास्त्रीय व्याख्या

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 8.1 विस्तृत सैद्धांतिक एवं समाजशास्त्रीय व्याख्या

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
(क) अति-संवेदनशील वर्गों (Vulnerable Sections) की अवधारणा एवं संवैधानिक रक्षा-तंत्र	(ख) राष्ट्रीय संवैधानिक एवं वैधानिक आयोग (Commissions for Vulnerable Sections)	(ग) अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं अल्पसंख्यकों हेतु प्रमुख योजनाएँ	(घ) दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विधिक और कल्याणकारी तंत्र

(क) अति-संवेदनशील वर्गों (Vulnerable Sections) की अवधारणा एवं संवैधानिक रक्षा-तंत्र

अति-संवेदनशील वर्ग वे सामाजिक समूह हैं जो ऐतिहासिक अन्याय, भौगोलिक अलगाव, सामाजिक कलंक, शारीरिक-मानसिक चुनौतियों या आयु-संबंधी सीमाओं के कारण मुख्यधारा के विकास से पीछे छूट जाने के जोखिम में रहते हैं। भारतीय संविधान ने इनके संरक्षण एवं उत्थान के लिए **'समानता के साथ सकारात्मक भेदभाव' (Protective Discrimination / Affirmative Action)** का एक व्यापक संवैधानिक तंत्र स्थापित किया है:

- **शैक्षणिक एवं आर्थिक हित संवर्धन (अनुच्छेद 46):** राज्य जनता के दुर्बलतर वर्गों के, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय व सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।
- **राजनीतिक आरक्षण:** लोकसभा में SC व ST के लिए सीटों का आरक्षण (**अनुच्छेद 330**) और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण (**अनुच्छेद 332**)—जिसे **104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019** द्वारा आगामी 10 वर्षों (2030 तक) के लिए बढ़ाया गया (और आंग्ल-भारतीय मनोनयन को समाप्त किया गया)।
- **सेवाओं में आरक्षण और दावे:** अनुच्छेद 16(4), 16(4A) (पदोन्नति में आरक्षण) तथा अनुच्छेद 335।

(ख) राष्ट्रीय संवैधानिक एवं वैधानिक आयोग (Commissions for Vulnerable Sections)

1. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC — अनुच्छेद 338):** मूल संविधान में एक विशेष अधिकारी का प्रावधान था। **89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003** द्वारा संयुक्त आयोग को विभाजित कर अनुच्छेद 338 के तहत NCSC और अनुच्छेद 338A के तहत NCST का पृथक गठन किया गया।

2. **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST — अनुच्छेद 338A):** जनजातियों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों, वनाधिकार (FRA 2006) एवं पेसा (PESA 1996) के क्रियान्वयन की निगरानी करता है।

3. **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC — अनुच्छेद 338B):** 1993 में यह एक वैधानिक निकाय के रूप में बना था, किंतु **102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018** द्वारा संविधान में **अनुच्छेद 338B** और **अनुच्छेद 342A** जोड़कर इसे **संवैधानिक दर्जा** प्रदान किया गया। साथ ही **105वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2021** द्वारा राज्यों की अपनी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC/OBC) की सूची तैयार करने की शक्ति को पुनः स्पष्ट किया गया।

4. **वैधानिक आयोग:** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (1992), राष्ट्रीय महिला आयोग (1990 अधिनियम, 1992 में गठन), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR — 2005 अधिनियम, 2007 में गठन) और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC — 1993 अधिनियम)।

(ग) अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं अल्पसंख्यकों हेतु प्रमुख योजनाएँ

- **अनुसूचित जाति कल्याण:**

• **पीएम-अजय (PM-AJAY — Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana):** पूर्ववर्ती तीन योजनाओं (प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना और विशेष केंद्रीय सहायता) का विलय कर बनाई गई योजना।

• **श्रेष्ठ योजना (SHRESHTA — Scheme for Residential Education for Students in High Schools in Targeted Areas):** मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों को देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों (CBSE/State Board) में कक्षा 9 और 11 में निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।

• **नमस्ते योजना (NAMASTE — National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem):** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल, जिसका उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई को 100% मशीनीकृत करना तथा किसी भी सफाई कर्मचारी की सीवर में मृत्यु न होने देना है।

• **अनुसूचित जनजाति कल्याण:**

• **प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN):** देश के 18 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश में निवास करने वाले **75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs — ढेबर आयोग द्वारा चिह्नित)** को पक्का आवास, स्वच्छ जल, सड़क, बिजली, मोबाइल मेडिकल यूनिट और वन धन केंद्र जैसी 11 बुनियादी सुविधाओं से 100% संतृप्त करने की ₹24,104 करोड़ की योजना।

• **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एवं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS):** जनजातीय बहुल गाँवों का समग्र विकास और प्रत्येक जनजातीय ब्लॉक में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर EMRS की स्थापना।

• **अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण:**

• **पीएम यशस्वी (PM YASASVI):** OBC, EBC और DNT (विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति — इदाते आयोग) के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति एवं छात्रावास योजना।

• **पीएम विकास (PM VIKAS — Pradhan Mantri Virasat Ka Samvardhan):** अल्पसंख्यक और कारीगर समुदायों के कौशल, उद्यमिता और पारंपरिक शिल्प के संवर्धन हेतु 5 पूर्ववर्ती योजनाओं (सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी, नई मंजिल) का एकीकृत रूप।

(घ) दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विधिक और कल्याणकारी तंत्र

• **दिव्यांगजन (Divyangjan): दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act, 2016)** ने 1995 के अधिनियम का स्थान लिया और मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं की श्रेणियों को 7 **से बढ़ाकर 21** (जिसमें एसिड अटैक पीड़ित, थैलेसीमिया, पार्किंसंस, ऑटिज्म आदि शामिल हैं) कर दिया। इसने सरकारी नौकरियों में बेंचमार्क दिव्यांगजनों (40% या अधिक दिव्यांगता) के लिए आरक्षण को **3% से बढ़ाकर 4%** और उच्च शिक्षण संस्थानों में **5%** कर दिया। साथ ही **सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign)** और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र **(UDID Card)** चलाए जा रहे हैं।

• **वृद्धजन (Senior Citizens): माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007, अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY — पूर्ववर्ती राष्ट्रीय वयोश्री योजना सहित),** एल्डरलाइन हेल्पलाइन **14567** और **आयुष्मान भारत वय वंदना योजना (1.20 करोड़+ नामांकित)**।

• **ट्रांसजेंडर एवं भिक्षावृत्ति से मुक्त व्यक्ति (SMILE Scheme): नालसा बनाम भारत संघ (NALSA Case, 2014)** में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 'तृतीय लिंग' (Third Gender) के रूप में संवैधानिक मान्यता दी, जिसके बाद संसद ने **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019** पारित किया। **पीआईबी के स्माइल (SMILE) योजना प्रतिवेदन (अगस्त 2026)** तथा **फरवरी 2026 विज्ञप्ति** के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित **'स्माइल' (SMILE — Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise)** योजना की दो उप-योजनाएँ हैं: (1) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना (जिसके तहत **23 गरिमा गृह** संचालित हैं और 'आयुष्मान भारत टीजी प्लस' कार्ड दिया जाता है) तथा (2) भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास ('भिक्षावृत्ति मुक्त भारत')। **पीआईबी विज्ञप्ति (अप्रैल 2026)** के अनुसार 2021-22 से 2025-26 के लिए स्माइल योजना का कुल परिव्यय ₹365 करोड़ (ट्रांसजेंडर कल्याण हेतु ₹265 करोड़) निर्धारित किया गया।

समावेशी सामाजिक सुरक्षा सूत्र (1D Conceptual Formula):

$$अंत्योदय सशक्तिकरण = संवैधानिक आयोग (अनु. 338, 338A, 338B) + लक्षित मिशन (PM-AJAY + PM-JANMAN + SMILE) + अधिकार विधान (RPwD + FRA)$$

8.2 परीक्षा जाल (Exam Trap)

परीक्षा जाल (Exam Trap): संवैधानिक आयोग अनुच्छेद, PVTGs एवं RPwD आरक्षण

1. **प्रथम भ्रम:** छात्र प्रायः 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (*NCBC*)' को आज भी वैधानिक निकाय लिख देते हैं—यह **गलत** है। **102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018** द्वारा संविधान में **अनुच्छेद 338B** जोड़कर NCBC को पूर्ण **संवैधानिक दर्जा** दिया जा चुका है।
2. **द्वितीय भ्रम: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act)** में सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा के आरक्षण प्रतिशत को उल्टा कर देना। याद रखें: सरकारी नौकरियों (Employment) में कम से कम **4% आरक्षण** है और उच्च शिक्षण संस्थानों (Higher Education Admission) में कम से कम **5% आरक्षण** है, तथा दिव्यांगता श्रेणियों की संख्या **21** है।
3. **तृतीय भ्रम: PVTGs (Particularly Vulnerable Tribal Groups)** की संख्या 75 राज्यों के बराबर या अनिश्चित मानना। भारत में कुल **75 PVTGs** (सर्वाधिक **ओडिशा** में 13 समूह) अधिसूचित हैं, जिनकी पहचान सर्वप्रथम 1973 के **ढेबर आयोग** की सिफारिश पर की गई थी।

8.3 4-नोड फ्लोचार्ट: अति-संवेदनशील वर्गों के संरक्षण एवं मुख्यधारा समावेशन का तंत्र

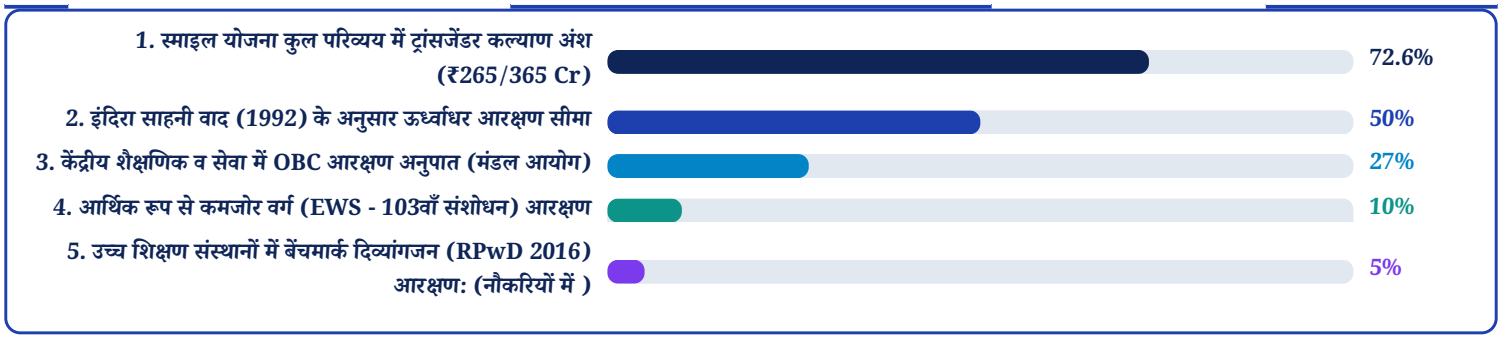
[नोड 1: संवैधानिक आधारशिला — अनुच्छेद 15, 16, 17, 46, 330-342A एवं पाँचवीं-छठी अनुसूची] **[नोड 2: निगरानी आयोग एवं विशेष कानून — NCSC (338), NCST (338A), NCBC (338B), PoA Act 1989, RPwD Act 2016 व FRA 2006]** **[नोड 3: लक्षित कल्याणकारी योजनाएँ — PM-AJAY, SHRESHTA, PM-JANMAN, NAMASTE, SMILE (23 गरिमा गृह) व AVYAY]** **[नोड 4: गरिमापूर्ण मुख्यधारा समावेशन — भिक्षावृत्ति व सीवर मृत्यु से मुक्ति, शैक्षिक उत्थान एवं आत्मनिर्भर उद्यमिता]**

8.4 विस्तृत तुलनात्मक सारणी: अति-संवेदनशील वर्गों के आयोग, अधिनियम एवं प्रमुख योजनाएँ

लक्षित वर्ग	संवैधानिक अनुच्छेद / आयोग	प्रमुख संरक्षण अधिनियम	प्रमुख कल्याणकारी योजनाएँ एवं प्रमाणित तथ्य
अनुसूचित जाति (SC)	अनुच्छेद 338 (NCSC — 89वाँ संशोधन, 2003); अनुच्छेद 341	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955; SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	**PM-AJAY**, **SHRESHTA** (आवासीय शिक्षा), **NAMASTE** (मशीनीकृत स्वच्छता), स्टैंड-अप इंडिया
अनुसूचित जनजाति (ST)	अनुच्छेद 338A (NCST); अनुच्छेद 244 (5वीं व 6वीं अनुसूची); अनुच्छेद 342	पेसा अधिनियम, 1996 (PESA); वनाधिकार अधिनियम, 2006 (FRA)	**PM-JANMAN** (75 PVTGs हेतु), एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS), वन धन विकास केंद्र
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं DNT	अनुच्छेद 338B (NCBC — 102वाँ संशोधन, 2018); अनुच्छेद 340 व 342A	105वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2021 (राज्य SEBC सूची अधिकार)	**PM-YASASVI** छात्रवृत्ति, **SEED योजना** (विमुक्त व घुमंतू समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु)
दिव्यांगजन (PwDs)	अनुच्छेद 41 (नीति निदेशक तत्व); मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन	**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act)** — 21 श्रेणियाँ	सरकारी नौकरी में 4% व उच्च शिक्षा में 5% आरक्षण; सुगम्य भारत अभियान; ADIP योजना; UDID कार्ड
वृद्धजन (Senior Citizens)	अनुच्छेद 41 (वृद्धावस्था में लोक सहायता का अधिकार)	माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007	**अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY)**, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, आयुष्मान वय वंदना (1.20 करोड़+ नामांकित)
ट्रांसजेंडर एवं भिक्षुक वर्ग	अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 (NALSA निर्णय, 2014); राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद	**ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019**	SMILE योजना — ₹365 करोड़ परिव्यय, 23 गरिमा गृह एवं भिक्षावृत्ति मुक्त भारत अभियान (PIB 2026)

8.5 चार्ट डेटा %: संवेदनशील वर्गों के आरक्षण, योजना आवंटन एवं समावेशन संकेतक

निम्नलिखित आँकड़े संवैधानिक/वैधानिक प्रावधानों तथा पीआईबी स्माइल योजना विज्ञप्ति (अप्रैल 2026) पर आधारित हैं:



8.6 स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks)

- **नवीनतम संविधान संशोधनों (101 से 106) को याद रखने का अचूक सूत्र — "101 जीएसटी, 102 पिछड़ा आयोग, 103 ईडब्ल्यूएस, 104 एससी-एसटी विस्तार, 105 राज्य ओबीसी सूची, 106 नारी शक्ति वंदन":**
- **101वाँ (2016):** वस्तु एवं सेवा कर (GST)
- **102वाँ (2018):** राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC — अनुच्छेद 338B) को संवैधानिक दर्जा
- **103वाँ (2019):** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 10% आरक्षण (अनुच्छेद 15(6) और 16(6))
- **104वाँ (2019):** लोकसभा व विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण 10 वर्ष बढ़ाया और आंग्ल-भारतीय मनोनयन समाप्त किया
- **105वाँ (2021):** राज्यों को अपनी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) की सूची बनाने का अधिकार बहाल किया
- **106वाँ (2023):** नारी शक्ति वंदन अधिनियम (लोकसभा व विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण)
- **स्माइल (SMILE) योजना के 2 लाभार्थी समूह याद रखने की ट्रिक — "SMILE से ट्रांसजेंडर को गरिमा गृह, भिक्षुक को पुनर्वास"।**

8.7 अभ्यास प्रश्नोत्तर (15 व्याख्यात्मक प्रश्न — अध्याय 8)

अभ्यास प्रश्न #106 — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 1. 89वें और 102वें संविधान संशोधन अधिनियमों का राष्ट्रीय आयोगों के संदर्भ में क्या महत्व है?

उत्तर एवं व्याख्या: **89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003** द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संयुक्त आयोग को विभाजित कर **अनुच्छेद 338** के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) और **अनुच्छेद 338A** के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) बनाया गया। **102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018** द्वारा संविधान में **अनुच्छेद 338B** जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

अभ्यास प्रश्न #107 — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 2. 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह' (PVTGs) की पहचान के चार मानदंड क्या हैं और इनकी संख्या कितनी है?

उत्तर एवं व्याख्या: ढेबर आयोग (1960–61) की सिफारिश पर चिह्नित **75 PVTGs** (सर्वाधिक 13 ओडिशा में) की पहचान के 4 मानदंड हैं: (1) कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी (Pre-agricultural level of technology), (2) स्थिर या घटती जनसंख्या (Stagnant or declining population), (3) अत्यंत कम साक्षरता (Extremely low literacy), और (4) निर्वाह स्तर की अर्थव्यवस्था (Subsistence level of economy)। इनके समग्र विकास हेतु **पीएम-जनमन (PM-JANMAN)** अभियान चलाया जा रहा है।

अभ्यास प्रश्न #108 — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 3. 'पेसा अधिनियम, 1996' (PESA Act, 1996) किस समिति की सिफारिश पर पारित हुआ और यह किन क्षेत्रों पर लागू होता है?

उत्तर एवं व्याख्या: पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) **दिलीप सिंह भूरिया समिति (1995)** की सिफारिश पर पारित हुआ। यह संविधान की **पाँचवीं अनुसूची (Fifth Schedule)** के अंतर्गत आने वाले **10 राज्यों** (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान) के अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को जल-जंगल-जमीन, लघु वनोपज और भूमि हस्तांतरण रोकने की विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है।

अभ्यास प्रश्न #109 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 4. वनाधिकार अधिनियम, 2006 (FRA 2006) के तहत 'अन्य पारंपरिक वन निवासी' (OTFD) को वनाधिकार प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों के निवास का प्रमाण देना होता है?

उत्तर एवं व्याख्या: अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों (FDST) को 13 दिसंबर 2005 से पूर्व वन भूमि पर काबिज होना आवश्यक है, जबकि **अन्य पारंपरिक वन निवासियों (OTFD)** को कम से कम **तीन पीढ़ियों (75 वर्ष)** से वन भूमि पर निवास और आजीविका निर्भरता प्रमाणित करनी होती है। इसमें अधिकतम **4 हेक्टेयर** तक व्यक्तिगत वनाधिकार दिया जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न #110 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 5. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act, 2016) में 'बेंचमार्क दिव्यांगता' (Benchmark Disability) किसे कहते हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: अधिनियम के तहत सूचीबद्ध 21 दिव्यांगता श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में कम से कम **40% या उससे अधिक प्रमाणित दिव्यांगता** वाले व्यक्ति को 'बेंचमार्क दिव्यांगजन' कहा जाता है, जो सरकारी नौकरियों में 4% और उच्च शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण का पात्र होता है।

अभ्यास प्रश्न #111 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 6. पीआईबी विज्ञप्ति (फरवरी व अगस्त 2026) के अनुसार 'स्माइल' (SMILE) योजना क्या है और इसके तहत कितने 'गरिमा गृह' संचालित हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की अंब्रेला योजना **SMILE (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise)** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के व्यापक पुनर्वास के लिए है। फरवरी 2026 के पीआईबी आँकड़ों के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा और कौशल प्रशिक्षण देने के लिए देश में **23 गरिमा गृह** समर्थित हैं।

अभ्यास प्रश्न #112 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 7. 'नमस्ते' (NAMASTE) योजना किस सामाजिक बुराई के उन्मूलन से संबंधित है?

उत्तर एवं व्याख्या: NAMASTE (National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem) हाथ से मैला ढोने (Manual Scavenging) और सीवर व सेप्टिक टैंकों की खतरनाक मानवीय सफाई को समाप्त कर 100% मशीनीकृत सफाई सुनिश्चित करने की योजना है। यह सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा किट (PPE), आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कवर और स्वच्छता उद्यमी बनने हेतु पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है।

अभ्यास प्रश्न #113 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 8. 'श्रेष्ठ' (SHRESHTA) और 'पीएम-अजय' (PM-AJAY) योजनाओं का संबंध किस वर्ग से है?

उत्तर एवं व्याख्या: दोनों योजनाएँ **अनुसूचित जाति (SC)** के कल्याण से संबंधित हैं। **SHRESHTA** मेधावी SC छात्रों को देश के शीर्ष निजी आवासीय स्कूलों (कक्षा 9 से 12) में निःशुल्क शिक्षा दिलाती है, जबकि **PM-AJAY** अनुसूचित जाति बहुल गाँवों को 'आदर्श ग्राम' के रूप में विकसित करने, छात्रावास निर्माण और आजीविका अनुदान प्रदान करने की एकीकृत योजना है।

अभ्यास प्रश्न #114 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 9. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: यह अधिनियम वयस्क बच्चों और कानूनी उत्तराधिकारियों पर अपने वृद्ध माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण का कानूनी दायित्व डालता है। भरण-पोषण न करने पर अधिकरण (Maintenance Tribunal) में अपील की जा सकती है, वरिष्ठ नागरिकों के परित्याग पर दंड का प्रावधान है, और यदि बच्चों ने देखभाल की शर्त पर संपत्ति हस्तांतरित करवाई है और बाद में देखभाल नहीं करते, तो अधिकरण उस संपत्ति हस्तांतरण को शून्य घोषित कर सकता है।

अभ्यास प्रश्न #115 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 10. ओबीसी आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' (Creamy Layer) की अवधारणा किस न्यायालय निर्णय और किस समिति से आई?

उत्तर एवं व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक **इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992 — मंडल केस)** निर्णय में न्यायालय ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को वैध ठहराया, किंतु ओबीसी के भीतर सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग ('क्रीमी लेयर') को आरक्षण से बाहर रखने का निर्देश दिया। क्रीमी लेयर की पहचान के लिए वर्ष 1993 में **राम नंदन प्रसाद समिति** गठित की गई थी।

अभ्यास प्रश्न #116 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 11. ओबीसी के उप-वर्गीकरण (Sub-categorization of OBCs) की जांच के लिए वर्ष 2017 में अनुच्छेद 340 के तहत कौन-सा आयोग गठित किया गया था?

उत्तर एवं व्याख्या: दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश **न्यायमूर्ति जी. रोहिणी की अध्यक्षता में 'रोहिणी आयोग'** गठित किया गया था, जिसका उद्देश्य केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल जातियों के मध्य 27% आरक्षण के लाभ के न्यायसंगत वितरण हेतु उप-वर्गीकरण की सिफारिश करना था।

अभ्यास प्रश्न #117 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 12. सर्वोच्च न्यायालय के 2024 के 'पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह' निर्णय का मुख्य निष्कर्ष क्या था?

उत्तर एवं व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय की 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से (ई. वी. चिन्नैया, 2004 के निर्णय को पलटते हुए) यह व्यवस्था दी कि राज्यों को अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के भीतर सबसे अधिक पिछड़ी जातियों को आरक्षण का वास्तविक लाभ पहुँचाने के लिए **अनुभवजन्य आँकड़ों (Empirical Data) के आधार पर उप-वर्गीकरण (Sub-classification)** करने का संवैधानिक अधिकार है।

अभ्यास प्रश्न #118 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 13. विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (DNTs) के लिए कौन-सा आयोग और कौन-सी योजना बनाई गई है?

उत्तर एवं व्याख्या: ब्रिटिश काल के अन्यायपूर्ण 'आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871' से पीड़ित रहे इन समुदायों को 1952 में अयंगर समिति की सिफारिश पर 'विमुक्त' (Denotified) किया गया। इनकी पहचान व कल्याण हेतु **भीकू रामजी इदाते आयोग** और **विकास एवं कल्याण बोर्ड (DWBDNC)** गठित किया गया तथा सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा **'सीड' (SEED — Scheme for Economic Empowerment of DNTs)** योजना शुरू की गई।

अभ्यास प्रश्न #119 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 14. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत गठित शीर्ष निकाय कौन-सा है?

उत्तर एवं व्याख्या: अधिनियम के तहत **'राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद' (National Council for Transgender Persons - NCTP)** का गठन किया गया है, जिसके पदेन अध्यक्ष **केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** होते हैं। साथ ही जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पहचान प्रमाण-पत्र जारी करने और भेदभाव निषेध का प्रावधान किया गया है।

अभ्यास प्रश्न #120 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 15. मुख्य परीक्षा (Mains) दृष्टिकोण: कल्याणकारी योजनाओं में 'अधिकार-आधारित दृष्टिकोण' (Rights-Based Approach) और 'संतृप्तिकरण दृष्टिकोण' (Saturation Approach) कैसे पूरक हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: 'अधिकार-आधारित दृष्टिकोण' (जैसे—RTE, मनरेगा, NFSA, RPwD Act) नागरिकों को कानूनी हकदारी देता है, जबकि 'संतृप्तिकरण दृष्टिकोण' (100% कवरेज—जैसे हर घर जल, PM-JANMAN, उज्ज्वला, ONORC) यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी पात्र व्यक्ति रिसाव (Exclusion Error), भ्रष्टाचार या तुष्टीकरण का शिकार न हो और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति (अंत्योदय) तक शत-प्रतिशत लाभ पहुँचे।

अध्याय 9: शासन व्यवस्था (Governance): सुशासन (Good Governance), ई-गवर्नेंस (डिजिटल इंडिया, DPI), नागरिक चार्टर (सेवोत्तम मॉडल), पारदर्शिता एवं जवाबदेही

9.1 विस्तृत सैद्धांतिक एवं समाजशास्त्रीय व्याख्या

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 9.1 विस्तृत सैद्धांतिक एवं समाजशास्त्रीय व्याख्या

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
(क) सरकार (Government) बनाम शासन (Governance) बनाम सुशासन (Good Governance)	(ख) ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया एवं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)	(ग) नागरिक चार्टर (Citizen's Charter) एवं सेवोत्तम मॉडल (Sevottam Model)	(घ) पारदर्शिता एवं जवाबदेही: सूचना का अधिकार (RTI), सोशल ऑडिट एवं लोकपाल

(क) सरकार (Government) बनाम शासन (Governance) बनाम सुशासन (Good Governance)

• **सरकार (Government):** वह औपचारिक संस्थागत तंत्र (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) जिसके पास राज्य की संप्रभु शक्ति का प्रयोग करने और कानून बनाने व लागू करने का अधिकार होता है।

• **शासन (Governance):** वह व्यापक प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज में शक्ति का प्रयोग किया जाता है और सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन होता है; इसमें सरकार के साथ-साथ **बाजार (निजी क्षेत्र), नागरिक समाज (Civil Society/NGOs) और मीडिया** भी भागीदार होते हैं।

• **सुशासन (Good Governance):** भारतीय परंपरा में **कौटिल्य के अर्थशास्त्र** में सुशासन का आदर्श सूत्र दिया गया है—"प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्" (प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही उसका हित है)। आधुनिक संदर्भ में *विश्व बैंक (1992 की रिपोर्ट Governance and Development) **और** संयुक्त राष्ट्र (*ESCAP*) **ने सुशासन की** 8 मूलभूत विशेषताएँ* निर्धारित की हैं:

1. **भागीदारी (Participation)**
2. **विधि का शासन (Rule of Law)**
3. **पारदर्शिता (Transparency)**
4. **अनुक्रियाशीलता (Responsiveness)**
5. **आम सहमति उन्मुखता (Consensus Oriented)**
6. **समता एवं समावेशिता (Equity and Inclusiveness)**
7. **प्रभावशीलता एवं दक्षता (Effectiveness and Efficiency)**
8. **जवाबदेही (Accountability)**

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के शासन सुधार प्रतिवेदन के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष **25 दिसंबर (पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती)** को 'सुशासन दिवस' मनाया जाता है और DARPG द्वारा 10 क्षेत्रों व 58 संकेतकों पर आधारित **'सुशासन सूचकांक' (Good Governance Index - GGI)** तथा जिला सुशासन सूचकांक जारी किया जाता है।

(ख) ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया एवं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC — वीरप्पा मोइली) की *11वीं रिपोर्ट (Promoting e-Governance: The Smart Way Forward) **ने ई-गवर्नेंस को** *SMART Governance (Simple, Moral, Accountable, Responsive and Transparent)* **का आधार बताया है। ई-गवर्नेंस के 4 प्रमुख अंतःक्रिया मॉडल हैं:** *G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business), G2G (Government to Government — जैसे e-Office ver 7.0) **और** G2E (Government to Employee — जैसे iGOT Karmayogi, Bhavishya)*।

• **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI — इंडिया स्टैक):** भारत ने विश्व के समक्ष डिजिटल लोक अवसंरचना (DPI) का अद्वितीय मॉडल प्रस्तुत किया है जिसकी तीन परतें हैं:

1. **पहचान की परत (Identity Layer):** आधार (Aadhaar — बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण)।

2. **भुगतान की परत (Payment Layer):** यूपीआई (UPI), रूपे और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS)।

3. **डेटा सशक्तिकरण परत (Data Empowerment Layer):** डिजिलॉकर (DigiLocker), अकाउंट एग्रीगेटर और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABHA)।

• **ई-ऑफिस (e-Office ver 7.0) एवं NeSDA:** DARPG शासन सुधार प्रतिवेदन के अनुसार केंद्रीय सचिवालय में **25 लाख से अधिक ई-फाइलें** परिचालन में हैं, निर्णय प्रक्रिया में फाइल प्रस्तुतीकरण के स्तर को 7–8 स्तरों से घटाकर **अधिकतम 4 स्तर (Flatter Organization)** कर दिया गया है, और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश (PPO) देने हेतु **'भविष्य' (Bhavishya)** पोर्टल 814 कार्यालयों में लागू किया गया है।

(ग) नागरिक चार्टर (Citizen's Charter) एवं सेवोत्तम मॉडल (Sevottam Model)

• **नागरिक चार्टर:** यह किसी सरकारी संगठन द्वारा अपने नागरिकों/उपभोक्ताओं के प्रति किया गया एक स्वैच्छिक और लिखित प्रतिबद्धता दस्तावेज है जिसमें सेवा की गुणवत्ता के मानक, समय-सीमा, सूचना की उपलब्धता और शिकायत निवारण तंत्र का स्पष्ट उल्लेख होता है। इसका प्रारंभ सर्वप्रथम वर्ष **1991 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर** द्वारा किया गया था और भारत में इसे **मई 1997 के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन** में अपनाया गया। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 12वीं रिपोर्ट (*Citizen Centric Administration*) में नागरिक चार्टर के **7-चरणीय मॉडल** की सिफारिश की।

• **सेवोत्तम मॉडल (Sevottam = 'सेवा' + 'उत्तम'):** DARPG और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS — **IS 15700:2005**) द्वारा विकसित सेवोत्तम मॉडल सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता के मूल्यांकन और सुधार का एक मानक ढाँचा है। इसके **3 मुख्य मॉड्यूल** हैं:

1. **नागरिक चार्टर (Citizen's Charter):** नागरिकों से इनपुट प्राप्त करना और सेवा मानक तय करना।

2. **लोक शिकायत निवारण प्रणाली (Public Grievance Redress Mechanism — CPGRAMS):** जब सेवा मानक पूरा न हो, तो शिकायतों का समयबद्ध समाधान। DARPG के CPGRAMS प्रतिवेदन (जून 2026) के अनुसार मंत्रालयों की शिकायत निवारण क्षमता को मापने के लिए **'शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक' (GRAI - Grievance Redressal Assessment and Index)** प्रारंभ किया गया है।

3. **सेवा वितरण क्षमता (Service Delivery Capability):** संगठन के भीतर अवसंरचना, संसाधन और कर्मचारियों का क्षमता निर्माण।

(घ) पारदर्शिता एवं जवाबदेही: सूचना का अधिकार (RTI), सोशल ऑडिट एवं लोकपाल

• **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005):** इसने 'शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923' की औपनिवेशिक संस्कृति को बदलकर शासन में पारदर्शिता का युग प्रारंभ किया। **धारा 4** के तहत लोक प्राधिकारियों द्वारा स्व-प्रेरणा से प्रकटीकरण (Suo-motu disclosure), **धारा 7** के तहत सामान्यतः 30 दिनों में (जीवन या स्वतंत्रता से जुड़े मामले में **48 घंटे** में) सूचना देना, और **धारा 8(1)** में राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता व निजता से जुड़ी छूटों का प्रावधान है।

• **सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit):** मनरेगा (MGNREGA) की धारा 17 के तहत ग्राम सभा द्वारा सरकारी योजनाओं के अभिलेखों का जमीनी भौतिक कार्य से मिलान करना। **मेघालय (2017)** सामाजिक अंकेक्षण को कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना।

• **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013:** भ्रष्टाचार निवारण हेतु केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना।

सुशासन समीकरण (1D Conceptual Formula):

$$सुशासन (Good Governance) = पारदर्शिता (RTI) + उत्तरदायित्व (Social Audit + CAG + Lokpal) + नागरिक-केंद्रित सेवा (Sevottam + DPI) - विवेकाधिकार एवं भ्रष्टाचार$$

9.2 परीक्षा जाल (Exam Trap)

परीक्षा जाल (Exam Trap): नागरिक चार्टर की वैधानिकता, सेवोत्तम के 3 घटक एवं सूचना का अधिकार

1. **प्रथम भ्रम:** छात्र प्रायः लिख देते हैं कि 'नागरिक चार्टर (*Citizen's Charter*) न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय एक कानूनी अधिकार है'—यह **गलत** है। नागरिक चार्टर एक नैतिक और प्रशासनिक प्रतिबद्धता है, यह स्वयं में **कानूनी रूप से प्रवर्तनीय (Legally Justiciable) नहीं** है। हाँ, राज्यों द्वारा पारित **'लोक सेवा गारंटी अधिनियम' (Right to Public Services Acts — सर्वप्रथम मध्य प्रदेश, 2010)** नागरिकों को समयबद्ध सेवा का वैधानिक अधिकार देते हैं और देरी पर अधिकारी पर अर्थदंड लगाते हैं।
2. **द्वितीय भ्रम: सूचना का अधिकार (Right to Information)** केवल एक वैधानिक अधिकार है या मौलिक अधिकार भी? याद रखें: सर्वोच्च न्यायालय ने **राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1975)** और **एस. पी. गुप्ता वाद (1981)** में स्पष्ट किया है कि जानने का अधिकार संविधान के **अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता)** तथा अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित एक **मौलिक अधिकार** भी है, जिसे RTI अधिनियम, 2005 ने प्रक्रियात्मक और वैधानिक रूप दिया।
3. **तृतीय भ्रम: सेवोत्तम मॉडल** को केवल ग्रामीण विकास की योजना समझ लेना। सेवोत्तम मॉडल (IS 15700) **DARPG** द्वारा विकसित संपूर्ण भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में सार्वजनिक सेवा वितरण उत्कृष्टता का मानक ढाँचा है।

9.3 4-नोड फ्लोचार्ट: सेवोत्तम (Sevottam) एवं डिजिटल लोक शिकायत निवारण चक्र

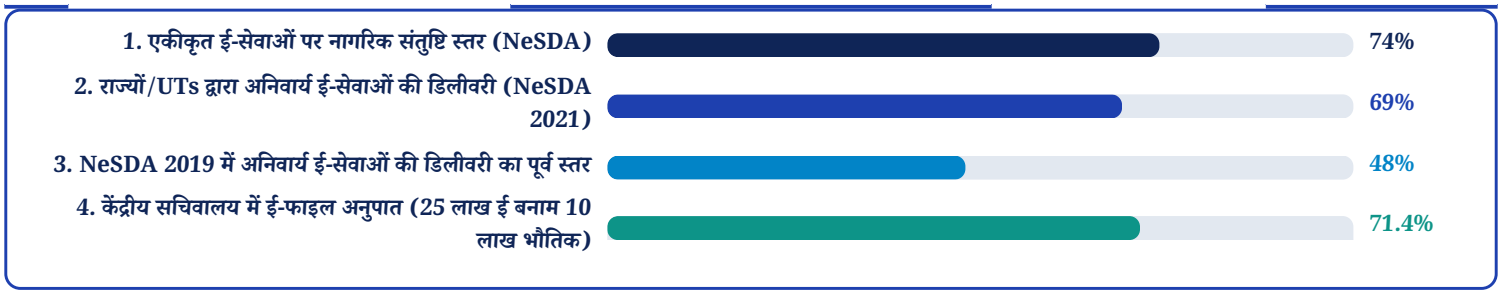
[नोड 1: नागरिक चार्टर मानक — सेवा की गुणवत्ता, समय-सीमा एवं नागरिक अपेक्षाओं का स्पष्ट प्रकाशन] **[नोड 2: डिजिटल सेवा वितरण (DPI) — ई-ऑफिस 7.0, डिजिलॉकर, उमंग ऐप, DBT एवं 69%+ अनिवार्य ई-सेवाएँ (NeSDA)]** **[नोड 3: लोक शिकायत निवारण (CPGRAMS) — AI-आधारित विश्लेषण, CSC-CPGRAMS दिवस एवं GRAI रैंकिंग]** **[नोड 4: जवाबदेही एवं प्रणालीगत सुधार — सोशल ऑडिट, RTI धारा 4 प्रकटीकरण एवं 74%+ नागरिक संतुष्टि]**

9.4 विस्तृत तुलनात्मक सारणी: शासन सुधार, ई-गवर्नेंस एवं जवाबदेही के प्रमुख स्तंभ

शासन तंत्र / पहल	वैधानिक / संस्थागत आधार	मुख्य कार्यप्रणाली एवं विशेषताएँ	प्रमाणित प्रभाव एवं आधिकारिक स्रोत
सुशासन सूचकांक (GGI) एवं सुशासन सप्ताह	DARPG एवं NCGG (25 दिसंबर सुशासन दिवस)	10 क्षेत्रों और 58 संकेतकों पर राज्यों/UTs तथा जिलों का मूल्यांकन; 'प्रशासन गाँव की ओर' अभियान	सुशासन सप्ताह में 6 लाख लोक शिकायतों का निवारण व 289 लाख सेवा आवेदनों का समाधान (DARPG)
ई-ऑफिस (e-Office ver 7.0) एवं सचिवालय सुधार	DARPG एवं NIC	कागज-रहित सचिवालय, फाइल प्रस्तुतीकरण के स्तर 7-8 से घटाकर अधिकतम 4 स्तर, डेस्क ऑफिसर सिस्टम	केंद्रीय सचिवालय में 25 लाख+ ई-फाइलें सक्रिय; J&K दरबार मूव में करोड़ों पृष्ठों का डिजिटलीकरण
NeSDA एवं केंद्रीय नागरिक पोर्टल	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन (DARPG)	विभागीय साइलो पोर्टलों के स्थान पर एकीकृत पोर्टलों से ई-सेवा वितरण; भविष्य (Bhavishya) पेंशन पोर्टल	राज्यों/UTs द्वारा 69% अनिवार्य ई-सेवाओं का वितरण; 74% नागरिक संतुष्टि; 814 कार्यालयों में भविष्य पोर्टल
CPGRAMS एवं GRAI सूचकांक	केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली	24x7 ऑनलाइन शिकायत पोर्टल, हर महीने की 20 तारीख को CSC-CPGRAMS दिवस, पेंशन अदालतें	पेंशन अदालतों में 18,000+ मामलों का समाधान; मंत्रालयों की GRAI रैंकिंग जारी (DARPG 2026)
सूचना का अधिकार (RTI) एवं सोशल ऑडिट	RTI अधिनियम, 2005 एवं मनरेगा धारा 17	केंद्रीय व राज्य सूचना आयोग; लोक प्राधिकारियों की जवाबदेही; ग्राम सभा द्वारा भौतिक सत्यापन	शासन में गोपनीयता के स्थान पर पारदर्शिता और जन-भागीदारी की स्थापना

9.5 चार्ट डेटा %: भारत में ई-गवर्नेंस सेवा वितरण एवं नागरिक संतुष्टि (DARPG प्रतिवेदन)

निम्नलिखित आँकड़े DARPG के शासन सुधार प्रतिवेदन पर आधारित हैं:



9.6 स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks)

- **संयुक्त राष्ट्र (UNESCAP) के सुशासन के 8 स्तंभ याद रखने का सूत्र — "PART-CEEA":**
- **P** = Participation (भागीदारी)
- **A** = Accountability (जवाबदेही)
- **R** = Rule of Law (विधि का शासन)
- **T** = Transparency (पारदर्शिता)
- **C** = Consensus Oriented (आम सहमति उन्मुख)
- **E** = Equity & Inclusiveness (समता और समावेशिता)
- **E** = Effectiveness & Efficiency (प्रभावशीलता और दक्षता)
- **A** (या **R**) = Responsiveness (अनुक्रियाशीलता)
- **सेवोत्तम (Sevottam) के 3 मॉड्यूल याद रखने की ट्रिक — "चर्चा (चार्टर), चिंता (शिकायत निवारण), क्षमता (सेवा वितरण क्षमता)"।**

9.7 अभ्यास प्रश्नोत्तर (15 व्याख्यात्मक प्रश्न — अध्याय 9)

अभ्यास प्रश्न #121 — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 1. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सुशासन (Good Governance) के कौन-से चार स्तंभ बताए गए हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: कौटिल्य ने "प्रजासुखे सुखं राज्ञः" के अंतर्गत सुशासन के चार क्रमिक दायित्व बताए हैं:

1. **रक्षण (Rakshan):** बाह्य आक्रमण व आंतरिक अव्यवस्था से प्रजा की सुरक्षा।
2. **पालन (Palan):** धर्म और विधि के शासन का अनुपालन।
3. **योगक्षेम (Yogakshema):** जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करना (योग) और जो प्राप्त है उसका संरक्षण व न्यायपूर्ण वितरण करना (क्षेम) अर्थात् लोक कल्याण।

अभ्यास प्रश्न #122 — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 2. 'सेवोत्तम मॉडल' (Sevottam Model) किस विभाग द्वारा विकसित किया गया है और इसका मानक कोड क्या है?

उत्तर एवं व्याख्या: सेवोत्तम मॉडल का विकास **प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG)** द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के सहयोग से वर्ष 2005 में किया गया था और इसका गुणवत्ता प्रबंधन मानक कोड **IS 15700:2005** है। इसके तीन घटक हैं: नागरिक चार्टर, लोक शिकायत निवारण तंत्र और सेवा वितरण क्षमता।

अभ्यास प्रश्न #123 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 3. भारत में 'लोक सेवा गारंटी अधिनियम' (Right to Public Services Act) लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन-सा था?

उत्तर एवं व्याख्या: मध्य प्रदेश ने वर्ष **2010** में सर्वप्रथम 'लोक सेवा गारंटी अधिनियम' पारित किया था। यह नागरिक चार्टर की स्वैच्छिक प्रकृति से आगे बढ़कर नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सार्वजनिक सेवाएँ (जैसे जाति/आय प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, बिजली कनेक्शन) प्राप्त करने का **कानूनी अधिकार** देता है और देरी होने पर दोषी अधिकारी पर प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड लगाता है।

अभ्यास प्रश्न #124 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 4. DARPG के शासन सुधार प्रतिवेदन के अनुसार 'सुशासन सूचकांक' (Good Governance Index - GGI) में कितने क्षेत्र और कितने संकेतक शामिल हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: सुशासन सूचकांक (GGI 2021 ढाँचे) में **10 क्षेत्र (Sectors)** और **58 संकेतक (Indicators)** शामिल हैं। इसके 10 क्षेत्रों में कृषि और संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिताएँ, आर्थिक शासन, समाज कल्याण और विकास, न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण तथा नागरिक-केंद्रित शासन सम्मिलित हैं।

अभ्यास प्रश्न #125 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 5. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) की धारा 4 और धारा 8 का क्या महत्व है?

उत्तर एवं व्याख्या: धारा 4 सभी लोक प्राधिकारियों पर यह दायित्व डालती है कि वे अपने अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत करें और अधिकतम जानकारी **स्व-प्रेरणा से (Suo-motu / Proactive Disclosure)** जनता के समक्ष प्रकाशित करें ताकि नागरिकों को सूचना माँगने के लिए कम से कम आवेदन करना पड़े। **धारा 8** उन संवेदनशील विषयों (जैसे भारत की संप्रभुता, अखंडता, रणनीतिक/वैज्ञानिक हित, मंत्रिमंडल के विचार-विमर्श के कागजात और व्यक्तिगत निजता) की सूची देती है जिन्हें प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है, किंतु धारा 8(2) के तहत व्यापक लोकहित होने पर सूचना दी जा सकती है।

अभ्यास प्रश्न #126 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 6. सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तों में क्या परिवर्तन किया?

उत्तर एवं व्याख्या: मूल 2005 अधिनियम में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष (या 65 वर्ष की आयु) निश्चित था और वेतन मुख्य चुनाव आयुक्त के समान था। **2019 के संशोधन** द्वारा केंद्र सरकार को अधिसूचना के माध्यम से केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों के सूचना आयुक्तों का कार्यकाल (अब 3 वर्ष अधिसूचित) और वेतन व भत्ते निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई।

अभ्यास प्रश्न #127 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 7. 'डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर' (DPI) या 'इंडिया स्टैक' (India Stack) क्या है?

उत्तर एवं व्याख्या: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) खुले मानकों (Open APIs) पर आधारित साझा डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स का समूह है जो उपस्थिति-रहित (Presenceless — Aadhaar), नकदी-रहित (Cashless — UPI) और कागज-रहित (Paperless — DigiLocker, e-Sign, Account Aggregator) सेवा वितरण को संभव बनाता है। भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान DPI को वैश्विक स्तर पर समावेशी विकास के मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया।

अभ्यास प्रश्न #128 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 8. DARPG के जून 2026 प्रतिवेदन के अनुसार 'GRAI' और 'CSC-CPGRAMS दिवस' क्या हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: GRAI (Grievance Redressal Assessment and Index) DARPG द्वारा केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की शिकायत निवारण दक्षता, गुणवत्ता और समयबद्धता की तुलनात्मक रैंकिंग करने वाला सूचकांक है। साथ ही, ग्रामीण नागरिकों को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा देने के लिए अक्टूबर 2023 से **प्रत्येक माह की 20 तारीख को 'CSC-CPGRAMS शिकायत दिवस'** मनाया जाता है।

अभ्यास प्रश्न #129 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 9. 'सामाजिक अंकेक्षण' (Social Audit) और 'वित्तीय अंकेक्षण' (Financial Audit - CAG) में क्या अंतर है?

उत्तर एवं व्याख्या: वित्तीय अंकेक्षण (CAG) एक विशेषज्ञ और संस्थागत प्रक्रिया है जिसमें सरकारी खातों, वाउचरों और व्यय की वैधानिकता की जांच की जाती है; जबकि **सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)** स्वयं लाभार्थियों और ग्राम सभा द्वारा किया जाने वाला सहभागी अंकेक्षण है जिसमें कागजी रिकॉर्ड का गाँव में बने वास्तविक भौतिक निर्माण कार्य (जैसे मनरेगा की सड़क या तालाब) से जमीनी मिलान किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न #130 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 10. DARPG शासन सुधार प्रतिवेदन के अनुसार केंद्रीय सचिवालय में निर्णय-प्रक्रिया की गति बढ़ाने के लिए कौन-से चार सुधार किए गए हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: DARPG के नेतृत्व में चार-सूत्रीय सुधार अपनाए गए हैं: (1) फाइल प्रस्तुतीकरण के चैनलों को 7–8 स्तरों से घटाकर **अधिकतम 4 स्तर** करना (Flatter Organizations), (2) निचले स्तर के अधिकारियों को वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन, (3) एकल बिंदु फाइल निस्तारण हेतु **डेस्क ऑफिसर प्रणाली** अपनाना, और (4) **ई-ऑफिस संस्करण 7.0** व केंद्रीय पंजीकरण इकाइयों का पूर्ण डिजिटलीकरण।

अभ्यास प्रश्न #131 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 11. 'भविष्य' (Bhavishya) और 'निधि आपके निकट 2.0' पहलें किससे संबंधित हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: DARPG प्रतिवेदन के अनुसार **'भविष्य'** पोर्टल सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही सभी देयकों का भुगतान और पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी करना सुनिश्चित करता है। वहीं CPGRAMS प्रतिवेदन (2026) के अनुसार **'निधि आपके निकट 2.0'** और EPFiGMS कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की जिला-स्तरीय आउटरीच और शिकायत निवारण पहल है।

अभ्यास प्रश्न #132 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 12. लोकपाल (Lokpal) की संरचना क्या है और इसकी चयन समिति में कौन-कौन शामिल होते हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत लोकपाल में **1 अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य** (जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होते हैं और कम से कम 50% सदस्य SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होने अनिवार्य हैं) होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें **प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश) और एक प्रख्यात न्यायविद** शामिल होते हैं।

अभ्यास प्रश्न #133 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 13. 'व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014' (Whistle Blowers Protection Act) का क्या उद्देश्य है?

उत्तर एवं व्याख्या: यह अधिनियम भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग या किसी सरकारी कर्मचारी/संस्थान की अनियमितता को उजागर करने वाले सचेत नागरिकों या कर्मचारियों (Whistleblowers) की पहचान को गोपनीय रखने और उन्हें किसी भी प्रकार के प्रतिशोध या उत्पीड़न (Victimization) से कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का तंत्र स्थापित करता है।

अभ्यास प्रश्न #134 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 14. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) ने अपनी 12वीं रिपोर्ट में नागरिक चार्टर को प्रभावी बनाने के लिए क्या मुख्य सुझाव दिया था?

उत्तर एवं व्याख्या: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा कि नागरिक चार्टर को "एक ही आकार सबके लिए" (One size fits all) के रूप में ऊपर से नहीं थोपा जाना चाहिए; बल्कि प्रत्येक अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय के लिए स्थानीय नागरिकों के परामर्श से चार्टर बनाया जाए, सेवा मानकों के उल्लंघन पर स्वतः मुआवजा/दंड हो, और सेवोत्तम मॉडल के तहत स्वतंत्र बाह्य मूल्यांकन किया जाए।

अभ्यास प्रश्न #135 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 15. मुख्य परीक्षा (Mains) दृष्टिकोण: 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' (Minimum Government, Maximum Governance) से क्या तात्पर्य है?

उत्तर एवं व्याख्या: इसका अर्थ सरकार के कल्याणकारी दायित्वों को कम करना नहीं है, बल्कि नागरिकों और उद्यमियों के दैनिक जीवन में अनावश्यक सरकारी लालफीताशाही, अप्रचलित कानूनों के बोझ और मानवीय हस्तक्षेप (Inspector Raj) को न्यूनतम करना तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी (DPI, Faceless Assessment, DBT, Single Window Clearance) के माध्यम से सेवा वितरण की गति, पारदर्शिता और पहुंच को अधिकतम करना है।

अध्याय 10: लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, स्वयं सहायता समूह (SHGs), गैर-सरकारी संगठन (NGOs - FCRA) एवं दबाव समूह

10.1 विस्तृत सैद्धांतिक एवं समाजशास्त्रीय व्याख्या

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 10.1 विस्तृत सैद्धांतिक एवं समाजशास्त्रीय व्याख्या

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
(क) लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका एवं 'मिशन कर्मयोगी'	(ख) स्वयं सहायता समूह (Self-Help Groups - SHGs): सूक्ष्म-वित्त से ग्रामीण रूपांतरण तक	(ग) गैर-सरकारी संगठन (NGOs): भूमिका, चुनौतियाँ एवं FCRA (2020 संशोधन)	(घ) दबाव समूह (Pressure Groups): लोकतंत्र के अदृश्य साम्राज्य

(क) लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका एवं 'मिशन कर्मयोगी'

सिविल सेवाएँ भारतीय संसदीय लोकतंत्र की **'स्थायी कार्यपालिका' (Permanent Executive)** हैं। जहाँ राजनीतिक कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) प्रत्येक चुनाव के साथ बदल सकती है, वहीं सिविल सेवाएँ नीतिगत निरंतरता, प्रशासनिक स्थिरता और संवैधानिक शासन का सातत्य सुनिश्चित करती हैं। **सरदार वल्लभभाई पटेल** ने संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवाओं को **'भारत का इस्पाती ढाँचा' (Steel Frame of India)** कहा था।

- **संवैधानिक प्रावधान:** संविधान के **भाग XIV (अनुच्छेद 308 से 323)** में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का प्रावधान है:
- **अनुच्छेद 310:** प्रसाद का सिद्धांत (Doctrine of Pleasure)।
- **अनुच्छेद 311:** सिविल सेवकों को मनमाने ढंग से पदच्युत किए जाने के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण (सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर)।
- **अनुच्छेद 312:** राज्यसभा द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर संसद द्वारा नई **अखिल भारतीय सेवा (All India Service — वर्तमान में IAS, IPS और IFoS)** का सृजन।
- **सिविल सेवाओं की बदलती भूमिका:** औपनिवेशिक काल में सिविल सेवा का मुख्य कार्य केवल 'कानून-व्यवस्था बनाए रखना और राजस्व वसूली' (Regulatory Administration) था; किंतु स्वतंत्र भारत में यह **'विकास प्रशासन' (Development Administration)** और अब **'नागरिक-केंद्रित सहभागी शासन एवं सुविधाप्रदाता' (Facilitator & Enabler)** में बदल चुका है।
- **मिशन कर्मयोगी (NPCSCB — National Programme for Civil Services Capacity Building):** पीआईबी के मिशन कर्मयोगी प्रतिवेदन (अगस्त 2026) के अनुसार सितंबर 2020 में स्वीकृत मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सिविल सेवाओं को **'नियम-आधारित' (Rule-based) से 'भूमिका-आधारित' (Role-based)** मानव संसाधन प्रबंधन की ओर ले जाना है। इसके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म **iGOT कर्मयोगी** पर अगस्त 2026 तक **1.70 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता** जुड़ चुके हैं और डोमेन, कार्यात्मक व व्यावहारिक दक्षताओं पर **5,600 से अधिक पाठ्यक्रम** (जिनमें **AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर 218 पाठ्यक्रम** शामिल हैं) उपलब्ध हैं। साथ ही, व्यक्तिगत शिक्षण हेतु **iGOT AI Tutor, iGOT AI Sarthi और AI-CBP Tool** भी लागू किए गए हैं।

(ख) स्वयं सहायता समूह (Self-Help Groups - SHGs): सूक्ष्म-वित्त से ग्रामीण रूपांतरण तक

स्वयं सहायता समूह (SHG) समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले ग्रामीण गरीबों (मुख्यतः महिलाओं) का **10 से 20 सदस्यों** का एक स्वैच्छिक और अनौपचारिक समूह होता है, जो पारस्परिक सहायता और सामूहिक जिम्मेदारी (Peer Pressure as Social Collateral) के सिद्धांत पर छोटी-छोटी बचत एकत्र करता है और सदस्यों को आपसी ऋण देता है।

- **ऐतिहासिक विकास:** बांग्लादेश में **प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस** (ग्रामीण बैंक मॉडल) से प्रेरित होकर भारत में वर्ष **1992 में नाबार्ड (NABARD)** द्वारा **'SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम' (SHG-BLP)** पायलट आधार पर शुरू किया गया।

• **राष्ट्रीय विस्तार एवं डिजिटल एकीकरण (2026 के नवीनतम आँकड़े):** पीआईबी के 15 नवंबर 2026 के तथ्य-पत्रक तथा लोकओएस (LokOS) पीआईबी विज्ञप्ति (जुलाई 2026) के अनुसार 12 नवंबर 2026 तक **दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)** ने देश के **10.13 करोड़ ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को 94.40 लाख स्वयं सहायता समूहों (SHGs)** में संगठित किया है। ये SHGs ग्राम संगठन (Village Organisations - VOs) और क्लस्टर स्तरीय संघों (Cluster Level Federations - CLFs) के त्रि-स्तरीय ढाँचे में कार्य करते हैं और **'LokOS' डिजिटल प्लेटफॉर्म** से इनका लेखांकन व पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है।

• **SHGs की बहुआयामी भूमिका:** वित्तीय समावेशन (बैंक सखी), डिजिटल साक्षरता, पोषण एवं स्वास्थ्य जागरूकता, पंचायती राज में महिला नेतृत्व निर्माण, नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता का विकास।

(ग) गैर-सरकारी संगठन (NGOs): भूमिका, चुनौतियाँ एवं FCRA (2020 संशोधन)

गैर-सरकारी संगठन (NGOs) या स्वैच्छिक संगठन (Voluntary Organizations) वे गैर-लाभकारी और स्वायत्त नागरिक समाज संस्थाएँ हैं जो सरकार से स्वतंत्र रहकर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, आपदा राहत और नीतिगत वकालत में कार्य करती हैं। भारत में NGOs का पंजीकरण मुख्यतः तीन कानूनों के तहत होता है:

1. **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** (Societies Registration Act, 1860)
2. **भारतीय न्यास अधिनियम, 1882** (Indian Trusts Act, 1882)
3. **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8** (Section 8 Non-Profit Companies)

• **नीति आयोग का 'दर्पण' पोर्टल (NGO-DARPAN):** सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले सभी गैर-सरकारी संगठनों के लिए नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण और विशिष्ट आईडी (Unique ID) प्राप्त करना अनिवार्य है।

• **विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 एवं FCRA (संशोधन) अधिनियम, 2020:** गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा प्रशासित FCRA यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी धन का उपयोग भारत की संप्रभुता, आंतरिक सुरक्षा या राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल गतिविधियों में न हो। **2020 के संशोधन** के प्रमुख प्रावधान हैं:

• प्रशासनिक खर्चों (Administrative Expenses) पर विदेशी अंशदान के उपयोग की अधिकतम सीमा **50% से घटाकर 20%** कर दी गई है।

• एक एनजीओ द्वारा प्राप्त विदेशी अंशदान को किसी दूसरे एनजीओ को **हस्तांतरित करने (Sub-granting) पर पूर्ण प्रतिबंध** लगा दिया गया है।

• विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए केवल **भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की नई दिल्ली मुख्य शाखा** में ही अनिवार्य 'FCRA खाता' खोलना होगा।

• सभी पदाधिकारियों के लिए **आधार (Aadhaar)** संख्या अनिवार्य की गई है और लोक सेवकों (Public Servants) को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है।

(घ) दबाव समूह (Pressure Groups): लोकतंत्र के अदृश्य साम्राज्य

राजनीतिक वैज्ञानिक **एस. ई. फाइनर** ने दबाव समूहों को **'अदृश्य साम्राज्य' (Anonymous Empire)** कहा है। दबाव समूह समान हितों वाले व्यक्तियों के वे संगठित समूह हैं जो **स्वयं चुनाव लड़कर सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास नहीं करते**, अपितु लॉबिंग, याचिका, जनमत निर्माण, प्रदर्शन और नीतिगत संवाद के माध्यम से सरकार की नीतियों को अपने सदस्यों के हित में प्रभावित करते हैं।

• **आलमंड और पावेल (Almond & Powell) का वर्गीकरण:**

1. **संस्थागत दबाव समूह (Institutional Pressure Groups):** प्रशासन, सेना या विधायिका के भीतर के औपचारिक समूह (जैसे—IAS एसोसिएशन, पुलिस एसोसिएशन)।
2. **समुदायात्मक दबाव समूह (Associational Pressure Groups):** विशेष आर्थिक या व्यावसायिक हितों के लिए गठित औपचारिक संगठन—जैसे **व्यापारिक मंडल** (FICCI, CII, ASSOCHAM), **श्रमिक संघ** (INTUC, BMS, AITUC) और **किसान संगठन** (BKU, AIKS) तथा छात्र संघ (ABVP, NSUI)।
3. **असमुदायात्मक दबाव समूह (Non-Associational Pressure Groups):** जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर अनौपचारिक रूप से सक्रिय समूह (जैसे—जातीय महासभाएँ, खाप पंचायतें)।

4. **प्रदर्शनात्मक या एनोमिक दबाव समूह (Anomic Pressure Groups):** किसी तात्कालिक घटना के विरोध में अचानक सड़कों पर उतरने वाले स्वतःस्फूर्त समूह।

सहभागी लोकतंत्र सूत्र (1D Conceptual Formula):

$$सहभागी लोकतंत्र = सक्षम सिविल सेवा (मिशन कर्मयोगी) + जमीनी सामूहिकता (94.4 लाख SHGs) + उत्तरदायी नागरिक समाज (NGOs + दबाव समूह)$$

10.2 परीक्षा जाल (Exam Trap)

परीक्षा जाल (Exam Trap): राजनीतिक दल बनाम दबाव समूह, अखिल भारतीय सेवाएँ एवं FCRA मंत्रालय

1. **प्रथम भ्रम:** छात्र प्रायः 'विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम - *FCRA*' का नोडल मंत्रालय 'वित्त मंत्रालय' या 'विदेश मंत्रालय' टिक कर देते हैं—यह **गलत** है। FCRA का प्रशासन और निगरानी **केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs - MHA)** द्वारा की जाती है (जबकि FEMA का प्रशासन वित्त मंत्रालय/RBI द्वारा होता है)।
2. **द्वितीय भ्रम: अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services - अनुच्छेद 312)** में भारतीय विदेश सेवा (IFS) को शामिल मान लेना—यह **गलत** है। वर्तमान में केवल **3 अखिल भारतीय सेवाएँ** हैं: (1) भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), (2) भारतीय पुलिस सेवा (IPS), और (3) **भारतीय वन सेवा (IFoS — Indian Forest Service, 1966 में गठित)**। भारतीय विदेश सेवा (Indian Foreign Service) एक 'केंद्रीय सेवा (समूह क)' है, अखिल भारतीय सेवा नहीं।
3. **तृतीय भ्रम:** दबाव समूह (Pressure Groups) और राजनीतिक दल (Political Parties) में अंतर भूल जाना। राजनीतिक दल प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ते हैं, व्यापक विचारधारा रखते हैं और सरकार बनाने का लक्ष्य रखते हैं; जबकि दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, उनका उद्देश्य विशिष्ट/संकीर्ण हितों के लिए बाहर से सरकार पर दबाव बनाना होता है।

10.3 4-नोड फ्लोचार्ट: सिविल सेवा, SHG एवं नागरिक समाज का सहक्रियात्मक शासन मॉडल

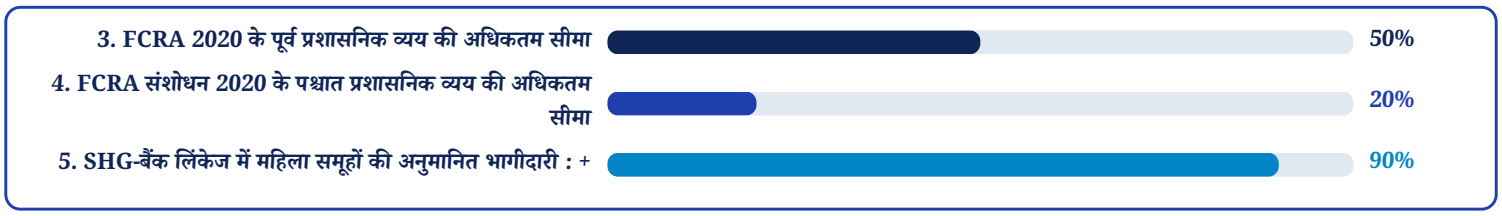
[नोड 1: नीति निर्माण एवं परामर्श — दबाव समूह (FICCI, किसान-श्रमिक संघ) व थिंक-टैंक द्वारा जमीनी इनपुट] **[नोड 2: प्रशासनिक क्रियान्वयन — मिशन कर्मयोगी से प्रशिक्षित भूमिका-आधारित सिविल सेवा (IAS/IPS/IFoS व केंद्रीय सेवाएँ)]** **[नोड 3: अंतिम छोर वितरण (Last-Mile Delivery) — 94.40 लाख SHGs (10.13 करोड़ महिलाएँ) एवं दर्पण-पंजीकृत NGOs]** **[नोड 4: जवाबदेही एवं राष्ट्रीय सुरक्षा — FCRA 2020 पारदर्शिता, LokOS डिजिटलीकरण एवं लोकतांत्रिक सुशासन]**

10.4 विस्तृत तुलनात्मक सारणी: राजनीतिक दल, दबाव समूह, एनजीओ एवं स्वयं सहायता समूह (SHGs)

तुलना का आधार	राजनीतिक दल (Political Parties)	दबाव समूह (Pressure Groups)	गैर-सरकारी संगठन (NGOs)	स्वयं सहायता समूह (SHGs)
प्राथमिक उद्देश्य	चुनाव लड़कर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना और सरकार का संचालन करना	सत्ता से बाहर रहकर अपने सदस्यों के विशिष्ट हितों के पक्ष में सरकारी नीतियों को प्रभावित करना	सामाजिक सेवा, कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, वकालत और वंचितों का उत्थान	सदस्यों के मध्य सूक्ष्म बचत, आपसी ऋण और सामूहिक आजीविका/उद्यमिता से गरीबी उन्मूलन
संगठनात्मक प्रकृति एवं आकार	व्यापक जन-आधार और बहु-आयामी राष्ट्रीय/क्षेत्रीय विचारधारा	विशिष्ट वर्ग-आधारित (व्यापारी, किसान, मजदूर, पेशेवर) संगठित समूह	सोसायटी (1860), ट्रस्ट (1882) या धारा 8 कंपनी (2013) के रूप में पंजीकृत	**10 से 20 ग्रामीण महिलाओं** का स्वैच्छिक समूह (VOs एवं CLFs में संघबद्ध)
नियामक / संस्थागत ढाँचा	भारत निर्वाचन आयोग (जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A)	संवैधानिक संघ बनाने का अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(c)); ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926	नीति आयोग का **NGO-DARPAN** पोर्टल एवं विदेशी फंडिंग हेतु **FCRA (गृह मंत्रालय)**	**NABARD** (SHG-BLP) एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय (**DAY-NRLM / LokOS**)
प्रमुख उदाहरण एवं आँकड़े	राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल	FICCI, CII, ASSOCHAM, BMS, INTUC, BKU, IMA	प्रथम (Pratham), गूंज, सेवा (SEWA), अक्षय पात्र	**12 नवंबर 2026 तक 94.40 लाख SHGs में 10.13 करोड़ महिला सदस्य (PIB)**

10.5 चार्ट डेटा %: मिशन कर्मयोगी, SHG नेटवर्क एवं FCRA मानदंड (2026 अद्यतन)

निम्नलिखित आँकड़े पीआईबी के लखपति दीदी/DAY-NRLM प्रतिवेदन (15 नवंबर 2026), मिशन कर्मयोगी पीआईबी विज्ञप्ति (अगस्त 2026) और FCRA अधिनियम पर आधारित हैं:



10.6 स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks)

- **मिशन कर्मयोगी के 6 स्तंभ याद रखने का सूत्र — "नीति, ढाँचा, निगरानी, ई-लर्निंग (iGOT), मूल्यांकन (FRAC), संस्थागत समन्वय"।**
- **FCRA संशोधन अधिनियम, 2020 के 4 कठोर नियम याद रखने की ट्रिक — "20% खर्च, नो ट्रांसफर, SBI दिल्ली खाता, आधार अनिवार्य":**

1. **20% खर्च:** प्रशासनिक खर्च की सीमा 50% से घटाकर 20%।
2. **नो ट्रांसफर:** एक एनजीओ से दूसरे एनजीओ को विदेशी धन के हस्तांतरण पर रोक।
3. **SBI दिल्ली खाता:** विदेशी अंशदान केवल एसबीआई, नई दिल्ली मुख्य शाखा में।
4. **आधार अनिवार्य:** सभी पदाधिकारियों व निदेशकों का आधार कार्ड और लोक सेवकों को पूर्ण निषेध।

10.7 अभ्यास प्रश्नोत्तर (15 व्याख्यात्मक प्रश्न — अध्याय 10)

अभ्यास प्रश्न #136 — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 1. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नई 'अखिल भारतीय सेवा' (All India Service) का सृजन किया जा सकता है?

उत्तर एवं व्याख्या: अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि **राज्यसभा** अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम **दो-तिहाई (2/3) बहुमत** से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं (जिनमें अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी शामिल है) का सृजन कर सकती है।

अभ्यास प्रश्न #137 — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 2. पीआईबी विज्ञप्ति (अगस्त 2026) के अनुसार 'मिशन कर्मयोगी' का मुख्य उद्देश्य क्या है और iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की वर्तमान पहुँच कितनी है?

उत्तर एवं व्याख्या: सितंबर 2020 में स्वीकृत मिशन कर्मयोगी (NPCSCB) का उद्देश्य भारतीय नौकरशाही को **'नियम-आधारित' (Rule-based) से 'भूमिका-आधारित' (Role-based)** मानव संसाधन प्रणाली में परिवर्तित करना है। अगस्त 2026 तक इसके **iGOT कर्मयोगी** डिजिटल प्लेटफॉर्म पर **1.70 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता** हैं और **5,600 से अधिक पाठ्यक्रम** (AI के 218 कोर्स तथा iGOT AI Tutor व AI Sarthi सहित) उपलब्ध हैं।

अभ्यास प्रश्न #138 — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 3. सिविल सेवा में 'अनामता' (Anonymity) और 'राजनीतिक तटस्थता' (Political Neutrality) का क्या अर्थ है?

उत्तर एवं व्याख्या: अनामता का अर्थ है कि सिविल सेवक पर्दे के पीछे रहकर नीति निर्माण और क्रियान्वयन में कार्य करते हैं तथा संसद व जनता के प्रति राजनीतिक जिम्मेदारी संबंधित मंत्री (मंत्रिपरिषद) की होती है, न कि व्यक्तिगत अधिकारी की। **राजनीतिक तटस्थता** का अर्थ है कि सिविल सेवक किसी भी राजनीतिक दल के प्रति पक्षपात किए बिना सत्ता में निर्वाचित किसी भी वैध सरकार को निष्पक्ष और पेशेवर सलाह देते हैं।

अभ्यास प्रश्न #139 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 4. 'लैटरल एंट्री' (Lateral Entry) क्या है और इसके पक्ष-विपक्ष के मुख्य तर्क क्या हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: निजी क्षेत्र, अकादमिक जगत और सार्वजनिक उपक्रमों के विषय-विशेषज्ञों को संयुक्त सचिव, निदेशक और उप-सचिव के स्तर पर संविदा के आधार पर सीधे सरकारी मंत्रालयों में नियुक्त करने को 'लैटरल एंट्री' कहते हैं। **पक्ष में तर्क:** डोमेन विशेषज्ञता (अर्थशास्त्र, फिनटेक, पर्यावरण, AI) का समावेश और प्रतिस्पर्धा। **विपक्ष में तर्क:** जमीनी क्षेत्रीय प्रशासन (Field Experience) का अभाव, संवैधानिक आरक्षण (SC/ST/OBC) का पालन और हितों के टकराव (Conflict of Interest) की चुनौतियाँ।

अभ्यास प्रश्न #140 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 5. पीआईबी के 15 नवंबर 2026 के तथ्य-पत्रक के अनुसार DAY-NRLM के तहत देश में कितने स्वयं सहायता समूह (SHGs) और कितनी महिला सदस्य संगठित हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: 12 नवंबर 2026 तक दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ने देश की लगभग **10.13 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को 94.40 लाख स्वयं सहायता समूहों (SHGs)** में संगठित किया है, जो विश्व का सबसे बड़ा सामुदायिक गरीबी उन्मूलन नेटवर्क है।

अभ्यास प्रश्न #141 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 6. पीआईबी विज्ञप्ति (जुलाई 2026) में वर्णित 'लोकओएस' (LokOS) प्लेटफॉर्म क्या है?

उत्तर एवं व्याख्या: LokOS (Livelihoods Open-source Operating System) ग्रामीण विकास मंत्रालय (DAY-NRLM) द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो स्वयं सहायता समूहों (SHGs), ग्राम संगठनों (VOs) और क्लस्टर स्तरीय संघों (CLFs) के वित्तीय लेनदेन, बहीखाते और प्रोफाइल का डिजिटलीकरण कर बैंक क्रेडिट लिंकेज और लखपति दीदी की निगरानी को पारदर्शी बनाता है।

अभ्यास प्रश्न #142 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 7. भारत में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के समक्ष आने वाली चार प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: (1) **क्षेत्रीय असमानता:** दक्षिणी राज्यों में SHG नेटवर्क अधिक परिपक्व है जबकि पूर्वोत्तर व कुछ उत्तरी क्षेत्रों में क्रेडिट विस्तार की गति भिन्न है, (2) **विपणन और ब्रांडिंग की कमी:** SHG उत्पादों को बहुराष्ट्रीय ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा, (3) केवल पारंपरिक आजीविका (अचार, पापड़, सिलाई) तक सीमित रहना, और (4) डिजिटल व वित्तीय लेखांकन कौशल की कमी।

अभ्यास प्रश्न #143 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 8. विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 (FCRA Amendment 2020) के तहत प्रशासनिक व्यय की सीमा कितनी कर दी गई है?

उत्तर एवं व्याख्या: FCRA संशोधन अधिनियम, 2020 ने किसी गैर-सरकारी संगठन (NGO) द्वारा प्राप्त कुल विदेशी अंशदान में से प्रशासनिक खर्चों (वेतन, कार्यालय किराया, यात्रा आदि) पर व्यय करने की अधिकतम सीमा को पूर्ववर्ती **50% से घटाकर 20%** कर दिया है, ताकि कम से कम 80% राशि सीधे मूल कल्याणकारी उद्देश्य पर खर्च हो।

अभ्यास प्रश्न #144 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 9. भारत में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) का पंजीकरण किन तीन प्रमुख वैधानिक मार्गों से होता है?

उत्तर एवं व्याख्या: भारत में NGOs का पंजीकरण मुख्यतः तीन कानूनों के अंतर्गत होता है: (1) **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** (सोसायटी के रूप में), (2) **भारतीय न्यास अधिनियम, 1882** (चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में), और (3) **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8** (गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में)।

अभ्यास प्रश्न #145 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 10. गैब्रियल आलमंड और जी. बिंघम पावेल ने दबाव समूहों को किन चार श्रेणियों में बाँटा है?

उत्तर एवं व्याख्या: आलमंड और पावेल ने दबाव समूहों को चार भागों में वर्गीकृत किया है: (1) **संस्थागत दबाव समूह** (नौकरशाही/सेना के भीतर), (2) **समुदायात्मक दबाव समूह** (FICCI, ट्रेड यूनियन, किसान संघ), (3) **असमुदायात्मक दबाव समूह** (जाति, धर्म, भाषा आधारित अनौपचारिक समूह), और (4) **प्रदर्शनात्मक/एनोमिक दबाव समूह** (दंगों या आकस्मिक विरोध में उभरे समूह)।

अभ्यास प्रश्न #146 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 11. सिविल सेवकों को प्राप्त 'अनुच्छेद 311' के दो मुख्य संवैधानिक सुरक्षा कवच कौन-से हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: अनुच्छेद 311 के तहत: (1) किसी भी सिविल सेवक को उस प्राधिकारी के अधीनस्थ (Subordinate) किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत (Dismiss) या पद से हटाया (Remove) नहीं जाएगा जिसके द्वारा उसकी नियुक्ति की गई थी, और (2) किसी सिविल सेवक को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच और **सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर (Reasonable opportunity of being heard)** दिए बिना पदच्युत, पद से हटाया या पदावनत नहीं किया जाएगा (राष्ट्रपति/राज्यपाल की राष्ट्रीय सुरक्षा संतुष्टि या आपराधिक दोषसिद्धि के अपवादों को छोड़कर)।

अभ्यास प्रश्न #147 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 12. 'प्रतिबद्ध नौकरशाही' (Committed Bureaucracy) से क्या आशय है और लोकतंत्र में इसका सही अर्थ क्या होना चाहिए?

उत्तर एवं व्याख्या: यदि 'प्रतिबद्ध नौकरशाही' का अर्थ सत्ताधारी राजनीतिक दल या व्यक्ति विशेष के प्रति निष्ठा से लिया जाए, तो यह लोकतांत्रिक निष्पक्षता के लिए घातक है। लोकतंत्र में सिविल सेवक की सच्ची प्रतिबद्धता किसी दल के प्रति नहीं, बल्कि **भारतीय संविधान के मूल्यों, विधि के शासन और जन-कल्याण (Constitutional Patriotism)** के प्रति होनी चाहिए।

अभ्यास प्रश्न #148 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 13. 'प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार' (PM's Awards for Excellence in Public Administration) कब प्रदान किए जाते हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: DARPG प्रतिवेदन के अनुसार देश भर के जिला कलेक्टरों तथा केंद्रीय व राज्य अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता वाली योजनाओं के संतृप्तिकरण और प्रशासनिक नवाचार में किए गए उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष **21 अप्रैल को 'राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस' (National Civil Services Day)** के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं (21 अप्रैल 1947 को सरदार पटेल ने मेटकाफ हाउस, दिल्ली में प्रथम बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया था)।

अभ्यास प्रश्न #149 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 14. स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए सरकार ने कौन-सी ई-कॉमर्स पहलें की हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने SHG उत्पादों के विपणन के लिए **'सरस आजीविका' (SARAS Aajeevika)** पोर्टल व सरस मेले शुरू किए हैं तथा इन्हें **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM)**, **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC)** और प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों से जोड़ा है।

अभ्यास प्रश्न #150 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 15. मुख्य परीक्षा (Mains) दृष्टिकोण: क्या गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और दबाव समूहों पर कड़े विनियमन (जैसे FCRA 2020) विकास और लोकतंत्र के बीच तनाव उत्पन्न करते हैं?

उत्तर एवं व्याख्या: एक जीवंत लोकतंत्र में रचनात्मक असहमति, नीतिगत संवाद और अंतिम छोर तक सेवा वितरण में NGOs व दबाव समूहों की भूमिका अपरिहार्य है; किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने **नोएल हार्पर बनाम भारत संघ (2022)** मामले में FCRA संशोधनों को वैध ठहराते हुए स्पष्ट किया कि विदेशी धन प्राप्त करना कोई निरपेक्ष मौलिक अधिकार नहीं है और राष्ट्र की संप्रभुता, आंतरिक सुरक्षा व वित्तीय पारदर्शिता सर्वोच्च है। अत: समाधान 'अति-विनियमन' में नहीं, बल्कि पारदर्शी डिजिटल अनुपालन (NGO-DARPAN) और स्वदेशी परोपकार (CSR फंडिंग) को प्रोत्साहित करने में निहित है।

IUC Academy — मास्टर त्वरित पुनरीक्षण एवं महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य सारणी (Quick Revision Matrix)

क्र.सं.	मुख्य विषय क्षेत्र	सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्री / आयोग / अनुच्छेद	परीक्षा हेतु स्वर्णिम तथ्य एवं नवीनतम प्रमाणित आँकड़े (2025–2026)
1.	भारतीय समाज एवं जाति	जी. एस. घुर्ये (6 विशेषताएँ), एम. एन. श्रीनिवास (संस्कृतिकरण, प्रभुत्वशाली जाति), रजनी कोठारी	संस्कृतिकरण केवल 'पदमुलक परिवर्तन' लाता है; भारतीय परिवार आज भी 'कार्यात्मक रूप से संयुक्त' (आई. पी. देसाई) हैं।
2.	महिला सशक्तिकरण	सरला देवी चौधरानी (1910), 106वाँ संशोधन (2023), मिशन शक्ति (संबल + सामर्थ्य)	लिंगानुपात 1,020 (NFHS-5); MMR घटकर 88 हुआ; 10.57 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन; माध्यमिक बालिका नामांकन 80.2%।
3.	जनसंख्या एवं गरीबी	1921 (महान विभाजक वर्ष), अलघ/तेंदुलकर/रंगराजन समिति, नीति आयोग राष्ट्रीय MPI (12 संकेतक)	राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी 24.85% से घटकर 14.96% हुई (13.5 करोड़ लोग बाहर निकले)।
4.	शहरीकरण एवं प्रवासन	74वाँ संशोधन (12वीं अनुसूची - 18 विषय), जनगणना नगर (5000 / 75% / 400)	SBM-U 2.0 में कचरा संग्रहण 98% व प्रसंस्करण 82%; PMAY-U में 98.10 लाख आवास; ONORC में 233 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन।
5.	भूमंडलीकरण	रोलैंड रॉबर्टसन (ग्लोकलाइजेशन), जॉर्ज रित्ज़र (मैकडोनाल्डाइजेशन), अर्जुन ऐपदुराई (5 स्केप्स)	भारत विश्व का शीर्ष रेमिटेंस प्राप्तकर्ता ($100B+); PLI में 106% लक्ष्य प्राप्ति; 2070 नेट-जीरो लक्ष्य।
6.	संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद व धर्मनिरपेक्षता	बिपिन चंद्र (3 चरण), राजीव भार्गव (सैद्धांतिक दूरी), एस. आर. बोम्मई वाद (1994), अनुच्छेद 262-263	भारतीय धर्मनिरपेक्षता 'सर्वधर्म समभाव' एवं सुधारात्मक हस्तक्षेप (अनुच्छेद 25(2)) पर आधारित है।
7.	स्वास्थ्य, शिक्षा व मानव संसाधन	जॉन रॉल्स (अंतर सिद्धांत), अनुच्छेद 21A, कस्तूरीरंगन समिति (NEP 2020: 5+3+3+4)	43.93 करोड़ आयुष्मान कार्ड; 88.33 करोड़ ABHA खाते; परिवार स्वास्थ्य बीमा कवरेज 60.2% (NFHS-6, मई 2026)।
8.	अति-संवेदनशील वर्ग	अनुच्छेद 338 (NCSC), 338A (NCST), 338B (NCBC - 102वाँ संशोधन), RPwD Act 2016 (21 श्रेणियाँ)	PM-JANMAN (75 PVTGs); स्माइल (SMILE) योजना में ₹365 करोड़ परिव्यय व 23 गरिमा गृह; आयुष्मान वय वंदना में 1.20 करोड़ बुजुर्ग।
9.	सुशासन एवं ई-गवर्नेंस	कौटिल्य (प्रजासुखे सुखं राज्ञः), सेवोत्तम मॉडल (IS 15700), RTI 2005, DPI (India Stack)	GGI (10 क्षेत्र, 58 संकेतक); NeSDA में 69% अनिवार्य ई-सेवाएँ व 74% नागरिक संतुष्टि; केंद्रीय सचिवालय में 25 लाख+ ई-फाइलें।
10.	सिविल सेवा, SHGs, NGOs व दबाव समूह	अनुच्छेद 311 व 312 (IAS, IPS, IFoS), मिशन कर्मयोगी, DAY-NRLM (LokOS), FCRA संशोधन 2020	iGOT कर्मयोगी पर 1.70 करोड़+ उपयोगकर्ता व 5,600+ कोर्स; DAY-NRLM में 94.40 लाख SHGs व 10.13 करोड़ महिला सदस्य (नवंबर 2026)।

यह खंड **IUC Academy लर्निंग पाथ** की पुस्तक 28 (भारतीय समाज, सामाजिक न्याय एवं अभिशासन) के लिए तैयार किया गया है, जिसमें **NCERT पाठ्यपुस्तक पोर्टल**, **विधायी विभाग — भारत का संविधान**, **नीति आयोग** और **भारत की जनगणना सारणी पोर्टल** के प्रामाणिक आंकड़ों व प्रावधानों पर आधारित 10 पूर्ण 'IUC प्रमुख अध्ययन इकाई' और 100-पॉइंट 'अंतिम समय त्वरित वन-लाइनर रिवीजन कैप्सूल' शामिल हैं।

मॉड्यूल 1: भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं — विविधता में एकता, जाति, परिवार एवं नातेदारी

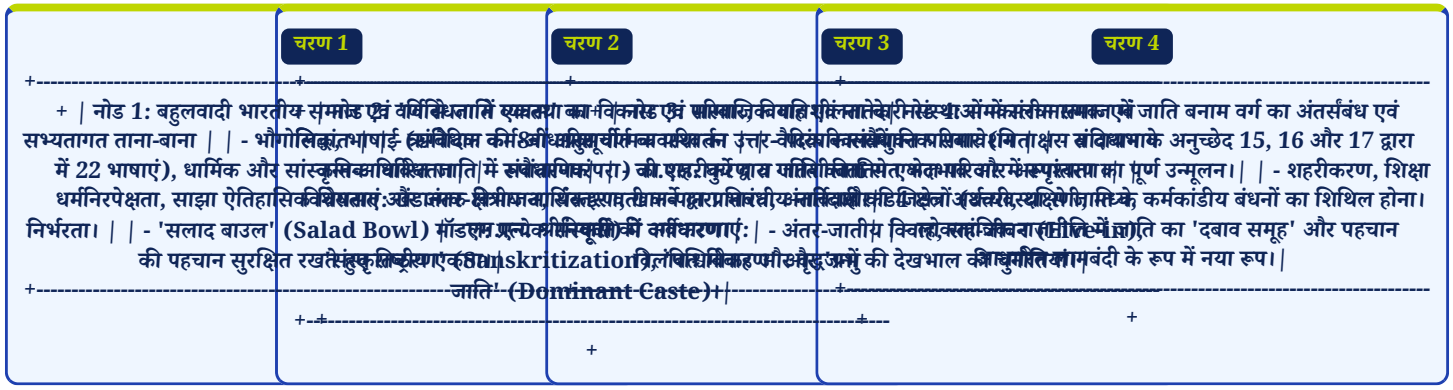
अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 1: भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं — विविधता में एकता, जाति, परिवार एवं नातेदारी

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स (Did You Know? Box)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स (Exam Trap Alert Box)

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)



2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: पारंपरिक जाति व्यवस्था बनाम आधुनिक वर्ग व्यवस्था एवं संयुक्त बनाम एकल परिवार

तुलना का आधार	पारंपरिक जाति व्यवस्था (Caste System)	आधुनिक वर्ग व्यवस्था (Class System)	संवैधानिक एवं समाजशास्त्रीय संदर्भ
निर्धारण का आधार	**प्रदत्त प्रस्थिति (Ascribed Status):** व्यक्ति की जाति का निर्धारण पूरी तरह जन्म और वंश से होता है (NCERT पाठ्यपुस्तक पोर्टल)।	**अर्जित प्रस्थिति (Achieved Status):** व्यक्ति का वर्ग उसकी शिक्षा, आय, संपत्ति, व्यवसाय और कौशल से निर्धारित होता है।	आधुनिक औद्योगिक और सेवा-क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में जन्म के स्थान पर योग्यता (Merit) का महत्व बढ़ा है।
सामाजिक गतिशीलता	**बंद व्यवस्था (Closed System):** व्यक्तिगत स्तर पर जाति बदलना असंभव; केवल सामूहिक स्तर पर एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार 'संस्कृतिकरण' द्वारा स्थिति में क्रमिक बदलाव।	**खुली व्यवस्था (Open System):** कोई भी व्यक्ति शिक्षा और उद्यम के माध्यम से निम्न वर्ग से मध्यम या उच्च वर्ग में ऊर्ध्वाधर गतिशीलता (Vertical Mobility) प्राप्त कर सकता है।	विधायी विभाग — भारत का संविधान के अनुच्छेद 16 द्वारा लोक नियोजन में अवसर की समता सुनिश्चित की गई है।
विवाह एवं सामाजिक नियम	**अंतर्विवाह (Endogamy):** अपनी ही जाति या उप-जाति के भीतर विवाह की कठोर सामाजिक बाध्यता तथा खान-पान व सहवास पर कर्मकांडीय प्रतिबंध।	**बहिर्विवाह की स्वतंत्रता:** विवाह में जाति की अपेक्षा शैक्षणिक स्तर, जीवनशैली और आर्थिक अनुकूलता को प्राथमिकता।	विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act, 1954) अंतर-धार्मिक और अंतर-जातीय विवाहों को कानूनी संरक्षण देता है।
व्यवसाय का स्वरूप	वंशानुगत पारंपरिक व्यवसाय और ग्रामीण **'जजमानी व्यवस्था'** (विलियम वाइजर द्वारा अध्ययनकृत वस्तु-विनिमय आधारित सेवा संबंध)।	व्यवसाय के चयन की पूर्ण स्वतंत्रता (संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g)); बाजार और अनुबंध आधारित आर्थिक संबंध।	महात्मा गांधी नरेगा, कौशल भारत और स्टार्टअप इंडिया ने ग्रामीण युवाओं को पारंपरिक बंधनों से बाहर नए रोजगार दिए हैं।

तुलना का आधार	पारंपरिक जाति व्यवस्था (Caste System)	आधुनिक वर्ग व्यवस्था (Class System)	संवैधानिक एवं समाजशास्त्रीय संदर्भ
परिवार की संरचना से संबंध	कृषि अर्थव्यवस्था और पितृसत्तात्मक प्राधिकार पर आधारित **बहु-पीढ़ीगत संयुक्त परिवार** (साझा रसोई, साझा संपत्ति और साझा पूजा)।	औद्योगीकरण, प्रवासन और व्यक्तिवाद से प्रेरित **नाभिकीय/एकल परिवार** (पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे), किंतु भावनात्मक रूप से 'कार्यात्मक संयुक्तता' कायम।	समाजशास्त्री आई.पी. देसाई और के.एम. कपाड़िया ने सिद्ध किया कि भारत में आवास भले ही एकल हुए हों, परंतु पारिवारिक दायित्वों में संयुक्तता की भावना जीवित है।

3. *'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स* (Did You Know? Box)

क्या आप जानते हैं? (रोचक समाजशास्त्रीय एवं संवैधानिक तथ्य)

1. शब्द **'कास्ट' (Caste)** मूल रूप से भारतीय शब्द नहीं है! यह पुर्तगाली और स्पेनिश शब्द **'कास्टा' (Casta)** से निकला है जिसका अर्थ 'नस्ल, प्रजाति या शुद्ध वंश' होता है; भारत में इसके लिए दो अलग-अलग संस्कृत संकल्पनाएं थीं — **'वर्ण'** (अखिल भारतीय सैद्धांतिक चतुर्वर्ण मॉडल) और **'जाति'** (जन्म आधारित क्षेत्रीय व व्यावहारिक इकाई) (NCERT पाठ्यपुस्तक पोर्टल)।

2. प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री **एम.एन. श्रीनिवास** ने 1952 में मैसूर के 'रामपुरा' गांव के क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर **'संस्कृतिकरण' (Sanskritization)** की अवधारणा दी, जिसके अनुसार कोई निम्न या मध्य हिंदू जाति या जनजाति उच्च (द्विज) जातियों के रीति-रिवाजों, कर्मकांडों और शाकाहार को अपनाकर एक-दो पीढ़ियों में स्थानीय जाति संस्करण में ऊपर उठने का दावा करती है।

3. भारतीय समाज में संयुक्त परिवार के उत्तराधिकार के दो प्राचीन कानूनी संप्रदाय रहे हैं: **'मिताक्षरा'** (विज्ञानेश्वर द्वारा रचित — जिसमें पुत्र को जन्म लेते ही पैतृक संपत्ति में सह-दायिकी अधिकार मिलता था; यह बंगाल व असम को छोड़कर पूरे भारत में प्रचलित था) और **'दायभाग'** (जीमूतवाहन द्वारा रचित — जिसमें पिता की मृत्यु के बाद ही संपत्ति पर अधिकार मिलता था; बंगाल व असम में प्रचलित)। **हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005** द्वारा अब बेटियों को भी बेटों के समान जन्म से ही पैतृक संपत्ति में बराबर का सह-दायिकी (Coparcenary) अधिकार दे दिया गया है (विधायी विभाग — भारत का संविधान)।

4. *'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स* (Exam Trap Alert Box)

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert — सावधानी से पढ़ें!)

• **जाल 1 (अस्पृश्यता की संविधान में परिभाषा):** प्रतियोगी परीक्षाओं में यह कथन दिया जाता है कि "भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में 'अस्पृश्यता' (Untouchability) शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।" सावधान! यह कथन **गलत** है। **अनुच्छेद 17** अस्पृश्यता का अंत करता है, किंतु संविधान में कहीं भी और न ही 'सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955' में 'अस्पृश्यता' शब्द की कोई शाब्दिक परिभाषा दी गई है।

• **जाल 2 ('मेल्टिंग पॉट' बनाम 'सलाद बाउल' मॉडल):** पश्चिमी देशों (विशेषकर अमेरिका) के सांस्कृतिक आत्मसात के मॉडल को अक्सर **'मेल्टिंग पॉट' (Melting Pot)** कहा जाता है जहां विभिन्न संस्कृतियां पिघलकर एक समरूप पहचान बनाती हैं; इसके विपरीत भारतीय समाज **'सलाद बाउल' (Salad Bowl) या 'मोजैक' मॉडल** का उदाहरण है, जहां विभिन्न भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हुए राष्ट्रीय एकता का निर्माण करती हैं (IUC Academy लर्निंग पाथ)।

• **जाल 3 (संस्कृतिकरण बनाम पश्चिमीकरण):** एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार 'संस्कृतिकरण' एक **आंतरिक या अंतर्जात (Endogenous)** प्रक्रिया है जो जाति व्यवस्था के भीतर ही स्थिति सुधारने का प्रयास करती है, जबकि 'पश्चिमीकरण' ब्रिटिश शासन के 150 वर्षों के संपर्क से उत्पन्न **बाह्य (Exogenous)** परिवर्तन है जिसने शिक्षा, कानून और मानवतावादी मूल्यों को बदला।

5. 'IUC *स्मृति ट्रिक*' (IUC Magic Memory Trick)

★ IUC स्मृति ट्रिक:

• **भारतीय समाजशास्त्र के 4 दिग्गज और उनकी अवधारणाएं याद रखने का सूत्र: "घु-6, श्री-सं-प्र, कर्वे-नाते, वाइजर-जजमान!"**

• **घु-6:** जी.एस. घुर्ये (भारतीय समाजशास्त्र के जनक) = जाति की 6 विशेषताएं (*Caste and Race in India*)

• **श्री-सं-प्र:** एम.एन. श्रीनिवास = **सं**स्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और **प्र**भु जाति (Dominant Caste)

• **कर्वे-नाते:** इरावती कर्वे = भारत में **नाते**दारी संगठन (*Kinship Organization in India*)

• **वाइजर-जजमान:** विलियम वाइजर = ग्रामीण **जजमानी** व्यवस्था का प्रथम व्यवस्थित अध्ययन

मॉड्यूल 2: भारत में महिला सशक्तिकरण, महिला संगठन एवं लैंगिक न्याय

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 2: भारत में महिला सशक्तिकरण, महिला संगठन एवं लैंगिक न्याय

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स (Did You Know? Box)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स (Exam Trap Alert Box)

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)

चरण 1 | चरण 2 | चरण 3 | चरण 4

नोड 1: 19वीं-20वीं शताब्दी के समाज सुधारक एवं संवैधानिक प्रावधान — महिला संगठन | - राजा राममोहन राय (सती प्रथा उन्मूलन, 1829) और ईश्वरचंद्र विद्यासागर (विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856) (प्रथम बालिका विद्यालय, पुणे 1848) — रमाबाई रानाडे) और भारत स्त्री महामंडल (1910) चौधरानी)। | - वूमेन्स इंडियन एसोसिएशन (1917) नेशनल काउंसिल ऑफ वूमेन (1925) और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस (1927 — मार्गरेट कजिन्स)।

नोड 2: संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान | - अनुच्छेद 14 (समानता), 15(1) (लिंग-आधारित भेदभाव का निषेध), 15(3) (महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान), 39(a) (पुरुष और महिला को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन), 39(d) (समान कार्य के लिए समान वेतन), 42 (प्रसूति सहायता), 51A(e) (महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग) | - दहेज निषेध अधिनियम, 1961 | - घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH Act)।

नोड 3: संसदीय एवं विधायी विकास — पंचायतों से 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' तक | - 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण। | - 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण। | - संविधान में नए अनुच्छेद 330A (लोकसभा), 332A (विधानसभा) और 239AA (दिल्ली विधानसभा) का समावेश।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण से संबंधित प्रमुख अधिनियम एवं संवैधानिक प्रावधान

अधिनियम / संवैधानिक प्रावधान	वर्ष / अनुच्छेद	मुख्य उद्देश्य एवं विधिक प्रावधान	प्रशासनिक एवं सामाजिक प्रभाव (विधायी विभाग)
विशेष प्रावधान एवं प्रसूति सहायता	अनुच्छेद 15(3), 39(d), 42 एवं 51A(e)	राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार (15(3)); समान कार्य के लिए समान वेतन (39(d)); प्रसूति सहायता (42) और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग (51A(e))।	मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत कामकाजी महिलाओं के सवेतन मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर **26 सप्ताह** किया गया।
दहेज निषेध अधिनियम एवं घरेलू हिंसा अधिनियम	1961 एवं 2005	दहेज लेना व देना दंडनीय अपराध (1961); **घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005** में शारीरिक के साथ-साथ भावनात्मक, मौखिक और आर्थिक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया गया।	पीड़ित महिला को साझा घर में निवास का अधिकार (Right to Residence), संरक्षण अधिकारी की सहायता और भरण-पोषण का त्वरित आदेश।
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम (POSH Act)	2013 (विशाखा दिशा-निर्देश 1997 पर आधारित)	10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक सरकारी व निजी संस्थान में **'आंतरिक शिकायत समिति' (ICC)** और जिला स्तर पर 'स्थानीय शिकायत समिति' (LCC) का गठन अनिवार्य।	संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों (घरेलू कामगारों सहित) की महिलाओं को सुरक्षित और गरिमापूर्ण कार्य वातावरण की गारंटी।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम एवं PC-PNDT अधिनियम	2006 एवं 1994	गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PC-PNDT) अधिनियम, 1994 द्वारा भ्रूण के लिंग परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध; बाल विवाह की रोकथाम (2006)।	कन्या भ्रूण हत्या पर रोक और नीति आयोग के SDG-5 (लैंगिक समानता) लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक।
106वां संविधान संशोधन अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम)	2023 (128वां संशोधन विधेयक)	लोकसभा (**अनुच्छेद 330A**), राज्य विधानसभाओं (**अनुच्छेद 332A**) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा (**अनुच्छेद 239AA**) में महिलाओं के लिए कुल सीटों का **एक-तिहाई (33%) आरक्षण**।	यह आरक्षण इसके लागू होने के बाद होने वाली पहली जनगणना और उसके आधार पर होने वाले परिसीमन (Delimitation) के पश्चात प्रभावी होगा (प्रारंभिक अवधि 15 वर्ष, चक्रानुक्रम में)।

3. 'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स (Did You Know? Box)

क्या आप जानते हैं? (रोचक ऐतिहासिक एवं विधिक तथ्य)

1. वर्ष 1910 में इलाहाबाद में **सरला देवी चौधरानी** द्वारा स्थापित **'भारत स्त्री महामंडल'** को किसी भारतीय महिला द्वारा स्थापित पहला अखिल भारतीय महिला संगठन माना जाता है (NCERT पाठ्यपुस्तक पोर्टल); इससे पहले 1882 में **पंडिता रमाबाई** ने पुणे में महिलाओं की शिक्षा और विधवाओं के उत्थान के लिए **'आर्य महिला समाज'** की स्थापना की थी।

2. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने **'विशाखा बनाम राजस्थान राज्य' (1997)** के ऐतिहासिक फैसले में जो 'विशाखा गाइडलाइंस' जारी की थीं, वे राजस्थान की एक जमीनी सामाजिक कार्यकर्ता **भंवरी देवी** के साहसिक संघर्ष (बाल विवाह रोकने के दौरान हुए हमले के विरुद्ध न्याय की लड़ाई) का परिणाम थीं, जिसने 16 वर्ष बाद **POSH अधिनियम, 2013** का रूप लिया।

3. **राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)** एक संवैधानिक निकाय नहीं, बल्कि **राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990** के तहत **जनवरी 1992** में गठित एक **सांविधिक निकाय (Statutory Body)** है, जिसकी प्रथम अध्यक्षा **जयंती पटनायक** थीं।

4. 'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स (Exam Trap Alert Box)

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert — सावधानी से पढ़ें!)

• **जाल 1 (106वें संविधान संशोधन में राज्यसभा और विधान परिषद का जाल!):** परीक्षा में सबसे खतरनाक जाल यह पूछा जाता है कि "106वें संविधान संशोधन अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023) के तहत संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है।" यह कथन **गलत** है! यह आरक्षण केवल **लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा** में है; **राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों (उच्च सदनों) में महिलाओं के लिए यह आरक्षण लागू नहीं है** (विधायी विभाग — भारत का संविधान)।

• **जाल 2 (SC/ST महिलाओं का कोटा अलग से या कोटे के भीतर?):** 106वें संशोधन के तहत अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण अलग से नहीं, बल्कि अनुच्छेद 330 और 332 के तहत **SC/ST के लिए पहले से आरक्षित सीटों के भीतर ही (Quota within Quota)** प्रदान किया गया है।

• **जाल 3 (मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 में दो से अधिक बच्चों का नियम):** मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत प्रथम दो जीवित बच्चों के लिए **26 सप्ताह** का सवेतन मातृत्व अवकाश मिलता है, किंतु **दो या अधिक जीवित बच्चे होने की स्थिति में तीसरे बच्चे के लिए यह अवकाश 26 सप्ताह नहीं, बल्कि 12 सप्ताह** होता है (तथा बच्चे को गोद लेने वाली या कमीशनिंग माताओं के लिए भी 12 सप्ताह का अवकाश है) (IUC Academy लर्निंग पाथ)।

5. 'IUC स्मृति ट्रिक' (IUC Magic Memory Trick)

★ IUC स्मृति ट्रिक:

• **स्वतंत्रता-पूर्व के 3 बड़े महिला संगठन याद करने का सूत्र: "W-N-A = 17-25-27 (एनी-मेहरबाई-मार्गरेट)"**

• **W (1917):** Women's Indian Association (वूमेन्स इंडियन एसोसिएशन, मद्रास) — एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स, सरोजिनी नायडू

• **N (1925):** National Council of Women in India (नेशनल काउंसिल ऑफ वूमेन) — लेडी मेहरबाई टाटा

• **A (1927):** All India Women's Conference (अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, पुणे) — मार्गरेट कजिन्स (प्रथम अध्यक्षा: महारानी चिमनाबाई गायकवाड़)

• **नारी शक्ति वंदन (106वां संशोधन, 2023) के 4 नए अनुच्छेद: "239AA (दिल्ली) + 330A (लोकसभा) + 332A (विधानसभा) + 334A (15 वर्ष व परिसीमन शर्त)"**

मॉड्यूल 3: जनसंख्या, जनसांख्यिकीय लाभांश, प्रवासन एवं शहरीकरण की समस्याएं व समाधान

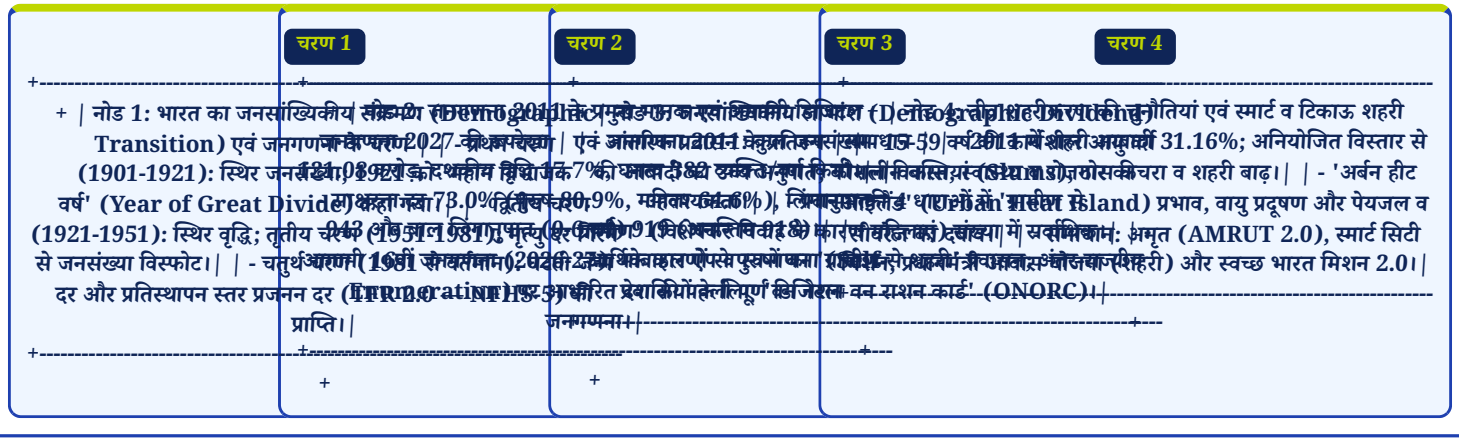
अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 3: जनसंख्या, जनसांख्यिकीय लाभांश, प्रवासन एवं शहरीकरण की समस्याएं व समाधान

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स (Did You Know? Box)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स (Exam Trap Alert Box)

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)



2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: भारत की जनगणना 2011 के शीर्ष एवं न्यूनतम राज्य तथा शहरीकरण व प्रवासन के आयाम

जनसांख्यिकीय मानक (जनगणना सारणी पोर्टल)	राष्ट्रीय औसत (जनगणना 2011)	शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य / केंद्रशासित प्रदेश	न्यूनतम स्तर वाले राज्य / नीतिगत फोकस क्षेत्र
कुल जनसंख्या एवं दशकीय वृद्धि (2001–2011)	**121.08 करोड़** (विश्व की जनसंख्या का 17.5%); दशकीय वृद्धि दर **17.7%** (वार्षिक 1.64%)	सर्वाधिक जनसंख्या: **उत्तर प्रदेश** (19.98 करोड़), महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल।	न्यूनतम जनसंख्या (राज्य): **सिक्किम**; एकमात्र ऋणात्मक दशकीय वृद्धि वाला राज्य: **नागालैंड (-0.6%)**, न्यूनतम धनात्मक वृद्धि: केरल (4.9%)।
जनसंख्या घनत्व (Population Density)	**382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी** (2001 में 325 था — 57 अंकों की वृद्धि)	राज्यों में सर्वाधिक: **बिहार (1,106 व्यक्ति/वर्ग किमी)**, पश्चिम बंगाल (1,028), केरल (860); केंद्रशासित प्रदेशों में: दिल्ली (11,320)।	न्यूनतम जनसंख्या घनत्व: **अरुणाचल प्रदेश (17 व्यक्ति/वर्ग किमी)**, मिजोरम (52); केंद्रशासित प्रदेशों में: अंडमान व निकोबार (46)।
लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष)	कुल लिंगानुपात: **943** (प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं); बाल लिंगानुपात: **919** (प्रोविजनल डेटा में 918)	सर्वाधिक लिंगानुपात (राज्य): **केरल (1,084)**, तमिलनाडु (996), आंध्र प्रदेश (993); केंद्रशासित प्रदेश: पुडुचेरी (1,037); बाल लिंगानुपात में शीर्ष: अरुणाचल प्रदेश (972)।	न्यूनतम लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात (राज्य): **हरियाणा** (कुल 879, बाल लिंगानुपात 834); केंद्रशासित प्रदेश: दमन और दीव (618)।
साक्षरता दर (7 वर्ष एवं अधिक आयु)	**73.0%** (पुरुष साक्षरता: **80.9%**, महिला साक्षरता: **64.6%**; लैंगिक अंतराल: 16.3%)	सर्वाधिक साक्षरता: **केरल (94.0%)**, लक्षद्वीप (91.8%), मिजोरम (91.3%), गोवा (88.7%)।	न्यूनतम कुल एवं महिला साक्षरता: **बिहार** (कुल 61.8%, महिला 51.5%); सर्वाधिक पुरुष-महिला साक्षरता अंतराल: राजस्थान।
शहरीकरण का स्तर (Urbanization)	**31.16% शहरी** (37.71 करोड़) एवं **68.84% ग्रामीण** (83.37 करोड़)	प्रतिशत में सर्वाधिक शहरीकृत राज्य: **गोवा (62.17%)**, मिजोरम (52.11%), तमिलनाडु (48.40%); कुल शहरी जनसंख्या में प्रथम: **महाराष्ट्र (5.08 करोड़)**।	प्रतिशत में न्यूनतम शहरीकृत (सर्वाधिक ग्रामीण) राज्य: **हिमाचल प्रदेश (10.03% शहरी, 89.97% ग्रामीण)**, इसके बाद बिहार (11.29% शहरी)।

3. 'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स (Did You Know? Box)

क्या आप जानते हैं? (रोचक जनसांख्यिकीय एवं संवैधानिक तथ्य)

1. वर्ष **1921** को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में **'महान विभाजक वर्ष' (Year of Great Divide)** इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1911–1921 का दशक भारतीय जनगणना के इतिहास का **एकमात्र ऐसा दशक** था जब अकाल और 1918 के इन्फ्लुएंजा महामारी के कारण भारत की कुल जनसंख्या बढ़ने के बजाय **-0.31% (लगभग 77 लाख) घट गई थी**; 1921 के बाद से भारत की जनसंख्या निरंतर बढ़ी है (NCERT पाठ्यपुस्तक पोर्टल)।

2. संवैधानिक रूप से **'जनगणना' (Census)** भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत **सातवीं अनुसूची की संघ सूची (Union List) की प्रविष्टि संख्या 69** का विषय है। इसे गृह मंत्रालय के अधीन 'भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय' द्वारा **जनगणना अधिनियम, 1948** के तहत संपन्न कराया जाता है (भारत की जनगणना सारणी पोर्टल)।

3. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5, 2019–21) के अनुसार भारत की **कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate - TFR)** घटकर **2.0** पर आ गई है, जो जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए आवश्यक **प्रतिस्थापन स्तर (Replacement Level — 2.1)** से भी नीचे है!

4. 'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स (Exam Trap Alert Box)

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert — सावधानी से पढ़ें!)

- **जाल 1 (1872 बनाम 1881 की जनगणना):** भारत में पहली जनगणना **1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो** के कार्यकाल में हुई थी (असमक्रमिक), जबकि भारत में **पहली समक्रमिक/नियमित दशकीय जनगणना (First Synchronous Census) 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन** के समय डब्ल्यू.सी. प्लोडेन (प्रथम जनगणना आयुक्त) के अधीन हुई। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 (आयुक्त: आर.ए. गोपालास्वामी) में हुई थी।
- **जाल 2 (सर्वाधिक शहरीकृत राज्य — प्रतिशत बनाम कुल संख्या):** यदि परीक्षा में पूछा जाए कि "प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक शहरीकृत बड़ा राज्य कौन-सा है?", तो उत्तर **गोवा (62.17%)** और बड़े राज्यों में **तमिलनाडु (48.4%)** है; परंतु यदि पूछा जाए कि "कुल शहरी जनसंख्या (निरपेक्ष संख्या) किस राज्य में सर्वाधिक है?", तो उत्तर **महाराष्ट्र (5.08 करोड़, इसके बाद उत्तर प्रदेश 4.44 करोड़)** है!
- **जाल 3 (अर्ध-शहरीकरण / Pseudo-Urbanization एवं Census Towns):** 2011 की जनगणना में शहरी जनसंख्या बढ़ने का एक बड़ा कारण **'जनगणना नगरों' (Census Towns)** की संख्या का 1,362 से बढ़कर 3,894 होना था। जनगणना नगर होने की **3 शर्तें** याद रखें: (1) न्यूनतम जनसंख्या **5,000**, (2) पुरुष मुख्य कार्यशील आबादी का कम से कम 75% **गैर-कृषि कार्यों** में संलग्न हो, और (3) जनसंख्या घनत्व कम से कम **400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी** हो (IUC Academy लर्निंग पाथ)।

5. 'IUC स्मृति ट्रिक' (IUC Magic Memory Trick)

★ IUC स्मृति ट्रिक:

- **जनगणना का इतिहास याद रखने का सूत्र: "72 में मेयो ने शुरू किया, 81 में रिपन ने नियमित किया, 21 ने महान विभाजन किया!"**
- **जनगणना नगर (Census Town) की 3 शर्तें: "5 हजार लोग, 75% गैर-कृषि, 400 का घनत्व!" (5000 - 75% - 400)**
- **राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 (NPP 2000):** जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य मूल रूप से वर्ष 2045 रखा गया था, जिसे बाद में संशोधित कर **2070** किया गया।

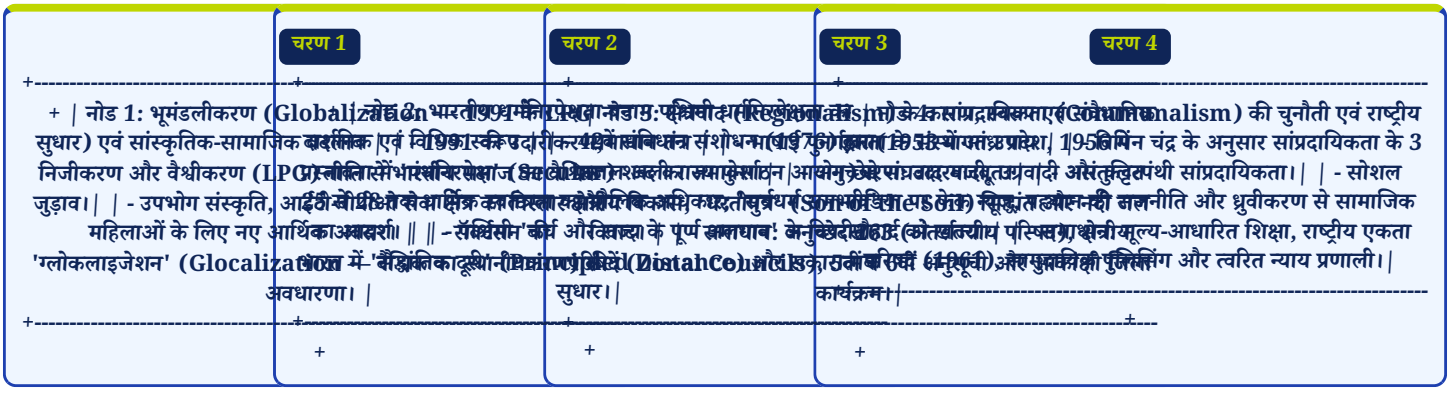
मॉड्यूल 4: भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, धर्मनिरपेक्षता, क्षेत्रवाद एवं सांप्रदायिकता

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 4: भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, धर्मनिरपेक्षता, क्षेत्रवाद एवं सांप्रदायिकता

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स (Did You Know? Box)	'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स (Exam Trap Alert Box)

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)



2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल बनाम भारतीय संवैधानिक मॉडल

तुलना का आधार	पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता मॉडल (फ्रांस / अमेरिका)	भारतीय धर्मनिरपेक्षता मॉडल (भारत का संविधान)	संवैधानिक एवं न्यायिक विश्लेषण (NCERT)
राज्य और धर्म का संबंध	राज्य और धर्म (चर्च) के बीच **कठोर और पूर्ण अलगाव (Mutual Exclusion)**; धर्म पूर्णतः निजी मामला है और राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करता।	**'सर्वधर्म समभाव'** और **'सैद्धांतिक दूरी' (Principled Distance):** राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है, किंतु वह सभी धर्मों का समान सम्मान करता है।	एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) के ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथनिरपेक्षता को संविधान के **'मूल ढांचे' (Basic Structure)** का अभिन्न अंग घोषित किया।
सामाजिक एवं धार्मिक सुधार में राज्य की भूमिका	राज्य किसी भी धर्म के आंतरिक मामलों या प्रथाओं में सुधार के लिए कानून बनाने से बचता है (नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता)।	संविधान का **अनुच्छेद 25(2)(b)** राज्य को सामाजिक कल्याण और सुधार (जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन, दलितों व महिलाओं के लिए मंदिर प्रवेश, तीन तलाक निषेध) के लिए हस्तक्षेप करने की सकारात्मक शक्ति देता है।	राजीव भार्गव के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल राज्य को धर्म से अलग नहीं रखती, बल्कि धर्म के भीतर व्याप्त पितृसत्ता और जातिगत पदानुक्रम से नागरिकों की रक्षा भी करती है।
अल्पसंख्यक एवं सामुदायिक अधिकार	मुख्यतः व्यक्ति-केंद्रित अधिकार; किसी धार्मिक समुदाय द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों को सरकारी सहायता नहीं दी जाती।	व्यक्ति की अंतःकरण की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25) के साथ-साथ **अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद 29 एवं 30)** भी सुरक्षित हैं।	राज्य धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों को बिना भेदभाव के वित्तीय अनुदान प्रदान करता है (अनुच्छेद 30(2))।
सार्वजनिक जीवन में धार्मिक प्रतीक	फ्रांस के 'लाइसिटे' (*Laïcité*) मॉडल में सरकारी स्कूलों और सार्वजनिक दफ्तरों में किसी भी धार्मिक प्रतीक (जैसे पगड़ी, क्रॉस, हिजाब) के प्रदर्शन पर कठोर प्रतिबंध है।	सार्वजनिक जीवन में सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता की अभिव्यक्ति को सम्मान दिया जाता है (जैसे अनुच्छेद 25 के स्पष्टीकरण I में सिखों को कृपाण धारण करने का संवैधानिक अधिकार)।	भारत में प्रमुख सभी धर्मों के त्योहारों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाते हैं, जो सभी संस्कृतियों के प्रति समान राजकीय आदर का प्रतीक है।

3. 'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स (Did You Know? Box)

क्या आप जानते हैं? (रोचक समाजशास्त्रीय एवं प्रशासनिक तथ्य)

1. भूमंडलीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को समझाने के लिए समाजशास्त्री **रोलैंड रॉबर्टसन** ने **'ग्लोकलाइजेशन' (Glocalization = Global + Local)** शब्द दिया; भारत में इसका सबसे सुंदर उदाहरण यह है कि कैसे वैश्विक बहुराष्ट्रीय फूड चेन (जैसे मैकडॉनल्ड्स या पिज्जा हट) ने भारत में सफल होने के लिए अपने मूल मेनू को बदलकर 'मैकआलू टिक्की', 'पनीर रैप' और नवरात्रि के दौरान 'शुद्ध शाकाहारी व्रत मेनू' शुरू किया (NCERT पाठ्यपुस्तक पोर्टल)!
2. क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए गठित **5 क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils — उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी)** संवैधानिक निकाय नहीं हैं, बल्कि इन्हें **राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956** के भाग III के तहत स्थापित किया गया है और इन सभी का पदेन अध्यक्ष **केंद्रीय गृह मंत्री** होता है (जबकि 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 'पूर्वोत्तर परिषद' का गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 के तहत किया गया)।
3. समाजशास्त्री **जॉर्ज रित्जर (George Ritzer)** ने वैश्वीकरण के कारण दुनिया भर में फास्ट-फूड रेस्तरां की तरह दक्षता, गणनाशीलता और एकरूपता के फैलने की प्रक्रिया को **'मैकडोनाल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी' (McDonaldization of Society)** नाम दिया है।

4. 'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स (Exam Trap Alert Box)

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert — सावधानी से पढ़ें!)

• **जाल 1 (अंतर्राज्यीय परिषद बनाम क्षेत्रीय परिषद):** परीक्षा में इन दोनों परिषदों के संवैधानिक दर्जे और अध्यक्ष में भारी भ्रम होता है:

• **अंतर्राज्यीय परिषद (Inter-State Council):** यह **अनुच्छेद 263** के तहत एक **संवैधानिक निकाय** है (सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में गठित), और इसके अध्यक्ष **प्रधानमंत्री** होते हैं (विधायी विभाग — भारत का संविधान)।

• **क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils):** ये **राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956** के तहत **सांविधिक निकाय** हैं, और इनके अध्यक्ष **केंद्रीय गृह मंत्री** होते हैं!

• **जाल 2 (मूल संविधान में 'पंथनिरपेक्ष' शब्द):** यद्यपि 'पंथनिरपेक्ष' (Secular) शब्द प्रस्तावना में **42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976** द्वारा जोड़ा गया, किंतु मूल संविधान (1950) के **अनुच्छेद 25(2)(a)** में 'Secular' शब्द पहले से ही मौजूद था ("धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य **लौकिक**/**पंथनिरपेक्ष** क्रियाकलाप का विनियमन")।

• **जाल 3 (भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की समितियां):** 1948 के **एस.के. धर आयोग** और **जे.वी.पी. समिति** (जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, पट्टाभि सीतारमैया) ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता दी थी; बाद में पोट्टी श्रीरामुलु के अनशन व निधन के बाद 1953 में आंध्र राज्य बना और **फजल अली आयोग (1953, अन्य सदस्य: के.एम. पणिक्कर व हृदयनाथ कुंजरू)** ने 'एक भाषा-एक राज्य' के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए भाषा और राष्ट्रीय एकता दोनों के आधार पर 1956 में 14 राज्यों व 6 केंद्रशासित प्रदेशों के पुनर्गठन की सिफारिश की (IUC Academy लर्निंग पाथ)।

5. 'IUC स्मृति ट्रिक' (IUC Magic Memory Trick)

★ IUC स्मृति ट्रिक:

• **राज्य पुनर्गठन आयोगों का क्रम: "धर (1948) -> JVP (1948) -> फजल अली (1953/1956 = -P-K: फजल अली, पणिक्कर, कुंजरू)!"**

• **5 क्षेत्रीय परिषदों के मुख्यालय याद रखने का सूत्र: "उ-दि, म-प्र, पू-को, प-मु, द-चे!"**

• **उ-दि:** उत्तरी क्षेत्रीय परिषद = नई **दि**ल्ली

• **म-प्र:** मध्य क्षेत्रीय परिषद = **प्र**यागराज (इलाहाबाद)

• **पू-को:** पूर्वी क्षेत्रीय परिषद = **को**लकाता

• **प-मु:** पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद = **मु**ंबई

• **द-चे:** दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद = **चे**न्नई (और पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय = शिलांग)

मॉड्यूल 5: सामाजिक न्याय — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिक

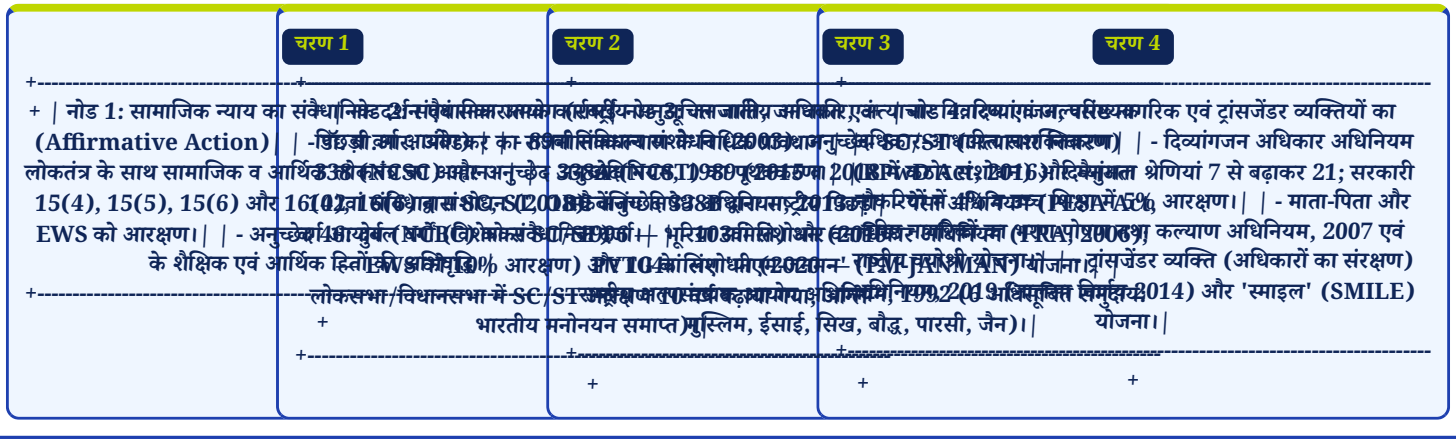
अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 5: सामाजिक न्याय — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिक

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स (Did You Know? Box)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स (Exam Trap Alert Box)

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)



2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु गठित प्रमुख राष्ट्रीय आयोगों एवं संवैधानिक संशोधनों का विश्लेषण

आयोग / अधिनियम का नाम	संवैधानिक अनुच्छेद / अधिनियम	संरचना एवं नियुक्ति प्राधिकारी	प्रमुख शक्तियां एवं परीक्षा-उपयोगी तथ्य (विधायी विभाग)
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)	**अनुच्छेद 338** (89वां संशोधन, 2003 द्वारा पुनर्गठित)	1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य; नियुक्ति **राष्ट्रपति** द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा।	किसी मामले की जांच करते समय इसे **सिविल न्यायालय (Civil Court)** की शक्तियां प्राप्त हैं; यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)	**अनुच्छेद 338A** (89वां संविधान संशोधन, 2003; वर्ष 2004 से प्रभावी)	1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त; कम से कम एक महिला सदस्य अनिवार्य)।	5वीं व 6वीं अनुसूची के क्षेत्रों में जनजातीय अधिकारों, वनाधिकार अधिनियम (2006) और खनिज व जल संसाधनों पर जनजातीय हितों का संरक्षण।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)	**अनुच्छेद 338B (102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2018)**	1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त)।	मूल रूप से इंद्रा साहनी वाद (1992) के बाद 1993 में सांविधिक निकाय बना था; 102वें संशोधन ने इसे संवैधानिक दर्जा दिया और **105वें संशोधन (2021)** ने राज्यों की अपनी OBC सूची बनाने की शक्ति बहाल की।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण	**103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 (अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6))**	सामान्य वर्ग के उन आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए जो SC, ST और OBC आरक्षण के दायरे में नहीं आते।	शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में **अधिकतम 10% आरक्षण**; जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) में सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी संवैधानिकता को 3:2 से वैध ठहराया।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD Act)	**2016** (1995 के अधिनियम का स्थान लिया; UNCRPD के अनुरूप)	दिव्यांगता के प्रकार 7 **से बढ़ाकर 21** किए गए (जिसमें एसिड अटैक पीड़ित, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, पार्किंसंस व बौनापन शामिल)।	'बेंचमार्क दिव्यांगता' (न्यूनतम 40% दिव्यांगता) वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में **4% आरक्षण** (पहले 3% था) और उच्च शिक्षण संस्थानों में **5% आरक्षण** तथा 'सुगम्य भारत अभियान'।

3. 'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स (Did You Know? Box)

क्या आप जानते हैं? (रोचक संवैधानिक एवं सामाजिक न्याय तथ्य)

1. भारत में कुल 75 **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups - PVTGs)** हैं जो 18 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) में निवास करते हैं। सबसे अधिक PVTG **ओडिशा (13 समूह)** में पाए जाते हैं। इन्हें ढेबर आयोग (1960–61) की सिफारिश पर 1973 में पहले 'आदिम जनजातीय समूह' (PTG) कहा गया और 2006 में इनका नाम बदलकर PVTG कर दिया गया। इनके समग्र विकास के लिए नवंबर 2023 में बिरसा मुंडा जयंती ('जनजातीय गौरव दिवस' — 15 नवंबर) पर ₹24,000 करोड़ का **'पीएम-जनमन' (PM-JANMAN)** अभियान शुरू किया गया (नीति आयोग)।
2. **'जैन' समुदाय** को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(c) के तहत मूल रूप से 1993 में जारी अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया था (उस समय केवल मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी शामिल थे); **जनवरी 2014** में केंद्र सरकार ने जैन समुदाय को छठे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में **'पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह' (अगस्त 2024)** के 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के ऐतिहासिक निर्णय (6:1 बहुमत) में(ई.वी. चिन्नाय्या 2004 के फैसले को पलटते हुए) यह व्यवस्था दी है कि राज्यों को अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के भीतर सबसे अधिक पिछड़े समूहों को आरक्षण का लाभ पहुंचाने के लिए **उप-वर्गीकरण (Sub-classification)** करने का संवैधानिक अधिकार है।

4. 'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स (Exam Trap Alert Box)

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert — सावधानी से पढ़ें!)

• **जाल 1 (101वां से 106वां संविधान संशोधन — सटीक मिलान):** हर परीक्षा में इनमें से कम से कम एक प्रश्न अवश्य आता है, इन्हें कभी गलत न करें (विधायी विभाग — भारत का संविधान):

• **101वां संशोधन (2016):** वस्तु एवं सेवा कर (GST — अनुच्छेद 246A, 269A, 279A)।

• **102वां संशोधन (2018):** राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा (अनुच्छेद 338B और 342A)।

• **103वां संशोधन (2019):** आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण (अनुच्छेद 15(6) और 16(6))।

• **104वां संशोधन (2020):** लोकसभा व विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण 2030 तक बढ़ाया गया और आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) समुदाय के मनोनयन (अनुच्छेद 331 व 333) को समाप्त किया गया।

• **105वां संशोधन (2021):** राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपनी स्वयं की सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC/OBC) की सूची तैयार करने की शक्ति बहाल की गई।

• **106वां संशोधन (2023):** लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण ('नारी शक्ति वंदन अधिनियम')।

• **जाल 2 (प्रथम बनाम द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग):** अनुच्छेद 340 के तहत **प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में काका कालेलकर** की अध्यक्षता में गठित हुआ था, जबकि **द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 में बी.पी. मंडल (मंडल आयोग)** की अध्यक्षता में गठित हुआ जिसने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी और 1990 में OBC के लिए 27% आरक्षण लागू हुआ (इंद्रा साहनी वाद, 1992 में 'क्रीमी लेयर' के सिद्धांत के साथ वैध ठहराया गया) (IUC Academy लर्निंग पाथ)।

5. 'IUC स्मृति ट्रिक' (IUC Magic Memory Trick)

★ IUC स्मृति ट्रिक:

• **101 से 106 संविधान संशोधन याद करने का सूत्र: "101 में टैक्स (GST), 102 में पिछड़ा आयोग (NCBC), 103 में 10% गरीब (EWS), 104 में एंग्लो बाहर, 105 में राज्य की OBC लिस्ट, 106 में नारी शक्ति वंदन!"**

• **अनुच्छेद 338 परिवार: "338 = SC, 338A = ST (A फॉर आदिवासी/Tribal), 338B = Backward (B फॉर Backward/OBC)!"**

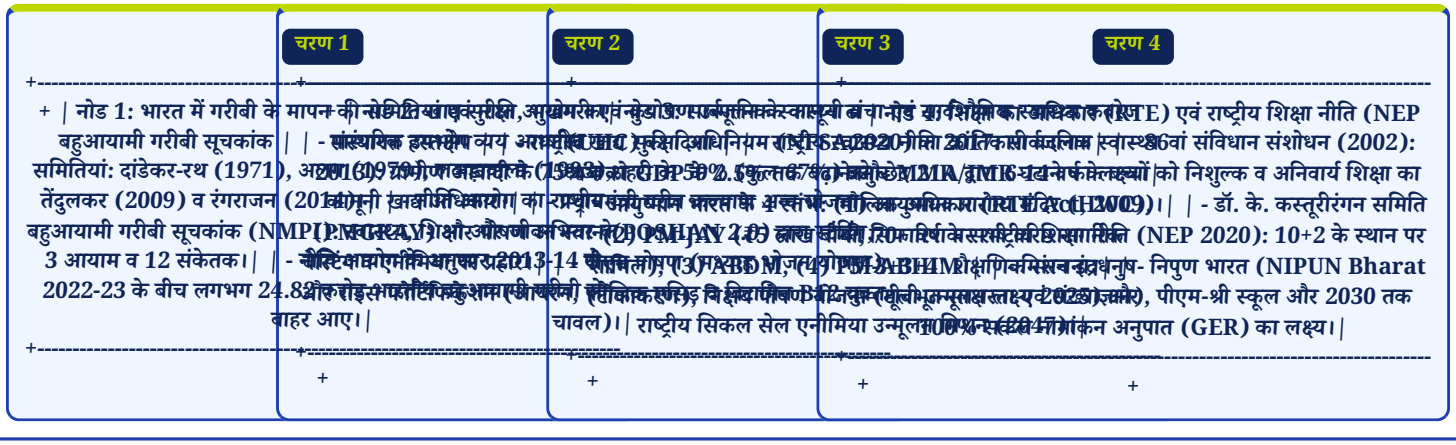
मॉड्यूल 6: गरीबी, भुखमरी, कुपोषण एवं मानव विकास (शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के हस्तक्षेप)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 6: गरीबी, भुखमरी, कुपोषण एवं मानव विकास (शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के हस्तक्षेप)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स (Did You Know? Box)	'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स (Exam Trap Alert Box)

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)



2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: गरीबी मापन की पारंपरिक विधि बनाम नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (NMPI)

तुलना का आधार	पारंपरिक गरीबी रेखा विधि (अलग, तेंदुलकर एवं रंगराजन समिति)	राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (NMPI — नीति आयोग)	नीतिगत एवं विकासात्मक महत्व
मापन का मूल आधार	**एक-आयामी (Uni-dimensional):** केवल प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय (Monthly Per Capita Consumption Expenditure - MPCE) और न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता पर आधारित।	**बहुआयामी (Multidimensional):** ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) व UNDP की अल्कायर-फॉस्टर पद्धति पर आधारित गैर-मौद्रिक वंचनों का प्रत्यक्ष मापन।	अमर्त्य सेन के 'क्षमता दृष्टिकोण' (Capability Approach) के अनुरूप गरीबी को केवल आय की कमी नहीं, बल्कि बुनियादी क्षमताओं से वंचन के रूप में देखा जाता है।
प्रमुख आयाम एवं संकेतक	**अलग समिति (1979):** ग्रामीण 2400 कैलोरी, शहरी 2100 कैलोरी; **तेंदुलकर समिति (2009):** शिक्षा व स्वास्थ्य व्यय को जोड़ा; **रंगराजन समिति (2014):** प्रोटीन व वसा मानक जोड़े।	**3 समान भारित आयाम (1/3 प्रत्येक) और 12 संकेतक:** (1) **स्वास्थ्य** (पोषण, बाल व किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य — प्रसवपूर्व देखभाल), (2) **शिक्षा** (स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति), (3) **जीवन स्तर** (रसोई ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, परिसंपत्तियां, बैंक खाता)।	वैश्विक MPI में केवल 10 संकेतक होते हैं; नीति आयोग ने भारत की प्राथमिकताओं के अनुरूप इसमें **2 अतिरिक्त संकेतक — 'मातृ स्वास्थ्य' और 'बैंक खाता' (जन-धन)** जोड़े हैं!
डेटा स्रोत एवं गणना	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) के आंकड़े।	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-4 एवं NFHS-5) के जिला-स्तरीय आंकड़े; यदि किसी परिवार का वंचन स्कोर 33.33% या अधिक है तो उसे बहुआयामी गरीब माना जाता है।	यह सूचकांक राज्य और जिला स्तर पर यह सटीक जानकारी देता है कि किस जिले में पोषण, स्वच्छता या स्कूल उपस्थिति में से किस क्षेत्र में तुरंत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
सतत विकास लक्ष्य (SDG) से जुड़ाव	केवल आय-आधारित गरीबी (SDG 1.1) से आंशिक रूप से संबंधित।	संयुक्त राष्ट्र के **सतत विकास लक्ष्य 1.2 (SDG 1.2)** — "2030 तक सभी आयामों में गरीबी में रहने वाले पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के अनुपात को कम से कम आधा करना" — की सीधी निगरानी करता है।	नीति आयोग के चर्चा पत्र (2024) के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में **11.28%** रह गई है (उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे तेज गिरावट)।

3. 'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स (Did You Know? Box)

क्या आप जानते हैं? (रोचक नीतिगत एवं विकासात्मक तथ्य)

1. भारत में स्वतंत्रता से पूर्व गरीबी रेखा का सबसे पहला वैज्ञानिक आकलन **दादाभाई नौरोजी** ने 1867–68 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया' (*Poverty and Un-British Rule in India*) में 'जेल की जीवन लागत' (Prison Cost of Living) के आधार पर प्रति व्यक्ति ₹16 से ₹35 वार्षिक निर्धारित करके किया था (NCERT पाठ्यपुस्तक पोर्टल)।

2. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020)** ने 34 वर्षों बाद (1986 की शिक्षा नीति के स्थान पर) भारत के शैक्षणिक ढांचे को बदल दिया है और साथ ही **'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' (MHRD)** का नाम पुनः बदलकर **'शिक्षा मंत्रालय' (Ministry of Education)** कर दिया गया है तथा शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के **6%** तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

3. वर्ष 2024 में केंद्र सरकार ने **आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)** का ऐतिहासिक विस्तार करते हुए **70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों** (चाहे उनकी आय या सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो) को प्रति वर्ष **₹5 लाख तक के निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज** ('आयुष्मान वय वंदना कार्ड') के दायरे में शामिल कर लिया है।

4. 'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स (Exam Trap Alert Box)

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert — सावधानी से पढ़ें!)

• **जाल 1 (वैश्विक MPI के 10 संकेतक बनाम नीति आयोग के NMPI के 12 संकेतक):** यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में यह प्रश्न बार-बार फंसाता है! UNDP और OPHI द्वारा जारी **वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 3 आयाम और 10 संकेतक** होते हैं, जबकि नीति आयोग द्वारा जारी **राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (NMPI) में 3 आयाम और 12 संकेतक** हैं (2 नए भारतीय संकेतक: स्वास्थ्य आयाम में **'मातृ स्वास्थ्य/प्रसवपूर्व देखभाल'** और जीवन स्तर आयाम में **'बैंक खाता'**)।

• **जाल 2 (स्टंटिंग बनाम वेस्टिंग बनाम अंडरवेट में अंतर):** कुपोषण के इन तीनों मानकों (जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स और पोषण ट्रैकर में प्रयुक्त होते हैं) में कभी भ्रमित न हों:

• **स्टंटिंग (Stunting — ठिगनापन): आयु के अनुपात में कम लंबाई** (Low height-for-age) — यह दीर्घकालिक या जीर्ण कुपोषण (Chronic Malnutrition) को दर्शाता है।

• **वेस्टिंग (Wasting — दुबलापन): लंबाई के अनुपात में कम वजन** (Low weight-for-height) — यह तीव्र या तात्कालिक कुपोषण (Acute Malnutrition) को दर्शाता है।

• **अंडरवेट (Underweight — कम वजन): आयु के अनुपात में कम वजन** (Low weight-for-age) — यह स्टंटिंग और वेस्टिंग दोनों का संयुक्त प्रतिबिंब है।

• **जाल 3 (86वें संविधान संशोधन ने संविधान के किन 3 भागों में बदलाव किया?): 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002** एकमात्र ऐसा प्रमुख संशोधन है जिसने एक साथ **मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21A — 6 से 14 वर्ष), नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 45 की भाषा बदली — 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा)** और **मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A(k) — 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा)** तीनों में परिवर्तन किया (विधायी विभाग — भारत का संविधान)।

5. 'IUC स्मृति ट्रिक' (IUC Magic Memory Trick)

★ IUC स्मृति ट्रिक:

• **गरीबी मापन समितियों का कालानुक्रम: "दां-अ-ल-तें-रं (Da-A-La-Te-Ra = 71-79-93-2009-2014)!"**

• **दां (1971):** दांडेकर एवं रथ समिति

• **अ (1979):** वाई.के. अलग समिति (कैलोरी आधार: 2400 ग्रामीण / 2100 शहरी)

• **ल (1993):** डी.टी. लकड़ावाला समिति (राज्य-विशिष्ट गरीबी रेखाएं)

• **तें (2009):** सुरेश तेंदुलकर समिति (कैलोरी से हटकर शिक्षा-स्वास्थ्य सहित उपभोग टोकरी)

• **रं (2014):** सी. रंगराजन समिति

• **NEP 2020 का '5+3+3+4' फॉर्मूला:**

• **5 वर्ष (Foundational — 3 से 8 वर्ष):** 3 वर्ष आंगनवाड़ी/प्री-स्कूल + कक्षा 1 और 2

• **3 वर्ष (Preparatory — 8 से 11 वर्ष):** कक्षा 3 से 5

• **3 वर्ष (Middle — 11 से 14 वर्ष):** कक्षा 6 से 8 (व्यावसायिक कौशल और कोडिंग की शुरुआत)

• **4 वर्ष (Secondary — 14 से 18 वर्ष):** कक्षा 9 से 12 (बहु-विषयक अध्ययन, स्ट्रीम का कठोर विभाजन समाप्त)

मॉड्यूल 7: अभिशासन (Governance), सुशासन (Good Governance), पारदर्शिता, RTI एवं सिटीजन चार्टर

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 7: अभिशासन (Governance), सुशासन (Good Governance), पारदर्शिता, RTI एवं सिटीजन चार्टर

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स (Did You Know? Box)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स (Exam Trap Alert Box)

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)

चरण 1 चरण 2 चरण 3 चरण 4

+---------- +---------- +---------- +----------

+ | नोड 1: सरकार (Government) और सुशासन (Good Governance) की अवधारणा | - पारंपरिक 'सरकार' (Government) बनाम 'अभिशासन' (राज्य + बाजार + सामाजिक संस्थाएँ) | - विश्व बैंक (1992) और UNDP द्वारा सुशासन के 8 प्रमुख लक्षण: सहभागिता, कानून का शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रभावशीलता, समानता, सर्वसम्मति, उत्तरदायित्व। | - भारत में 'न्यूनतम शासन, अधिकतम सुशासन' (Minimum Government, Maximum Governance) और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। | +---------- + | नोड 2: सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act, 2005) | - संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार में अंतर्निहित। | - प्रमुख प्रावधान: 30 दिनों में (जीवन/स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे) सूचना, ₹250/दिन जुर्माना (अधिकतम ₹25,000), केंद्रीय/राज्य सूचना आयोग। | - संशोधन: RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा केंद्र में CIC व IC के कार्यकाल व वेतन केंद्र सरकार द्वारा तय। | +---------- + | नोड 3: नागरिक चार्टर (Citizen's Charter) | - 1997 से लागू, गैर-न्यायोचित (Non-justiciable)। | - उद्देश्य: सेवा मानकों में पारदर्शिता, विकल्प की व्याख्या, शिकायत निवारण तंत्र। | - 6 मूल सिद्धांत: गुणवत्ता, विकल्प, मानक, मूल्य (पैसा वसूल), जवाबदेही, पारदर्शिता। | +---------- + | नोड 4: सेवोत्तम मॉडल (Sevottam Model) | - DARPG द्वारा विकसित, BIS के साथ मिलकर IS 15700:2005 गुणवत्ता प्रमाणन मानक। | - 3 मॉड्यूल: (1) प्रभावी सिटीजन चार्टर, (2) लोक शिकायत निवारण प्रणाली (CPGRAMS), (3) सेवा वितरण क्षमता। | +---------- + | नोड 5: सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) | - संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 243G, 11वीं अनुसूची, पंचायती राज संस्थाओं के लिए। | - उद्देश्य: सार्वजनिक व्यय और योजनाओं के कार्यान्वयन की जाँच, भ्रष्टाचार कम करना। | - प्रक्रिया: सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई द्वारा ग्राम सभा में रिपोर्ट प्रस्तुत। | +---------- + | नोड 6: सोशल ऑडिट (Social Audit) | - परिभाषा: सामाजिक अंकेक्षण का पर्यायवाची, सरकारी योजनाओं के रिकॉर्ड का भौतिक सत्यापन। | - कानूनी मान्यता: मनरेगा के तहत 2005 में, फिर अन्य योजनाओं में। | - प्रक्रिया: ग्राम सभा द्वारा 17 के तहत ग्राम सभा द्वारा सोशल ऑडिट इकाई का गठन, रिपोर्ट प्रस्तुत, कार्रवाई। | +---------- + | नोड 7: मेघालय समुदाय भागीदारी और जवाबदेही अधिनियम, 2017 | - पहला सिटीजन चार्टर, 'मेघालय समुदाय भागीदारी और जवाबदेही अधिनियम, 2017' पारित किया। | - सोशल ऑडिट को वैधानिक दर्जा। | - सेवा प्रदाताओं को सीधे जवाबदेह बनाना। | +----------

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: सूचना का अधिकार (RTI Act, 2005), सिटीजन चार्टर एवं सेवोत्तम मॉडल का संस्थागत विश्लेषण

अभिशासन तंत्र का नाम	कानूनी प्रवर्तनीयता एवं स्वरूप	मुख्य प्रावधान एवं समय-सीमा	प्रमुख कमियां एवं द्वितीय ARC (2nd ARC) के सुधार सुझाव
सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act, 2005)	**वैधानिक अधिकार** (अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार में अंतर्निहित); उल्लंघन पर केंद्रीय/राज्य सूचना आयोग द्वारा जन सूचना अधिकारी (PIO) पर **₹250 प्रतिदिन से अधिकतम ₹25,000 तक का अर्थदंड**।	सामान्य आवेदन पर **30 दिन**, सहायक जन सूचना अधिकारी (APIO) के माध्यम से 35 दिन, और किसी व्यक्ति के **जीवन या स्वतंत्रता (Life or Liberty)** से संबंधित होने पर मात्र **48 घंटे** के भीतर सूचना देना अनिवार्य।	लंबित अपीलों की संख्या, धारा 4 के तहत स्वत: प्रकटीकरण (Suo-motu disclosure) की कमी; **RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019** द्वारा सूचना आयुक्तों का कार्यकाल (3 वर्ष) व वेतन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया।
नागरिक चार्टर (Citizen's Charter — भारत में 1997 से)	**कानूनी रूप से बाध्यकारी या वाद-योग्य नहीं (Non-justiciable):** यह किसी सरकारी विभाग द्वारा अपने नागरिकों के प्रति सेवा की गुणवत्ता, मानक और समय-सीमा की एक नैतिक व प्रशासनिक प्रतिबद्धता है।	इसके 6 मूल सिद्धांत हैं: गुणवत्ता, विकल्प, मानक, मूल्य (पैसा वसूल), जवाबदेही और पारदर्शिता।	नागरिकों व कर्मचारियों से परामर्श के बिना ऊपर से थोपा गया ढांचा और चूक होने पर दंड का अभाव; इसी कमी को दूर करने के लिए राज्यों (सर्वप्रथम मध्य प्रदेश, 2010) ने कानूनी **'लोक सेवा गारंटी अधिनियम' (Right to Public Services Act)** बनाए।
सेवोत्तम मॉडल (Sevottam Model — DARPG द्वारा विकसित)	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के साथ मिलकर विकसित **IS 15700:2005 गुणवत्ता प्रमाणन मानक**।	इसमें 3 मॉड्यूल (प्रत्येक में 3 मानदंड = कुल 9 मानदंड) हैं: (1) प्रभावी **सिटीजन चार्टर**, (2) **लोक शिकायत निवारण प्रणाली** (CPGRAMS), और (3) **सेवा वितरण क्षमता**।	द्वितीय ARC ने अपनी 12वीं रिपोर्ट (*Citizen Centric Administration: The Heart of Governance*) में सभी मंत्रालयों और राज्यों में 'सेवोत्तम मॉडल' को अनिवार्य रूप से लागू करने की सिफारिश की।

अभिशासन तंत्र का नाम	कानूनी प्रवर्तनीयता एवं स्वरूप	मुख्य प्रावधान एवं समय-सीमा	प्रमुख कमियां एवं द्वितीय ARC (2nd ARC) के सुधार सुझाव
सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)	मनरेगा अधिनियम, 2005 (धारा 17) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत **वैधानिक रूप से अनिवार्य**।	ग्राम सभा द्वारा मस्टर रोल, बिल-वाउचर और निर्माण कार्यों की जमीनी वास्तविकता का सार्वजनिक वाचन और मिलान ('जन सुनवाई')।	सरपंच-सचिव के दबाव को रोकने के लिए स्वतंत्र 'सोशल ऑडिट यूनिट' (SAU) का गठन और CAG के साथ समन्वय कर सामाजिक अंकेक्षण मानक (SAAS) लागू किए गए हैं।

3. 'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स (Did You Know? Box)

क्या आप जानते हैं? (रोचक प्रशासनिक एवं विधिक तथ्य)

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के **'शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923' (Official Secrets Act, 1923)** की मानसिकता को बदल दिया; RTI अधिनियम की **धारा 22** में स्पष्ट लिखा है कि इस अधिनियम के प्रावधान शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 या किसी अन्य कानून में किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी (Overriding Effect) होंगे (**विधायी विभाग — भारत का संविधान**)!

2. भारत में जमीनी स्तर पर सूचना के अधिकार और सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) के आंदोलन की शुरुआत 1990 के दशक में राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम तहसील (देवडूंगरी) से अरुणा रॉय, निखिल डे और शंकर सिंह के नेतृत्व में **मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS)** ने "हमारा पैसा, हमारा हिसाब" और "जानने का अधिकार, जीने का अधिकार" नारे के साथ की थी (**NCERT पाठ्यपुस्तक पोर्टल**)।

3. **सुशासन सूचकांक (Good Governance Index - GGI)** प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा 25 दिसंबर (पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती — **सुशासन दिवस**) के अवसर पर 10 क्षेत्रों और 58 संकेतकों के आधार पर राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए जारी किया जाता है।

4. 'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स (Exam Trap Alert Box)

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert — सावधानी से पढ़ें!)

• **जाल 1 (क्या मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं?):** यह यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का सबसे पसंदीदा जाल है! याद रखें: केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा **3-सदस्यीय समिति** की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं: (1) **प्रधानमंत्री** (अध्यक्ष), (2) **लोकसभा में विपक्ष का नेता**, और (3) **प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री**। **इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) या लोकसभा अध्यक्ष शामिल नहीं होते!**

• **जाल 2 (RTI अधिनियम की धारा 24 और दूसरी अनुसूची की छूट का अपवाद):** RTI अधिनियम की धारा 24 के तहत दूसरी अनुसूची में शामिल केंद्रीय खुफिया और सुरक्षा संगठनों (जैसे IB, RAW, DRI, ED, BSF, CRPF, ITBP, NSG, CBI आदि) को सामान्यतः RTI के दायरे से बाहर रखा गया है; किंतु यदि मांगी गई सूचना **'भ्रष्टाचार के आरोपों' (Allegations of Corruption)** या **'मानवाधिकारों के उल्लंघन' (Human Rights Violations)** से संबंधित है, तो इन सुरक्षा एजेंसियों को भी सूचना देनी पड़ती है!

• **जाल 3 (RTI संशोधन अधिनियम, 2019 के बाद कार्यकाल):** मूल 2005 अधिनियम में मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष (या 65 वर्ष की आयु) निश्चित था, किंतु **सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019** और उसके तहत बने नियमों के बाद अब कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है (वर्तमान नियम के अनुसार **3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु**, और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते) (**IUC Academy लर्निंग पाथ**)।

5. 'IUC स्मृति ट्रिक' (IUC Magic Memory Trick)

★ IUC स्मृति ट्रिक:

• **सुशासन (Good Governance — UNDP/विश्व बैंक) के 8 स्तंभ याद करने का सूत्र: "PARTNERS (पार्टनर्स)!"**
• **P:** Participatory (भागीदारीपूर्ण)
• **A:** Accountable (जवाबदेह)
• **R:** Rule of Law (विधि का शासन)
• **T:** Transparent (पारदर्शी)
• **N (C):** Consensus-oriented (सर्वसम्मति उन्मुख)
• **E:** Equitable & Inclusive (समतामूलक एवं समावेशी)
• **R:** Responsive (संवेदनशील / अनुक्रियाशील)
• **S (E):** Effective & Efficient (प्रभावी एवं दक्ष)
• **सेवोत्तम (Sevottam) के 3 स्तंभ: "चा-शि-क्ष (चार्टर + शिकायत निवारण + क्षमता निर्माण)!"**

मॉड्यूल 8: ई-गवर्नेंस (e-Governance), डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) एवं साइबर सुरक्षा चुनौतियां

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 8: ई-गवर्नेंस (e-Governance), डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) एवं साइबर सुरक्षा चुनौतियां

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स (Did You Know? Box)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स (Exam Trap Alert Box)

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)

चरण 1 | चरण 2 | चरण 3 | चरण 4

नोड 1: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP 2006) से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत — आधार, UPI, DigiLocker और GSTN जैसे DPI स्तंभों का विकास — आधार (पुट्टस्वामी वाद 2017) एवं इंडिया' (2015) व ई-क्रांति | | - निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित — DPDP अधिनियम, 2023, पुरुषोत्तमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत के माध्यम से सरकारी सेवाओं को 'सिंगल विंडो, सिमलेस, मोबाइल-फर्स्ट और पेपरलेस' बनाने का संघ (2021 के बाद के फैसलों में डिजिटल निजता के अधिकार' को अनुच्छेद 21 के संवेदनशील, पारदर्शी) बनाना। | | विजन के साथ 2006 में | डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (2015) का | | - न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा कार्यक्रम का शुभारंभ (9 स्तंभ, जिनमें ई-क्रांति, ई-क्रांति, NPCI, GSTN, DigiLocker, MCA21 आदि शामिल थे) | | — 44 मिशन मोड परियोजनाएं)। | | (डिजिटलीकरण के 4 अंतरक्रिया मॉडल — | | - 'डेटा G2C (नागरिक), G2B (व्यवसाय), G2G (सरकार), G2E (कर्मचारी)। | UMANG ऐप, PRAGATI और ई-ऑफिस। | | संस्था) पर डेटा ब्रीच होने पर ₹250 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: ई-गवर्नेंस के 4 अंतरक्रिया मॉडल एवं प्रमुख डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) पहलें

ई-गवर्नेंस मॉडल / DPI स्तंभ	लक्षित समूह एवं उद्देश्य	प्रमुख सरकारी प्लेटफॉर्म एवं उदाहरण	शासन एवं सामाजिक न्याय पर प्रभाव (नीति आयोग)
G2C (Government to Citizen — सरकार से नागरिक)	नागरिकों को सरकारी प्रमाण-पत्र, कल्याणकारी सब्सिडी, स्वास्थ्य, शिक्षा और शिकायत निवारण सेवाएं सीधे उनके द्वार/मोबाइल पर उपलब्ध कराना।	**UMANG ऐप**, **डिजिलॉकर (DigiLocker)**, **CPGRAMS** (लोक शिकायत), **CoWIN/U-WIN**, **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)**, **भूमि** (कर्नाटक), **ई-मित्र** (राजस्थान)।	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से फर्जी लाभार्थियों (Ghost Beneficiaries) को हटाकर ₹3.48 लाख करोड़ से अधिक की सरकारी बचत।
G2B (Government to Business — सरकार से व्यवसाय)	उद्योगों और उद्यमियों के लिए लाइसेंस, पंजीकरण, कर भुगतान और सरकारी खरीद प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाना ('ईज ऑफ डूइंग बिजनेस')।	**GeM पोर्टल (Government e-Marketplace)**, **MCA21** (कंपनी मामलों का मंत्रालय), **GSTN पोर्टल**, **ई-बिज (e-Biz)**, **उद्यम पंजीकरण पोर्टल** और **ONDC**।	GeM पोर्टल ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) तथा महिला स्वयं सहायता समूहों ('सरस कलेक्शन') को बिना बिचौलियों के सीधे सरकारी विभागों को सामान बेचने का मंच दिया।
G2G (Government to Government — सरकार से सरकार)	केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के बीच फाइलों के आदान-प्रदान और परियोजना निगरानी में तेजी लाना।	**PRAGATI** (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन — प्रधानमंत्री द्वारा सीधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा), **ई-ऑफिस (e-Office)**, **PFMS** और **CCTNS** (पुलिस नेटवर्क)।	फाइलों के लालफीताशाही में अटकने की समस्या कम हुई और अंतर-मंत्रालयी व केंद्र-राज्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समयबद्ध पूर्णता संभव हुई।
G2E (Government to Employee — सरकार से कर्मचारी)	सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड, वेतन, भविष्य निधि, प्रशिक्षण और पेंशन निपटान का डिजिटलीकरण।	**मिशन कर्मयोगी (iGOT Karmayogi प्लेटफॉर्म)**, **भविष्य (Bhavishya — ऑनलाइन पेंशन ट्रैकिंग)**, **जीवन प्रमाण** (डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट) और **SPARROW** (ऑनलाइन APAR)।	सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति और सिविल सेवकों का 'नियम-आधारित' से 'भूमिका-आधारित' क्षमता निर्माण।

ई-गवर्नेंस मॉडल / DPI स्तंभ	लक्षित समूह एवं उद्देश्य	प्रमुख सरकारी प्लेटफॉर्म एवं उदाहरण	शासन एवं सामाजिक न्याय पर प्रभाव (नीति आयोग)
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act, 2023)	नागरिकों (**Data Principal**) के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता की रक्षा और डेटा प्रोसेसिंग करने वाली संस्थाओं (**Data Fiduciary**) की जवाबदेही।	**भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (Data Protection Board of India)** का गठन; बच्चों के डेटा प्रोसेसिंग के लिए माता-पिता की सत्यापित सहमति अनिवार्य और उनके ट्रैकिंग/लक्षित विज्ञापनों पर रोक।	विधायी विभाग — भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 (पुट्टस्वामी निर्णय, 2017) के अनुरूप तकनीकी नवाचार और नागरिक निजता के बीच संतुलन।

3. 'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स (Did You Know? Box)

क्या आप जानते हैं? (रोचक तकनीकी एवं प्रशासनिक तथ्य)

1. प्रधानमंत्री द्वारा मार्च 2015 में शुरू किया गया **'प्रगति' (PRAGATI — Pro-Active Governance and Timely Implementation)** प्लेटफॉर्म एक अनूठा त्रि-स्तरीय (Three-tier) डिजिटल तंत्र है, जिसमें प्रधानमंत्री प्रत्येक माह के **चौथे बुधवार** को केंद्रीय सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लंबित राष्ट्रीय परियोजनाओं, जन-शिकायतों और प्रमुख योजनाओं की वास्तविक समय (Real-time) में समीक्षा करते हैं!

2. भारत के **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI — आधार, UPI, डिजिलॉकर)** की वैश्विक सफलता को वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान विश्व बैंक और UNDP ने सराहा; विश्व बैंक की G20 वित्तीय समावेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत ने DPI की बदौलत मात्र **6 वर्षों में 80% से अधिक वयस्क वित्तीय समावेशन** का वह लक्ष्य हासिल कर लिया, जिसे पारंपरिक तरीकों से पूरा करने में **47 वर्ष** लग जाते!

3. सुप्रीम कोर्ट ने जहां 2017 के **के.एस. पुट्टस्वामी वाद (प्रथम)** में 9-न्यायाधीशों की पीठ से निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 का मौलिक अधिकार माना, वहीं 2018 के **पुट्टस्वामी वाद (द्वितीय — आधार निर्णय)** में 5-न्यायाधीशों की पीठ ने **आधार अधिनियम, 2016** की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा (कल्याणकारी योजनाओं व पैन कार्ड के लिए आधार को वैध माना, किंतु निजी कंपनियों, सिम कार्ड व बैंक खातों के लिए इसकी अनिवार्यता वाली धारा 57 को रद्द कर दिया)।

4. 'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स (Exam Trap Alert Box)

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert — सावधानी से पढ़ें!)

• **जाल 1 (ई-गवर्नेंस में 'SMART' का पूर्ण रूप):** प्रशासनिक सुधार रिपोर्टों और परीक्षाओं में 'SMART Governance' का अर्थ पूछा जाता है — यहां S का अर्थ Smart नहीं बल्कि **Simple (सरल)** है! पूरा सूत्र: **S = Simple (सरल), M = Moral (नैतिक), A = Accountable (जवाबदेह), R = Responsive (संवेदनशील/अनुक्रियाशील), T = Transparent (पारदर्शी)**।

• **जाल 2 (डेटा प्रिंसिपल बनाम डेटा फिड्यूशियरी — DPDP Act, 2023): डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023** की शब्दावली में छात्र अक्सर उल्टा समझ लेते हैं:

• **डेटा प्रिंसिपल (Data Principal):** वह **आम नागरिक या व्यक्ति** जिसका व्यक्तिगत डेटा है (यदि डेटा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे या दिव्यांग का है, तो उसके माता-पिता/वैध अभिभावक भी डेटा प्रिंसिपल में शामिल हैं)।

• **डेटा फिड्यूशियरी (Data Fiduciary):** वह **कंपनी, संस्था या सरकारी विभाग** जो डेटा के संग्रहण का उद्देश्य और साधन निर्धारित करता है।

• **जाल 3 (राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना बनाम डिजिटल इंडिया का वर्ष): राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP)** की शुरुआत **मई 2006** में (मूल रूप से 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स के साथ) हुई थी, जबकि **'डिजिटल इंडिया'** कार्यक्रम **1 जुलाई 2015** को शुरू हुआ जिसके 5वें स्तंभ **'ई-क्रांति' (e-Kranti / NeGP 2.0)** में मिशन मोड परियोजनाओं की संख्या बढ़ाकर **44** कर दी गई (IUC Academy लर्निंग पाथ)।

5. 'IUC स्मृति ट्रिक' (IUC Magic Memory Trick)

★ IUC स्मृति ट्रिक:

• **SMART गवर्नेंस के 5 अक्षर: "सरल (Simple), नैतिक (Moral), जवाबदेह (Accountable), संवेदनशील (Responsive), पारदर्शी (Transparent)!"**

• **इंडिया स्टैक (India Stack) की 3 परतें: "प-भु-डे (पहचान = आधार, भुगतान = UPI, डेटा = डिजिलॉकर/अकाउंट एग्रीगेटर)!"**

• **DPDP Act 2023 का जुर्माना: "ब्रीच रोको वरना ₹250 करोड़ भरो!"** (सुरक्षा उपायों में विफलता पर अधिकतम ₹250 करोड़ का दंड)।

मॉड्यूल 9: लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, पुलिस एवं प्रशासनिक सुधार, लोकपाल व भ्रष्टाचार निवारण

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 9: लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, पुलिस एवं प्रशासनिक सुधार, लोकपाल व भ्रष्टाचार निवारण

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स (Did You Know? Box)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स (Exam Trap Alert Box)

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)

चरण 1 | चरण 2 | चरण 3 | चरण 4

नोड 1: संवैधानिक ढांचा, 'स्टील फ्रेम' की अवधारणा एवं प्रारंभिक चुनौतियाँ (अनुच्छेद 308–323) | - सरदार वल्लभभाई पटेल ('भारतीय सिविल सेवा के जनक') द्वारा सिविल सेवा की स्थापना, विशेषज्ञता एवं निष्पक्षता पर बल। | - संविधान का भाग XIV, अनुच्छेद 311 (सिविल सेवकों को सुरक्षा) एवं अनुच्छेद 312: राज्यसभा के 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन। | - शक्ति (IAS, IPS एवं अन्य सेवाओं का विवरण)।

नोड 2: अखिल भारतीय सेवाओं एवं केंद्रीय सेवाओं का विकास (1947–1990) | - प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC, 1966): प्रथम ARC का गठन; मुख्य सिफारिशें — लोक सेवा आयोग की स्वायत्तता, प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना। | - द्वितीय ARC (2005): अध्यक्ष — वीरप्पा मोइली; 15 रिपोर्टें प्रस्तुत; मुख्य सिफारिशें — नैतिकता संहिता, सिविल सेवा बोर्ड, लोक शिकायत निवारण तंत्र, सूचना का अधिकार का सशक्तीकरण। | - भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर का अधिकार अधिनियम, 2013 (LARR Act, 2013) — सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) एवं सहमति प्रावधान।

नोड 3: पुलिस सुधार — ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं आवश्यकता | - पुलिस अधिनियम, 1861 की औपनिवेशिक प्रकृति; पुलिस आयोग (1902–03) की सिफारिशें। | - प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) में सर्वोच्च न्यायालय के 7 निर्देश: राज्य सुरक्षा आयोग, पुलिस स्थापना बोर्ड (PEB), पुलिस शिकायत प्राधिकरण, पृथक जाँच एवं कानून व्यवस्था कार्य, चयन एवं कार्यकाल हेतु न्यूनतम 2 वर्ष। | - मॉडल पुलिस अधिनियम, 2006 (मॉडल पुलिस एक्ट) — प्रमुख प्रावधान।

नोड 4: लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 तथा पुलिस सुधारों की वर्तमान स्थिति | - लोकपाल: गठन, संरचना (1 अध्यक्ष + अधिकतम 8 सदस्य)। | - प्रधानमंत्री (कुछ अपवादों सहित), केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य तथा समूह A, B, C, D के सभी अधिकारी — लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में। | - लोकपाल बनाम CBI: अधीक्षण एवं निदेशन का विवाद; CBI (संशोधन) अधिनियम, 2014। | - भारतीय न्याय संहिता (BNS/BNSS/BSA 2023 — 1 जुलाई 2024 से लागू)।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: भ्रष्टाचार निवारण एवं जवाबदेही के प्रमुख निकाय — लोकपाल बनाम CVC बनाम CBI

तुलना का आधार	लोकपाल (Lokpal)	केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)	केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)
वैधानिक दर्जा एवं उत्पत्ति	**सांविधिक निकाय (Statutory Body):** प्रथम ARC (1966) की सिफारिश और अन्ना हजारे आंदोलन के बाद **लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013** के तहत गठित (प्रथम अध्यक्ष: न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, 2019)।	**सांविधिक निकाय: के. संथानम समिति (1962–64)** की सिफारिश पर फरवरी 1964 में कार्यपालिका प्रस्ताव से गठित; बाद में **CVC अधिनियम, 2003** द्वारा सांविधिक दर्जा मिला।	**गैर-सांविधिक निकाय:** संथानम समिति की सिफारिश पर 1963 में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव से गठित; यह अपनी कानूनी शक्तियां **दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946** से प्राप्त करता है।
संरचना एवं कार्यकाल	**1 अध्यक्ष + अधिकतम 8 सदस्य** (जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य और कम से कम 50% सदस्य SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होने अनिवार्य); कार्यकाल: **5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु**।	बहु-सदस्यीय निकाय: **1 केंद्रीय सतर्कता आयुक्त + अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त**; कार्यकाल: **4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु** (पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं)।	**CBI निदेशक** (पुलिस महानिरीक्षक स्तर से ऊपर के IPS अधिकारी); विनीत नारायण वाद (1997) और लोकपाल अधिनियम के तहत न्यूनतम **2 वर्ष का निश्चित कार्यकाल** (2021 संशोधन से 1+1+1 वर्ष बढ़ाकर अधिकतम 5 वर्ष तक संभव)।
चयन / नियुक्ति समिति	**5-सदस्यीय चयन समिति:** (1) प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), (2) लोकसभा अध्यक्ष, (3) लोकसभा में विपक्ष का नेता, (4) भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट जज), और (5) एक प्रख्यात न्यायविद।	**3-सदस्यीय समिति:** (1) प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), (2) केंद्रीय गृह मंत्री, और (3) लोकसभा में विपक्ष का नेता (नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा)।	**3-सदस्यीय समिति (DSPE संशोधित):** (1) प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), (2) लोकसभा में विपक्ष का नेता, और (3) भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश)।

तुलना का आधार	लोकपाल (Lokpal)	केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)	केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)
अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction)	प्रधानमंत्री (अंतर्राष्ट्रीय संबंध, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और लोक व्यवस्था को छोड़कर), केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य, समूह A, B, C व D के सभी सरकारी सेवक और ₹10 लाख से अधिक विदेशी अनुदान (FCRA) लेने वाले NGO।	केंद्र सरकार के मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU), राष्ट्रीयकृत बैंक और समूह 'A' के राजपत्रित अधिकारी तथा लोकपाल द्वारा भेजे गए मामले; भ्रष्टाचार के मामलों में CBI पर अधीक्षण (Superintendence) की शक्ति।	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (DoPT) के अधीन कार्य करता है; किसी राज्य के क्षेत्राधिकार में जांच के लिए DSPE एक्ट की **धारा 6 के तहत राज्य सरकार की 'सामान्य सहमति' (General Consent)** आवश्यक (जब तक सुप्रीम कोर्ट/हाईकोर्ट आदेश न दे)।

3. 'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स (Did You Know? Box)

क्या आप जानते हैं? (रोचक प्रशासनिक एवं संवैधानिक तथ्य)

1. विश्व में नागरिकों की शिकायतों की जांच के लिए स्वतंत्र **'ओम्बड्समैन' (Ombudsman)** संस्था की शुरुआत सबसे पहले **1809 में स्वीडन** में हुई थी; भारत में इस संस्था के लिए **'लोकपाल' (Lokpal)** शब्द सबसे पहले वर्ष **1963 में प्रसिद्ध विधिवेत्ता और सांसद डॉ. एल.एम. सिंघवी** ने गढ़ा था, और **महाराष्ट्र (1971)** लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना (जबकि ओडिशा ने 1970 में अधिनियम सबसे पहले पारित किया था, पर लागू 1983 में किया) (NCERT पाठ्यपुस्तक पोर्टल)।
2. प्रत्येक वर्ष **21 अप्रैल** को भारत में **'राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस' (National Civil Services Day)** मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन **21 अप्रैल 1947** को स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री **सरदार वल्लभभाई पटेल** ने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में स्वतंत्र भारत के पहले बैच के परिवीक्षाधीन प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्हें **'स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया' (Steel Frame of India)** कहा था।
3. भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को औपनिवेशिक मानसिकता (दंड) से मुक्त कर 'न्याय और नागरिक सुरक्षा' पर केंद्रित करने के लिए **1 जुलाई 2024** से तीन नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं: IPC (1860) के स्थान पर **भारतीय न्याय संहिता (BNS, 2023)**, CrPC (1973) के स्थान पर **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS, 2023)** और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) के स्थान पर **भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA, 2023)**, जिनमें जीरो एफआईआर (Zero FIR), ई-एफआईआर और 7 वर्ष या अधिक सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य की गई है (विधायी विभाग — भारत का संविधान)।

4. 'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स (Exam Trap Alert Box)

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert — सावधानी से पढ़ें!)

• **जाल 1 (कौन-सी 3 सेवाएं 'अखिल भारतीय सेवाएं' हैं?):** परीक्षा में अक्सर 'भारतीय विदेश सेवा' (Indian Foreign Service - IFS) को अखिल भारतीय सेवा बताकर फंसाया जाता है! सावधान रहें: भारत के संविधान के **अनुच्छेद 312** के तहत वर्तमान में केवल **3 अखिल भारतीय सेवाएं (All India Services)** हैं — (1) **भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)**, (2) **भारतीय पुलिस सेवा (IPS)**, और (3) **भारतीय वन सेवा (Indian Forest Service - IFoS, 1966 में सृजित)**। **भारतीय विदेश सेवा (Indian Foreign Service) अखिल भारतीय सेवा नहीं, बल्कि एक 'केंद्रीय सेवा' (Central Service Group-A) है!** (अनुच्छेद 312 में 42वें संशोधन 1976 द्वारा 'अखिल भारतीय न्यायिक सेवा' का प्रावधान भी जोड़ा गया है, किंतु इसका अभी तक गठन नहीं हुआ है)।

• **जाल 2 (अनुच्छेद 311 का संरक्षण क्या सैन्य कर्मियों को भी प्राप्त है?):** संविधान का **अनुच्छेद 311** सिविल सेवकों को नियुक्ति प्राधिकारी से नीचे के अधिकारी द्वारा पदच्युत न किए जाने और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने का सुरक्षा कवच देता है, किंतु यह संरक्षण केवल संघ या राज्य के **सिविल पदों** के धारकों को प्राप्त है; **रक्षा या सैन्य सेवाओं (Defence Services) के सदस्यों को अनुच्छेद 311 का संरक्षण प्राप्त नहीं है** (उन पर अनुच्छेद 310 का 'प्रसाद का सिद्धांत' लागू होता है)।

• **जाल 3 (लोकपाल बनाम CVC का कार्यकाल):** लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल **5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु** होता है, जबकि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC) का कार्यकाल **4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु** होता है (IUC Academy लर्निंग पाथ)।

5. 'IUC स्मृति ट्रिक' (IUC Magic Memory Trick)

★ IUC स्मृति ट्रिक:

• संथानम समिति (1962-64) के दो जुड़वां बच्चे: "63 में CBI, 64 में CVC!"

• सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह वाद (2006) के मुख्य पुलिस सुधार: "DGP को 2 साल की गारंटी + स्टेट सिक्योरिटी कमीशन + पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड + जांच और कानून-व्यवस्था अलग + पुलिस शिकायत प्राधिकरण!"

• लोकपाल चयन समिति के 5 सदस्य: "PM + स्पीकर + विपक्ष का नेता + CJI + न्यायविद (गृह मंत्री इसमें नहीं हैं; गृह मंत्री CVC की समिति में होते हैं!)"

मॉड्यूल 10: विकास प्रक्रिया में गैर-सरकारी संगठनों (NGO), स्वयं सहायता समूहों (SHG), दबाव समूहों एवं पंचायती राज की भूमिका

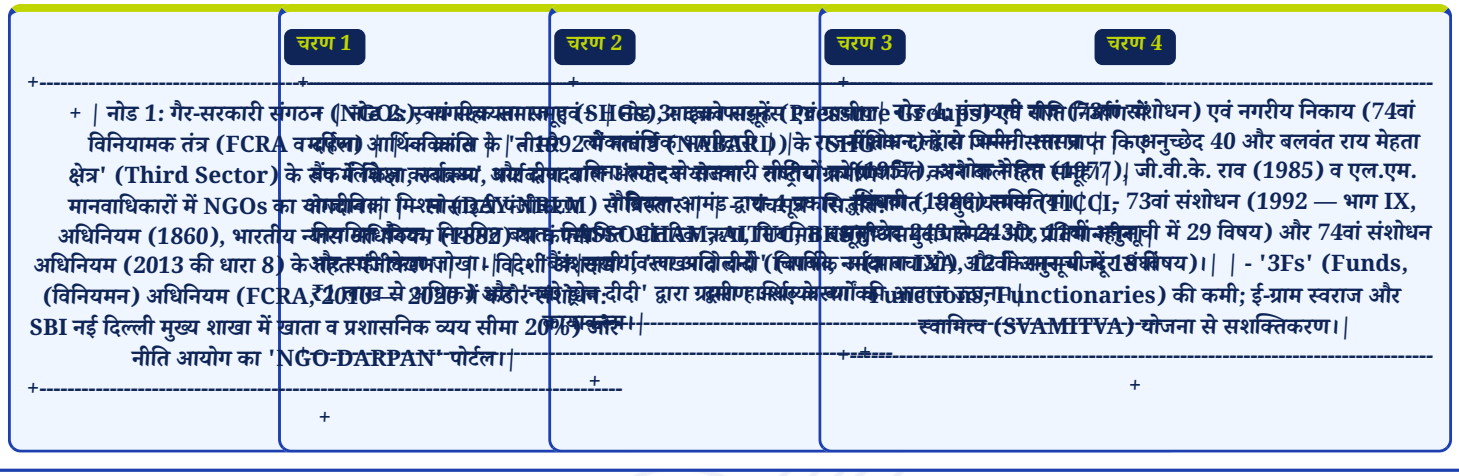
अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 10: विकास प्रक्रिया में गैर-सरकारी संगठनों (NGO), स्वयं सहायता समूहों (SHG), दबाव समूहों एवं पंचायती राज की भूमिका

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स (Did You Know? Box)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स (Exam Trap Alert Box)

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)



2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: विकास प्रक्रिया के सहभागी स्तंभ — NGOs बनाम SHGs बनाम दबाव समूह बनाम पंचायती राज संस्थाएं (PRIs)

तुलना का आधार	गैर-सरकारी संगठन (NGOs)	स्वयं सहायता समूह (SHGs)	दबाव समूह (Pressure Groups)	पंचायती राज संस्थाएं (PRIs — 73वां संशोधन)
प्रकृति एवं संरचना	गैर-लाभकारी स्वैच्छिक संगठन, जो किसी विशेष सामाजिक, शैक्षणिक या पर्यावरणीय उद्देश्य के लिए पेशेवर रूप से कार्य करते हैं।	समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के **10 से 20 सदस्यों (विशेषकर ग्रामीण महिलाओं)** का अनौपचारिक या पंजीकृत स्व-सहायता और सूक्ष्म-बचत समूह।	समान व्यावसायिक, आर्थिक या सामाजिक हितों वाले लोगों का संगठित समूह जो सरकार पर नीतिगत दबाव बनाता है।	**संवैधानिक स्थानीय स्वशासन निकाय** (भारत का संविधान — भाग IX); ग्राम, मध्यवर्ती (ब्लॉक) और जिला स्तर पर त्रि-स्तरीय निर्वाचित ढांचा।
वित्तीय स्रोत एवं विनियमन	सरकारी अनुदान (नीति आयोग का **NGO-DARPAN** पोर्टल), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और विदेशी अंशदान (**FCRA 2010/2020** — गृह मंत्रालय के अधीन)।	सदस्यों की अपनी छोटी बचत, NRLM का रिवॉल्विंग फंड और **NABARD के SHG-बैंक लिंकेज** के तहत बिना गारंटी (Collateral-free) का बैंक ऋण।	सदस्यों का चंदा और संबंधित उद्योग या व्यवसाय संघों (जैसे FICCI, CII, ट्रेड यूनियनों) का अंशदान।	**राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243I)** और केंद्रीय वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) के अनुदान तथा स्थानीय कर व शुल्क (अनुच्छेद 243H)।
प्रमुख कार्यप्रणाली	सेवा वितरण (अस्पताल, स्कूल, आश्रय गृह चलाना), नीतिगत अनुसंधान और जन-जागरूकता अभियान।	आपसी विश्वास ('सामाजिक पूंजी') के आधार पर महाजनों के चंगुल से मुक्ति, सूक्ष्म-उद्यम, **'लखपति दीदी'** और **'नमो ड्रोन दीदी'** के रूप में कृषि आधुनिकीकरण।	लॉबिंग, ज्ञापन, जनमत निर्माण, मीडिया अभियान, न्यायिक जनहित याचिका (PIL) और शांतिपूर्ण प्रदर्शन।	**ग्राम सभा (अनुच्छेद 243A)** के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) बनाना, 11वीं अनुसूची के 29 विषयों का क्रियान्वयन और सोशल ऑडिट।

तुलना का आधार	गैर-सरकारी संगठन (NGOs)	स्वयं सहायता समूह (SHGs)	दबाव समूह (Pressure Groups)	पंचायती राज संस्थाएं (PRIs — 73वां संशोधन)
प्रमुख चुनौतियां	पारदर्शिता व ऑडिट की कमी, विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग के आरोप और शहरी-केंद्रित कार्यप्रणाली।	विपणन (Marketing) और ब्रांडिंग की कमी, डिजिटल व वित्तीय साक्षरता का अभाव और क्षेत्रीय असमानता (दक्षिण भारत में अधिक, उत्तर-पूर्व में कम)।	संकीर्ण वर्गीय हितों को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखना और कभी-कभी हड़ताल या बंद से सार्वजनिक जीवन बाधित करना।	**'3Fs' (Funds, Functions, Functionaries — धन, कार्य और कर्मचारी)** के वास्तविक हस्तांतरण की कमी और 'सरपंच पति' संस्कृति।

3. *'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स* (Did You Know? Box)

क्या आप जानते हैं? (रोचक प्रशासनिक एवं संवैधानिक तथ्य)

1. **विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 (FCRA Amendment Act, 2020)** के तहत गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे विदेशी अंशदान (Foreign Contribution) केवल **भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की नई दिल्ली मुख्य शाखा** में खोले गए निर्दिष्ट 'FCRA खाते' में ही प्राप्त कर सकते हैं, अपने प्रशासनिक खर्चों पर विदेशी फंड का **अधिकतम 20%** (पहले यह सीमा 50% थी!) ही खर्च कर सकते हैं, और किसी एक NGO द्वारा प्राप्त विदेशी फंड को किसी दूसरे NGO को हस्तांतरित (Sub-granting) करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है!

2. भारत में पंचायती राज का शुभारंभ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा **2 अक्टूबर 1959** को राजस्थान के **नागौर जिले (बगदरी गांव)** से किया गया था (जबकि आंध्र प्रदेश 1959 में ही इसे पूरे राज्य में लागू करने वाला दूसरा राज्य बना); बाद में **एल.एम. सिंघवी समिति (1986)** की सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 पारित हुआ जो **24 अप्रैल 1993** से लागू हुआ, इसीलिए **24 अप्रैल** को प्रतिवर्ष **'राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस'** मनाया जाता है (विधायी विभाग — भारत का संविधान)।

3. **पेसा अधिनियम, 1996 (PESA — पंचायत के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996)** दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर 5वीं अनुसूची के **10 राज्यों** (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान) के जनजातीय क्षेत्रों में भाग IX के प्रावधानों का विस्तार करता है और **ग्राम सभा** को लघु वनोपज (Minor Forest Produce) के स्वामित्व, भूमि हस्तांतरण रोकने और लघु खनिजों के पट्टे की सिफारिश करने की सर्वोच्च शक्ति देता है।

4. *'परीक्षा जाल सतर्कता' बॉक्स* (Exam Trap Alert Box)

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert — सावधानी से पढ़ें!)

• **जाल 1 (NGO-DARPAN पोर्टल कौन संचालित करता है और FCRA का नोडल मंत्रालय कौन-सा है?):** परीक्षार्थी अक्सर दोनों का उत्तर गृह मंत्रालय या सामाजिक न्याय मंत्रालय लगा देते हैं! याद रखें:

• **NGO-DARPAN पोर्टल** का संचालन नीति आयोग **(NITI Aayog)** द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से किया जाता है (जहां सरकारी अनुदान पाने के लिए NGOs को 'यूनिक आईडी' लेनी होती है)।

• **विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA, 2010)** का क्रियान्वयन वित्त मंत्रालय नहीं, बल्कि **केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs - MHA)** द्वारा किया जाता है!

• **जाल 2 (पंचायत का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष नहीं, 21 वर्ष है!):** संविधान के **अनुच्छेद 243F** के अनुसार पंचायत (और अनुच्छेद 243V के अनुसार नगरपालिका) का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु **25 वर्ष नहीं, बल्कि 21 वर्ष** है! साथ ही, यदि कोई पंचायत अपने 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले भंग कर दी जाती है, तो 6 माह के भीतर पुनर्गठित नई पंचायत पूरे 5 वर्ष के लिए नहीं, बल्कि **केवल शेष बची हुई अवधि (Remainder of the period)** के लिए ही कार्य करती है (अनुच्छेद 243E(4))।

• **जाल 3 (20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती पंचायत की छूट):** संविधान के **अनुच्छेद 243B(2)** के अनुसार जिन राज्यों की जनसंख्या **20 लाख से अनधिक (20 लाख से कम)** है, वहां मध्यवर्ती (ब्लॉक) स्तर पर पंचायत का गठन करना अनिवार्य नहीं है (IUC Academy लर्निंग पाथ)।

5. 'IUC स्मृति ट्रिक' (IUC Magic Memory Trick)

★ **IUC स्मृति ट्रिक:**
- **पंचायती राज की 5 प्रमुख समितियों का कालानुक्रम: "ब-अ-जी-सिं-थु (B-A-G-S-T = 57-77-85-86-88)!"**
- **ब (1957):** बलवंत राय मेहता समिति (त्रि-स्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण)
- **अ (1977):** अशोक मेहता समिति (द्वि-स्तरीय पंचायत: मंडल पंचायत और जिला परिषद)
- **जी (1985):** जी.वी.के. राव समिति (नौकरशाहीकरण के कारण पंचायतों को 'बिना जड़ की घास' कहा)
- **सिं (1986):** एल.एम. सिंघवी समिति (पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा और ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया)
- **थु (1988):** पी.के. थुंगन समिति
- **73वें संशोधन के महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद करने का सूत्र: "A में ग्राम सभा, D में आरक्षण, E में 5 साल कार्यकाल, I में वित्त आयोग (Income), K में चुनाव आयोग (K = चुनाव)!"** (243A, 243D, 243E, 243I, 243K)।

अंतिम समय त्वरित वन-लाइनर रिवीजन कैप्सूल (100-पॉइंट — भारतीय समाज, सामाजिक न्याय एवं अभिशासन)

यह 100-पॉइंट वन-लाइनर कैप्सूल IUC Academy लर्निंग पाथ, NCERT पाठ्यपुस्तक पोर्टल, विधायी विभाग — भारत का संविधान, नीति आयोग और भारत की जनगणना सारणी पोर्टल के आधार पर तैयार किया गया है:

1. **भारतीय समाजशास्त्र के जनक:** प्रो. **जी.एस. घुर्ये (Govind Sadashiv Ghurye)** को भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है; उनकी प्रसिद्ध पुस्तक '*Caste and Race in India*' (1932) है।

2. **संस्कृतिकरण की अवधारणा:** समाजशास्त्री **एम.एन. श्रीनिवास** ने अपनी पुस्तक '*Religion and Society among the Coorgs of South India*' में 'संस्कृतिकरण' (Sanskritization) की अवधारणा प्रतिपादित की।

3. **प्रभु जाति (Dominant Caste):** एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार संख्याबल, कृषि भूमि के स्वामित्व और राजनीतिक प्रभाव वाली स्थानीय जाति को 'प्रभु जाति' कहा जाता है।

4. **जजमानी व्यवस्था:** ग्रामीण भारत में विभिन्न जातियों के बीच पारस्परिक और वंशानुगत आर्थिक-सेवा विनिमय प्रणाली को **'जजमानी व्यवस्था'** कहा गया, जिसका प्रथम विस्तृत अध्ययन **विलियम एच. वाइजर** ने किया।

5. **भारत में नातेदारी संगठन:** प्रसिद्ध नृवंशविज्ञानी **इरावती कर्वे** ने भारत की नातेदारी व्यवस्था को भाषाई और भौगोलिक आधार पर 4 क्षेत्रों में विभाजित किया।

6. **हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005:** इस संशोधन द्वारा मिताक्षरा संयुक्त परिवार संपत्ति में बेटियों को बेटों के समान जन्म से सह-दायिकी (Coparcenary) अधिकार दिया गया; सर्वोच्च न्यायालय ने **विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020)** में इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू माना।

7. **सती प्रथा का उन्मूलन (1829):** राजा राममोहन राय के प्रयासों से गवर्नर-जनरल **लॉर्ड विलियम बैंटिक** ने बंगाल रेगुलेशन XVII (1829) द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित किया।

8. **हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856):** पंडित **ईश्वरचंद्र विद्यासागर** के अथक प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में यह अधिनियम पारित हुआ।

9. **भारत का प्रथम बालिका विद्यालय (1848):** महात्मा **ज्योतिबा फुले** और **सावित्रीबाई फुले** (भारत की प्रथम महिला शिक्षिका) ने 1848 में पुणे के भिडेवाड़ा में देश का पहला बालिका विद्यालय खोला।

10. **शारदा एक्ट (1929):** हरबिलास शारदा के प्रयासों से पारित 'बाल विवाह अवरोधक अधिनियम, 1929' ने विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष तय की थी (वर्तमान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 में यह क्रमशः 18 और 21 वर्ष है)।

11. **वूमेन्स इंडियन एसोसिएशन (1917):** वर्ष 1917 में मद्रास (अड्यार) में **एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स और सरोजिनी नायडू** ने वूमेन्स इंडियन एसोसिएशन (WIA) की स्थापना की।

12. **अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (AIWC, 1927):** महिलाओं की शिक्षा और समाज सुधार के लिए **मार्गरेट कजिन्स** की पहल पर 1927 में पुणे में AIWC की स्थापना हुई।

13. **राष्ट्रीय महिला आयोग (1992):** राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत जनवरी 1992 में गठित यह एक **सांविधिक निकाय** है (प्रथम अध्यक्ष: जयंती पटनायक)।

14. **घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005:** यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ और यह महिलाओं को शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक हिंसा से सिविल उपचार व आवास का अधिकार देता है।

15. **POSH अधिनियम, 2013:** सर्वोच्च न्यायालय के **विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)** दिशा-निर्देशों को वैधानिक रूप देते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु 2013 में यह कानून बना।

16. **106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023:** 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' ने लोकसभा (**अनुच्छेद 330A**), राज्य विधानसभाओं (**अनुच्छेद 332A**) और दिल्ली विधानसभा (**अनुच्छेद 239AA**) में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की हैं।

17. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (2015):** गिरते बाल लिंगानुपात (CSR) को सुधारने और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए **22 जनवरी 2015** को हरियाणा के **पानीपत** से तीन मंत्रालयों (महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा) की संयुक्त पहल के रूप में शुरू किया गया।

18. **मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017:** संगठित क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं के लिए प्रथम दो बच्चों तक सवेतन मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर **26 सप्ताह** किया गया तथा 50 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में **क्रेच (Crèche — शिशुगृह)** सुविधा अनिवार्य की गई।

19. **महान विभाजक वर्ष (1921):** भारतीय जनगणना के इतिहास में **1921** को 'महान विभाजक वर्ष' कहा जाता है क्योंकि 1911–21 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक (-0.31%) रही थी।

20. **जनगणना का संवैधानिक आधार:** जनगणना संविधान के **अनुच्छेद 246** के तहत **संघ सूची की प्रविष्टि 69** का विषय है और इसका संचालन **जनगणना अधिनियम, 1948** के अंतर्गत गृह मंत्रालय के अधीन होता है।

21. **जनगणना 2011 के मुख्य आंकड़े:** कुल जनसंख्या 121.08 करोड़, दशकीय वृद्धि दर **17.7%**, जनसंख्या घनत्व **382 व्यक्ति/वर्ग किमी**, साक्षरता दर **73.0%** और लिंगानुपात **943**।

22. **सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात (2011):** राज्यों में सर्वाधिक लिंगानुपात **केरल (1084)** और न्यूनतम **हरियाणा (879)** में दर्ज किया गया।

23. **सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व (2011):** राज्यों में सर्वाधिक घनत्व **बिहार (1106 व्यक्ति/वर्ग किमी)** और न्यूनतम **अरुणाचल प्रदेश (17 व्यक्ति/वर्ग किमी)** में है।

24. **कुल प्रजनन दर (TFR — NFHS-5):** राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) घटकर **2.0** हो गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से कम है।

25. **जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend):** संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के अनुसार जब किसी देश की कुल जनसंख्या में कार्यशील आयु वर्ग (15 से 59/64 वर्ष) का अनुपात गैर-कार्यशील (आश्रित) जनसंख्या से अधिक होता है, तो उससे प्राप्त आर्थिक वृद्धि क्षमता को जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं।

26. **भारत में प्रवासन की सबसे बड़ी धारा:** जनगणना आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल आंतरिक प्रवासन में **'ग्रामीण से ग्रामीण' (Rural-to-Rural)** धारा का हिस्सा सर्वाधिक है (मुख्यतः विवाह के कारण महिला प्रवासन), जबकि पुरुषों में आर्थिक व रोजगार कारणों से 'ग्रामीण से शहरी' प्रवासन प्रमुख है।

27. **वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC):** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) के तहत प्रवासी श्रमिकों को बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (e-PoS) के माध्यम से देश की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन लेने की पोर्टेबिलिटी सुविधा देता है।

28. **पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi, 2020):** आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं (Street Vendors) को बिना गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण (₹10,000, ₹20,000 और ₹50,000 की तीन किस्तों में) उपलब्ध कराने की योजना है।

29. **ग्लोकलाइजेशन (Glocalization):** वैश्वीकरण के दौर में वैश्विक उत्पादों और विचारों का स्थानीय संस्कृति व आवश्यकताओं के अनुरूप ढल जाना 'ग्लोकलाइजेशन' कहलाता है (प्रतिपादक: रोलैंड रॉबर्टसन)।

30. **एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994):** सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मामले में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर रोक लगाई और **'पंथनिरपेक्षता' (Secularism)** को संविधान के मूल ढांचे का भाग घोषित किया।

31. **राज्य पुनर्गठन आयोग (1953):** न्यायमूर्ति **फजल अली** की अध्यक्षता में गठित आयोग (अन्य सदस्य: के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू) की सिफारिश पर 7वें संविधान संशोधन और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए।

32. **क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils):** राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत गठित 5 क्षेत्रीय परिषदें **सांविधिक निकाय** हैं और केंद्रीय **गृह मंत्री** इनके पदेन अध्यक्ष होते हैं।

33. **अंतर्राज्यीय परिषद (Inter-State Council):** संविधान के **अनुच्छेद 263** के तहत सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में राष्ट्रपति द्वारा गठित यह एक **संवैधानिक निकाय** है जिसके अध्यक्ष **प्रधानमंत्री** होते हैं।

34. **आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme, 2018):** नीति आयोग द्वारा जनवरी 2018 में देश के **112 सबसे कम विकसित जिलों** में स्वास्थ्य-पोषण (30%), शिक्षा (30%), कृषि-जल संसाधन (20%), वित्तीय समावेशन-कौशल (10%) और बुनियादी ढांचे (10%) में सुधार के लिए शुरू किया गया (2023 में 500 ब्लॉकों के लिए **'आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम'** शुरू हुआ)।

35. **अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद 17):** संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है; इसके प्रवर्तन हेतु संसद ने 'अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955' पारित किया जिसका नाम 1976 में बदलकर **'सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955'** कर दिया गया।

36. **SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:** अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और विशेष न्यायालयों (Special Courts) द्वारा त्वरित विचारण के लिए यह अधिनियम बनाया गया (2018 के संशोधन द्वारा धारा 18A जोड़कर बिना प्रारंभिक जांच के FIR और अग्रिम जमानत पर रोक बरकरार रखी गई)।

37. **मैनुअल स्कैवेंजिंग निषेध अधिनियम, 2013:** 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' शुष्क शौचालयों की सफाई व सीवर-सेप्टिक टैंक की जोखिमपूर्ण सफाई को प्रतिबंधित करता है; इसके मशीनीकरण के लिए **'नमस्ते' (NAMASTE)** योजना चलाई जा रही है।

38. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC):** संविधान के **अनुच्छेद 338** के तहत गठित संवैधानिक निकाय।

39. **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST): 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003** द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन कर **अनुच्छेद 338A** जोड़ा गया और 2004 में पृथक NCST अस्तित्व में आया।

40. **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC): 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018** द्वारा संविधान में **अनुच्छेद 338B** जोड़कर NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

41. **इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992 — मंडल केस):** सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की पीठ ने OBC के लिए 27% आरक्षण को वैध ठहराया, **'क्रीमी लेयर' (Creamy Layer)** को बाहर रखने का निर्देश दिया (राम नंदन समिति, 1993) और कुल आरक्षण की 50% सीमा निर्धारित की।

42. **रोहिणी आयोग (2017):** संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत न्यायमूर्ति **जी. रोहिणी** की अध्यक्षता में केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के **उप-वर्गीकरण (Sub-categorization)** की जांच के लिए आयोग गठित किया गया, जिसने 2023 में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

43. **103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 (EWS आरक्षण):** संविधान में **अनुच्छेद 15(6) और 16(6)** जोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया।

44. **104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2020:** अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC व ST के आरक्षण को 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया गया तथा आंग्ल-भारतीय समुदाय के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया।

45. **105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2021:** अनुच्छेद 338B, 342A और 366(26C) में संशोधन कर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की अपनी स्वयं की सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC/OBC) की सूची पहचानने और अधिसूचित करने की शक्ति बहाल की गई।

46. **वनाधिकार अधिनियम (FRA, 2006):** 'अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' जनजातियों और कम से कम **3 पीढ़ियों (75 वर्षों)** से वन भूमि पर निर्भर अन्य परंपरागत वनवासियों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार प्रदान करता है (नोडल मंत्रालय: **जनजातीय कार्य मंत्रालय**)।

47. **PVTG और पीएम-जनमन (PM-JANMAN):** ढेबर आयोग की सिफारिश पर चिह्नित **75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs)** को पक्का आवास, पेयजल, सड़क, शिक्षा व स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए नवंबर 2023 में 'प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान' शुरू किया गया।

48. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (1992):** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत गठित सांविधिक निकाय; भारत में भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है (अनुच्छेद 29 और 30 में केवल उल्लेख है)।

49. **सच्चर समिति (2005) और रंगनाथ मिश्र आयोग (2004):** भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन के लिए **न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर समिति (2005)** तथा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए **न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र आयोग** गठित किया गया था।

50. **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD Act, 2016):** इस अधिनियम ने दिव्यांगता श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर **21** किया और बेंचमार्क दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों में **4% आरक्षण** तथा उच्च शिक्षा में **5% आरक्षण** प्रदान किया।

51. **वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम, 2007:** 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007' बच्चों और कानूनी उत्तराधिकारियों पर वृद्ध माता-पिता के भरण-पोषण की कानूनी बाध्यता डालता है और प्रत्येक उप-खंड में अधिकरण (Tribunal) का प्रावधान करता है।

52. **नालसा निर्णय (2014) और ट्रांसजेंडर अधिनियम (2019):** सर्वोच्च न्यायालय ने **NALSA बनाम भारत संघ (2014)** में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 'तृतीय लिंग' (Third Gender) के रूप में संवैधानिक मान्यता दी, जिसके बाद संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 पारित किया।

53. **स्माइल योजना (SMILE Scheme):** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के व्यापक पुनर्वास के लिए **'SMILE' (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise)** योजना चलाई जा रही है।

54. **राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (NMPI):** नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के **3 आयामों और 12 संकेतकों** के आधार पर जारी किया जाता है।

55. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA, 2013):** यह देश की **67% जनसंख्या** (75% ग्रामीण और 50% शहरी) को कानूनी रूप से सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न (अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को **35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह** और प्राथमिकता वाले परिवारों को **5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह**) का अधिकार देता है।

56. **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY):** केंद्र सरकार ने NFSA के लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की इस योजना को 1 जनवरी 2024 से आगामी **5 वर्षों (दिसंबर 2028 तक)** के लिए बढ़ा दिया है।

57. **पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन, 2018):** कुपोषण, बौनेपन (Stunting), दुबलेपन (Wasting) और एनीमिया को कम करने के लिए **8 मार्च 2018** को राजस्थान के **झुंझुनू** से शुरू किया गया; वर्तमान में आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को मिलाकर **'सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0'** चलाया जा रहा है।

58. **आयुष्मान भारत (2018):** इसके तहत 1.5 लाख से अधिक उप-केंद्रों को **'आयुष्मान आरोग्य मंदिर'** (पूर्व नाम: हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर) में बदला गया है और **PM-JAY** (23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से शुरू) विश्व की सबसे बड़ी सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है (प्रति परिवार ₹5 लाख प्रतिवर्ष)।

59. **राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन:** जनजातीय आबादी में व्याप्त आनुवंशिक सिकल सेल रोग को वर्ष **2047** तक जड़ से समाप्त करने के लिए जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश के शहडोल से यह मिशन शुरू किया गया।

60. **शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A एवं RTE Act, 2009):** 86वें संविधान संशोधन (2002) द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 21A के तहत 'नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' **1 अप्रैल 2010** से लागू हुआ; इसकी **धारा 12(1)(c)** निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में कमजोर व वंचित वर्ग के बच्चों के लिए प्रवेश स्तर पर **25% सीटें** आरक्षित करती है।

61. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020):** डॉ. **के. कस्तूरीरंगन समिति** की सिफारिश पर आधारित NEP 2020 ने '5+3+3+4' स्कूली संरचना, कक्षा 5 तक मातृभाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षण, बहु-प्रवेश व निकास (Multiple Entry-Exit) के साथ 'अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (ABC) और एकल उच्च शिक्षा नियामक **HECI** का प्रावधान किया है।

62. **निपुण भारत मिशन (NIPUN Bharat, 2021):** शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य ग्रेड 3 के अंत तक (3 से 9 वर्ष के) प्रत्येक बच्चे में **मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy - FLN)** सुनिश्चित करना है।

63. **मनरेगा (MGNREGA, 2005):** ग्रामीण परिवारों के अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम **100 दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार** का कानूनी अधिकार देता है (महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 भागीदारी अनिवार्य और 15 दिन में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता)।

64. **सुशासन की अवधारणा (विश्व बैंक 1992):** विश्व बैंक ने 1992 की अपनी रिपोर्ट '*Governance and Development*' में विकास के लिए सुशासन (Good Governance) को अनिवार्य शर्त बताया।

65. **सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act, 2005):** संसद द्वारा जून 2005 में पारित यह अधिनियम **12 अक्टूबर 2005** से पूरे देश में लागू हुआ (इसने 'सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002' का स्थान लिया)।

66. **RTI अपीलीय संरचना:** प्रथम अपील जन सूचना अधिकारी (PIO) से वरिष्ठ विभागीय अधिकारी को 30 दिन में की जाती है, और **द्वितीय अपील** केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग को 90 दिनों के भीतर की जाती है।

67. **नागरिक चार्टर का जन्मदाता देश:** लोक सेवाओं में **'सिटीजन चार्टर'** की शुरुआत सबसे पहले वर्ष **1991 में ग्रेट ब्रिटेन** के प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने की थी; भारत में इसे मई 1997 में अपनाया गया।

68. **लोक सेवा गारंटी अधिनियम (2010):** सिटीजन चार्टर को कानूनी बाध्यता देते हुए नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में लोक सेवाएं प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य **मध्य प्रदेश (2010)** बना, जिसके बाद बिहार (2011) और राजस्थान सहित 20 से अधिक राज्यों ने इसे अपनाया।

69. **CPGRAMS पोर्टल:** प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा विकसित **'केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली' (CPGRAMS)** एक 24x7 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को किसी भी केंद्रीय व राज्य विभाग के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने और 21 दिनों में निवारण की सुविधा देता है।

70. **मेघालय सोशल ऑडिट अधिनियम (2017): मेघालय** सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) को कानून का हिस्सा बनाने वाला भारत का पहला राज्य है।

71. **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP, 2006):** 18 मई 2006 को अनुमोदित इस योजना की परिकल्पना "सभी सरकारी सेवाओं को आम आदमी को उसके इलाके में कॉमन सर्विस डिलीवरी आउटलेट के माध्यम से सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराना" थी।

72. **डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ (2015):** ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई-गवर्नेंस (प्रौद्योगिकी द्वारा सरकार में सुधार), ई-क्रांति, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नौकरियों के लिए आईटी और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम।

73. **JAM ट्रिनिटी और DBT:** भारत सरकार ने 1 जनवरी 2013 से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) शुरू किया और आर्थिक सर्वेक्षण 2014–15 में **JAM ट्रिनिटी (Jan Dhan - Aadhaar - Mobile)** की संकल्पना प्रस्तुत की।

74. **एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI, 2016):** भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (**NPCI — भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की पहल, 2008**) द्वारा वर्ष **2016** में लॉन्च किया गया UPI आज विश्व का सबसे बड़ा रीयल-टाइम डिजिटल भुगतान तंत्र है।

75. **ONDC (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स):** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के **DPIIT** की पहल पर स्थापित ONDC एक गैर-लाभकारी ओपन-सोर्स नेटवर्क है जो छोटे दुकानदारों को बड़े ई-कॉमर्स एकाधिकारों से मुक्त कर डिजिटल बाजार से जोड़ता है।

76. **भाषिणी (BHASHINI):** राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP) का उपयोग कर सभी भारतीय भाषाओं में आवाज-आधारित इंटरनेट व डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने का मंच है।

77. **पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017):** सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि **'निजता का अधिकार' (Right to Privacy)** संविधान के **अनुच्छेद 21** (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता) के तहत मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है।

78. **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act, 2023):** न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा समिति (2018) की पृष्ठभूमि के बाद अगस्त 2023 में अधिनियमित यह कानून व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए सहमति, डेटा फिड्यूशियरी के दायित्व और 'भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड' की स्थापना का प्रावधान करता है।

79. **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और CERT-In:** भारत में साइबर अपराधों और ई-कॉमर्स को कानूनी मान्यता देने के लिए **IT Act, 2000** (2008 में संशोधित) बनाया गया; इसकी धारा 70B के तहत **CERT-In (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल)** साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने वाली राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।

80. **अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन (अनुच्छेद 312):** यदि **राज्यसभा** उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम **दो-तिहाई (2/3) बहुमत** से राष्ट्रहित में संकल्प पारित करे, तो संसद कानून द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है।

81. **संघ और राज्य लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315–323):** संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से 323 तक UPSC और SPSC के गठन, नियुक्ति और स्वतंत्रता का प्रावधान है (UPSC अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल: **6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु**; SPSC के लिए: **6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु**)।

82. **केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT, 1985):** 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा जोड़े गए **अनुच्छेद 323A** के तहत लोक सेवकों के भर्ती और सेवा संबंधी विवादों के त्वरित निपटारे के लिए **प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985** द्वारा CAT की स्थापना की गई।

83. **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC, 2005):** 31 अगस्त 2005 को **वीरप्पा मोइली** की अध्यक्षता में गठित द्वितीय ARC ने शासन के विभिन्न पहलुओं पर कुल **15 रिपोर्टें** प्रस्तुत कीं (प्रथम रिपोर्ट: *Right to Information: Master Key to Good Governance*, चतुर्थ रिपोर्ट: *Ethics in Governance*)।

84. **मिशन कर्मयोगी (NPCSCB, 2020):** सिविल सेवकों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने और उन्हें 'नियम-उन्मुख' से 'भूमिका-उन्मुख' बनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद और **iGOT Karmayogi** डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है।

85. **केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC): के. संथानम समिति (1962–64)** की सिफारिश पर फरवरी 1964 में गठित CVC को वर्ष **2003** में संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया (प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त: **एन. श्रीनिवास राव**)।

86. **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013:** इस अधिनियम के तहत केंद्र में **लोकपाल** और राज्यों में **लोकायुक्त** के गठन का प्रावधान है; भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष **न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष** (मार्च 2019) नियुक्त किए गए थे।

87. **व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014:** सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग या अनियमितता का पर्दाफाश करने वाले मुखबिरों (Whistleblowers) की पहचान गुप्त रखने और उन्हें प्रतिशोध से बचाने के लिए यह अधिनियम बनाया गया (इसमें CVC सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है)।

88. **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA, 2002):** काले धन को वैध बनाने (Money Laundering) को रोकने और अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए PMLA, 2002 (1 जुलाई 2005 से लागू) बनाया गया, जिसका प्रवर्तन वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन **प्रवर्तन निदेशालय (ED)** करता है।

89. **भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA):** ₹100 करोड़ या उससे अधिक के आर्थिक अपराध में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भारतीय न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए देश छोड़कर भागने वाले अपराधियों की देश-विदेश स्थित समस्त संपत्तियों को बिना दोषसिद्धि के तुरंत जब्त करने का अधिकार देता है।

90. **प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006 — पुलिस सुधार):** सर्वोच्च न्यायालय ने इस ऐतिहासिक मामले में पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त करने के लिए 7 **बाध्यकारी निर्देश** जारी किए, जिनमें राज्य सुरक्षा आयोग का गठन, DGP का न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल और विवेचना (Investigation) को कानून-व्यवस्था (Law & Order) से अलग करना शामिल है।

91. **कंपनी अधिनियम, 2013 और CSR (धारा 135):** भारत विश्व के उन पहले देशों में से है जिसने **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135** के तहत पात्र कंपनियों के लिए अपने पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम **2% 'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व' (CSR)** गतिविधियों (शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण आदि) पर खर्च करना कानूनी रूप से अनिवार्य किया है।

92. **विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA, 2010 एवं संशोधन 2020):** गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित इस कानून में 2020 के संशोधन द्वारा लोक सेवकों के विदेशी अंशदान लेने पर रोक लगाई गई, FCRA पंजीकरण व नवीनीकरण के लिए पदाधिकारियों का **आधार नंबर अनिवार्य** किया गया और प्रशासनिक व्यय की सीमा 50% से घटाकर **20%** कर दी गई।

93. **NGO-DARPAN पोर्टल:** नीति आयोग द्वारा संचालित यह पोर्टल देश भर के स्वैच्छिक संगठनों (VOs) और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) तथा सरकारी मंत्रालयों के बीच एक पारदर्शी इंटरफेस प्रदान करता है।

94. **SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (1992): एस.के. कालिया समिति** की सिफारिश पर **नाबार्ड (NABARD)** द्वारा 1992 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया यह कार्यक्रम आज विश्व की सबसे बड़ी सूक्ष्म-वित्त (Microfinance) पहल बन चुका है।

95. **लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी पहल:** ग्रामीण विकास मंत्रालय की **'लखपति दीदी'** योजना का लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की **3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं** को कौशल प्रशिक्षण देकर प्रतिवर्ष कम से कम **₹1 लाख की स्थायी आय** अर्जित करने में सक्षम बनाना है, जबकि **'नमो ड्रोन दीदी'** योजना के तहत 15,000 महिला SHGs को कृषि कार्य (तरल उर्वरक व कीटनाशक छिड़काव) के लिए ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

96. **सहकारिता मंत्रालय एवं 97वां संविधान संशोधन (2011): 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011** द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देते हुए अनुच्छेद 19(1)(c) में मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 43B में नीति निदेशक तत्व और संविधान में नया **भाग IXB (अनुच्छेद 243ZH से 243ZT)** जोड़ा गया; जुलाई 2021 में "सहकार से समृद्धि" के विजन को साकार करने के लिए पृथक **केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय** का गठन किया गया।

97. **73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (पंचायती राज):** संविधान में **भाग IX** और **11वीं अनुसूची (29 विषय)** जोड़ी गई; **अनुच्छेद 243D** के तहत सभी स्तरों पर SC/ST को जनसंख्या के अनुपात में और **महिलाओं को कम से कम 1/3 (33%) आरक्षण** (अध्यक्ष पदों सहित) अनिवार्य किया गया।

98. **74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (नगरपालिकाएं):** संविधान में **भाग IXA (अनुच्छेद 243P से 243ZG)** और **12वीं अनुसूची (18 विषय)** जोड़ी गई; इसमें **अनुच्छेद 243ZD** के तहत **'जिला योजना समिति' (DPC)** और **अनुच्छेद 243ZE** के तहत **'महानगर योजना समिति' (MPC)** के गठन का संवैधानिक प्रावधान किया गया।

99. **स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme, 2020):** पंचायती राज मंत्रालय द्वारा **24 अप्रैल 2020** (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस) को शुरू की गई इस योजना में ड्रोन तकनीक से ग्रामीण आबादी (Abadi) भूमि का सर्वेक्षण कर ग्रामीण गृहस्वामियों को कानूनी **'संपत्ति कार्ड' (Property Cards / घरौनी)** प्रदान किए जाते हैं।

100. **नीति आयोग (NITI Aayog — 1 जनवरी 2015):** 15 मार्च 1950 को गठित योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा **1 जनवरी 2015** को भारत सरकार के शीर्ष पॉलिसी 'थिंक टैंक' के रूप में **नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान)** की स्थापना की गई, जो 'टॉप-डाउन' के स्थान पर **'बॉटम-अप' (Bottom-up)** दृष्टिकोण तथा **सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद** के सिद्धांत पर कार्य करता है (**नीति आयोग**)।

2.0 पुस्तक 28 का गहन अकादमिक ऑडिट एवं अपग्रेड मैट्रिक्स

IUC Academy (www.iucacademy.com) की पुस्तक 28 (भारतीय समाज, सामाजिक न्याय एवं अभिशासन) का संघ लोक सेवा आयोग (UPSC CSE GS-I एवं GS-II), राज्य लोक सेवा आयोगों (UPPSC, BPSC), UGC-NET (Sociology / Public Administration / Political Science) तथा DSSSB PGT के नवीनतम पाठ्यक्रम व 2019–2026 के प्रश्नों के आलोक में गहन ऑडिट किया गया। प्रमुख सुधार एवं संवर्द्धन नीचे प्रस्तुत हैं:

क्र.सं.	विषय क्षेत्र (Domain)	पूर्व संस्करण की स्थिति (Audit Gap)	अपग्रेड संस्करण में जोड़े गए उन्नत बिंदु (Upgraded Additions)	परीक्षा प्रासंगिकता
1	भारतीय जाति एवं परिवार व्यवस्था	पारंपरिक विशेषताओं का सामान्य वर्णन	एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुर्ये, लुई ड्यूमों, आंद्रे बेतेई व ए.एम. शाह के समाजशास्त्रीय सिद्धांत; अंतर-जातीय, अंतर-पीढ़ीगत व डिजिटल युग के परिवर्तन	UPSC GS-I, UGC-NET Sociology, UPPSC
2	महिला सुरक्षा एवं विधिक ढाँचा	पुरानी IPC धाराओं का उल्लेख	भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) की नई धाराएँ (धारा 63–99), 106वाँ संविधान संशोधन (2023), POSH Act 2013, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 व MTP संशोधन 2021	UPSC GS-I & II, BPSC, NDA/CDS
3	जनसांख्यिकीय लाभांश एवं प्रवासन	2011 की जनगणना के सामान्य आँकड़े	NFHS-5 (TFR 2.0), प्रजनन प्रतिस्थापन स्तर, 'सिल्वर इकॉनमी' (वृद्धजन डेटा), आंतरिक प्रवासन की 4 धाराएँ, नारीकरण व ONORC/ई-श्रम एकीकरण	UPSC CSE, UPPSC, UGC-NET
4	ई-गवर्नेंस, सेवोत्तम, RTI व लोकपाल	योजनाओं का संक्षिप्त परिचय	India Stack (DPI), सेवोत्तम (IS 15700) के 3 स्तंभ व 7 चरण, RTI संशोधन 2019, DPDP Act 2023 का प्रभाव एवं लोकपाल अधिनियम 2013 का न्यायिक विश्लेषण	UPSC GS-II, GS-IV, UGC-NET PubAd
5	संवेदनशील वर्गों की कल्याणकारी योजनाएँ	पुरानी योजनाओं की सूची	PM-JANMAN, धरती आबा अभियान, PM-AJAY, SHRESHTA, PM-YASASVI, NAMASTE, SMILE, AVYAY तथा SC उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का 2024 का निर्णय	UPSC CSE Prelims & Mains, State PCS

2.1 उन्नत गहन अध्ययन मॉड्यूल (5 New Advanced Deep-Study Modules — Book 28)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 2.1 उन्नत गहन अध्ययन मॉड्यूल (5 New Advanced Deep-Study Modules — Book 28)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
मॉड्यूल 1: भारतीय जाति व परिवार व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन (Modern Transformations in Indian Caste & Family System)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
मॉड्यूल 2: महिलाओं के विरुद्ध अपराध, संवैधानिक प्रावधान व विधिक सुरक्षा ढाँचा (Crimes Against Women & Legal Safeguards)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
मॉड्यूल 3: जनसांख्यिकीय लाभांश, प्रजनन संक्रमण व प्रवासन डेटा विश्लेषण (Demographic Dividend & Migration Data Analysis)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
मॉड्यूल 4: ई-गवर्नेंस मॉडल, DPI, सेवोत्तम, नागरिक चार्टर, RTI एवं लोकपाल (E-Governance, Sevottam, RTI & Lokpal)

मॉड्यूल 1: भारतीय जाति व परिवार व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन (Modern Transformations in Indian Caste & Family System)

(क) जाति व्यवस्था का समाजशास्त्रीय सैद्धांतिक ढाँचा एवं आधुनिक रूपांतरण

1. *जी.एस. घुर्ये (*G.S. Ghurye* — Caste and Race in India, 1932): **घुर्ये ने पारंपरिक जाति व्यवस्था की** 6 मुख्य विशेषताएँ* बताईं—

- (i) समाज का खंडात्मक विभाजन (Segmental division of society),
- (ii) संस्तरण या पदानुक्रम (Hierarchy),

• (iii) भोजन एवं सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध (Restrictions on feeding and social intercourse),

• (iv) नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएँ तथा विशेषाधिकार (Civil and religious disabilities and privileges),

• (v) पेशे के स्वतंत्र चुनाव का अभाव (Lack of unrestricted choice of occupation), और

• (vi) अंतर्विवाह (Endogamy — जिसे घुर्ये ने जाति व्यवस्था का केंद्रीय सार माना)।

2. **एम.एन. श्रीनिवास (M.N. Srinivas) की गतिशीलता की अवधारणाएँ:**

• *संस्कृतिकरण (*Sanskritization* — Religion and Society among the Coorgs of South India, 1952): **वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति किसी उच्च और प्रायः 'द्विज' जाति के रीति-रिवाजों, कर्मकांडों, विचारधारा और जीवन-शैली का अनुकरण कर दो-तीन पीढ़ियों में जातीय पदानुक्रम में उच्च स्थान का दावा करती है। यह** 'संरचनात्मक परिवर्तन' (*Structural change*) **नहीं बल्कि केवल** 'पदगत परिवर्तन' (*Positional change*)* लाती है।

• **पश्चिमीकरण (Westernization):** 150 वर्षों के ब्रिटिश शासन के परिणामस्वरूप भारतीय समाज की प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, विचारधारा और मूल्यों (मानवतावाद, समतावाद, तर्कवाद) में आया परिवर्तन।

• **प्रभु जाति (Dominant Caste — रामपुरा गाँव अध्ययन, 1955):** कोई जाति किसी क्षेत्र में 'प्रभु जाति' तब कहलाती है जब उसके पास— (1) स्थानीय कृषि योग्य भूमि का बड़ा हिस्सा हो, (2) संख्यात्मक शक्ति अधिक हो, (3) स्थानीय अनुष्ठानिक पदानुक्रम में अपेक्षाकृत उच्च या मध्यम स्थान हो, और (4) आधुनिक शिक्षा व प्रशासनिक पदों तक पहुँच हो (जैसे— कर्नाटक में वोक्कालिगा व लिंगायत, आंध्र में रेड्डी व कम्मा, उत्तर भारत में जाट, यादव, कुर्मी, मराठा आदि)।

• **धर्मनिरपेक्षीकरण (Secularization):** जाति के कर्मकांडीय शुद्धता-प्रदूषण (*Purity and Pollution*) के आयाम का कमजोर पड़ना और शिक्षा, रोजगार व नागरिक जीवन में तर्कसंगत मानदंडों का बढ़ना।

3. **लुई ड्यूमों बनाम आंद्रे बेतेई एवं रजनी कोठारी:**

• *लुई ड्यूमों (Homo Hierarchicus, 1966):* भारतीय जाति व्यवस्था को 'शुद्धता और अशुद्धता' (Pure and Impure) के वैचारिक द्विभाजन पर आधारित एक अनूठी पदानुक्रमिक व्यवस्था माना जहाँ प्रस्थिति (Status) शक्ति (Power) से ऊपर है।

• *आंद्रे बेतेई (Caste, Class and Power, 1965 — तंजौर के श्रीपुरम गाँव का अध्ययन): **सिद्ध किया कि आधुनिक भारत में भूमि सुधार, लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था के कारण 'जाति, वर्ग और शक्ति' का पारंपरिक संकेंद्रण टूट रहा है और यह 'संचयी असमानता' (*Cumulative Inequality*) से** 'बिखरी हुई असमानता' (*Dispersed Inequality*)* की ओर बढ़ रहा है।

• *रजनी कोठारी (Caste in Indian Politics, 1970): "यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो रही है, बल्कि यह जाति है जो राजनीतिकृत (Politicization of Caste) हो रही है।"* जाति संघों (Caste Associations) ने पारंपरिक अनुष्ठानिक भूमिका छोड़कर आधुनिक दबाव समूहों, शैक्षणिक ट्रस्टों और चुनावी गठबंधनों का रूप ले लिया है।

(ख) भारतीय परिवार और विवाह व्यवस्था में संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक परिवर्तन

• **संयुक्त परिवार से नाभिकीय एवं संशोधित विस्तारित परिवार की ओर:**

• *इरावती कर्वे (Kinship Organization in India, 1953):* संयुक्त परिवार को एक ही छत के नीचे रहने वाले, एक रसोई में पका भोजन करने वाले, साझा संपत्ति रखने वाले और सामान्य पारिवारिक पूजा में भाग लेने वाले समूह के रूप में परिभाषित किया।

• **आई.पी. देसाई (महुआ अध्ययन) एवं के.एम. कपाड़िया:** इन्होंने सिद्ध किया कि भारत में औद्योगीकरण और नगरीकरण ने संयुक्त परिवार की 'आवासीय एकता' को भले ही कम किया हो, किंतु **'प्रकार्यात्मक संयुक्तता' (Functional Jointness)** और आपसी दायित्व की भावना आज भी बनी हुई है।

• *ए.एम. शाह (The Household Dimension of the Family in India):* जनगणना और समाजशास्त्रीय साक्ष्यों से स्पष्ट किया कि भारत में 'गृहस्थी' (Household) का औसत आकार घटा है, किंतु बुजुर्ग माता-पिता के साथ रहने की प्रवृत्ति के कारण 'अनुपूरक एकल परिवार' (Supplemented Nuclear Family) बढ़ रहे हैं।

• **समकालीन परिवर्तन के प्रमुख आयाम:**

1. **सत्ता संरचना का लोकतंत्रीकरण:** पितृसत्तात्मक 'कर्ता' के एकछत्र अधिकार के स्थान पर पति-पत्नी और वयस्क बच्चों की सहभागी निर्णय-प्रक्रिया (*Filial Democracy*)।

2. **विवाह के स्वरूप में बदलाव:** मैट्रिमोनियल पोर्टल्स के माध्यम से 'चयनित अरेंज्ड मैरिज' (*Assisted/Semi-Arranged Marriages*), अंतर-जातीय एवं अंतर-धार्मिक विवाहों में वृद्धि (विशेष विवाह अधिनियम, 1954), विवाह की औसत आयु में वृद्धि।

3. **नवीन पारिवारिक रूप:** दोहरी आय वाले दंपति (*Dual-Career Families*), एकल अभिभावक परिवार (*Single-Parent Families*), DINK (*Double Income No Kids*), लिव-इन रिलेशनशिप (जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रा सरमा बनाम वी.के.वी. सरमा, 2013 तथा लता सिंह वाद में अनुच्छेद 21 व घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सीमित कानूनी संरक्षण दिया है)।

4. **देखभाल का संकट (Crisis of Care):** कामकाजी दंपतियों के कारण शिशु देखभाल (*Crèche* की आवश्यकता) तथा अकेले रहने वाले वृद्धजनों (*Empty Nest Syndrome*) की भावनात्मक व स्वास्थ्य सुरक्षा की चुनौती।

मॉड्यूल 2: महिलाओं के विरुद्ध अपराध, संवैधानिक प्रावधान व विधिक सुरक्षा ढाँचा (Crimes Against Women & Legal Safeguards)

(क) संवैधानिक सुरक्षा कवच (Constitutional Matrix for Women)

• **मूल अधिकार: अनुच्छेद 14** (विधि के समक्ष समता), **अनुच्छेद 15(1)** (लिंग के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध), **अनुच्छेद 15(3)** (महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की राज्य की शक्ति — सकारात्मक विभेद), **अनुच्छेद 16(2)** (लोक नियोजन में अवसर की समता), **अनुच्छेद 21** (गरिमापूर्ण जीवन एवं प्रजनन चयन का अधिकार — सुचिता श्रीवास्तव वाद, 2009 व एक्स बनाम प्रमुख सचिव स्वास्थ्य दिल्ली, 2022), **अनुच्छेद 23** (मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध)।

• **नीति निदेशक तत्व (DPSP) एवं मूल कर्तव्य: अनुच्छेद 39(a)** (समान आजीविका के साधन), **अनुच्छेद 39(d)** (पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन), **अनुच्छेद 39(e)** (श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न होना), **अनुच्छेद 42** (प्रसूति सहायता और काम की न्यायसंगत व मानवोचित दशाएँ), **अनुच्छेद 51A(e)** (स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना)।

• **राजनीतिक प्रतिनिधित्व: अनुच्छेद 243D एवं 243T** (पंचायती राज और नगरपालिकाओं में महिलाओं को न्यूनतम एक-तिहाई आरक्षण; कई राज्यों में 50%) तथा **106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम)** — जिसके द्वारा **अनुच्छेद 330A** (लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण), **अनुच्छेद 332A** (राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण) और **अनुच्छेद 239AA** (दिल्ली विधानसभा में 33% आरक्षण) जोड़े गए (परिसीमन के पश्चात 15 वर्षों के लिए प्रभावी — अनुच्छेद 334A)।

(ख) भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 एवं प्रमुख महिला-केंद्रित विधान (1 जुलाई 2024 से प्रभावी अद्यतन ढाँचा)

कानून / संहिता	प्रमुख धाराएँ / प्रावधान	मुख्य विधिक सुरक्षा एवं दंड प्रावधान	ऐतिहासिक महत्व / न्यायिक संदर्भ
भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 (अध्याय V: महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध)	**धारा 63–73:** बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार; **धारा 69:** शादी का झांसा देकर यौन संबंध; **धारा 74–79:** शील भंग, यौन उत्पीड़न, ताक-झांक (Voyeurism), पीछा करना (Stalking — धारा 78); **धारा 80:** दहेज मृत्यु; **धारा 85–86:** पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (पूर्व IPC 498A)	18 वर्ष से कम आयु की बालिका से सामूहिक बलात्कार पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास (धारा 70(2)); विवाह के झूठे वादे या पहचान छिपाकर यौन संबंध को पहली बार पृथक अपराध (धारा 69 — 10 वर्ष तक कारावास) बनाया गया	महिला एवं बाल अपराधों को संहिता में प्राथमिकता देते हुए एकीकृत अध्याय V में रखा गया; इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ (2017) के अनुरूप नाबालिग पत्नी के साथ संबंध भी अपराध
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH Act)	10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर **आंतरिक शिकायत समिति (ICC)** और जिला स्तर पर असंगठित क्षेत्र/10 से कम कर्मचारियों हेतु **स्थानीय शिकायत समिति (LCC)** का गठन	ICC की अध्यक्ष वरिष्ठ महिला कर्मचारी होगी, आधे सदस्य महिलाएँ होंगी और एक बाहरी NGO सदस्य अनिवार्य है; 90 दिनों के भीतर जांच पूर्ण करना अनिवार्य; 'शी-बॉक्स' (SHe-Box) ऑनलाइन पोर्टल	विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 14, 19(1)(g), 21 और CEDAW अभिसमय के तहत जारी दिशा-निर्देशों को वैधानिक रूप दिया गया

कानून / संहिता	प्रमुख धाराएँ / प्रावधान	मुख्य विधिक सुरक्षा एवं दंड प्रावधान	ऐतिहासिक महत्व / न्यायिक संदर्भ
घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA)	शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और **आर्थिक दुर्व्यवहार** को पहली बार व्यापक रूप से परिभाषित किया गया	'साझा गृहस्थी' (Shared Household) में निवास का अधिकार, संरक्षण आदेश, मौद्रिक राहत और अभिरक्षा आदेश; संरक्षण अधिकारी (Protection Officer) की नियुक्ति; यह मुख्यतः एक दीवानी (Civil) कानून है किंतु संरक्षण आदेश का उल्लंघन दंडनीय अपराध है	सतीश चंद्र आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा (2020) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बहू को ससुराल के 'साझा घर' में रहने का अधिकार है, भले ही घर पर पति का एकल स्वामित्व न हो
मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017	1961 के मूल अधिनियम में संशोधन; 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू	प्रथम दो जीवित बच्चों के लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश **12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह** किया गया; दत्तक (गोद लेने वाली) और कमीशनिंग (सरोगेसी) माताओं के लिए 12 सप्ताह का अवकाश; 50+ कर्मचारियों वाले संस्थानों में **क्रेच (Crèche)** सुविधा अनिवार्य	औपचारिक क्षेत्र में महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (MTP Amendment Act)	1971 के MTP अधिनियम में संशोधन	एक डॉक्टर की राय से गर्भपात की सीमा 12 से बढ़ाकर **20 सप्ताह** और विशेष श्रेणियों (बलात्कार पीड़िता, नाबालिग, दिव्यांग, वैवाहिक स्थिति में बदलाव, भ्रूण विकृति) के लिए दो डॉक्टरों की राय से **20 से 24 सप्ताह** की गई; मेडिकल बोर्ड की मंजूरी से भ्रूण विकृति में 24 सप्ताह के बाद भी अनुमति	अविवाहित महिलाओं को भी गर्भनिरोधक विफलता के आधार पर 24 सप्ताह तक सुरक्षित गर्भपात का समान अधिकार (*X vs Principal Secretary Health*, 2022)
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006	दहेज लेना, देना या मांगना दंडनीय; बाल विवाह (लड़की <18 वर्ष, लड़का <21 वर्ष) शून्यकरणीय (Voidable) और अपहरण/धोखे की स्थिति में शून्य (Void)	दहेज मामलों में सबूत का भार (Burden of Proof — भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118, पूर्व धारा 113B) अभियुक्त पर होता है यदि विवाह के 7 वर्ष के भीतर संदिग्ध मृत्यु हो	सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध निवारक एवं दंडात्मक कवच

मॉड्यूल 3: जनसांख्यिकीय लाभांश, प्रजनन संक्रमण व प्रवासन डेटा विश्लेषण (Demographic Dividend & Migration Data Analysis)

(क) भारत का जनसांख्यिकीय संक्रमण एवं NFHS-5 के मुख्य संकेतक

जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend): संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के अनुसार जब किसी देश में प्रजनन दर और मृत्यु दर में गिरावट के कारण आश्रित जनसंख्या (0–14 वर्ष और 60/65+ वर्ष) की तुलना में **कार्यशील आयु वर्ग (15–59 वर्ष या 15–64 वर्ष)** की जनसंख्या का अनुपात बढ़ जाता है, तो उससे उत्पन्न आर्थिक विकास की क्षमता को 'जनसांख्यिकीय लाभांश' कहते हैं। भारत में यह स्वर्णिम खिड़की (*Window of Opportunity*) **2018 से 2055 (लगभग 37 वर्ष)** तक खुली है, और भारत की मध्यिका आयु (Median Age) लगभग **28.4–29 वर्ष** है।

जनसांख्यिकीय / स्वास्थ्य संकेतक	NFHS-4 (2015–16)	NFHS-5 (2019–21)	नीतिगत निहितार्थ एवं परीक्षा विश्लेषण
कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate — TFR)	2.2 बच्चे प्रति महिला	**2.0 बच्चे प्रति महिला** (शहरी: 1.6, ग्रामीण: 2.1)	भारत ने प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर (**Replacement Level TFR = 2.1**) से नीचे का ऐतिहासिक स्तर प्राप्त कर लिया है (केवल बिहार 3.0, मेघालय 2.9, यूपी 2.4, झारखंड 2.3 और मणिपुर 2.2 ही 2.1 से ऊपर हैं)
जन्म के समय लिंगानुपात (SRB — पिछले 5 वर्ष)	919	**929** प्रति 1000 बालक	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और PC-PNDT अधिनियम के प्रवर्तन से सुधार, किंतु प्राकृतिक अनुपात (~952) से अभी भी कम
संस्थागत प्रसव (Institutional Births)	78.9%	**88.6%**	जननी सुरक्षा योजना और आभा/आयुष्मान भारत के विस्तार से मातृ मृत्यु अनुपात (MMR: 97 प्रति लाख जीवित जन्म — SRS) में तीव्र गिरावट
बच्चों में बौनापन (Stunting — 5 वर्ष से कम)	38.4%	**35.5%** (कम वजन: 32.1%, दुबलापन/Wasting: 19.3%)	कुपोषण में कमी आई है, किंतु 6–59 माह के बच्चों में **एनीमिया (67.1%)** और महिलाओं में एनीमिया (57.0%) अभी भी गंभीर चुनौती है

जनसांख्यिकीय / स्वास्थ्य संकेतक	NFHS-4 (2015–16)	NFHS-5 (2019–21)	नीतिगत निहितार्थ एवं परीक्षा विश्लेषण
आधुनिक गर्भनिरोधक प्रसार दर (mCPR)	47.8%	**56.5%**	परिवार नियोजन की अपूर्ण आवश्यकता (Unmet Need) घटकर 9.4% रह गई है

(ख) वृद्ध होती जनसंख्या (Ageing Population) और 'सिल्वर इकॉनमी' (Silver Economy)

• **UNFPA 'India Ageing Report 2023'** के अनुसार भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वृद्धजनों की हिस्सेदारी 2022 के **10.5% (14.9 करोड़)** से बढ़कर ***2050 तक 20.8% (34.7 करोड़)*** हो जाएगी।

• **दक्षिण बनाम उत्तर का जनसांख्यिकीय अंतराल:** केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में TFR बहुत पहले गिरने के कारण वहाँ वृद्ध जनसंख्या का अनुपात तेजी से बढ़ रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में युवा कार्यबल का घनत्व अधिक है।

• **वृद्धजन की तिहरी संवेदनशीलता:** (1) **वृद्धावस्था का नारीकरण (Feminization of Ageing)** — महिलाओं की उच्च जीवन प्रत्याशा के कारण वृद्ध विधवाओं की संख्या अधिक है जिनके पास संपत्ति या पेंशन नहीं है, (2) **ग्रामीणीकरण (Ruralization)** — युवाओं के शहरों में प्रवासन के कारण गाँवों में बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं, और (3) जराचिकित्सा (Geriatric healthcare) की कमी।

(ग) भारत में प्रवासन (Migration): धाराएँ, कारण और नीतिगत पहल

1. **आंतरिक प्रवासन की चार धाराएँ (जनगणना एवं NSSO/PLFS पैटर्न):**

• **ग्रामीण से ग्रामीण (Rural-to-Rural):** कुल आंतरिक प्रवासन का **सबसे बड़ा हिस्सा (~47–50%)**; इसमें महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है जिसका मुख्य कारण **विवाह-आधारित प्रवासन** है।

• **ग्रामीण से शहरी (Rural-to-Urban): पुरुष प्रवासन** में सबसे प्रमुख धारा, जिसका मुख्य कारण रोजगार, कृषि संकट और बेहतर मजदूरी है।

• **शहरी से शहरी (Urban-to-Urban):** सेवा क्षेत्र, उच्च शिक्षा और कॉर्पोरेट स्थानांतरण से प्रेरित।

• **शहरी से ग्रामीण (Urban-to-Rural):** सेवानिवृत्ति या कोविड-19 जैसी आपदाओं के समय 'रिवर्स माइग्रेशन'।

2. **पुश (Push — धकेलने वाले) बनाम पुल (Pull — आकर्षित करने वाले) कारक:**

• **पुश कारक:** जोत का घटता आकार (औसत 1.08 हेक्टेयर), प्रच्छन्न बेरोजगारी, मानसून की अनिश्चितता/बाढ़-सूखा, ग्रामीण ऋणग्रस्तता और जातिगत उत्पीड़न।

• **पुल कारक:** शहरी निर्माण व गिग इकॉनमी में नकद मजदूरी, बेहतर स्वास्थ्य-शिक्षा सुविधाएँ और सामाजिक गुमनामी (जातिगत बंधनों से मुक्ति)।

3. **प्रवासी श्रमिकों के लिए कल्याणकारी एवं संस्थागत तंत्र:**

• **वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC):** NFSA, 2013 के तहत बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण द्वारा देश में कहीं भी राशन की पोर्टेबिलिटी।

• **ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal):** असंगठित क्षेत्र के 30 करोड़+ श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस और 12-अंकीय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN)।

• **अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979** का **व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता (OSH Code), 2020** में समामेलन।

मॉड्यूल 4: ई-गवर्नेंस मॉडल, DPI, सेवोत्तम, नागरिक चार्टर, RTI एवं लोकपाल (E-Governance, Sevottam, RTI & Lokpal)

(क) ई-गवर्नेंस के 4 मॉडल एवं भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI / India Stack)

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की *11वीं रिपोर्ट ("Promoting e-Governance: The SMART Way Forward") **के अनुसार ई-गवर्नेंस का उद्देश्य शासन को** *SMART* **(*Simple, Moral, Accountable, Responsive,* T*ransparent)** बनाना है।

ई-गवर्नेंस मॉडल	संपर्क की प्रकृति	प्रमुख भारतीय उदाहरण (Real-World Initiatives)	मुख्य लाभ एवं प्रभाव
1. G2C (सरकार से नागरिक)	नागरिकों को सीधे सार्वजनिक सेवाएँ, प्रमाण-पत्र व सब्सिडी प्रदान करना	**UMANG ऐप**, **DigiLocker**, **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT / JAM Trinity)**, **CPGRAMS**, **ई-संजीवनी (टेलीमेडिसिन)**, **भूमि/भूलेख पोर्टल**	बिचौलियों (Middlemen) की समाप्ति, 24×7 सेवा उपलब्धता और सब्सिडी रिसाव की रोकथाम
2. G2B (सरकार से व्यवसाय)	उद्योगों व व्यापारियों के लिए लाइसेंस, कर भुगतान, खरीद और अनुपालन को सुगम बनाना	**GeM (Government e-Marketplace)**, **MCA21**, **GSTN पोर्टल**, **ई-बिज़ (e-Biz)**, **राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS)**, **ONDC**	'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' में सुधार, सरकारी खरीद में पारदर्शिता और MSMEs की बाजार पहुँच
3. G2G (सरकार से सरकार)	केंद्र, राज्यों और विभिन्न विभागों के बीच डेटा साझाकरण एवं फाइल संचालन	**ई-ऑफिस (e-Office)**, **PRAGATI** (प्रधानमंत्री द्वारा परियोजनाओं की रियल-टाइम समीक्षा), **CCTNS (अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क)**, **PFMS**	अंतर-विभागीय समन्वय ('लालफीताशाही' और 'साइलो' कार्यसंस्कृति का अंत) तथा त्वरित निगरानी
4. G2E (सरकार से कर्मचारी)	सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड, वेतन, प्रशिक्षण और भविष्य निधि का प्रबंधन	**मिशन कर्मयोगी (iGOT Karmayogi प्लेटफॉर्म)**, **SPARROW** (ऑनलाइन APAR मूल्यांकन), **भविष्य (पेंशन पोर्टल)**, **HRMS**	नियम-आधारित (*Rule-based*) से भूमिका-आधारित (*Role-based*) मानव संसाधन क्षमता निर्माण

(ख) नागरिक चार्टर (Citizen's Charter) एवं 'सेवोत्तम' मॉडल (Sevottam Framework)

1. **नागरिक चार्टर की उत्पत्ति एवं सिद्धांत:** 1991 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसके **6 मूल सिद्धांत** थे— (i) गुणवत्ता (Quality), (ii) विकल्प (Choice), (iii) मानक (Standards), (iv) मूल्य (Value for Money), (v) जवाबदेही (Accountability), और (vi) पारदर्शिता (Transparency)। भारत में **मई 1997 के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन** में इसे अपनाया गया।

2. *नागरिक चार्टर की कमियाँ (*2nd ARC*, 12वीं रिपोर्ट — Citizen Centric Administration):* अधिकांश विभागों ने नागरिकों या जमीनी कर्मचारियों से परामर्श किए बिना ऊपर से चार्टर थोप दिए, समय-सीमा के उल्लंघन पर किसी दंडात्मक मुआवजे का प्रावधान नहीं था और यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था।

3. **सेवोत्तम मॉडल (Sevottam = 'सेवा' + 'उत्तम'):** प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा वर्ष 2006 में विकसित और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा **IS 15700** मानक के रूप में प्रमाणित यह मॉडल सार्वजनिक सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने वाला विश्व का पहला मानक ढाँचा है। इसके **3 मुख्य स्तंभ (Modules)** हैं:

- **स्तंभ 1: नागरिक चार्टर (Citizen's Charter):** सेवा मानकों का प्रकाशन और नागरिकों से फीडबैक प्राप्त करने का चैनल।
- **स्तंभ 2: लोक शिकायत निवारण प्रणाली (Public Grievance Redress Mechanism):** शिकायतों की प्राप्ति, समयबद्ध निवारण और असंतोष के मूल कारणों को दूर करना (**CPGRAMS** — निवारण की समय-सीमा अब घटाकर **21–30 दिन** कर दी गई है)।
- **स्तंभ 3: सेवा प्रदायगी क्षमता (Service Delivery Capability):** ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु आंतरिक अवसंरचना, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और संसाधन प्रबंधन।

4. **2nd ARC का 7-चरणीय मॉडल (Seven-Step Model for Citizen Centricity):** (1) सेवाओं को परिभाषित करना व ग्राहकों की पहचान, (2) मानक तय करना, (3) मानकों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, (4) प्रदर्शन करना, (5) प्रदर्शन की निगरानी करना, (6) स्वतंत्र मूल्यांकन, और (7) निरंतर सुधार।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act, 2005) एवं अद्यतन संशोधन

- **प्रमुख धाराएँ: धारा 4** (लोक प्राधिकारियों द्वारा स्वत: संज्ञान से सूचना का प्रकटीकरण — *Suo Motu Disclosure*), **धारा 6** (सूचना प्राप्त करने का आवेदन), **धारा 7** (30 दिनों के भीतर सूचना देना; यदि मामला किसी व्यक्ति के **जीवन या स्वतंत्रता** से संबंधित हो तो **48 घंटे** के भीतर), **धारा 8(1)** (सूचना प्रकटीकरण से छूट के 10 आधार — संप्रभुता, सुरक्षा, कैबिनेट दस्तावेज, विदेशी संबंध, निजता आदि), **धारा 8(2)** (यदि लोकहित संरक्षित हित से बड़ा हो तो गोपनीयता अधिनियम, 1923 के बावजूद सूचना दी जा सकती है), **धारा 24** (अनुसूची 2 में शामिल खुफिया और सुरक्षा संगठनों को छूट, किंतु **भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन** के आरोपों पर छूट लागू नहीं होगी)।

• **RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019:** मूल 2005 अधिनियम में मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष का निश्चित था और वेतन मुख्य चुनाव आयुक्त/चुनाव आयुक्त के बराबर था। 2019 के संशोधन द्वारा केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों का कार्यकाल (अब 3 वर्ष) और वेतन व सेवा शर्तें निर्धारित करने की शक्ति दे दी गई।

• **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act, 2023) द्वारा संशोधन:** DPDP अधिनियम की धारा 44(3) ने RTI अधिनियम की **धारा 8(1)(j)** में संशोधन कर व्यक्तिगत सूचना के प्रकटीकरण पर मौजूद 'लोकहित अपवाद' को हटाकर व्यक्तिगत डेटा की निजता को पूर्ण संरक्षण दिया है।

(घ) लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (Lokpal and Lokayuktas Act, 2013)

• **संरचना:** लोकपाल एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें **1 अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य** होते हैं। सदस्यों में से **50% न्यायिक सदस्य** होने अनिवार्य हैं, और कम से कम **50% सदस्य SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों और महिलाओं** में से होने चाहिए।

• **चयन समिति (Selection Committee):** (1) प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), (2) लोकसभा अध्यक्ष, (3) लोकसभा में विपक्ष का नेता, (4) भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश), और (5) राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रख्यात न्यायविद (चयन समिति के प्रथम चार सदस्यों की सिफारिश पर)।

• **कार्यकाल एवं पात्रता:** 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो); पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं।

• **क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): प्रधानमंत्री** (अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बाह्य व आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष को छोड़कर, और केवल तभी जब लोकपाल की पूर्ण पीठ के कम से कम दो-तिहाई सदस्य जांच की अनुमति दें), सभी केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य, तथा समूह A, B, C और D के सभी केंद्र सरकार के अधिकारी एवं 1 करोड़ रुपये से अधिक सरकारी अनुदान या 10 लाख रुपये से अधिक विदेशी अंशदान (FCRA) पाने वाले NGO/ट्रस्ट।

मॉड्यूल 5: संवेदनशील वर्गों के लिए संवैधानिक संरक्षण एवं प्रमुख कल्याणकारी योजनाएँ (Welfare Architecture for Vulnerable Sections)

(क) संवैधानिक एवं वैधानिक सुरक्षा तंत्र का एकीकृत चार्ट

संवेदनशील वर्ग	प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद एवं संशोधन	राष्ट्रीय आयोग एवं वैधानिक अधिनियम
अनुसूचित जाति (SC)	अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(4A) (पदोन्नति में आरक्षण — 77वाँ व 85वाँ संशोधन), अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत), अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 330, 332, 341	**अनुच्छेद 338: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)** (89वाँ संशोधन, 2003); नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955; SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (2018 संशोधन); मैनुअल स्कैवेंजर्स नियोजन प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम, 2013
अनुसूचित जनजाति (ST)	अनुच्छेद 244 (पाँचवीं और छठी अनुसूची), अनुच्छेद 275(1) (विशेष जनजातीय अनुदान), अनुच्छेद 330, 332, 339, 342	**अनुच्छेद 338A: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)**; पेसा (PESA) अधिनियम, 1996 (भूरिया समिति); वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं EWS	अनुच्छेद 15(4), 15(5) (93वाँ संशोधन, 2005 — उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 340, 342A (105वाँ संशोधन, 2021 — राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने की शक्ति बहाल); **अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6)** (103वाँ संशोधन, 2019 — EWS को 10% आरक्षण)	**अनुच्छेद 338B: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)** (102वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा संवैधानिक दर्जा); क्रीमी लेयर सिद्धांत (इंद्रा साहनी वाद, 1992 एवं राम नंदन समिति)
अल्पसंख्यक (Minorities)	अनुच्छेद 29 (अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार) एवं अनुच्छेद 30 (शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार)	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (6 अधिसूचित समुदाय: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन [2014]); राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004
दिव्यांगजन (PwDs)	अनुच्छेद 41 (काम, शिक्षा और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी व निःशक्तता की दशा में लोक सहायता पाने का अधिकार)	**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD Act), 2016** — दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर **21** किया गया (एसिड अटैक पीड़ित, पार्किंसंस, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल शामिल); सरकारी नौकरियों में **4%** और उच्च शिक्षा में **5%** आरक्षण

संवेदनशील वर्ग	प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद एवं संशोधन	राष्ट्रीय आयोग एवं वैधानिक अधिनियम
वृद्धजन एवं ट्रांसजेंडर	अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 एवं अनुच्छेद 41	माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007; **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019** (नालसा बनाम भारत संघ, 2014 निर्णय के बाद) एवं राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद

• **ऐतिहासिक न्यायिक अद्यतन (अगस्त 2024): पंजाब राज्य बनाम देविंदर सिंह (2024)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (6:1 के बहुमत से, ई.वी. चिन्नैया वाद, 2004 को पलटते हुए) ने निर्णय दिया कि राज्यों को अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के भीतर अधिक पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अनुभवजन्य डेटा के आधार पर **उप-वर्गीकरण (Sub-classification)** करने का संवैधानिक अधिकार है।

(ख) संवेदनशील वर्गों के लिए नवीनतम प्रमुख फ्लैगशिप कल्याणकारी योजनाएँ (2021–2026)

योजना का नाम (Scheme)	नोडल मंत्रालय	लक्षित समूह (Target Group)	मुख्य उद्देश्य एवं प्रमुख घटक
1. PM-JANMAN (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, नवंबर 2023)	जनजातीय कार्य मंत्रालय (9 मंत्रालयों के अभिसरण से)	18 राज्यों और 1 UT में निवास करने वाले 75 **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs)**	लगभग 24,104 करोड़ रुपये के परिव्यय से पक्के मकान, स्वच्छ पेयजल, सड़क, बिजली, मोबाइल मेडिकल यूनिट, वन धन विकास केंद्र और आंगनवाड़ी जैसी 11 बुनियादी सुविधाओं से 100% संतृप्ति
2. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA, 2024)	जनजातीय कार्य मंत्रालय (17 मंत्रालयों का अभिसरण)	63,000 से अधिक जनजातीय-बहुल गाँवों के 5 करोड़ से अधिक जनजातीय नागरिक	79,156 करोड़ रुपये के परिव्यय से सामाजिक अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में अंतराल को पाटना
3. PM-AJAY (प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	अनुसूचित जाति (SC) समुदाय	तीन पूर्व योजनाओं— (i) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, (ii) बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, और (iii) विशेष केंद्रीय सहायता (SCA to SCSP) का विलय कर कौशल विकास व आय सृजन अनुदान देना
4. SHRESHTA (श्रेष्ठा योजना)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	अनुसूचित जाति (SC) के मेधावी छात्र (जिनके माता-पिता की वार्षिक आय ≤ ₹2.5 लाख है)	NTA द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा (NETS) के माध्यम से देश के सर्वश्रेष्ठ निजी CBSE/राज्य बोर्ड आवासीय विद्यालयों में **कक्षा 9 और कक्षा 11** में निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
5. PM-YASASVI (प्रधानमंत्री यशस्वी योजना)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	**OBC, EBC (आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग) और DNT (विमुक्त, घुमंतू व अर्ध-घुमंतू जनजाति)** छात्र	प्री-मैट्रिक व पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, टॉप क्लास स्कूल व कॉलेज शिक्षा तथा छात्रावास निर्माण की एकीकृत छत्र योजना
6. NAMASTE योजना (नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम)	सामाजिक न्याय मंत्रालय एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल	सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले स्वच्छता कर्मी (Sanitation Workers)	सीवर की सफाई में शून्य मृत्यु दर सुनिश्चित करना, 100% मशीनीकृत सफाई, सफाई कर्मियों को PPE किट, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा और स्वच्छता उद्यमियों हेतु पूंजीगत सब्सिडी
7. SMILE योजना (आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु सहायता)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	**ट्रांसजेंडर समुदाय** एवं **भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्ति**	दो उप-योजनाएँ: (1) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु गरिमा गृह (आश्रय गृह), छात्रवृत्ति और **'आयुष्मान भारत TG Plus'** (लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी हेतु ₹5 लाख तक कवर); (2) भिक्षावृत्ति मुक्त शहर और पुनर्वास
8. PM-VIKAS (प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन)	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	देश के 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय (विशेषतः पारंपरिक कारीगर, महिलाएँ और युवा)	5 पूर्व योजनाओं (सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी, नई मंजिल) का एकीकरण कर कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता, ऋण लिंकेज और स्कूल ड्रॉपआउट्स की शिक्षा
9. अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizens)	इसके तहत वयोवृद्धों के लिए आश्रय गृह (IPSrC), **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY)** (BPL वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायक उपकरण), **SACRED पोर्टल** (वरिष्ठ नागरिक रोजगार) और **एल्डरलाइन हेल्पलाइन (14567)** संचालित हैं
10. PM विश्वकर्मा योजना (सितंबर 2023)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)	अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले **18 पारंपरिक व्यवसायों के कारीगर और शिल्पकार**	PM विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र, ₹15,000 का टूलकिट ई-वाउचर, ₹500/दिन स्टाइपेंड के साथ कौशल प्रशिक्षण और 5% रियायती ब्याज दर पर **₹3 लाख तक का कोलेटरल-मुक्त ऋण** (₹1 लाख + ₹2 लाख)

2.2 पुस्तक 28: 60 वास्तविक परीक्षा-स्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्न (60 Authentic 4-Option MCQs)

निर्देश: प्रत्येक प्रश्न में चार विशिष्ट विकल्प (A), (B), (C), (D) दिए गए हैं। सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या प्रश्न के ठीक नीचे दी गई है।

अभ्यास प्रश्न #1 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 1. [UPSC CSE / UGC-NET 2021]

प्रसिद्ध समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित 'संस्कृतिकरण' (Sanskritization) की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सर्वाधिक सटीक है?

(A) यह जाति व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने वाली एक 'संरचनात्मक परिवर्तन' (Structural Change) की प्रक्रिया है।

(B) यह केवल एक 'पदगत परिवर्तन' (Positional Change) की प्रक्रिया है, जिसमें कोई निम्न जाति उच्च/द्विज जातियों के रीति-रिवाजों व जीवनशैली को अपनाकर जातीय सोपान में अपनी स्थिति ऊपर उठाने का प्रयास करती है, किंतु स्वयं जाति व्यवस्था बनी रहती है।

(C) यह केवल उच्च जातियों द्वारा पश्चिमी शिक्षा और ईसाई धर्म अपनाने की प्रक्रिया है।

(D) इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लुई ड्यूमों ने अपनी पुस्तक *Homo Hierarchicus* में किया था।

सही उत्तर: (B)

व्याख्या: एम.एन. श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के कुर्गों के अध्ययन (1952) और अपनी पुस्तक *Social Change in Modern India* (1966) में स्पष्ट किया कि संस्कृतिकरण से प्रणाली के भीतर केवल किसी जाति की सापेक्ष स्थिति में बदलाव आता है ('Positional Change'), न कि स्वयं जाति प्रणाली की संरचना में ('Structural Change')।

अभ्यास प्रश्न #2 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 2. [UPPSC / UGC-NET 2022]

अपनी क्लासिक पुस्तक "*Caste and Race in India*" (1932) में किस भारतीय समाजशास्त्री ने जाति व्यवस्था की छह मूलभूत विशेषताओं (समाज का खंडात्मक विभाजन, संस्तरण, भोजन व सहवास पर प्रतिबंध, नागरिक व धार्मिक निर्योग्यताएँ, पेशे के चुनाव का अभाव और अंतर्विवाह) का सूत्रबद्ध विश्लेषण किया?

(A) डी.पी. मुखर्जी

(B) जी.एस. घुर्ये (Govind Sadashiv Ghurye)

(C) ए.आर. देसाई

(D) इरावती कर्वे

सही उत्तर: (B)

व्याख्या: भारतीय समाजशास्त्र के जनक माने जाने वाले गोविंद सदाशिव घुर्ये ने 1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक *Caste and Race in India* में इंडोलॉजिकल (भारतीय विद्याशास्त्रीय) परिप्रेक्ष्य से जाति की इन 6 विशेषताओं को प्रतिपादित किया और अंतर्विवाह (Endogamy) को जाति व्यवस्था की रीढ़ बताया।

अभ्यास प्रश्न #3 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 3. [BPSC / DSSSB PGT 2023]

तमिलनाडु के तंजौर जिले के 'श्रीपुरम' गाँव का गहन क्षेत्रीय अध्ययन कर "*Caste, Class and Power*" (1965) नामक पुस्तक किसने लिखी, जिसमें यह दर्शाया गया कि आधुनिक भारत में भूमि, आर्थिक वर्ग और राजनीतिक शक्ति अब केवल पारंपरिक उच्च जाति तक सीमित नहीं रह गई है?

(A) आंद्रे बेतेई (André Béteille)

(B) एस.सी. दुबे

(C) मैकिम मैरियट

(D) योगेंद्र सिंह

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: आंद्रे बेतेई ने मैक्स वेबर के त्रि-आयामी स्तरीकरण मॉडल (Class, Status, Party/Power) का प्रयोग करते हुए तंजौर के श्रीपुरम गाँव (ब्राह्मण, गैर-ब्राह्मण और आदि-द्रविड़) का अध्ययन किया और दिखाया कि लोकतंत्रीकरण व बाजार के प्रभाव से 'संचयी असमानता' (Cumulative Inequality) अब 'बिखरी हुई असमानता' (Dispersed Inequality) में बदल रही है।

अभ्यास प्रश्न #4 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 4. **[UPSC CSE 2022]**

भारतीय परिवार व्यवस्था के अध्ययन में किस समाजशास्त्री ने जनगणना और ऐतिहासिक आँकड़ों के आधार पर "*The Household Dimension of the Family in India*" (1973) में यह प्रचलित मिथक तोड़ा कि प्राचीन भारत में केवल विशाल संयुक्त परिवार ही थे और औद्योगीकरण ने उन्हें सीधे तोड़ दिया है?

(A) ए.एम. शाह (A.M. Shah)

(B) बी.आर. अंबेडकर

(C) टी.एन. मदान

(D) पैट्रिशिया ओबेरॉय

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: ए.एम. शाह ने 'परिवार' (Family) और 'गृहस्थी' (Household — सह-निवासी इकाई) के बीच सूक्ष्म अंतर किया और सिद्ध किया कि भारत में परिवार एक 'विकासात्मक चक्र' (Developmental Cycle — विस्तार और विखंडन के चरण) से गुजरता है और शहरी क्षेत्रों में भी संयुक्त परिवार की भावना मजबूत है।

अभ्यास प्रश्न #5 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 5. **[UGC-NET 2023]**

भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों (उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और पूर्वी ज़ोन) की नातेदारी व्यवस्था (Kinship System) का तुलनात्मक मानवशास्त्रीय अध्ययन अपनी पुस्तक "*Kinship Organization in India*" (1953) में किसने प्रस्तुत किया था?

(A) लीला दुबे

(B) इरावती कर्वे (Irawati Karve)

(C) वीणा दास

(D) गेल ओमवेट

सही उत्तर: (B)

व्याख्या: भारत की प्रथम महिला मानवशास्त्री इरावती कर्वे ने भारत को चार सांस्कृतिक-भाषाई नातेदारी क्षेत्रों में बाँटा और स्पष्ट किया कि उत्तर भारत में गोत्र बहिर्विवाह और गाँव बहिर्विवाह (Village Exogamy) का नियम प्रचलित है, जबकि दक्षिण भारत के द्रविड़ नातेदारी तंत्र में ममेरे-फुफेरे भाई-बहनों के बीच विवाह (*Cross-cousin Marriage*) को प्राथमिकता दी जाती है।

अभ्यास प्रश्न #6 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 6. **[UPSC CSE / CDS 2023]**

रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर द्वारा भारतीय सभ्यता के अध्ययन में प्रयुक्त 'वृहद परंपरा' (Great Tradition) और 'लघु परंपरा' (Little Tradition) की पारस्परिक क्रिया को समझाने के लिए मैकिम मैरियट ने उत्तर प्रदेश के 'किशनगढ़ी' गाँव के अध्ययन में किन दो प्रक्रियाओं का प्रतिपादन किया?

(A) संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण

(B) सार्वभौमीकरण (Universalization) और संकीर्णीकरण/स्थानीयकरण (Parochialization)

(C) आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण

(D) ब्राह्मणीकरण और जनजातीयकरण

सही उत्तर: (B)

व्याख्या: मैकिम मैरियट ने अपनी कृति *Village India* (1955) में बताया कि जब स्थानीय लोक-परंपरा के तत्व ऊपर उठकर अखिल भारतीय शास्त्रीय परंपरा का अंग बनते हैं तो उसे **'सार्वभौमीकरण' (Universalization)** कहते हैं, और जब शास्त्रीय तत्व नीचे आकर स्थानीय बोली व रीति-रिवाजों में ढल जाते हैं तो उसे **'संकीर्णीकरण/स्थानीयकरण' (Parochialization)** कहते हैं।

अभ्यास प्रश्न #7 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 7. **[UPPSC 2024]**

भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान (सकारात्मक विभेद / Affirmative Action) करने की संवैधानिक शक्ति प्रदान करता है?

(A) अनुच्छेद 14

(B) अनुच्छेद 15(3)

(C) अनुच्छेद 16(4)

(D) अनुच्छेद 21A

सही उत्तर: (B)

व्याख्या: अनुच्छेद 15(1) राज्य को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है, किंतु **अनुच्छेद 15(3)** स्पष्ट अपवाद बनाता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

अभ्यास प्रश्न #8 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 8. **[UPSC CSE 2024]**

106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 ('नारी शक्ति वंदन अधिनियम') के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह लोकसभा (अनुच्छेद 330A), राज्य विधानसभाओं (अनुच्छेद 332A) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा (अनुच्छेद 239AA) में महिलाओं के लिए कुल सीटों का एक-तिहाई (33%) आरक्षित करता है।
2. यह राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करता है।
3. अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षित सीटों के भीतर भी एक-तिहाई सीटें SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी ('कोटा के भीतर कोटा')।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 1 और 3

(C) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 और 3 सभी

सही उत्तर: (B)

व्याख्या: कथन 2 गलत है क्योंकि 106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम केवल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदनों— लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा— में ही 33% महिला आरक्षण लागू करता है; राज्यसभा और विधान परिषदों में इसका प्रावधान नहीं है। यह नई जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन (Delimitation) के पश्चात 15 वर्षों के लिए प्रभावी होगा।

अभ्यास प्रश्न #9 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 9. **[BPSC / UPPSC 2024]**

1 जुलाई 2024 से लागू हुई **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023** की किस धारा में विवाह का झूठा वादा करके या रोजगार/पदोन्नति का प्रलोभन देकर अथवा अपनी पहचान छिपाकर किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने को एक विशिष्ट दंडनीय अपराध (10 वर्ष तक का कारावास) बनाया गया है?

(A) धारा 63

(B) धारा 69

(C) धारा 78

(D) धारा 85

सही उत्तर: (B)

व्याख्या: भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय V की **धारा 69** में कपटपूर्ण साधनों (Deceitful means — जिसमें विवाह का झूठा वादा, पदोन्नति/रोजगार का प्रलोभन या पहचान छिपाकर विवाह करना शामिल है) से यौन संबंध बनाने को बलात्कार की श्रेणी से अलग एक स्पष्ट अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है।

अभ्यास प्रश्न #10 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 10. **[NDA/CDS 2024]**

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 में पुरानी भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के प्रतिस्थापन के संदर्भ में कौन-सा युग्म सही सुमेलित है?

(A) धारा 80 BNS — दहेज मृत्यु (पूर्व IPC धारा 304B) तथा धारा 85 BNS — पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के प्रति क्रूरता (पूर्व IPC धारा 498A)

(B) धारा 63 BNS — चोरी तथा धारा 85 BNS — राजद्रोह

(C) धारा 103 BNS — दहेज मृत्यु तथा धारा 144 BNS — घरेलू हिंसा

(D) धारा 302 BNS — हत्या तथा धारा 376 BNS — बलात्कार

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: BNS 2023 में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को एकीकृत कर अध्याय V में रखा गया है, जहाँ **धारा 80** दहेज मृत्यु (पूर्व IPC 304B), **धारा 85–86** पति/रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (पूर्व IPC 498A), **धारा 63–64** बलात्कार (पूर्व IPC 375–376) और **धारा 103** हत्या (पूर्व IPC 302) से संबंधित है।

अभ्यास प्रश्न #11 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 11. **[UPSC CSE / UGC-NET 2022]**

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH Act) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन **सही नहीं** है?

(A) यह अधिनियम केवल संगठित सरकारी क्षेत्र की स्थायी महिला कर्मचारियों पर लागू होता है और घरेलू कामगार महिलाओं (Domestic Workers) तथा असंगठित क्षेत्र को इससे बाहर रखता है।

(B) 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर नियोक्ता द्वारा 'आंतरिक शिकायत समिति' (ICC) का गठन अनिवार्य है।

(C) जिन प्रतिष्ठानों में 10 से कम कर्मचारी हैं या शिकायत स्वयं नियोक्ता के विरुद्ध है, वहाँ मामलों की सुनवाई जिला अधिकारी द्वारा गठित 'स्थानीय शिकायत समिति' (LCC) करती है।

(D) आंतरिक शिकायत समिति को दीवानी न्यायालय (Civil Court) की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और जांच 90 दिनों के भीतर पूरी करनी होती है।

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: कथन (A) गलत है क्योंकि POSH अधिनियम, 2013 की धारा 2(o) और 2(a) में 'कार्यस्थल' और 'व्यथित महिला' की परिभाषा अत्यंत व्यापक है—इसमें संगठित, असंगठित, संविदाकर्मी, प्रशिक्षु (Interns), आगंतुक और घरों में काम करने वाली **घरेलू कामगार महिलाएँ (Domestic Workers)** सभी शामिल हैं।

अभ्यास प्रश्न #12 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 12. **[DSSSB PGT 2023]**

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA) के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता शामिल है?

(A) यह अधिनियम केवल शारीरिक मारपीट को घरेलू हिंसा मानता है, भावनात्मक और आर्थिक शोषण को नहीं।

(B) यह पीड़ित महिला को 'साझा गृहस्थी' (Shared Household) में निवास करने का अधिकार देता है, चाहे उस मकान में महिला या उसके पति का कोई कानूनी स्वामित्व न हो।

(C) इसके अंतर्गत केवल विवाहित महिलाएँ ही शिकायत दर्ज करा सकती हैं; माँ, बहन या विवाह की प्रकृति के संबंध (लिव-इन) में रहने वाली महिलाएँ इसमें शामिल नहीं हैं।

(D) इस अधिनियम के तहत शिकायत सीधे केवल उच्च न्यायालय में ही दर्ज की जा सकती है।

सही उत्तर: (B)

व्याख्या: घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 17 प्रत्येक पीड़ित महिला (पत्नी, माँ, बहन, विधवा या विवाह की प्रकृति के संबंध में रहने वाली महिला) को 'साझा घर' में रहने और बेदखल न किए जाने का अधिकार देती है, तथा धारा 3 में शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार सभी को शामिल किया गया है।

अभ्यास प्रश्न #13 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 13. **[UPSC CSE 2021]**

मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रथम दो जीवित बच्चों के लिए महिलाओं को 26 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश मिलता है, जबकि दो या अधिक जीवित बच्चों वाली महिला को तीसरे बच्चे के लिए 12 सप्ताह का अवकाश मिलता है।
2. 3 माह से कम आयु के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने वाली महिला (Adoptive Mother) और कमीशनिंग माँ को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देय है।
3. 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए निर्धारित दूरी के भीतर क्रेच (Crèche — शिशुगृह) की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य है, जहाँ महिला को दिन में चार बार जाने की अनुमति होगी।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3 सभी

सही उत्तर: (D)

व्याख्या: मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के ये तीनों प्रावधान पूर्णतः सही हैं। यह कानून 10 या अधिक कर्मचारियों वाले सभी कारखानों, खानों, बागानों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।

अभ्यास प्रश्न #14 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 14. **[UPPSC / BPSC 2023]**

गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (MTP Amendment Act, 2021) और उस पर सर्वोच्च न्यायालय के सितंबर 2022 के निर्णय (*X vs. Principal Secretary, Health Dept. of Delhi*) के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

(A) विशेष श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई है, और सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अविवाहित या एकल महिलाएँ भी सहमतिपूर्ण संबंधों से उत्पन्न गर्भ को 20–24 सप्ताह के बीच समाप्त कराने की समान हकदार हैं।

(B) अविवाहित महिलाओं को केवल 12 सप्ताह तक ही गर्भपात की अनुमति है।

(C) किसी भी परिस्थिति में (भ्रूण में गंभीर विकृति होने पर भी) 24 सप्ताह के बाद गर्भपात की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(D) गर्भपात के लिए महिला के पति या परिवार के सदस्यों की लिखित सहमति कानूनी रूप से अनिवार्य है।

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: MTP संशोधन अधिनियम, 2021 ने 20 सप्ताह तक 1 डॉक्टर और 20–24 सप्ताह तक 2 डॉक्टरों की राय से गर्भपात की अनुमति दी (गंभीर भ्रूण विकृति में राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की अनुमति से 24 सप्ताह के बाद भी संभव)। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में निर्णय दिया कि अनुच्छेद 14 और 21 के तहत वैवाहिक स्थिति के आधार पर विवाहित और अविवाहित महिलाओं में भेद नहीं किया जा सकता, और केवल वयस्क गर्भवती महिला की अपनी सहमति ही पर्याप्त है।

अभ्यास प्रश्न #15 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 15. **[UPSC CSE 2023]**

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5, 2019–21) के अंतिम आँकड़ों के अनुसार भारत की 'कुल प्रजनन दर' (Total Fertility Rate — TFR) घटकर कितनी हो गई है?

(A) 2.4

(B) 2.2

(C) 2.0

(D) 1.7

सही उत्तर: (C)

व्याख्या: NFHS-5 (2019–21) के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) NFHS-4 (2015–16) के 2.2 से घटकर **2.0 बच्चे प्रति महिला** (शहरी क्षेत्रों में 1.6 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1) पर आ गई है, जो जनसंख्या स्थिरता के प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से नीचे है।

अभ्यास प्रश्न #16 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 16. **[UGC-NET 2023]**

'जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत' (Demographic Transition Theory — फ्रैंक नोटेस्टीन और थॉम्पसन) के किस चरण में मृत्यु दर में तो तीव्र गिरावट आती है किंतु जन्म दर उच्च बनी रहती है, जिसके परिणामस्वरूप 'जनसंख्या विस्फोट' (Population Explosion) की स्थिति उत्पन्न होती है?

(A) प्रथम चरण (उच्च स्थिर चरण)

(B) द्वितीय चरण (प्रारंभिक विस्तारशील चरण / Early Expanding Stage)

(C) तृतीय चरण (विलंबित विस्तारशील चरण)

(D) चतुर्थ चरण (निम्न स्थिर चरण)

सही उत्तर: (B)

व्याख्या: द्वितीय चरण में आधुनिक चिकित्सा, टीकाकरण और स्वच्छता के प्रसार से मृत्यु दर तेजी से घटती है, किंतु सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों के कारण जन्म दर तत्काल नहीं घटती, जिससे जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि होती है (भारत में 1951–1981 की अवधि इसी चरण का उदाहरण थी; वर्तमान में भारत तृतीय से चतुर्थ चरण के संक्रमण में है)।

अभ्यास प्रश्न #17 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 17. **[UPPSC / CDS 2022]**

भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में किस जनगणना वर्ष को **'महान विभाजक वर्ष' (Year of the Great Divide)** कहा जाता है, क्योंकि इस दशक (1911–1921) में अकाल और 1918 के इन्फ्लूएंजा महामारी के कारण भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक (-0.31%) रही थी?

(A) 1891

(B) 1901

(C) 1921

(D) 1951

सही उत्तर: (C)

व्याख्या: 1921 से पूर्व भारत की जनसंख्या वृद्धि अस्थिर थी, किंतु 1911–1921 के दशक में जनसंख्या लगभग 77 लाख घट गई (-0.31%)। 1921 के बाद से भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई है, इसलिए जनसांख्यिकीविद गोपालस्वामी ने **1921** को 'महान विभाजक वर्ष' कहा।

अभ्यास प्रश्न #18 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 18. **[BPSC / DSSSB PGT 2022]**

भारत में आंतरिक प्रवासन (Internal Migration) की चार दिशात्मक धाराओं में से संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ी धारा कौन-सी है और उसका प्रमुख कारण क्या है?

(A) ग्रामीण से शहरी प्रवासन; पुरुषों का रोजगार हेतु पलायन

(B) ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासन; महिलाओं का विवाह के कारण प्रवासन

(C) शहरी से शहरी प्रवासन; उच्च शिक्षा और आईटी क्षेत्र

(D) शहरी से ग्रामीण प्रवासन; सेवानिवृत्ति

सही उत्तर: (B)

व्याख्या: भारत की जनगणना और NSSO सर्वेक्षणों के अनुसार कुल आंतरिक प्रवासियों में सबसे बड़ा हिस्सा **ग्रामीण से ग्रामीण (Rural-to-Rural)** प्रवासन का है, जिसमें ग्राम बहिर्विवाह और पितृस्थानीय निवास (Patrilocal residence) की प्रथा के कारण महिलाओं का विवाहजन्य प्रवासन सर्वाधिक है। पुरुषों के प्रवासन में 'ग्रामीण से शहरी' धारा प्रमुख है।

अभ्यास प्रश्न #19 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 19. **[UPSC CSE 2023]**

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की '*India Ageing Report 2023*' के अनुसार भारत में वृद्ध होती जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सी प्रमुख प्रवृत्ति देखी जा रही है?

(A) वृद्धावस्था का नारीकरण (Feminization of Ageing), वृद्धजनों का ग्रामीणीकरण और 80+ आयु वर्ग ('Oldest-Old') की सबसे तेज वृद्धि दर

(B) पुरुषों की जीवन प्रत्याशा महिलाओं से 10 वर्ष अधिक होने के कारण वृद्ध पुरुषों का अनुपात बढ़ रहा है

(C) उत्तर प्रदेश और बिहार में बुजुर्गों का प्रतिशत केरल और तमिलनाडु की तुलना में दोगुना है

(D) 2050 तक भारत में वृद्धजनों की संख्या घटकर 5% से कम रह जाएगी

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: 60 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से अधिक होने के कारण वृद्ध जनसंख्या में महिलाओं (विशेषत: विधवा महिलाओं) का अनुपात बढ़ रहा है जिसे **'Feminization of Ageing'** कहते हैं। साथ ही, लगभग 70% वृद्ध ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और 2050 तक वृद्ध आबादी दोगुनी होकर 20.8% होने का अनुमान है।

अभ्यास प्रश्न #20 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 20. **[UGC-NET 2024]**

प्रवासन के समाजशास्त्र में 'पुल' (Pull) और 'पुश' (Push) कारकों के साथ-साथ 'मध्यवर्ती बाधाओं' (Intervening Obstacles) और व्यक्तिगत कारकों का प्रसिद्ध **'प्रवासन का सिद्धांत' (A Theory of Migration, 1966)** किस विद्वान ने प्रस्तुत किया था?

(A) एवरेट एस. ली (Everett S. Lee)

(B) किंग्सले डेविस

(C) फ्रैंक नोटेस्टीन

(D) वारेन थॉम्पसन

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: रेवेनस्टीन (1885) के प्रवासन नियमों को आगे बढ़ाते हुए अमेरिकी जनसांख्यिकीविद **एवरेट एस. ली (1966)** ने प्रवासन के निर्णय को 4 कारकों के रूप में समझाया: (1) उद्गम स्थान से जुड़े कारक, (2) गंतव्य स्थान से जुड़े कारक, (3) मध्यवर्ती बाधाएँ (दूरी, परिवहन लागत, प्रवासन कानून), और (4) व्यक्तिगत कारक।

अभ्यास प्रश्न #21 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 21. **[UPSC CSE / UPPSC 2022]**

विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 1992 के अपने किस दस्तावेज़ में 'अभिशासन' (Governance) को "विकास के लिए किसी देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति के प्रयोग के तरीके" के रूप में परिभाषित किया गया और 'सुशासन' (Good Governance) की 8 विशेषताएँ निर्धारित की गईं?

(A) *Governance and Development* (1992)

(B) *World Development Report* 1978

(C) *Brundtland Report* 1987

(D) *Beveridge Report* 1942

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: विश्व बैंक ने अपनी 1992 की रिपोर्ट "*Governance and Development*" में सुशासन की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। संयुक्त राष्ट्र (UNESCAP) के अनुसार सुशासन के **8 स्तंभ** हैं: भागीदारी, विधि का शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, सर्वसम्मति उन्मुखता, समता व समावेशिता, प्रभावशीलता व दक्षता, और अनुक्रियाशीलता।

अभ्यास प्रश्न #22 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 22. **[UGC-NET PubAd 2023]**

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा लोक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए विकसित **'सेवोत्तम' (Sevottam — IS 15700)** फ्रेमवर्क के तीन मुख्य घटक (Modules) कौन-कौन से हैं?

(A) नागरिक चार्टर (Citizen's Charter), लोक शिकायत निवारण तंत्र (Public Grievance Redress Mechanism) और सेवा प्रदायगी क्षमता (Service Delivery Capability)

(B) ई-ऑफिस, बायोमेट्रिक उपस्थिति और जीएसटी पोर्टल

(C) लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग और सीबीआई

(D) बजट निर्माण, लेखापरीक्षा और संसदीय समितियाँ

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: 'सेवोत्तम' (सेवा + उत्तम) मॉडल के तीन मुख्य स्तंभ हैं: (1) प्रभावी **नागरिक चार्टर** का क्रियान्वयन, (2) सुदृढ़ **लोक शिकायत निवारण प्रणाली**, और (3) **सेवा प्रदायगी क्षमता** (आंतरिक प्रक्रियाएँ और मानव संसाधन)। प्रत्येक स्तंभ में 3-3 मानदंड (कुल 9 मानदंड और 33 तत्व) शामिल हैं।

अभ्यास प्रश्न #23 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 23. **[UPSC CSE 2021]**

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC, अध्यक्ष: वीरप्पा मोइली) की कौन-सी रिपोर्ट विशेष रूप से *'नागरिक-केंद्रित प्रशासन: शासन का हृदय' (Citizen Centric Administration: The Heart of Governance)* और सेवोत्तम के 7-चरणीय मॉडल को समर्पित है?

(A) पहली रिपोर्ट

(B) चौथी रिपोर्ट

(C) ग्यारहवीं रिपोर्ट

(D) बारहवीं रिपोर्ट (12th Report)

सही उत्तर: (D)

व्याख्या: 2nd ARC की प्रमुख रिपोर्टें हैं: पहली रिपोर्ट (*Right to Information: Master Key to Good Governance*), चौथी रिपोर्ट (*Ethics in Governance*), दसवीं रिपोर्ट (*Refurbishing of Personnel Administration*), ग्यारहवीं रिपोर्ट (*Promoting e-Governance*) और *बारहवीं रिपोर्ट (Citizen Centric Administration)*।

अभ्यास प्रश्न #24 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 24. **[UPPSC / BPSC 2022]**

नागरिक चार्टर (Citizen's Charter) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अवधारणा सर्वप्रथम 1991 में यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री जॉन मेजर की सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
2. भारत में मई 1997 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में 'प्रभावी और उत्तरदायी प्रशासन के लिए कार्ययोजना' के तहत केंद्र और राज्य स्तर पर नागरिक चार्टर बनाने का निर्णय लिया गया।
3. वर्तमान में भारत में केंद्रीय स्तर पर सभी मंत्रालयों के नागरिक चार्टर एक केंद्रीय अधिनियम द्वारा न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय (Justiciable) और दंडनीय हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3 सभी

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: कथन 3 गलत है क्योंकि केंद्रीय स्तर पर नागरिक चार्टर अभी भी एक नैतिक व प्रशासनिक प्रतिबद्धता है, वह कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं है (हालाँकि मध्य प्रदेश [2010], बिहार, राजस्थान, दिल्ली व कर्नाटक जैसे कई राज्यों ने अपने अलग **'लोक सेवा गारंटी अधिनियम'** पारित कर चिह्नित सेवाओं को कानूनी अधिकार बनाया है)।

अभ्यास प्रश्न #25 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 25. **[UPSC CSE 2023]**

भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) अर्थात् **'इंडिया स्टैक' (India Stack)** की विभिन्न परतों (Layers) और उनके घटकों का सही मिलान क्या है?

(A) पहचान परत (Presenceless Layer): आधार (Aadhaar) | काग़ज़-रहित परत (Paperless Layer): DigiLocker व e-Sign | भुगतान परत (Cashless Layer): UPI व Aadhaar Enabled Payment System | डेटा सशक्तीकरण परत (Consent Layer): Account Aggregator (DEPA)

(B) पहचान परत: पैन कार्ड | भुगतान परत: स्विफ्ट (SWIFT) | डेटा परत: केवल भौतिक स्टाम्प पेपर

(C) इंडिया स्टैक केवल क्रिप्टोकरेंसी खनन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का एक निजी पोर्टल है

(D) इंडिया स्टैक का संचालन केवल विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया जाता है

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: 'इंडिया स्टैक' खुले एपीआई (Open APIs) का एक एकीकृत सेट है जिसमें 4 मुख्य परतें हैं: (1) Presenceless Layer (Aadhaar), (2) Paperless Layer (DigiLocker, e-Sign), (3) Cashless Layer (UPI, IMPS, AEPS), और (4) Consent Layer (Account Aggregator फ्रेमवर्क)।

अभ्यास प्रश्न #26 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 26. **[NDA/CDS 2023]**

केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए शुरू किए गए **'मिशन कर्मयोगी' (NPCSCB — राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम)** का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(A) सिविल सेवकों को 'नियम-आधारित' (Rule-based) कार्यसंस्कृति से 'भूमिका-आधारित' (Role-based) मानव संसाधन प्रबंधन की ओर ले जाना और **iGOT कर्मयोगी** डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सतत प्रशिक्षण देना

(B) सभी सरकारी पदों पर केवल अनुबंध के आधार पर भर्ती करना

(C) संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा को समाप्त करना

(D) केवल ग्रामीण मनरेगा श्रमिकों को कृषि उपकरण वितरित करना

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: सितंबर 2020 में स्वीकृत 'मिशन कर्मयोगी' का लक्ष्य भारतीय नौकरशाही को भविष्य के लिए तैयार करना (*Future-ready*), कार्य-दक्षता ढाँचे (*Framework of Roles, Activities and Competencies — FRAC*) को अपनाना और iGOT-Karmayogi पोर्टल पर ऑनलाइन लर्निंग उपलब्ध कराना है।

अभ्यास प्रश्न #27 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 27. **[UPSC CSE / UGC-NET 2022]**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005) के अंतर्गत यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के **'जीवन या स्वतंत्रता' (Life or Liberty)** से संबंधित है, तो जन सूचना अधिकारी (PIO) को कितने समय के भीतर सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है?

(A) 24 घंटे के भीतर

(B) 48 घंटे के भीतर

(C) 7 दिन के भीतर

(D) 30 दिन के भीतर

सही उत्तर: (B)

व्याख्या: RTI अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के अनुसार सामान्य स्थिति में आवेदन प्राप्त होने के **30 दिनों** के भीतर (सहायक जन सूचना अधिकारी के माध्यम से आने पर 35 दिन) सूचना देनी होती है, किंतु परंतुक (Proviso) के अनुसार यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी है, तो उसे **48 घंटे** के भीतर देना अनिवार्य है।

अभ्यास प्रश्न #28 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 28. [UPPSC 2023]

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की कौन-सी धारा लोक प्राधिकारियों (Public Authorities) पर यह वैधानिक दायित्व डालती है कि वे अपने संगठन के कार्य, बजट, निर्देशिका और निर्णयों का **स्वतः संज्ञान से प्रकटीकरण (Suo Motu / Proactive Disclosure)** करें ताकि जनता को सूचना मांगने के लिए RTI लगाने की कम से कम आवश्यकता पड़े?

(A) धारा 2(f)

(B) धारा 4(1)(b)

(C) धारा 8(1)(a)

(D) धारा 19

सही उत्तर: (B)

व्याख्या: RTI अधिनियम की **धारा 4** (विशेषकर धारा 4(1)(b) के 17 बिंदु) 'प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर' की आत्मा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी किशन चंद जैन बनाम भारत संघ (2023) में केंद्र और राज्यों को धारा 4 के तहत RTI पोर्टलों के नियमित ऑडिट का निर्देश दिया है।

अभ्यास प्रश्न #29 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 29. [BPSC / UGC-NET 2023]

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची (धारा 24) में सूचीबद्ध खुफिया और सुरक्षा संगठनों (जैसे IB, RAW, ED, BSF, CRPF आदि) को सामान्यतः RTI के दायरे से छूट प्राप्त है, किंतु किन दो मामलों से संबंधित सूचना होने पर यह छूट लागू **नहीं** होती?

(A) केवल वेतन और पदोन्नति के मामलों में

(B) भ्रष्टाचार के आरोपों और मानवाधिकारों के उल्लंघन (Allegations of Corruption and Human Rights Violations) से संबंधित सूचना पर

(C) विदेशी सरकारों के साथ गुप्त रक्षा सौदों की तकनीकी जानकारी पर

(D) सैनिकों की सीमा पर तैनाती के स्थान पर

सही उत्तर: (B)

व्याख्या: RTI अधिनियम की धारा 24(1) के प्रथम परंतुक में स्पष्ट उल्लेख है कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित सूचना को इस छूट से बाहर रखा गया है (मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में केंद्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन से 45 दिनों के भीतर सूचना दी जाएगी)।

अभ्यास प्रश्न #30 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 30. [UPSC CSE 2020]

सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने मूल RTI अधिनियम, 2005 की धारा 13 और धारा 16 में क्या प्रमुख परिवर्तन किया?

(A) इसने मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के 5 वर्ष के निश्चित वैधानिक कार्यकाल और चुनाव आयुक्त के समकक्ष वेतन के प्रावधान को बदलकर केंद्र सरकार को उनका कार्यकाल एवं वेतन-भत्ते निर्धारित करने की शक्ति दे दी।

(B) इसने राजनीतिक दलों को स्पष्ट रूप से 'लोक प्राधिकारी' घोषित कर दिया।

(C) इसने राज्य सूचना आयोगों को समाप्त कर केवल केंद्रीय सूचना आयोग को बनाए रखा।

(D) इसने RTI आवेदन शुल्क को ₹10 से बढ़ाकर ₹1,000 कर दिया।

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: 2019 के संशोधन अधिनियम ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों के सूचना आयुक्तों की पदावधि (जिसे बाद में नियमों द्वारा 3 वर्ष किया गया) तथा वेतन व सेवा शर्तें तय करने का अधिकार केंद्र सरकार को सौंप दिया।

अभ्यास प्रश्न #31 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 31. **[UPSC CSE / UPPSC 2024]**

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च-स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन इस चयन समिति का सदस्य **नहीं** होता है?

(A) प्रधानमंत्री (अध्यक्ष) और लोकसभा अध्यक्ष

(B) लोकसभा में विपक्ष का नेता

(C) भारत का मुख्य न्यायाधीश (या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश) और एक प्रख्यात न्यायविद

(D) केंद्रीय गृह मंत्री और राज्यसभा के सभापति

सही उत्तर: (D)

व्याख्या: लोकपाल अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के अनुसार 5-सदस्यीय चयन समिति में शामिल हैं: (1) प्रधानमंत्री, (2) लोकसभा अध्यक्ष, (3) लोकसभा में विपक्ष का नेता, (4) CJI या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट जज, और (5) एक प्रख्यात न्यायविद। केंद्रीय गृह मंत्री या राज्यसभा सभापति इसमें शामिल नहीं हैं। (भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे; वर्तमान में न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर हैं)।

अभ्यास प्रश्न #32 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 32. **[UGC-NET 2022]**

भारत में 'लोकपाल' (Lokpal) और 'लोकायुक्त' (Lokayukta) शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में किसने किया था, और किस आयोग की प्रथम रिपोर्ट (1966) की सिफारिश पर यह संस्था प्रस्तावित की गई थी?

(A) डॉ. एल.एम. सिंघवी ने शब्द गढ़ा; मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1st ARC, 1966) ने इसकी सिफारिश की

(B) के. संथानम ने शब्द गढ़ा; सतर्कता आयोग ने सिफारिश की

(C) एम.सी. सीतलवाड़ ने शब्द गढ़ा; विधि आयोग ने सिफारिश की

(D) अन्ना हजारे ने शब्द गढ़ा; नीति आयोग ने सिफारिश की

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: स्कैंडिनेवियाई देशों (स्वीडन, 1809) के 'ओम्बड्समैन' (Ombudsman) के भारतीय प्रतिरूप के रूप में न्यायविद और सांसद डॉ. एल.एम. सिंघवी ने 1963 में 'लोकपाल' शब्द गढ़ा। 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (अध्यक्ष: मोरारजी देसाई, बाद में के. हनुमंतैया) ने अपनी पहली रिपोर्ट '*Problems of Redress of Citizens' Grievances*' में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की। (महाराष्ट्र 1971 में लोकायुक्त स्थापित करने वाला पहला राज्य बना, जबकि ओडिशा ने 1970 में सबसे पहले अधिनियम पारित किया था)।

अभ्यास प्रश्न #33 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 33. **[UPSC CSE 2022]**

केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission — CVC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसकी स्थापना 1964 में संथानम समिति (भ्रष्टाचार निवारण समिति, 1962–64) की सिफारिश पर एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा की गई थी।
2. विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1997) के निर्णय के पश्चात संसद द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 पारित कर इसे बहु-सदस्यीय (1 केंद्रीय सतर्कता आयुक्त + अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त) **वैधानिक निकाय** का दर्जा दिया गया।

3. इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) होता है और उनकी चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3 सभी

सही उत्तर: (D)

व्याख्या: CVC के संबंध में तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। CVC एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है, संवैधानिक निकाय नहीं।

अभ्यास प्रश्न #34 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 34. [BPSC / DSSSB PGT 2023]

सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला केंद्रीय कानून कौन-सा था, और देश में अपनी स्वतंत्र 'सामाजिक अंकेक्षण इकाई' व ग्राम सभा आधारित ऑडिट को संस्थागत रूप देने में कौन-सा राज्य अग्रणी रहा है?

(A) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 (धारा 17); आंध्र प्रदेश (SSAAT) और मेघालय (2017 का पहला सोशल ऑडिट कानून पारित करने वाला राज्य)

(B) कंपनी अधिनियम, 2013; गुजरात

(C) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986; केरल

(D) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019; पंजाब

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: मनरेगा अधिनियम, 2005 की **धारा 17** ग्राम सभा को कार्यों का नियमित सामाजिक अंकेक्षण करने का वैधानिक अधिकार देती है। **मेघालय (2017)** सामुदायिक भागीदारी और लोक सेवा वितरण की सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए समर्पित कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना।

अभ्यास प्रश्न #35 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 35. [UPSC CSE 2024]

अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय की 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने किस ऐतिहासिक निर्णय में ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2004) के फैसले को पलटते हुए यह व्यवस्था दी कि अनुसूचित जातियों (SC) एक समरूप (Homogeneous) वर्ग नहीं हैं और राज्य सरकारें अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत SC/ST कोटे के भीतर अधिक वंचित जातियों के लिए **उप-वर्गीकरण (Sub-classification)** कर सकती हैं?

(A) पंजाब राज्य बनाम देविंदर सिंह (State of Punjab vs. Davinder Singh, 2024)

(B) जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022)

(C) जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018)

(D) एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006)

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: 1 अगस्त 2024 को मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7-सदस्यीय संविधान पीठ ने पंजाब राज्य बनाम देविंदर सिंह वाद में 6:1 के बहुमत से निर्णय दिया कि अनुसूचित जातियों के भीतर असमानता के ठोस व मात्रात्मक डेटा के आधार पर राज्य उप-वर्गीकरण कर सकते हैं, बशर्ते किसी एक उप-जाति को 100% सीटें न दी जाएँ।

अभ्यास प्रश्न #36 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 36. [UPPSC / BPSC 2022]

भारतीय संविधान के निम्नलिखित संशोधनों और उनके विषय का सही मिलान चुनिए:

1. 102वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 — राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को अनुच्छेद 338B के तहत संवैधानिक दर्जा
2. 103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 — अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण
3. 104वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2020 — लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण को 10 वर्ष (2030 तक) बढ़ाया गया और आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) मनोनयन को समाप्त किया गया
4. 105वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2021 — राज्य सरकारों को अपनी स्वयं की सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC/OBC) की सूची पहचानने और अधिसूचित करने की शक्ति बहाल की गई

(A) केवल 1, 2 और 3

(B) केवल 2, 3 और 4

(C) केवल 1 और 4

(D) 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं

सही उत्तर: (D)

व्याख्या: संवेदनशील वर्गों से जुड़े ये चारों नवीनतम संविधान संशोधन (102वाँ से 105वाँ) और उनके प्रावधान पूर्णतः सही हैं। 105वाँ संशोधन मराठा आरक्षण मामले (जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल वाद, 2021) में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के बाद राज्यों की शक्ति बहाल करने के लिए लाया गया था।

अभ्यास प्रश्न #37 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 37. [UPSC CSE 2023]

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 [Forest Rights Act — FRA, 2006] के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों के दावों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने वाली प्रथम स्तर की प्राधिकारी संस्था कौन-सी है?

(A) जिला कलेक्टर कार्यालय

(B) वन विभाग का प्रभागीय वनाधिकारी (DFO)

(C) ग्राम सभा (Gram Sabha)

(D) जनजातीय कार्य मंत्रालय

सही उत्तर: (C)

व्याख्या: वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 6(1) के अनुसार वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा का निर्धारण करने की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार **ग्राम सभा** को दिया गया है (जो अपनी 'वन अधिकार समिति' के माध्यम से दावों का सत्यापन कर उप-खंड और जिला स्तरीय समिति को भेजती है)। इस अधिनियम के तहत प्रति परिवार अधिकतम **4 हेक्टेयर** तक भूमि का अधिकार दिया जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न #38 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 38. [NDA/CDS 2022]

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 [PESA Act, 1996] किस समिति की सिफारिशों पर अधिनियमित किया गया था और यह संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों (वर्तमान में 10 राज्यों) पर लागू होता है?

(A) दिलीप सिंह भूरिया समिति (1995); पाँचवीं अनुसूची (Fifth Schedule) के क्षेत्र

(B) बलवंत राय मेहता समिति; छठी अनुसूची के क्षेत्र

(C) खाखा समिति; ग्यारहवीं अनुसूची के सभी राज्य

(D) ढेबर आयोग; आठवीं अनुसूची

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: 73वें संविधान संशोधन (भाग IX) के प्रावधान अनुच्छेद 243M के तहत अनुसूचित क्षेत्रों पर स्वतः लागू नहीं होते थे। अतः **दिलीप सिंह भूरिया समिति (1995)** की सिफारिश पर दिसंबर 1996 में पेसा (PESA) अधिनियम पारित किया गया, जो **पाँचवीं अनुसूची** वाले 10 राज्यों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान) में ग्राम सभा को गौण वनोपज (Minor Forest Produce), भूमि हस्तांतरण रोकथाम और लघु खनिजों पर विशेष अधिकार देता है।

अभ्यास प्रश्न #39 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 39. **[UPSC CSE 2024]**

नवंबर 2023 में जनजातीय गौरव दिवस (15 नवंबर — भगवान बिरसा मुंडा जयंती) पर प्रारंभ किए गए **'पीएम-जनमन' (PM-JANMAN — प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान)** के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अभियान विशेष रूप से देश के 18 राज्यों और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाले 75 **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs)** के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए लक्षित है।
2. यह 9 केंद्रीय मंत्रालयों के अभिसरण (Convergence) से पक्के घर, स्वच्छ पेयजल, सड़क, बिजली, शिक्षा और मोबाइल चिकित्सा जैसी 11 महत्वपूर्ण सुविधाओं से PVTG बस्तियों को संतृप्त करता है।
3. भारत में PVTGs की पहचान सर्वप्रथम 1973 के ढेबर आयोग की सिफारिश पर 'आदिम जनजातीय समूह' (PTGs) के रूप में की गई थी और ओडिशा में इनकी संख्या सर्वाधिक (13 समूह) है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3 सभी

सही उत्तर: (D)

व्याख्या: PM-JANMAN योजना के तीनों कथन पूर्णतः सही हैं। PVTGs की पहचान के 4 मानदंड हैं: (i) पूर्व-कृषि स्तर की प्रौद्योगिकी, (ii) स्थिर या घटती जनसंख्या, (iii) अत्यंत निम्न साक्षरता, और (iv) निर्वाह स्तर की अर्थव्यवस्था।

अभ्यास प्रश्न #40 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 40. **[UPPSC / BPSC 2024]**

अनुसूचित जाति (SC) के मेधावी छात्रों को देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों (CBSE/State Board) में कक्षा 9 और कक्षा 11 में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कौन-सी योजना संचालित की जा रही है?

(A) श्रेष्ठा योजना (SHRESHTA — Scheme for Residential Education for Students in High Schools in Targeted Areas)

(B) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)

(C) नवोदय विद्यालय योजना

(D) पीएम-यशस्वी योजना

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: SHRESHTA योजना के तहत उन SC छात्रों (जिनके माता-पिता की वार्षिक आय ₹2.5 लाख तक है) का चयन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की परीक्षा (NETS) द्वारा करके शीर्ष निजी आवासीय स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक की संपूर्ण शिक्षण व छात्रावास फीस सरकार द्वारा वहन की जाती है। (EMRS अनुसूचित जनजाति ST के छात्रों के लिए है)।

अभ्यास प्रश्न #41 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 41. [UGC-NET 2023]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल **'नमस्ते' (NAMASTE — National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem)** योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

(A) भारत में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के कार्यों में शून्य मृत्यु दर (Zero Fatalities) प्राप्त करना, पूर्ण मशीनीकरण सुनिश्चित करना और सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका व आयुष्मान स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना

(B) विदेशी पर्यटकों का हवाई अड्डों पर स्वागत करना

(C) ग्रामीण क्षेत्रों में केवल सौर ऊर्जा पंप लगाना

(D) अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रचार-प्रसार करना

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: 'नमस्ते' योजना ने पूर्ववर्ती SRMS (मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास की स्वरोजगार योजना) का स्थान लिया है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी स्वच्छता कर्मी मानव मल के प्रत्यक्ष संपर्क में न आए और उन्हें सुरक्षा उपकरण (PPE), स्वास्थ्य बीमा और स्वच्छता मशीनें खरीदने हेतु पूंजीगत सब्सिडी मिले।

अभ्यास प्रश्न #42 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 42. [UPSC CSE / CDS 2023]

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की **'स्माइल' (SMILE — Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise)** छत्र योजना किन दो अत्यंत हाशिए पर स्थित समूहों के पुनर्वास और कल्याण के लिए बनाई गई है?

(A) ट्रांसजेंडर व्यक्ति और भिक्षावृत्ति (Begging) में संलग्न व्यक्ति

(B) एकल माताएँ और अनाथ बच्चे

(C) प्रवासी निर्माण श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर्स

(D) वृद्ध किसान और हथकरघा बुनकर

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: फरवरी 2022 में शुरू की गई **SMILE** योजना की दो उप-योजनाएँ हैं: (1) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना (जिसमें 'गरिमा गृह' आश्रय, छात्रवृत्ति और जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी हेतु ₹5 लाख का स्वास्थ्य कवर शामिल है), और (2) भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास की उप-योजना (**SMILE-75** पहल)।

अभ्यास प्रश्न #43 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 43. [DSSSB PGT / UGC-NET 2022]

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act — RPwD Act, 2016), जिसे संयुक्त राष्ट्र के UNCRPD अभिसमय के अनुरूप लागू किया गया, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा मिलान सही है?

(A) मान्यता प्राप्त दिव्यांगता श्रेणियाँ: 7 से बढ़ाकर **21** की गईं | सरकारी नौकरियों में बेंचमार्क दिव्यांगजनों (≥40% दिव्यांगता) को आरक्षण: **4%** | सरकारी व सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण: **5%**

(B) दिव्यांगता श्रेणियाँ: 10 | नौकरियों में आरक्षण: 3% | उच्च शिक्षा में आरक्षण: 3%

(C) दिव्यांगता श्रेणियाँ: 21 | नौकरियों में आरक्षण: 10% | उच्च शिक्षा में आरक्षण: 2%

(D) दिव्यांगता श्रेणियाँ: 15 | नौकरियों में आरक्षण: 5% | उच्च शिक्षा में आरक्षण: 4%

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: RPwD अधिनियम, 2016 ने 1995 के पुराने अधिनियम को प्रतिस्थापित किया। इसने दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर **21** कर दिया (जिसमें पहली बार एसिड अटैक पीड़ित, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, बौनापन, ऑटिज्म और पार्किंसंस शामिल किए गए) तथा नौकरियों में आरक्षण 3% से बढ़ाकर **4%** और उच्च शिक्षा में **5%** किया।

अभ्यास प्रश्न #44 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 44. **[UPSC CSE 2022]**

नालसा बनाम भारत संघ (*National Legal Services Authority vs. Union of India*, 2014) के ऐतिहासिक निर्णय और उसके बाद पारित **'ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019'** के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?

(A) सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 'तृतीय लिंग' (Third Gender) के रूप में मौलिक अधिकार और स्व-पहचान का अधिकार दिया, और 2019 के अधिनियम की धारा 16 के तहत केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री की अध्यक्षता में एक **'राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद' (NCTP)** का गठन किया गया है।

(B) 2019 के अधिनियम के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मतदान के अधिकार से वंचित रखा गया है।

(C) राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं।

(D) इस अधिनियम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव को अपराध नहीं माना गया है।

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: नालसा वाद (2014) ने लिंग पहचान को अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा का मूल हिस्सा माना। 2019 के अधिनियम ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आवास में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ भेदभाव को प्रतिबंधित किया और नीतिगत सलाह हेतु **राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद** का गठन किया।

अभ्यास प्रश्न #45 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 45. **[UPPSC 2023]**

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान शामिल है?

(A) वरिष्ठ नागरिक वे भारतीय नागरिक हैं जिनकी आयु 60 वर्ष या अधिक है; यदि बच्चे या कानूनी उत्तराधिकारी इस शर्त पर संपत्ति हस्तांतरित कराने के बाद कि वे बुजुर्ग की देखभाल करेंगे, उनकी उपेक्षा करते हैं, तो अधिकरण (Tribunal) उस संपत्ति हस्तांतरण को **शून्य और कपटपूर्ण (Void)** घोषित कर सकता है (धारा 23)।

(B) इस अधिनियम के तहत भरण-पोषण के दावे की सुनवाई में वकीलों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है।

(C) यह अधिनियम केवल उन माता-पिता पर लागू होता है जिनके पास कम से कम 5 एकड़ कृषि भूमि है।

(D) भरण-पोषण अधिकरण को निर्णय देने के लिए 5 वर्ष का समय दिया गया है।

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: 2007 के अधिनियम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को त्वरित, सरल और सस्ता भरण-पोषण (अधिकरण द्वारा 90 दिनों में निपटारा, वकीलों के हस्तक्षेप पर रोक — धारा 17) दिलाना है, और **धारा 23** बुजुर्गों को संपत्ति हस्तांतरण के बाद परित्याग किए जाने से सुरक्षा देती है।

अभ्यास प्रश्न #46 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 46. **[BPSC / UGC-NET 2024]**

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 (Juvenile Justice Amendment Act, 2021) के द्वारा गोद लेने (Adoption) के आदेश जारी करने की शक्ति दीवानी न्यायालय (Civil Court) से हटाकर किसे प्रदान कर दी गई है ताकि गोद लेने की प्रक्रिया में होने वाले विलंब को समाप्त किया जा सके?

(A) ग्राम पंचायत के सरपंच को

(B) जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate — DM) और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) को

(C) पुलिस अधीक्षक (SP) को

(D) केवल सर्वोच्च न्यायालय को

सही उत्तर: (B)

व्याख्या: किशोर न्याय (संशोधन) अधिनियम, 2021 ने मूल 2015 अधिनियम में संशोधन कर गोद लेने के आदेश (Adoption Orders) जारी करने और बाल देखभाल संस्थानों (CCIs) के निरीक्षण व पंजीकरण का अंतिम अधिकार **जिला मजिस्ट्रेट (DM)** को सौंप दिया है।

अभ्यास प्रश्न #47 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 47. **[UPSC CSE / CDS 2021]**

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012 — 2019 में संशोधित) के मुख्य प्रावधानों के संबंध में कौन-सा कथन सही है?

(A) यह एक **लैंगिक-तटस्थ (Gender-Neutral)** कानून है जो 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों (बालक एवं बालिका दोनों) को यौन अपराधों से संरक्षण देता है, और 2019 के संशोधन द्वारा गंभीर प्रवेशन यौन हमले (Aggravated Penetrative Sexual Assault) के लिए न्यूनतम 20 वर्ष के कारावास से लेकर मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है।

(B) यह कानून केवल 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं पर ही लागू होता है।

(C) POCSO के तहत अपराध की जानकारी होने पर पुलिस को सूचित करना वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं।

(D) इस कानून के तहत बच्चे का बयान केवल पुलिस थाने के लॉकअप में ही दर्ज किया जा सकता है।

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: POCSO अधिनियम, 2012 पूर्णतः **जेंडर-न्यूट्रल** है। इसकी धारा 19 के तहत अपराध की जानकारी होने पर रिपोर्ट करना कानूनी रूप से अनिवार्य (Mandatory Reporting) है, बयान बच्चे के निवास या उसकी पसंद के स्थान पर सादे कपड़ों में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाता है और विशेष न्यायालय का गठन होता है।

अभ्यास प्रश्न #48 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 48. **[UGC-NET 2023]**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA, 2013) के अंतर्गत महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया किसे माना गया है?

(A) परिवार के सबसे बुजुर्ग पुरुष सदस्य को

(B) परिवार की **18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे वरिष्ठ महिला** को

(C) केवल सरकारी नौकरी करने वाले सदस्य को

(D) ग्राम पंचायत के सचिव को

सही उत्तर: (B)

व्याख्या: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (जो ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को कानूनी खाद्य अधिकार देता है: अंत्योदय परिवार को 35 किग्रा/माह और प्राथमिकता परिवार को 5 किग्रा/व्यक्ति/माह; अब **PMGKAY** के तहत दिसंबर 2028 तक पूर्णतः निःशुल्क) की **धारा 13** के तहत घर की सबसे वरिष्ठ वयस्क महिला (≥18 वर्ष) को राशन कार्ड का मुखिया बनाया गया है।

अभ्यास प्रश्न #49 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 49. **[UPSC CSE 2023]**

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum — WEF) द्वारा प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाले **'ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स' (Global Gender Gap Index)** में देशों का मूल्यांकन किन चार आयामों (Sub-indices) के आधार पर किया जाता है?

(A) आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षणिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, तथा राजनीतिक सशक्तीकरण

(B) प्रति व्यक्ति आय, रक्षा बजट, इंटरनेट गति और अंतरिक्ष कार्यक्रम

(C) केवल मातृ मृत्यु दर और साक्षरता दर

(D) कृषि भूमि स्वामित्व, बैंक खाते, पासपोर्ट और वाहन लाइसेंस

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: WEF के *Global Gender Gap Index* के 4 मुख्य स्तंभ हैं: (1) Economic Participation and Opportunity, (2) Educational Attainment, (3) Health and Survival, और (4) Political Empowerment। (जबकि UNDP के *Gender Inequality Index — GII* के 3 आयाम हैं: प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तीकरण और श्रम बाजार)।

अभ्यास प्रश्न #50 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 50. **[UPPSC / BPSC 2023]**

ऑक्सफैम और डिजिटल समावेशन अध्ययनों में चर्चित **'डिजिटल जेंडर डिवाइड' (Digital Gender Divide)** का भारतीय समाज और अभिशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है?

(A) महिलाओं के पास स्मार्टफोन स्वामित्व और इंटरनेट साक्षरता कम होने के कारण वे टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग (UPI) और ई-गवर्नेंस पोर्टलों के लाभ से पुरुषों की तुलना में पीछे छूट जाती हैं।

(B) इससे केवल शहरी आईटी कंपनियों के निर्यात में वृद्धि होती है।

(C) डिजिटल डिवाइड का अर्थ केवल 4G से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से है।

(D) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में तीन गुना अधिक स्मार्टफोन हैं।

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: NFHS-5 के आँकड़े दर्शाते हैं कि भारत में जहाँ लगभग 57% पुरुषों ने इंटरनेट का कभी प्रयोग किया था, वहीं महिलाओं में यह आँकड़ा लगभग 33% (ग्रामीण महिलाओं में और कम) था। इसे पाटने के लिए सरकार द्वारा **PMGDISHA (प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान)** और 'लखपति दीदी / नमो ड्रोन दीदी' जैसी योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

अभ्यास प्रश्न #51 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 51. **[UGC-NET 2022]**

भारतीय धर्मनिरपेक्षता (Indian Secularism) के मॉडल और पश्चिमी (विशेषकर फ्रांसीसी *Laïcité*) धर्मनिरपेक्षता के मॉडल में मुख्य सैद्धांतिक अंतर क्या है, जिसे राजनीतिक दार्शनिक राजीव भार्गव ने **'सैद्धांतिक दूरी' (Principled Distance)** की संज्ञा दी है?

(A) पश्चिमी मॉडल चर्च और राज्य के बीच पूर्ण पारस्परिक बहिष्कार (Strict Wall of Separation) पर आधारित है, जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान (सर्वधर्म समभाव) रखते हुए सामाजिक कुरीतियों (जैसे अस्पृश्यता, तीन तलाक, देवदासी प्रथा) के सुधार हेतु धर्म में सकारात्मक हस्तक्षेप और अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण की अनुमति देती है।

(B) भारतीय मॉडल में एक राजकीय धर्म घोषित किया गया है जबकि पश्चिमी मॉडल में नहीं।

(C) पश्चिमी मॉडल धार्मिक अल्पसंख्यकों को सरकारी बजट से मदरसे व मिशनरी स्कूल चलाने का संवैधानिक अधिकार देता है जबकि भारत नहीं देता।

(D) दोनों मॉडलों में कोई अंतर नहीं है।

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: राजीव भार्गव के अनुसार भारतीय संविधान का धर्मनिरपेक्ष मॉडल धर्म से आँख मूँदने वाला नहीं है, बल्कि यह **'सैद्धांतिक दूरी' (Principled Distance)** निभाता है— अर्थात् राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, परंतु वह समानता व मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए अनुच्छेद 25(2)(b) के तहत धार्मिक कुप्रथाओं में सुधार कर सकता है और अनुच्छेद 29–30 के तहत अल्पसंख्यक संस्कृति का संरक्षण भी कर सकता है।

अभ्यास प्रश्न #52 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 52. **[UPSC CSE 2021]**

भारत में नगरीकरण (Urbanization) की प्रक्रिया में **'छद्म नगरीकरण' (Pseudo-Urbanization / Over-Urbanization)** और **'जनगणना नगर' (Census Towns)** की अवधारणा का क्या अर्थ है?

(A) छद्म नगरीकरण में औद्योगीकरण और बुनियादी ढाँचे के आनुपातिक विकास के बिना ग्रामीण संकट (Push factors) के कारण शहरों में जनसंख्या का अति-संकेंद्रण व मलिन बस्तियों का विस्तार होता है; और 'जनगणना नगर' वे बस्तियाँ हैं जो जनसंख्या (≥5,000), घनत्व (≥400 व्यक्ति/वर्ग किमी) और गैर-कृषि पुरुष रोजगार (≥75%) की शहरी कसौटी पूरी करती हैं किंतु उनका प्रशासन अभी भी ग्राम पंचायत द्वारा होता है।

(B) जनगणना नगर केवल वे महानगर हैं जिनकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है।

(C) छद्म नगरीकरण का अर्थ स्मार्ट सिटी में केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग है।

(D) जनगणना नगरों में 75% से अधिक पुरुष कृषि कार्य में संलग्न होते हैं।

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: किंग्सले डेविस और एन.वी. सोवानी ने विकासशील देशों के नगरीकरण को 'अति-नगरीकरण' या 'छद्म नगरीकरण' कहा जहाँ विनिर्माण (Manufacturing) के बजाय अनौपचारिक सेवा क्षेत्र में भीड़ बढ़ती है। साथ ही, 2011 की जनगणना में भारत के शहरी विकास का बड़ा हिस्सा 2,532 नए **'जनगणना नगरों' (Census Towns)** के उदय से आया, जिन्हें शहरी नगर निकाय (Statutory ULB) का दर्जा न मिलने से सीवेज और कचरा प्रबंधन की कमी झेलनी पड़ती है।

अभ्यास प्रश्न #53 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 53. **[DSSSB PGT / BPSC 2023]**

भारत में क्षेत्रीयतावाद (Regionalism) की अभिव्यक्ति के रूप में 'धरतीपुत्र सिद्धांत' (*Sons of the Soil Doctrine* — माइरां वीनर द्वारा विश्लेषित) का मुख्य कारण क्या है?

(A) स्थानीय मध्यम वर्ग और युवाओं की यह भावना कि उनके राज्य के संसाधनों, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक अवसरों पर बाहरी राज्यों से आए प्रवासियों का वर्चस्व हो रहा है, इसलिए स्थानीय निवासियों (Domicile) को प्राथमिकता मिलनी चाहिए

(B) किसानों द्वारा जैविक खेती को अपनाने का आंदोलन

(C) वनों की कटाई के विरुद्ध जनजातीय आंदोलन

(D) नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना का समर्थन

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: पॉल ब्रास और माइरां वीनर (*Sons of the Soil: Migration and Ethnic Conflict in India*, 1978) ने स्पष्ट किया कि जब किसी क्षेत्र में प्रवासियों को शिक्षा और रोजगार में बढ़त मिलती है और स्थानीय शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी बढ़ती है, तो nativist या 'धरतीपुत्र' आंदोलन उभरते हैं (जबकि संविधान का अनुच्छेद 16(2) निवास स्थान के आधार पर भेदभाव रोकता है और केवल संसद ही अनुच्छेद 16(3) के तहत कानून बना सकती है)।

अभ्यास प्रश्न #54 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 54. **[UPSC CSE 2022]**

स्वयं सहायता समूहों (Self-Help Groups — SHGs) और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के माध्यम से ग्रामीण महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में **'लखपति दीदी'** और **'नमो ड्रोन दीदी'** पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(A) SHG महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण (जैसे प्लंबिंग, एलईडी बल्ब निर्माण, ड्रोन संचालन, डेयरी व फूड प्रोसेसिंग) और माइक्रो-एंटरप्राइज से जोड़कर प्रति परिवार न्यूनतम **₹1 लाख या अधिक की सतत वार्षिक आय** सुनिश्चित करना, तथा 15,000 महिला SHGs को कृषि कार्यों (तरल उर्वरक छिड़काव) हेतु ड्रोन प्रदान करना

(B) प्रत्येक महिला के बैंक खाते में बिना किसी कार्य के ₹1 लाख नकद जमा करना

(C) केवल रक्षा सेनाओं में महिला पायलटों की भर्ती करना

(D) केवल महानगरों की कॉर्पोरेट महिलाओं को शेयर बाजार में निवेश कराना

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: भारत में 90 लाख से अधिक महिला SHGs में 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाएँ जुड़ी हैं। **'लखपति दीदी'** योजना का संशोधित लक्ष्य **3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं** को प्रतिवर्ष न्यूनतम ₹1 लाख की स्थायी आय अर्जित करने में सक्षम बनाना है, और **'नमो ड्रोन दीदी'** के तहत 15,000 महिला SHGs को कृषि ड्रोन और पायलट प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

अभ्यास प्रश्न #55 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 55. **[UGC-NET PubAd 2024]**

भारत सरकार के **CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System)** पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(A) यह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा संचालित 24×7 ऑनलाइन मंच है जो भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्यों से जुड़ा है, और इसमें भाषिणी (Bhashini) AI के एकीकरण से 22 संविधान-मान्यता प्राप्त भाषाओं में शिकायत दर्ज करने तथा अपील तंत्र की सुविधा है।

(B) इस पर केवल केंद्र सरकार के सेवारत प्रथम श्रेणी के अधिकारी ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

(C) इस पोर्टल पर न्यायाधीन मामलों (Sub-judice cases) और RTI अपीलों का भी अंतिम न्यायिक निपटारा किया जाता है।

(D) शिकायत निवारण की अधिकतम समय-सीमा 2 वर्ष निर्धारित है।

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: 2007 में शुरू किए गए CPGRAMS पोर्टल में व्यापक सुधार कर शिकायत निवारण की अधिकतम समय-सीमा को 60 दिनों से घटाकर पहले 30 दिन और अब **21 दिन** कर दिया गया है। (न्यायाधीन मामले, सेवा संबंधी व्यक्तिगत अनुशासनात्मक मामले और RTI मामले इसके दायरे से बाहर होते हैं)।

अभ्यास प्रश्न #56 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 56. **[UPSC CSE 2023]**

कंपनी अधिनियम, 2013 की **धारा 135** के अंतर्गत 'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व' (Corporate Social Responsibility — CSR) को कानूनी रूप से अनिवार्य करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। इसके पात्रता मानदंड और व्यय के संबंध में कौन-सा कथन सही है?

(A) ₹500 करोड़ या अधिक की निवल संपत्ति (Net Worth), या ₹1,000 करोड़ या अधिक का कारोबार (Turnover), या ₹5 करोड़ या अधिक का शुद्ध लाभ (Net Profit) अर्जित करने वाली प्रत्येक कंपनी को अपने पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम **2%** अनुसूची VII में निर्दिष्ट सामाजिक कल्याण कार्यों पर खर्च करना अनिवार्य है।

(B) सभी पंजीकृत स्टार्टअप्स को अपने कुल राजस्व का 10% राजनीतिक दलों को दान करना अनिवार्य है।

(C) CSR राशि को कंपनी के स्वयं के कर्मचारियों के वेतन और सामान्य व्यावसायिक प्रचार पर खर्च किया जा सकता है।

(D) CSR केवल सरकारी नवरत्न कंपनियों पर लागू होता है, निजी कंपनियों पर नहीं।

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची VII के तहत पात्र कंपनियों को पिछले 3 वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का न्यूनतम **2%** गरीबी उन्मूलन, भूख व कुपोषण समाप्ति, शिक्षा, लैंगिक समानता, पर्यावरण स्थिरता, पीएम नेशनल रिलीफ फंड आदि पर खर्च करना होता है।

अभ्यास प्रश्न #57 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 57. **[UPPSC / CDS 2023]**

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 [FCRA Amendment Act, 2020] द्वारा गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के अभिशासन और पारदर्शिता के लिए कौन-से प्रमुख बदलाव किए गए?

(A) विदेशी अंशदान को किसी अन्य गैर-पंजीकृत या पंजीकृत NGO को हस्तांतरित करने (Sub-granting) पर रोक लगाई गई, प्रशासनिक खर्चों की सीमा 50% से घटाकर **20%** की गई, पदाधिकारियों के लिए आधार अनिवार्य किया गया और विदेशी धन केवल **भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की नई दिल्ली मुख्य शाखा** में खोले गए निर्दिष्ट FCRA खाते में ही प्राप्त करना अनिवार्य किया गया।

(B) NGOs को विदेशी धन से चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई।

(C) FCRA का नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय के स्थान पर नीति आयोग को बनाया गया।

(D) प्रशासनिक व्यय की सीमा 50% से बढ़ाकर 80% कर दी गई।

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: केंद्रीय **गृह मंत्रालय (MHA)** द्वारा प्रशासित FCRA (मूल अधिनियम 2010, संशोधित 2020) में ये सभी कड़े प्रावधान किए गए ताकि विदेशी धन का उपयोग वास्तविक सामाजिक कल्याण कार्यों में ही हो और फर्जी सब-ग्रांटिंग या प्रशासनिक अपव्यय रुके।

अभ्यास प्रश्न #58 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 58. **[BPSC 2024]**

सार्वजनिक स्वास्थ्य अभिशासन की फ्लैगशिप योजना **'आयुष्मान भारत'** के दो प्रमुख स्तंभ कौन-से हैं और मार्च/सितंबर 2024 के कैबिनेट विस्तार निर्णय के बाद किस आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आय की सीमा के बिना इसमें शामिल किया गया है?

(A) पहला स्तंभ: 1.5 लाख+ आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पूर्व नाम: हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर — प्राथमिक देखभाल) और दूसरा स्तंभ: PM-JAY (द्वितीयक व तृतीयक अस्पताल भर्ती हेतु ₹5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष का कैशलेस कवर); तथा अब **70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों** (चाहे उनकी आय कुछ भी हो) को ₹5 लाख का निःशुल्क स्वास्थ्य कवर ('आयुष्मान वय वंदना कार्ड') दिया गया है।

(B) केवल जिला अस्पतालों का निजीकरण और 50 वर्ष से अधिक के नागरिकों को नकद पेंशन।

(C) केवल संक्रामक रोगों का टीकाकरण और 85 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को कवर।

(D) केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए CGHS का विस्तार।

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 की सिफारिश पर 2018 में शुरू किए गए 'आयुष्मान भारत' के दो पूरक स्तंभ हैं: (1) आयुष्मान आरोग्य मंदिर (व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल), और (2) PM-JAY (₹5 लाख का बीमा)। 2024 में सरकार ने आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ **70 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक** को (सामाजिक-आर्थिक स्थिति से परे) ₹5 लाख के स्वास्थ्य कवर के दायरे में शामिल कर लिया है।

अभ्यास प्रश्न #59 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 59. **[UGC-NET / DSSSB PGT 2024]**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (NEP 2020 — कस्तूरीरंगन समिति) द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक समावेशन और अभिशासन के लिए प्रस्तावित सुधारों में निम्नलिखित में से कौन-सा शामिल है?

(A) 10+2 के स्थान पर **5+3+3+4** की नई शैक्षणिक व पाठ्यचर्या संरचना, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs — महिलाएँ, ट्रांसजेंडर, SC/ST/OBC, दिव्यांग, अल्पसंख्यक) के लिए **'जेंडर इंक्लूजन फंड' (Gender Inclusion Fund)** एवं **'विशेष शिक्षा क्षेत्र' (Special Education Zones — SEZs)** की स्थापना, तथा उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक **HECI (भारतीय उच्च शिक्षा आयोग)** का गठन

(B) कक्षा 1 से ही अंग्रेजी माध्यम को एकमात्र अनिवार्य भाषा बनाना और मातृभाषा पर रोक लगाना

(C) सकल नामांकन अनुपात (GER) को घटाकर 25% पर स्थिर रखना

(D) व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) को केवल स्नातकोत्तर स्तर के बाद शुरू करना

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: NEP 2020 ने 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए **5+3+3+4** संरचना (Foundational, Preparatory, Middle, Secondary), कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा व इंटर्नशिप, कक्षा 5 (संभव हो तो 8) तक मातृभाषा में शिक्षण, SEDGs के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र (SEZs) व जेंडर इंक्लूजन फंड, तथा शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को GDP के **6%** तक ले जाने का लक्ष्य रखा है।

अभ्यास प्रश्न #60 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 60. **[UPSC CSE 2024]**

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act — DPDP Act, 2023) के अंतर्गत 'डेटा फिड्यूशियरी' (Data Fiduciary), 'डेटा प्रिंसिपल' (Data Principal) और 'कंसेंट मैनेजर' (Consent Manager) की शब्दावली का सही अर्थ क्या है?

(A) **डेटा प्रिंसिपल:** वह व्यक्ति जिससे व्यक्तिगत डेटा संबंधित है (बच्चों के मामले में माता-पिता/अभिभावक); **डेटा फिड्यूशियरी:** वह संस्था/कंपनी या राज्य जो डेटा प्रसंस्करण का उद्देश्य और साधन निर्धारित करता है; **कंसेंट मैनेजर:** भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI) में पंजीकृत वह एकल मंच जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी सहमति दे सकता है, प्रबंधित कर सकता है या वापस ले सकता है।

(B) डेटा प्रिंसिपल: कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी; डेटा फिड्यूशियरी: इंटरनेट उपयोगकर्ता।

(C) यह अधिनियम केवल कागजी फाइलों और हस्तलिखित डायरियों पर लागू होता है, डिजिटल डेटा पर नहीं।

(D) इस अधिनियम के उल्लंघन पर अधिकतम जुर्माना केवल ₹500 निर्धारित किया गया है।

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किए जाने और न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा समिति की रिपोर्ट के बाद अगस्त 2023 में **DPDP अधिनियम, 2023** पारित हुआ। इसमें व्यक्ति को 'Data Principal', डेटा प्रोसेस करने वाली इकाई को 'Data Fiduciary' कहा गया है, और डेटा ब्रीच या बच्चों के डेटा के नियमों के उल्लंघन पर भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI) द्वारा **₹250 करोड़ तक के जुर्माने** का प्रावधान है।

2.3 मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन प्रारूप एवं मॉडल उत्तर (Mains Answer-Writing Frameworks — Book 28)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 2.3 मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन प्रारूप एवं मॉडल उत्तर (Mains Answer-Writing Frameworks — Book 28)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
मॉडल प्रश्न 1 (UPSC CSE GS Paper-I / UPPSC Mains — 15 अंक, 250 शब्द)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
मॉडल प्रश्न 2 (UPSC CSE GS Paper-II / BPSC Mains — 15 अंक, 250 शब्द)

मॉडल प्रश्न 1 (UPSC CSE GS Paper-I / UPPSC Mains — 15 अंक, 250 शब्द)

अभ्यास प्रश्न #61 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न: "समकालीन भारत में जाति ने अपनी पारंपरिक अनुष्ठानिक-दानवीय कठोरता को भले ही खो दिया हो, किंतु उसने राजनीति, अर्थव्यवस्था और डिजिटल नेटवर्क में नए अवतार धारण कर लिए हैं।" सोदाहरण चर्चा कीजिए।

- **उत्तर संरचना प्रारूप (Answer Structure Blueprint):**

1. **प्रस्तावना (Introduction — 30–40 शब्द):** एम.एन. श्रीनिवास की कृति "*Caste in Its New Avatar*" और जी.एस. घुर्ये के क्लासिक लक्षणों का उल्लेख करते हुए बताना कि संविधान (अनुच्छेद 15, 17), नगरीकरण और बाजार अर्थव्यवस्था ने जाति के 'अनुष्ठानिक शुद्धता-प्रदूषण' (Ritual purity-pollution) पक्ष को कमजोर किया है, किंतु उसकी 'धर्मनिरपेक्ष और संबद्धतावादी' भूमिका मजबूत हुई है।

2. **मुख्य भाग - खंड A: जाति के पारंपरिक बंधनों में शिथिलता (Decline of Ritual Dimensions):**

• सार्वजनिक परिवहन, कार्यस्थलों, रेस्तरां और शहरी अपार्टमेंटों में खान-पान व सहवास के प्रतिबंधों का टूटना।

• वंशानुगत जजमानी व्यवस्था का विघटन और पेशे का जाति से अलगाव (आंद्रे बेतेई का 'संचयी से बिखरी हुई असमानता' का संक्रमण)।

3. **मुख्य भाग - खंड B: जाति के आधुनिक 'नए अवतार' (Resilience & New Avatars of Caste):**

• **जाति का राजनीतिकरण (रजनी कोठारी):** 'वोट बैंक', सूक्ष्म जातिगत समीकरण (Non-dominant OBCs और दलित उप-जातियों की पहचान की राजनीति) और दबाव समूहों के रूप में जाति महासंघों का उभार।

• **आर्थिक व सामाजिक पूँजी नेटवर्क:** अनौपचारिक व्यवसाय, प्रवासन नेटवर्क और शहरी आवास किराए पर देने में सूक्ष्म जातीय प्राथमिकता।

• **डिजिटल अंतर्विवाह (Digital Endogamy):** मैट्रिमोनियल वेबसाइटों और सोशल मीडिया ग्रुप्स ने अंतर्विवाह (Endogamy) को समाप्त करने के बजाय जाति-विशिष्ट जीवनसाथी खोजने को भौगोलिक सीमाओं से परे और आसान बना दिया है (NFHS व IHDS डेटा के अनुसार आज भी ~90–94% विवाह स्व-जाति में होते हैं)।

• **ऑनर किलिंग और प्रतीकात्मक संघर्ष:** अंतर-जातीय विवाहों के विरुद्ध खाप या पारिवारिक हिंसा।

4. **निष्कर्ष (Conclusion — 30–40 शब्द):** डॉ. बी.आर. अंबेडकर के 'जाति का विनाश' (*Annihilation of Caste*) के दृष्टिकोण से समापन कि जब तक अंतर्विवाह और मानसिक पदानुक्रम समाप्त नहीं होते, तब तक संवैधानिक नैतिकता (*Constitutional Morality*), गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिक्षा और अंतर-जातीय नागरिक बंधुत्व को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

मॉडल प्रश्न 2 (UPSC CSE GS Paper-II / BPSC Mains — *15 अंक, 250 शब्द*)

अभ्यास प्रश्न #62 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न: भारत में शासन को नागरिक-केंद्रित और पारदर्शी बनाने में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (*DPI*) और 'सेवोत्तम' मॉडल की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इस मार्ग में अभी भी कौन-सी संरचनात्मक बाधाएँ विद्यमान हैं?

• **उत्तर संरचना प्रारूप (Answer Structure Blueprint):**

1. **प्रस्तावना:** 2nd ARC की 11वीं व 12वीं रिपोर्ट के संदर्भ में 'सरकार-केंद्रित' (औपनिवेशिक बाबूशाही) से 'नागरिक-केंद्रित' (Citizen-Centric Governance) प्रतिमान में बदलाव का परिचय।

2. **मुख्य भाग - खंड A: DPI (India Stack) और सेवोत्तम की परिवर्तनकारी उपलब्धियाँ:**

• **वित्तीय समावेशन एवं रिसाव की समाप्ति:** JAM ट्रिनिटी और DBT के माध्यम से ₹38 लाख करोड़ से अधिक का प्रत्यक्ष हस्तांतरण, जिसने फर्जी लाभार्थियों को हटाकर लगभग ₹3.48 लाख करोड़ की बचत की।

• **सेवा मानकीकरण (सेवोत्तम — IS 15700):** नागरिक चार्टर, CPGRAMS (21-दिवसीय निवारण समय-सीमा व AI-आधारित भाषिणी एकीकरण) और आंतरिक सेवा क्षमता के त्रिकोणीय एकीकरण ने समयबद्ध जवाबदेही तय की।

• **पोर्टेबिलिटी व कागज़-रहित शासन:** ONORC द्वारा प्रवासी श्रमिकों को राशन, DigiLocker द्वारा 600 करोड़+ प्रमाणित दस्तावेज और ई-संजीवनी द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य परामर्श।

3. **मुख्य भाग - खंड B: विद्यमान संरचनात्मक चुनौतियाँ:**

• **बायोमेट्रिक बहिष्करण और डिजिटल डिवाइड:** वृद्धों व श्रमिकों के अंगूठे के निशान घिसने या ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी से कल्याणकारी लाभ से वंचित होना (*Exclusion by Technology*)।

• **अदंत नागरिक चार्टर (Toothless Citizen's Charters):** केंद्रीय स्तर पर चार्टर के उल्लंघन पर स्वतः मुआवजे या दंड का वैधानिक प्रावधान न होना।

• **साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता:** फिशिंग धोखाधड़ी और नागरिकों में अपने डेटा अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव।

4. **निष्कर्ष (Way Forward):** DPDP अधिनियम 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन, ऑफलाइन/मानवीय विकल्प (*Assisted Digital Access — CSCs*) को बनाए रखने और 'लोक सेवा के अधिकार' को केंद्रीय स्तर पर कानूनी दर्जा देने का सुझाव।

2.4 मास्टर एनसाइक्लोपीडिया सारणी (Master Encyclopedia Reference Table — Book *28*)

आयोग / समिति / न्यायिक निर्णय / अधिनियम	वर्ष	संबंधित क्षेत्र (Domain)	मुख्य संस्तुति / ऐतिहासिक निर्णय / प्रावधान
काका कालेलकर आयोग	1953	प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (अनुच्छेद 340)	सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान का प्रथम प्रयास
संथानम समिति	1962–64	भ्रष्टाचार निवारण	इसी की सिफारिश पर 1964 में **केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)** की स्थापना हुई
प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1st ARC)	1966	मोरारजी देसाई / के. हनुमंतैया	भारत में नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु **लोकपाल एवं लोकायुक्त** की स्थापना की प्रथम सिफारिश
मंडल आयोग (बी.पी. मंडल)	1979–80 (1990 में लागू)	द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग	OBC को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश; इंद्रा साहनी वाद (1992) में 50% सीमा व क्रीमी लेयर के साथ वैध ठहराया गया
विशाखा बनाम राजस्थान राज्य	1997	कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने हेतु बाध्यकारी गाइडलाइंस, जो 2013 में **POSH Act** बनीं
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC)	2005–09	वीरप्पा मोइली (15 रिपोर्टें)	शासन में नैतिकता (4वीं), ई-गवर्नेंस (11वीं), नागरिक-केंद्रित प्रशासन व सेवोत्तम (12वीं रिपोर्ट)
सच्चर समिति एवं रंगनाथ मिश्रा आयोग	2005–07	अल्पसंख्यक कल्याण	मुस्लिम समुदाय की सामाजिक-आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का मूल्यांकन और समान अवसर आयोग का सुझाव
नालसा बनाम भारत संघ	2014	ट्रांसजेंडर अधिकार	ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 'तृतीय लिंग' के रूप में संवैधानिक मान्यता; इसके बाद 2019 का अधिनियम बना
के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (9-जज पीठ)	2017	निजता एवं आधार	निजता के अधिकार (Right to Privacy) को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया; इसके बाद **DPDP Act 2023** बना
जनहित अभियान बनाम भारत संघ (5-जज पीठ)	2022	EWS आरक्षण (103वाँ संशोधन)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण को 3:2 के बहुमत से संवैधानिक रूप से वैध ठहराया
पंजाब राज्य बनाम देविंदर सिंह (7-जज पीठ)	2024	SC/ST उप-वर्गीकरण	ई.वी. चिन्नैया (2004) के निर्णय को पलटकर राज्यों को SC/ST कोटे के भीतर अधिक पिछड़ी जातियों के लिए उप-वर्गीकरण की अनुमति दी
भारतीय न्याय संहिता (BNS), BNSS एवं BSA	2023 (1 जुलाई 2024 से लागू)	आपराधिक न्याय प्रणाली का वि-उपनिवेशीकरण	IPC 1860, CrPC 1973 और साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रतिस्थापन; महिला व बाल अपराधों को प्राथमिकता, जीरो FIR, ई-FIR और फॉरेंसिक साक्ष्य की अनिवार्यता

28.1 उच्च-स्तरीय समाजशास्त्रीय एवं सामाजिक न्याय तथ्य संकलन

एनसीईआरटी के समाजशास्त्र ग्रंथों ('भारतीय समाज' तथा 'भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास' - ncert.nic.in) एवं संवैधानिक प्रावधानों (dopt.gov.in, www.iucacademy.com) के अनुसार भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं विविधता में एकता, जाति एवं वर्ग संरचना का गतिशील अंतर्संबंध, संयुक्त परिवार प्रणाली में संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक परिवर्तन, जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend), नगरीकरण, धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक सकारात्मक विभेद (Affirmative Action) हैं।

- **प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री एवं उनकी मौलिक अवधारणाएं:**
- **एम.एन. श्रीनिवास (M.N. Srinivas):** 'संस्कृतिकरण' (Sanskritisation), 'पश्चिमीकरण' (Westernisation), 'प्रभु जाति' (Dominant Caste) तथा 'धर्मनिरपेक्षीकरण' (Secularisation) की अवधारणाएं (प्रसिद्ध कृति: *Social Change in Modern India*)।
- **जी.एस. घुर्ये (G.S. Ghurye):** भारतीय समाजशास्त्र के जनक; जाति व्यवस्था की छह मूलभूत विशेषताओं (खंडात्मक विभाजन, संस्तरण, भोजन व सहवास पर प्रतिबंध, नागरिक व धार्मिक निर्योग्यताएं, पेशे के चुनाव का अभाव और अंतर्विवाह) का विश्लेषण (कृति: *Caste and Race in India*)।
- **इरावती कर्वे:** भारत में नातेदारी संगठन (*Kinship Organization in India*) का चार सांस्कृतिक क्षेत्रों (उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और पूर्वी) में तुलनात्मक अध्ययन।
- **संवैधानिक एवं वैधानिक सामाजिक न्याय तंत्र:** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण हेतु संविधान के भाग-III (मौलिक अधिकार) व भाग-IV (राज्य के नीति निदेशक तत्व) तथा विशिष्ट वैधानिक आयोग कार्यरत हैं।

28.2 विस्तृत तुलनात्मक सारणियाँ (खंड 28)

तुलनात्मक सारणी 28.1: भारतीय समाज के प्रमुख समाजशास्त्रीय प्रक्रमों एवं अवधारणाओं का तुलनात्मक विश्लेषण

समाजशास्त्रीय अवधारणा	प्रतिपादक विद्वान एवं प्रमुख कृति (ncert.nic.in)	अवधारणा की मूल परिभाषा एवं समाजशास्त्रीय तंत्र	भारतीय समाज पर प्रभाव एवं परिवर्तन की प्रकृति	मुख्य सीमाएं एवं समालोचना
संस्कृतिकरण (Sanskritisation)	**एम.एन. श्रीनिवास** (*Religion and Society among the Coorgs of South India*)	वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति किसी उच्च और प्रायः 'द्विज' जाति के रीति-रिवाजों, कर्मकांडों, विचारधारा और जीवन-शैली का अनुकरण कर स्थानीय जाति संस्तरण में अपनी प्रस्थिति (Status) ऊंची करने का दावा करती है	यह केवल **'स्थितिमूलक परिवर्तन' (Positional Change)** लाती है, संपूर्ण जाति ढांचे में कोई 'संरचनात्मक परिवर्तन' (Structural Change) नहीं करती	यह ऊंच-नीच और पवित्रता-अपवित्रता की श्रेणीबद्ध मानसिकता को चुनौती देने के बजाय उसे प्रकारांतर से स्वीकार कर लेती है
प्रभु जाति (Dominant Caste)	**एम.एन. श्रीनिवास** (*The Dominant Caste in Rampura*)	ग्रामीण भारत में वह जाति जो संख्यात्मक शक्ति, कृषि भूमि के बड़े हिस्से पर स्वामित्व, स्थानीय राजनीतिक प्रभाव और संस्कारगत रूप से मध्यम या उच्च स्थान रखती है	स्वतंत्रता के पश्चात जमींदारी उन्मूलन और वयस्क मताधिकार के कारण मध्यम कृषक जातियों का क्षेत्रीय राजनीति और पंचायती राज में प्रभावशाली उदय हुआ	आधुनिक नगरीकरण, गैर-कृषि रोजगार और दलित-पिछड़ा राजनीतिक चेतना के विस्तार से एकल जाति के प्रभुत्व में कमी आई है

समाजशास्त्रीय अवधारणा	प्रतिपादक विद्वान एवं प्रमुख कृति (ncert.nic.in)	अवधारणा की मूल परिभाषा एवं समाजशास्त्रीय तंत्र	भारतीय समाज पर प्रभाव एवं परिवर्तन की प्रकृति	मुख्य सीमाएं एवं समालोचना
पश्चिमीकरण (Westernisation) एवं आधुनिकीकरण	**एम.एन. श्रीनिवास** एवं **योगेंद्र सिंह** (*Modernization of Indian Tradition*)	150 वर्षों से अधिक के ब्रिटिश शासन के परिणामस्वरूप भारतीय समाज की प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, विचारधारा और मूल्यों (मानवतावाद, तर्कबुद्धिवाद, समतावाद) में आया परिवर्तन	आधुनिक शिक्षा, प्रेस, न्याय प्रणाली, परिवहन और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार हुआ, किंतु पारंपरिक मूल्यों ने भी अनुकूलन (Adaptive Modernization) किया	बाह्य जीवन-शैली या उपभोक्तावाद का अंधानुकरण वास्तविक वैज्ञानिक और तार्किक आधुनिकीकरण से भिन्न है
लघु परंपरा एवं वृहद परंपरा (Little and Great Tradition)	**रॉबर्ट रेडफील्ड** एवं भारतीय संदर्भ में **मिल्टन सिंगर** व **मैकिम मैरियट**	वृहद परंपरा शास्त्रीय, लिखित एवं अभिजात वर्ग की अखिल भारतीय सांस्कृतिक परंपरा है; लघु परंपरा स्थानीय, मौखिक और लोक-समुदायों की अलिखित परंपरा है	मैकिम मैरियट ने किशनगढ़ी गांव के अध्ययन में **'सार्वभौमीकरण' (Universalisation)** (लघु का वृहद में मिलना) और **'स्थानीयकरण' (Parochialisation)** (वृहद तत्वों का लोक रूप लेना) को स्पष्ट किया	भारत की सांस्कृतिक एकता स्थानीय लोक परंपराओं और अखिल भारतीय शास्त्रीय परंपराओं के निरंतर संवाद से निर्मित हुई है
सांप्रदायिकता (Communalism) बनाम भारतीय धर्मनिरपेक्षता	एनसीईआरटी समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान (ncert.nic.in)	सांप्रदायिकता धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है; भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के प्रति समान आदर (**'सर्वधर्म समभाव'**) तथा सैद्धांतिक दूरी (Principled Distance) पर आधारित है	पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के 'राज्य और चर्च के पूर्ण अलगाव' के विपरीत भारतीय राज्य धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए सामाजिक कुरीतियों (जैसे अस्पृश्यता, तीन तलाक) के उन्मूलन हेतु सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है	संवैधानिक मूल्यों (अनुच्छेद 25–28) और बंधुता का सुदृढ़ीकरण बहुलतावादी समाज के सामंजस्य के लिए अनिवार्य है

तुलनात्मक सारणी 28.2: सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक एवं वैधानिक आयोगों की संरचना, अनुच्छेद एवं शक्तियों का विश्लेषण

आयोग का नाम	संवैधानिक / वैधानिक आधार एवं स्थापना वर्ष	संरचना (अध्यक्ष एवं सदस्य)	नियुक्ति एवं सेवा शर्तें (dopt.gov.in)	प्रमुख कार्य एवं न्यायिक शक्तियां
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)	**अनुच्छेद 338** (89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा फरवरी 2004 में पृथक संवैधानिक निकाय बना)	1 अध्यक्ष + 1 उपाध्यक्ष + 3 अन्य सदस्य (कुल 5 सदस्य)	राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र (Warrant under his hand and seal) द्वारा नियुक्ति; सामान्य कार्यकाल 3 वर्ष	अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षणों की निगरानी व शिकायतों की जांच; जांच करते समय इसे **सिविल न्यायालय (Civil Court)** की समस्त शक्तियां प्राप्त हैं
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)	**अनुच्छेद 338A** (89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा 19 फरवरी 2004 से प्रभावी)	1 अध्यक्ष + 1 उपाध्यक्ष + 3 अन्य सदस्य (कम से कम एक महिला सदस्य अनिवार्य)	राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति; अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री के समकक्ष दर्जा	अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों, वनाधिकार, विस्थापन से सुरक्षा और पांचवीं/छठी अनुसूची के विषयों पर राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)	**अनुच्छेद 338B** (मूलतः 1993 में वैधानिक; **102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018** द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त)	1 अध्यक्ष + 1 उपाध्यक्ष + 3 अन्य सदस्य	राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति; केंद्र या राज्य सरकार को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) से संबंधित नीतिगत मामलों में परामर्श देना	सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के संवैधानिक व विधिक रक्षोपायों के क्रियान्वयन की जांच करना और सिविल न्यायालय के समान साक्ष्य तलब करना
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)	मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, **1993** (यथासंशोधित **2019**) — एक वैधानिक निकाय	1 अध्यक्ष (भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश) + 5 पूर्णकालिक सदस्य + 7 पदेन सदस्य	प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6-सदस्यीय समिति (लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता व राज्यसभा के उपसभापति) की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति	कार्यकाल: **3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु** (2019 के संशोधन द्वारा 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष किया गया तथा पुनर्नियुक्ति की पात्रता दी गई)

आयोग का नाम	संवैधानिक / वैधानिक आधार एवं स्थापना वर्ष	संरचना (अध्यक्ष एवं सदस्य)	नियुक्ति एवं सेवा शर्तें (dopt.gov.in)	प्रमुख कार्य एवं न्यायिक शक्तियां
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)	NCW: राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, **1990** (गठन जनवरी 1992); NCPCR: बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, **2005** (गठन मार्च 2007)	NCW: 1 अध्यक्ष + 5 सदस्य + 1 सदस्य-सचिव; NCPCR: 1 अध्यक्ष + 6 सदस्य (जिनमें कम से कम 2 महिलाएं अनिवार्य)	केंद्र सरकार (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) द्वारा नियुक्ति; कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष	महिलाओं के संवैधानिक व विधिक अधिकारों की समीक्षा और शिकायतों पर स्वतः संज्ञान (Suo-motu notice); NCPCR द्वारा 0 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के अधिकारों, POCSO व RTE अधिनियम की निगरानी

तुलनात्मक सारणी 28.3: कमजोर वर्गों, महिलाओं, बच्चों एवं दिव्यांगजनों के संरक्षण हेतु प्रमुख अधिनियमों एवं कल्याणकारी योजनाओं का विश्लेषण

लक्षित वर्ग	प्रमुख सुरक्षात्मक अधिनियम एवं वर्ष	संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद (ncert.nic.in)	प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं / मिशन (www.iucacademy.com)	मुख्य वैधानिक अधिकार एवं दंडात्मक/लाभकारी प्रावधान
महिलाएं (Women Empowerment & Protection)	घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम (2005); कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम - **POSH Act (2013)**; दहेज प्रतिषेध अधिनियम (1961)	अनुच्छेद 14, 15(3), 16, 39(a), 39(d) (समान कार्य के लिए समान वेतन), अनुच्छेद 42 (प्रसूति सहायता), अनुच्छेद 51A(e), अनुच्छेद 243D व **106वां संविधान संशोधन (2023)**	मिशन शक्ति (संबल और सामर्थ्य उप-योजनाएं), बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ (2015), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना	POSH अधिनियम 2013 (विशाखा दिशानिर्देश 1997 पर आधारित) के तहत 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर **'आंतरिक शिकायत समिति' (ICC)** का गठन अनिवार्य; 106वें संशोधन (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण
बच्चे (Child Rights & Nutrition)	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act, 2009); लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (**POCSO Act, 2012** व संशोधन 2019); किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act, 2015); बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम (2016)	अनुच्छेद 21A (6–14 वर्ष निःशुल्क शिक्षा), अनुच्छेद 24 (14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों/खानों में नियोजन निषिद्ध), अनुच्छेद 39(e)-(f), अनुच्छेद 45	सक्षम आंगनवाड़ी एवं **पोषण 2.0 (POSHAN 2.0)**, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM-POSHAN), मिशन वात्सल्य, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन	बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 (labour.gov.in) के तहत **14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों में रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध** और 14–18 वर्ष के किशोरों के खतरनाक व्यवसायों में नियोजन पर प्रतिबंध
अनुसूचित जाति एवं जनजाति (SC & ST)	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम (1955); अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, **1989** (संशोधित 2015 व 2018); अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम - **FRA (2006)**	अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत), अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 244 (5वीं व 6वीं अनुसूची), अनुच्छेद 330 व 332 (लोकसभा व विधानसभाओं में आरक्षण - **104वें संशोधन द्वारा 2030 तक विस्तारित**)	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY), स्टैंड-अप इंडिया योजना, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS), प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (**PM-JANMAN - 75 PVTG समूहों हेतु**)	वनाधिकार अधिनियम (FRA) 2006 वनवासी अनुसूचित जनजातियों और कम से कम 3 पीढ़ियों (75 वर्ष) से वन भूमि पर निर्भर अन्य परंपरागत वन निवासियों को व्यक्तिगत (अधिकतम 4 हेक्टेयर) और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रदान करता है

लक्षित वर्ग	प्रमुख सुरक्षात्मक अधिनियम एवं वर्ष	संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद (ncert.nic.in)	प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं / मिशन (www.iucacademy.com)	मुख्य वैधानिक अधिकार एवं दंडात्मक/लाभकारी प्रावधान
दिव्यांगजन (Persons with Disabilities)	**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act, 2016)** (इसने 1995 के अधिनियम का स्थान लिया और संयुक्त राष्ट्र के UNCRPD अभिसमय को लागू किया)	अनुच्छेद 41 (काम, शिक्षा और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी व निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार)	सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign), एडिप (ADIP) योजना, दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (DDRS), विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID)	RPwD अधिनियम 2016 में दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 **से बढ़ाकर 21** किया गया (जिसमें एसिड अटैक पीड़ित, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल रोग, पार्किंसंस, ऑटिज्म आदि शामिल हैं); सरकारी नौकरियों में बेंचमार्क दिव्यांगजनों (40%+) को **4% आरक्षण** और उच्च शिक्षण संस्थानों में **5% आरक्षण**
वरिष्ठ नागरिक एवं ट्रांसजेंडर समुदाय	माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम (**2007**); ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम (**2019**)	अनुच्छेद 14, 15, 21 (गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार - नालसा बनाम भारत संघ, 2014) एवं अनुच्छेद 41	अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY), राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना; ट्रांसजेंडर एवं भिक्षावृत्ति में लगे लोगों हेतु **'स्माइल' (SMILE) योजना**	2007 के अधिनियम के तहत संतान/उत्तराधिकारियों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण की विधिक बाध्यता और अधिकरण (Tribunal) का गठन; 2019 के अधिनियम द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्व-अनुभूत लिंग पहचान का अधिकार और राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन

28.3 उच्च-स्तरीय व्याख्या सहित बहुविकल्पीय प्रश्न (खंड 28: प्रश्न 1 से 20)

अभ्यास प्रश्न #1 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 1. जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत (Demographic Transition Theory) के संदर्भ में, जब कोई समाज उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की प्रथम अवस्था से निकलकर दूसरी अवस्था (जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास से मृत्यु दर तेजी से गिरती है किंतु जन्म दर ऊंची बनी रहती है, जिससे जनसंख्या विस्फोट होता है) को पार कर 'तीसरी अवस्था' में प्रवेश करता है, तो उसकी मुख्य जनसांख्यिकीय विशेषता क्या होती है, और 'प्रतिस्थापन स्तर की कुल प्रजनन दर' (Replacement Level Total Fertility Rate - TFR) का मानक मान कितना माना जाता है?

(A) तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाती हैं और जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर होने लगती है; प्रतिस्थापन स्तर की कुल प्रजनन दर (TFR) का मानक मान **2.1 बच्चे प्रति महिला** माना जाता है

(B) तीसरी अवस्था में मृत्यु दर जन्म दर से दोगुनी हो जाती है; प्रतिस्थापन स्तर TFR 5.0 होता है

(C) तीसरी अवस्था में केवल शिशु मृत्यु दर बढ़ती है; प्रतिस्थापन स्तर TFR 1.0 होता है

(D) जनसांख्यिकीय संक्रमण का जन्म दर या मृत्यु दर से कोई संबंध नहीं है

सही उत्तर: (A) तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाती हैं और जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर होने लगती है; प्रतिस्थापन स्तर की कुल प्रजनन दर (TFR) का मानक मान **2.1 बच्चे प्रति महिला** माना जाता है

विस्तृत व्याख्या:

- एनसीईआरटी समाजशास्त्र ('भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना' - ncert.nic.in) के अनुसार फ्रैंक डब्ल्यू. नोटेस्टीन द्वारा विकसित जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत में तीन मुख्य चरण हैं: प्रथम चरण (अल्पविकसित कृषि समाज—उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर, जैसे 1921 से पूर्व का भारत; 1921 को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में 'महान विभाजक वर्ष' कहा जाता है); द्वितीय चरण (संक्रमणकारी अवस्था—मृत्यु दर में तीव्र गिरावट किंतु जन्म दर उच्च रहने से 'जनसंख्या विस्फोट'); तथा तृतीय चरण (विकसित/आधुनिक अवस्था—शिक्षा और शहरीकरण से जन्म दर में भी गिरावट और कम मृत्यु दर)।
- जब कुल प्रजनन दर (TFR) **2.1** पर आ जाती है, तो एक पीढ़ी स्वयं को अगली पीढ़ी से बिना जनसंख्या बढ़ाए प्रतिस्थापित कर लेती है (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार भारत राष्ट्रीय स्तर पर 2.0 TFR प्राप्त कर चुका है)।

अभ्यास प्रश्न #2 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 2. भारतीय समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित 'संस्कृतिकरण' (Sanskritisation) की अवधारणा की समालोचना करते हुए एनसीईआरटी समाजशास्त्र में इसके किन विरोधाभासी आयामों को रेखांकित किया गया है?

(A) संस्कृतिकरण निम्न जातियों की केवल व्यक्तिगत/सामूहिक स्थिति में ऊर्ध्वगामी गतिशीलता (Positional Mobility) लाता है किंतु जाति व्यवस्था की असमान संरचना को समाप्त नहीं करता; साथ ही उच्च जातियों के अनुकरण के परिणामस्वरूप उन समुदायों में महिलाओं की पूर्ववर्ती अपेक्षाकृत स्वतंत्र स्थिति के स्थान पर पर्दा प्रथा, दहेज और लैंगिक बंधनों को बढ़ावा मिलता है।

(B) संस्कृतिकरण से भारत में जाति व्यवस्था एक ही वर्ष में पूर्णतः समाप्त हो गई।

(C) संस्कृतिकरण का अर्थ केवल अंग्रेजी भाषा सीखना और पश्चिमी वेशभूषा अपनाना है।

(D) यह अवधारणा कार्ल मार्क्स द्वारा यूरोपीय कारखानों के लिए दी गई थी।

सही उत्तर: (A) संस्कृतिकरण निम्न जातियों की केवल व्यक्तिगत/सामूहिक स्थिति में ऊर्ध्वगामी गतिशीलता (Positional Mobility) लाता है किंतु जाति व्यवस्था की असमान संरचना को समाप्त नहीं करता; साथ ही उच्च जातियों के अनुकरण के परिणामस्वरूप उन समुदायों में महिलाओं की पूर्ववर्ती अपेक्षाकृत स्वतंत्र स्थिति के स्थान पर पर्दा प्रथा, दहेज और लैंगिक बंधनों को बढ़ावा मिलता है।

विस्तृत व्याख्या:

• एनसीईआरटी ('सांस्कृतिक परिवर्तन' - ncert.nic.in) में स्पष्ट किया गया है कि एम.एन. श्रीनिवास की 'संस्कृतिकरण' की अवधारणा से पूर्व यह माना जाता था कि जाति व्यवस्था पूरी तरह कठोर और गतिहीन है; श्रीनिवास ने दिखाया कि जाति के भीतर स्थितिमूलक गतिशीलता संभव है।

• किंतु समाजशास्त्रियों (विशेषकर नारीवादी और दलित चिंतकों) ने इसकी दो प्रमुख सीमाएं बताई हैं: प्रथम, यह असमानता और बहिष्कार पर टिके जातिगत सोपान (Hierarchy) को स्वाभाविक मान लेती है; द्वितीय, जिन श्रमिक और जनजातीय समुदायों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और सामाजिक स्वतंत्रता अधिक थी, वहाँ संस्कृतिकरण के प्रभाव से वधू-मूल्य (Bride Price) के स्थान पर 'दहेज प्रथा' (Dowry) और महिलाओं के श्रम व आवागमन पर कठोर नियंत्रण जैसी पितृसत्तात्मक प्रवृत्तियां बढ़ीं।

अभ्यास प्रश्न #3 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में क्रमशः **103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019** द्वारा कौन-से नए खंड जोड़े गए, जिनके माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically Weaker Sections - EWS) के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नियुक्तियों में अधिकतम **10% आरक्षण** का प्रावधान किया गया, और सर्वोच्च न्यायालय की किस संविधान पीठ ने नवंबर 2022 में इसकी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा?

(A) अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6); सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) (3:2 के बहुमत से संविधान के मूल ढांचे के अनुकूल घोषित)

(B) अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4); इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992)

(C) अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 51A; केशवानंद भारती मामला (1973)

(D) अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332; मिनर्वा मिल्स मामला (1980)

सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6); सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) (3:2 के बहुमत से संविधान के मूल ढांचे के अनुकूल घोषित)

विस्तृत व्याख्या:

• मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस.आर. सिन्हा आयोग की पृष्ठभूमि में संसद द्वारा पारित **103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019** (dopt.gov.in) ने संविधान में दो नए खंड जोड़े: **अनुच्छेद 15(6)** (निजी शिक्षण संस्थानों—अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर—सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु EWS को अधिकतम 10% आरक्षण) तथा **अनुच्छेद 16(6)** (लोक नियोजन/सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़े वर्गों से भिन्न आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अधिकतम 10% आरक्षण)।

• 7 नवंबर 2022 को जनहित अभियान बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5-सदस्यीय संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से निर्णय दिया कि आर्थिक मानदंड पर आधारित यह आरक्षण संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) या समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता।

अभ्यास प्रश्न #4 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 4. भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के कल्याण और आरक्षण के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित आयोगों/निर्णयों का सही कालानुक्रमिक और तथ्यात्मक विवरण कौन-सा है?

(A) प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग: काका कालेलकर आयोग (1953, अनुच्छेद 340 के तहत); द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग: बी.पी. मंडल आयोग (1979 में गठित, 1980 में रिपोर्ट प्रस्तुत — 27% आरक्षण की सिफारिश); सर्वोच्च न्यायालय का इंद्रा साहनी निर्णय (1992) — क्रीमी लेयर (Creamy Layer) के अपवर्जन और 50% की सामान्य आरक्षण सीमा के साथ 27% OBC आरक्षण की वैधता; तथा अक्टूबर 2017 में गठित **न्यायमूर्ति जी. रोहिणी आयोग** — केंद्रीय OBC सूची के उप-वर्गीकरण (Sub-categorization) के अध्ययन हेतु।

(B) प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1990 में बना था और काका कालेलकर आयोग 2015 में।

(C) क्रीमी लेयर की अवधारणा अनुसूचित जनजातियों के लिए 1950 में लागू की गई थी।

(D) पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत की जाती है।

सही उत्तर: (A) प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग: काका कालेलकर आयोग (1953, अनुच्छेद 340 के तहत); द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग: बी.पी. मंडल आयोग (1979 में गठित, 1980 में रिपोर्ट प्रस्तुत — 27% आरक्षण की सिफारिश); सर्वोच्च न्यायालय का इंद्रा साहनी निर्णय (1992) — क्रीमी लेयर (Creamy Layer) के अपवर्जन और 50% की सामान्य आरक्षण सीमा के साथ 27% OBC आरक्षण की वैधता; तथा अक्टूबर 2017 में गठित **न्यायमूर्ति जी. रोहिणी आयोग** — केंद्रीय OBC सूची के उप-वर्गीकरण (Sub-categorization) के अध्ययन हेतु।

विस्तृत व्याख्या:

- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 340** के तहत राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है (ncert.nic.in, dopt.gov.in)।
- इसके तहत जनवरी 1953 में **काका कालेलकर** की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग और जनवरी 1979 में **बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल (बी.पी. मंडल)** की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ।
- 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने पर इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) के ऐतिहासिक निर्णय में 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने OBC के 27% आरक्षण को वैध ठहराया, किंतु संपन्न तबके ('क्रीमी लेयर' — जिसके मानदंड तय करने हेतु राम नंदन प्रसाद समिति बनी) को आरक्षण लाभ से बाहर करने का निर्देश दिया।
- बाद में केंद्रीय OBC सूची के भीतर लाभ के न्यायसंगत वितरण हेतु अनुच्छेद 340 के तहत अक्टूबर 2017 में **न्यायमूर्ति जी. रोहिणी आयोग** का गठन किया गया।

अभ्यास प्रश्न #5 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 5. अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधानों को जनजातीय स्वशासन और परंपराओं के अनुरूप विस्तारित करने वाला **'पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996' (PESA Act, 1996)** किस समिति की सिफारिश पर पारित किया गया, और यह संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आने वाले कितने राज्यों पर लागू होता है?

(A) भूरिया समिति (दिलीप सिंह भूरिया समिति, 1994–95) की सिफारिश पर; यह संविधान की **पांचवीं अनुसूची (Fifth Schedule)** वाले **10 राज्यों** (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान) के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होता है।

(B) बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर; छठी अनुसूची के 4 राज्यों पर लागू होता है।

(C) सरकारिया आयोग की सिफारिश पर; भारत के सभी 28 राज्यों पर लागू होता है।

(D) फजल अली आयोग की सिफारिश पर; केवल केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है।

सही उत्तर: (A) भूरिया समिति (दिलीप सिंह भूरिया समिति, 1994–95) की सिफारिश पर; यह संविधान की **पांचवीं अनुसूची (Fifth Schedule)** वाले **10 राज्यों** (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान) के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होता है।

विस्तृत व्याख्या:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243M के अनुसार भाग-IX (पंचायत) के प्रावधान अनुच्छेद 244(1) में निर्दिष्ट पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों और अनुच्छेद 244(2) के जनजातीय क्षेत्रों पर स्वतः लागू नहीं होते थे, अपितु संसद विधि द्वारा उन्हें संशोधनों सहित विस्तारित कर सकती थी।

• इसी क्रम में **दिलीप सिंह भूरिया समिति** की सिफारिश पर संसद ने **PESA अधिनियम, 1996** पारित किया (ncert.nic.in, www.iucacademy.com)।

• यह पांचवीं अनुसूची के 10 राज्यों में ग्राम सभा को अत्यंत व्यापक शक्तियां देता है—जैसे गौण वनोपज (Minor Forest Produce) का स्वामित्व, भूमि हस्तांतरण की रोकथाम, हाट-बाजारों का प्रबंधन, मादक द्रव्यों की बिक्री पर नियंत्रण और गौण खनिजों के खनन पट्टे से पूर्व ग्राम सभा की अनिवार्य अनुशंसा/परामर्श।

अभ्यास प्रश्न #6 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 6. भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (Particularly Vulnerable Tribal Groups - PVTGs), जिन्हें पूर्व में 'आदिम जनजातीय समूह' (PTGs) कहा जाता था, की पहचान सर्वप्रथम किस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर की गई, और गृह मंत्रालय द्वारा भारत में ऐसे कुल कितने PVTG समूहों को अधिसूचित किया गया है (जिनमें सर्वाधिक किस राज्य में हैं)?

(A) ढेबर आयोग (1960–61, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग); भारत में कुल **75 PVTG समूह** (18 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान-निकोबार में) अधिसूचित हैं, जिनमें सर्वाधिक **13 समूह ओडिशा** राज्य में हैं।

(B) मंडल आयोग (1980); कुल 50 समूह, सर्वाधिक पंजाब में हैं।

(C) कोठारी आयोग (1964); कुल 100 समूह, सर्वाधिक हरियाणा में हैं।

(D) सच्चर समिति (2005); कुल 25 समूह, सर्वाधिक गोवा में हैं।

सही उत्तर: (A) ढेबर आयोग (1960–61, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग); भारत में कुल **75 PVTG समूह** (18 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान-निकोबार में) अधिसूचित हैं, जिनमें सर्वाधिक **13 समूह ओडिशा** राज्य में हैं।

विस्तृत व्याख्या:

• संविधान के अनुच्छेद 339(1) के तहत वर्ष 1960 में गठित **यू.एन. ढेबर आयोग** ने पाया कि अनुसूचित जनजातियों के भीतर भी कुछ समूह विकास के पैमाने पर अत्यंत पीछे हैं (ncert.nic.in, www.iucacademy.com)।

• इसके आधार पर 1973 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 52 समूहों को और बाद में 23 और समूहों को जोड़कर कुल **75 जनजातीय समूहों** को PVTG घोषित किया गया।

• इनकी पहचान के चार मुख्य मानदंड हैं: (1) कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी (Pre-agricultural level of technology), (2) स्थिर या घटती जनसंख्या (Stagnant or declining population), (3) अत्यधिक निम्न साक्षरता दर, और (4) निर्वाह स्तर की अर्थव्यवस्था (Subsistence level of economy)।

• राज्यवार सर्वाधिक 13 PVTG समूह **ओडिशा** में (और उसके बाद आंध्र प्रदेश में 12) पाए जाते हैं।

• नवंबर 2023 में इनके समग्र विकास हेतु **'पीएम-जनमन' (PM-JANMAN)** अभियान प्रारंभ किया गया।

अभ्यास प्रश्न #7 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 7. कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (**POSH Act, 2013**) के वैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1997 में विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य के ऐतिहासिक मामले में जारी दिशा-निर्देशों को वैधानिक रूप प्रदान करता है।

2. इस अधिनियम के तहत 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक शासकीय एवं निजी कार्यस्थल पर नियोक्ता द्वारा एक 'आंतरिक शिकायत समिति' (Internal Complaints Committee - ICC) का गठन करना अनिवार्य है, जिसकी पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) अनिवार्य रूप से कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर पर नियोजित एक महिला होनी चाहिए और समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होनी चाहिए।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 और न ही 2

सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों

विस्तृत व्याख्या:

• कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (dopt.gov.in) और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित POSH अधिनियम, 2013 (9 दिसंबर 2013 से लागू) संवैधानिक अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(g) और अनुच्छेद 21 के तहत महिलाओं के सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण कार्यवातावरण के मौलिक अधिकार को संरक्षित करता है।

• दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं: अधिनियम की धारा 4 के अनुसार 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान में 'आंतरिक समिति' (IC) का गठन अनिवार्य है (तथा 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों या असंगठित क्षेत्र की घरेलू कामगार महिलाओं के लिए जिला अधिकारी द्वारा जिला स्तर पर 'स्थानीय समिति' - Local Committee गठित की जाती है)।

• आंतरिक समिति की अध्यक्ष वरिष्ठ महिला अधिकारी होती हैं, कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होती हैं और एक बाह्य सदस्य महिला-अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन (NGO) या विधिक विशेषज्ञ होता है।

अभ्यास प्रश्न #8 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 8. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (**NFSA, 2013** — जिसे 'भोजन के अधिकार' का वैधानिक आधार माना जाता है) के अंतर्गत देश की कितनी आबादी को कवरेज प्रदान किया गया है, और इसमें 'अंत्योदय अन्न योजना' (AAY) परिवारों तथा 'प्राथमिकता वाले परिवारों' (Priority Households - PHH) को प्रतिमाह कितना खाद्यान्न प्राप्त करने की कानूनी पात्रता है?

(A) ग्रामीण आबादी का 75% तक और शहरी आबादी का 50% तक (समग्र देश की लगभग 67% जनसंख्या); अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के परिवारों को **35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह** तथा प्राथमिकता वाले परिवारों (PHH) को **5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह** खाद्यान्न (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वर्तमान में पूर्णतः निःशुल्क) प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है।

(B) केवल 10% आबादी को; सभी को 2 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह।

(C) केवल शहरी आबादी के 100% को; ग्रामीण आबादी इसमें शामिल नहीं है।

(D) केवल नकद राशि दी जाती है, अनाज देने का प्रावधान नहीं है।

सही उत्तर: (A) ग्रामीण आबादी का 75% तक और शहरी आबादी का 50% तक (समग्र देश की लगभग 67% जनसंख्या); अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के परिवारों को **35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह** तथा प्राथमिकता वाले परिवारों (PHH) को **5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह** खाद्यान्न (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वर्तमान में पूर्णतः निःशुल्क) प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है।

विस्तृत व्याख्या:

• 5 जुलाई 2013 से प्रवृत्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (ncert.nic.in, www.iucacademy.com) ने खाद्य सुरक्षा को 'कल्याणकारी दृष्टिकोण' (Welfare Approach) से बदलकर 'अधिकार-आधारित दृष्टिकोण' (Rights-based Approach) बना दिया।

• इसमें दो श्रेणियां हैं: सबसे गरीब 'अंत्योदय अन्न योजना' (AAY - दिसंबर 2000 में प्रारंभ) के परिवार, जिन्हें परिवार के सदस्यों की संख्या के निरपेक्ष **35 किग्रा प्रति परिवार प्रतिमाह** अनाज मिलता है; तथा 'प्राथमिकता वाले परिवार' (PHH), जिन्हें **5 किग्रा प्रति व्यक्ति प्रतिमाह** अनाज मिलता है।

• इसके अतिरिक्त अधिनियम में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण के साथ कम से कम ₹6,000 का मातृत्व लाभ, 6 माह से 14 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी व विद्यालयों में निःशुल्क पोषाहार, और राशन कार्ड के लिए परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वरिष्ठतम महिला को 'परिवार का मुखिया' मानने का प्रावधान है।

अभ्यास प्रश्न #9 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 9. भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index - MPI) के संदर्भ में, वैश्विक MPI किन संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है, और नीति आयोग द्वारा जारी 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक' में वैश्विक MPI के 10 संकेतकों के अतिरिक्त कौन-से **दो नए भारतीय संकेतक** जोड़े गए हैं (जिससे राष्ट्रीय सूचकांक में कुल **3 आयाम और 12 संकेतक** हो जाते हैं)?

(A) वैश्विक MPI: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) द्वारा; नीति आयोग के राष्ट्रीय MPI में जोड़े गए 2 अतिरिक्त संकेतक हैं: स्वास्थ्य आयाम में **'मातृ स्वास्थ्य' (Maternal Health)** और जीवन-स्तर आयाम में **'बैंक खाता' (Bank Account)**

(B) वैश्विक MPI: विश्व व्यापार संगठन द्वारा; अतिरिक्त संकेतक: कार का स्वामित्व और विदेश यात्रा

(C) वैश्विक MPI: अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा; अतिरिक्त संकेतक: शेयर बाजार निवेश और क्रेडिट कार्ड

(D) राष्ट्रीय MPI में केवल प्रति व्यक्ति मासिक आय को ही एकमात्र संकेतक माना जाता है

सही उत्तर: (A) वैश्विक MPI: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) द्वारा; नीति आयोग के राष्ट्रीय MPI में जोड़े गए 2 अतिरिक्त संकेतक हैं: स्वास्थ्य आयाम में **'मातृ स्वास्थ्य' (Maternal Health)** और जीवन-स्तर आयाम में **'बैंक खाता' (Bank Account)**

विस्तृत व्याख्या:

- अलकायर और फोस्टर (Alkire-Foster) पद्धति पर आधारित वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2010 से **UNDP और OPHI** द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें 3 समान भार (1/3 प्रत्येक) वाले आयाम—**स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-स्तर**—तथा 10 संकेतक होते हैं (ncert.nic.in, www.iucacademy.com)।
- भारत में **नीति आयोग** राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (NFHS आंकड़ों पर आधारित) जारी करता है, जिसमें भारत की विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप 10 वैश्विक संकेतकों (पोषण, बाल व किशोर मृत्यु दर; स्कूली शिक्षा के वर्ष, विद्यालय में उपस्थिति; खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, आवास, परिसंपत्तियां) के साथ **2 अतिरिक्त संकेतक** जोड़े गए हैं: (1) स्वास्थ्य आयाम में **मातृ स्वास्थ्य** (प्रसवपूर्व देखभाल व संस्थागत प्रसव) और (2) जीवन-स्तर आयाम में **बैंक खाता** (वित्तीय समावेशन)।
- इस प्रकार राष्ट्रीय MPI में कुल **12 संकेतक** हैं।

अभ्यास प्रश्न #10 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 10. भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर, लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा तथ्य युग्म पूर्णतः सही है?

(A) भारत का समग्र लिंगानुपात: 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष; बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष): 919 बालिकाएं प्रति 1000 बालक; समग्र साक्षरता दर: 74.04% (पुरुष: 82.14%, महिला: 65.46%); सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य: मेघालय (27.95%) तथा ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य: नागालैंड (-0.58%)

(B) समग्र लिंगानुपात: 980; बाल लिंगानुपात: 960; साक्षरता दर: 85%

(C) सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य: अरुणाचल प्रदेश; न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य: बिहार

(D) सर्वाधिक शहरीकृत प्रतिशत वाला बड़ा राज्य: हिमाचल प्रदेश (90%)

सही उत्तर: (A) भारत का समग्र लिंगानुपात: 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष; बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष): 919 बालिकाएं प्रति 1000 बालक; समग्र साक्षरता दर: 74.04% (पुरुष: 82.14%, महिला: 65.46%); सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य: मेघालय (27.95%) तथा ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य: नागालैंड (-0.58%)

विस्तृत व्याख्या: भारत की 15वीं जनगणना (2011) के आधिकारिक आंकड़ों (ncert.nic.in) के अनुसार:

- देश की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ और दशकीय वृद्धि दर (2001–2011) **17.7%** रही।
- समग्र लिंगानुपात 2001 के 933 से बढ़कर 2011 में **943** हो गया (सर्वाधिक केरल: 1084, न्यूनतम राज्य हरियाणा: 879), किंतु 0–6 वर्ष का बाल लिंगानुपात 2001 के 927 से घटकर **919** रह गया (सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश: 972, न्यूनतम हरियाणा: 834)।
- जनसंख्या घनत्व **382 व्यक्ति/वर्ग किमी** रहा (राज्यों में सर्वाधिक बिहार: 1106 और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश: 17)।
- नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत **31.16%** और ग्रामीण जनसंख्या **68.84%** रही (प्रतिशत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा: 62.17%, बड़े राज्यों में तमिलनाडु: 48.4%, तथा सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत हिमाचल प्रदेश: 89.97%)।

अभ्यास प्रश्न #11 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 11. भारत में गरीबी रेखा (Poverty Line) के आकलन के लिए स्वतंत्रता के पश्चात गठित प्रमुख विशेषज्ञ समितियों को उनके गठन के सही कालानुक्रम (Chronological Order) में व्यवस्थित कीजिए:

1. वाई.के. अलग समिति (Y.K. Alagh Committee)
2. डी.टी. लकड़ावाला समिति (D.T. Lakdawala Committee)
3. सुरेश तेंदुलकर समिति (Suresh Tendulkar Committee)
4. सी. रंगराजन समिति (C. Rangarajan Committee)

सही कूट का चयन कीजिए:

(A) 1 → 2 → 3 → 4

(B) 2 → 1 → 4 → 3

(C) 4 → 3 → 2 → 1

(D) 1 → 3 → 2 → 4

सही उत्तर: (A) 1 → 2 → 3 → 4

विस्तृत व्याख्या: एनसीईआरटी अर्थशास्त्र (ncert.nic.in) के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण से जुड़ी प्रमुख आधिकारिक समितियों का कालानुक्रम इस प्रकार है:

1. **वाई.के. अलग कार्यदल (1979):** इसने पहली बार पोषण एवं न्यूनतम दैनिक कैलोरी आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा निर्धारित की—ग्रामीण क्षेत्र में **2,400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन** और शहरी क्षेत्र में **2,100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन**।
2. **डी.टी. लकड़ावाला समिति (1989 में गठित, 1993 में रिपोर्ट):** इसने राज्य-विशिष्ट गरीबी रेखाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 'कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' (CPI-AL) और शहरी क्षेत्र में 'औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' (CPI-IW) का प्रयोग करने की सिफारिश की।
3. **सुरेश तेंदुलकर समिति (2005 में गठित, 2009 में रिपोर्ट):** इसने कैलोरी मानदंड से हटकर स्वास्थ्य और शिक्षा पर निजी व्यय को गरीबी की टोकरी में शामिल किया, समरूप संदर्भ अवधि (URP) के स्थान पर मिश्रित संदर्भ अवधि (MRP) अपनाई और 2011-12 के लिए अखिल भारतीय गरीबी दर 21.9% आकलित की।
4. **सी. रंगराजन समिति (2012 में गठित, 2014 में रिपोर्ट):** इसने संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि (MMRP) के आधार पर कैलोरी के साथ-साथ प्रोटीन और वसा के मानकों को भी शामिल किया और 2011-12 के लिए गरीबी दर 29.5% आकलित की।

अभ्यास प्रश्न #12 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 12. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (यथासंशोधित 2021) के अंतर्गत 'जघन्य अपराध' (Heinous Offences — जिनके लिए किसी कानून में न्यूनतम 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का प्रावधान है) में संलिप्त किस आयु वर्ग के किशोरों के मामले में 'किशोर न्याय बोर्ड' (JJB) प्रारंभिक मूल्यांकन करके उन्हें वयस्क की भांति विचारण हेतु 'बाल न्यायालय' (Children's Court) में हस्तांतरित कर सकता है?

(A) 16 से 18 वर्ष के मध्य की आयु के किशोरों के मामले में

(B) 7 से 12 वर्ष के बच्चों के मामले में

(C) केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के मामले में

(D) 10 से 14 वर्ष के बच्चों के मामले में

सही उत्तर: (A) 16 से 18 वर्ष के मध्य की आयु के किशोरों के मामले में

विस्तृत व्याख्या:

- वर्ष 2012 के दिल्ली निर्भया कांड के पश्चात पुराने किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के स्थान पर **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015** (www.iucacademy.com) पारित किया गया।

• इसमें अपराधों को तीन श्रेणियों—छोटे अपराध (Petty - 3 वर्ष तक सजा), गंभीर अपराध (Serious - 3 से 7 वर्ष सजा) और जघन्य अपराध (Heinous - न्यूनतम 7 वर्ष या अधिक सजा)—में बांटा गया।

• अधिनियम की धारा 15 के अनुसार यदि **16 से 18 वर्ष** की आयु का कोई किशोर जघन्य अपराध करता है, तो किशोर न्याय बोर्ड (JJB) मनोवैज्ञानिकों की सहायता से उसकी मानसिक व शारीरिक क्षमता और अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता का प्रारंभिक मूल्यांकन करता है और उपयुक्त पाए जाने पर मामले को वयस्क के रूप में विचारण हेतु बाल न्यायालय (सत्र न्यायालय) को सौंप सकता है (किंतु किसी भी किशोर को मृत्युदंड या बिना रिहाई की संभावना वाला आजीवन कारावास नहीं दिया जा सकता)।

• साथ ही, 2021 के संशोधन द्वारा बच्चों के दत्तक ग्रहण (Adoption) का आदेश जारी करने का अधिकार न्यायालय के स्थान पर **जिला मजिस्ट्रेट (DM)** को दिया गया है।

अभ्यास प्रश्न #13 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 13. भारतीय समाज में नातेदारी (Kinship), परिवार और विवाह के समाजशास्त्रीय अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दावलियों का कौन-सा युग्म सही सुमेलित है?

(A) पितृवंशीय एवं पितृस्थानीय परिवार — जहाँ वंश पिता की रेखा से चलता है और विवाह के पश्चात वधू वर के पिता के घर रहती है; मातृवंशीय परिवार (जैसे मेघालय की खासी, गारो व जयंतिया जनजाति तथा केरल का पारंपरिक नायर समुदाय) — जहाँ वंश एवं संपत्ति का उत्तराधिकार माता से पुत्री को मिलता है, यद्यपि सत्ता एवं निर्णय का अधिकार प्रायः मामा (मातृ-भ्राता) के पास रहता है।

(B) मातृवंशीय समाज और मातृसत्तात्मक समाज दोनों हर परिस्थिति में एक ही होते हैं और वहाँ पुरुषों का कोई स्थान नहीं होता।

(C) बहिर्विवाह (Exogamy) का अर्थ केवल अपनी ही गोत्र या सपिंड के भीतर विवाह करना है।

(D) अंतर्विवाह (Endogamy) का अर्थ अपनी जाति के बाहर विवाह करना है।

सही उत्तर: (A) पितृवंशीय एवं पितृस्थानीय परिवार — जहाँ वंश पिता की रेखा से चलता है और विवाह के पश्चात वधू वर के पिता के घर रहती है; मातृवंशीय परिवार (जैसे मेघालय की खासी, गारो व जयंतिया जनजाति तथा केरल का पारंपरिक नायर समुदाय) — जहाँ वंश एवं संपत्ति का उत्तराधिकार माता से पुत्री को मिलता है, यद्यपि सत्ता एवं निर्णय का अधिकार प्रायः मामा (मातृ-भ्राता) के पास रहता है।

विस्तृत व्याख्या:

• एनसीईआरटी समाजशास्त्र ('सामाजिक संस्थाएं: निरंतरता एवं परिवर्तन' - ncert.nic.in) में स्पष्ट किया गया है कि **'मातृवंशीयता' (Matriliny)** और **'मातृसत्ता' (Matriarchy)** में महत्वपूर्ण अंतर है।

• मेघालय के खासी समाज में वंश और उत्तराधिकार माता से सबसे छोटी पुत्री ('का खद्दूह') को जाता है (मातृवंशीय), किंतु संपत्ति के नियंत्रण और पारिवारिक अधिकार की वास्तविक शक्ति पत्नी के भाई अर्थात मामा के हाथों में केंद्रित रहती है, इसलिए वे मातृवंशीय तो हैं किंतु पूर्णतः मातृसत्तात्मक नहीं।

• वहीं, विवाह के नियमों में **'अंतर्विवाह' (Endogamy)** का अर्थ अपनी ही जाति या उप-जाति के भीतर विवाह करना है, जबकि **'बहिर्विवाह' (Exogamy)** का अर्थ अपने गोत्र, कुल, प्रवर, सपिंड या गांव (उत्तरी भारत में ग्राम बहिर्विवाह) के बाहर विवाह करना है।

अभ्यास प्रश्न #14 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 14. भारत सरकार की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना **'आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (AB-PMJAY)** तथा इसके प्राथमिक स्वास्थ्य घटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(A) आयुष्मान भारत के दो अंतर्संबंधित घटक हैं: प्रथम, 1.5 लाख से अधिक 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' (पूर्व नाम: हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर) जो व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और निःशुल्क जांच/दवाइयां प्रदान करते हैं; तथा द्वितीय, 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (PM-JAY, 23 सितंबर 2018 को रांची से प्रारंभ) जो द्वितीयक और तृतीयक स्तर के अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रतिवर्ष **₹5 लाख** तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है (जिसमें अब **70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों** को उनकी आय के निरपेक्ष शामिल कर लिया गया है)।

(B) इस योजना में केवल ओपीडी की दवाइयों के लिए ₹10,000 प्रति व्यक्ति दिए जाते हैं और अस्पताल में भर्ती का खर्च शामिल नहीं है।

(C) इस योजना में परिवार के सदस्यों की संख्या अधिकतम 4 तक सीमित है और पहले से मौजूद बीमारियां 5 वर्ष बाद कवर होती हैं।

(D) यह योजना केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है।

सही उत्तर: (A) आयुष्मान भारत के दो अंतर्संबंधित घटक हैं: प्रथम, 1.5 लाख से अधिक 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' (पूर्व नाम: हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर) जो व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और निःशुल्क जांच/दवाइयां प्रदान करते हैं; तथा द्वितीय, 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (PM-JAY, 23 सितंबर 2018 को रांची से प्रारंभ) जो द्वितीयक और तृतीयक स्तर के अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रतिवर्ष **₹5 लाख** तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है (जिसमें अब **70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों** को उनकी आय के निरपेक्ष शामिल कर लिया गया है)।

विस्तृत व्याख्या:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 की अनुशंसा पर प्रारंभ 'आयुष्मान भारत' विश्व की सबसे बड़ी सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है (www.iucacademy.com)।
- इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा किया जाता है।
- इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें परिवार के आकार (Family Size) या आयु की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, पहले दिन से ही सभी पूर्व-विद्यमान रोग (Pre-existing diseases) कवर होते हैं, तथा अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पूर्व और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का नैदानिक व औषधि व्यय भी ₹5 लाख प्रति परिवार प्रतिवर्ष के कैशलेस कवर में सम्मिलित है।
- हाल ही में केंद्र सरकार ने **70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों** (चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो) को ₹5 लाख के निःशुल्क आयुष्मान वय वंदना कार्ड कवरेज के दायरे में शामिल किया है।

अभ्यास प्रश्न #15 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 15. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों (Unorganised Workers) के राष्ट्रीय डेटाबेस और सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अगस्त 2021 में प्रारंभ किए गए **'ई-श्रम पोर्टल' (e-Shram Portal)** तथा **'प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना' (PM-SYM)** के संबंध में कौन-सा कथन सत्य है?

(A) ई-श्रम पोर्टल पर 16 से 59 वर्ष आयु के असंगठित श्रमिकों (जो EPFO/ESIC के सदस्य और आयकरदाता न हों) को 12 अंकों का सार्वभौमिक खाता संख्या (UAN) युक्त ई-श्रम कार्ड जारी किया जाता है; तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (2019) एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसमें 18 से 40 वर्ष की आयु में जुड़ने वाले असंगठित श्रमिक (मासिक आय ₹15,000 तक) को **60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ₹3,000 प्रतिमाह** की निश्चित न्यूनतम पेंशन मिलती है।

(B) ई-श्रम कार्ड केवल संगठित क्षेत्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को दिया जाता है।

(C) प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना में 45 वर्ष की आयु से ही ₹25,000 प्रतिमाह पेंशन मिलती है।

(D) इस योजना में सरकार कोई अंशदान नहीं करती है।

सही उत्तर: (A) ई-श्रम पोर्टल पर 16 से 59 वर्ष आयु के असंगठित श्रमिकों (जो EPFO/ESIC के सदस्य और आयकरदाता न हों) को 12 अंकों का सार्वभौमिक खाता संख्या (UAN) युक्त ई-श्रम कार्ड जारी किया जाता है; तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (2019) एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसमें 18 से 40 वर्ष की आयु में जुड़ने वाले असंगठित श्रमिक (मासिक आय ₹15,000 तक) को **60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ₹3,000 प्रतिमाह** की निश्चित न्यूनतम पेंशन मिलती है।

विस्तृत व्याख्या:

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (labour.gov.in) द्वारा असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों, प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी-पटरी वालों, घरेलू कामगारों, कृषि श्रमिकों और गिग व प्लेटफॉर्म श्रमिकों के पंजीकरण हेतु 26 अगस्त 2021 को **ई-श्रम पोर्टल** लॉन्च किया गया।
- वहीं, फरवरी 2019 में प्रारंभ **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM)** के अंतर्गत ₹15,000 या उससे कम मासिक आय वाले 18–40 वर्ष के असंगठित श्रमिक अपनी प्रवेश आयु के अनुसार ₹55 से ₹200 प्रतिमाह का अंशदान करते हैं और केंद्र सरकार भी ठीक उतनी ही राशि (50:50 Matching Contribution) का अंशदान करती है।
- लाभार्थी के 60 वर्ष का होने पर उसे आजीवन ₹3,000 प्रतिमाह पेंशन (तथा मृत्यु होने पर जीवनसाथी को 50% अर्थात ₹1,500 प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन) LIC के पेंशन फंड के माध्यम से प्रदान की जाती है।

अभ्यास प्रश्न #16 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 16. भारतीय संविधान में धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों (Religious and Linguistic Minorities) के शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकारों और 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992' के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(A) भारतीय संविधान में 'अल्पसंख्यक' शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में किया गया है (किंतु संविधान में इसे परिभाषित नहीं किया गया है), और अनुच्छेद 30(1) के तहत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का मौलिक अधिकार प्राप्त है; साथ ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत केंद्र सरकार द्वारा **6 धार्मिक समुदायों** (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी/जोरास्ट्रियन और जैन — जैन समुदाय को जनवरी 2014 में) को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक अधिसूचित किया गया है।

(B) अनुच्छेद 30 केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों पर लागू होता है, भाषाई अल्पसंख्यकों पर नहीं।

(C) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक संवैधानिक निकाय के रूप में हुई है।

(D) भारत में केवल 3 धार्मिक समुदायों को ही अल्पसंख्यक माना गया है।

सही उत्तर: (A) भारतीय संविधान में 'अल्पसंख्यक' शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में किया गया है (किंतु संविधान में इसे परिभाषित नहीं किया गया है), और अनुच्छेद 30(1) के तहत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का मौलिक अधिकार प्राप्त है; साथ ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत केंद्र सरकार द्वारा **6 धार्मिक समुदायों** (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी/जोरास्ट्रियन और जैन — जैन समुदाय को जनवरी 2014 में) को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक अधिसूचित किया गया है।

विस्तृत व्याख्या:

- एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान (ncert.nic.in) और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अनुच्छेद 29 भारत के किसी भी भाग में निवासी नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है, जबकि **अनुच्छेद 30** धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित व संचालित करने का अधिकार देता है (टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, 2002 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्य को इकाई मानकर किया जाता है)।
- इसके अलावा **अनुच्छेद 350A** में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं और **अनुच्छेद 350B** में 'भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी' (Special Officer for Linguistic Minorities - 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया) का संवैधानिक प्रावधान है।

अभ्यास प्रश्न #17 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 17. नगरीकरण (Urbanisation) और शहरी सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में, भारत की जनगणना में किसी बसावट को 'जनगणना नगर' (Census Town — गैर-वैधानिक नगर) घोषित करने के लिए कौन-से तीन एकसाथ पूरे होने वाले मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

(A) (1) न्यूनतम जनसंख्या **5,000** हो; (2) कामकाजी पुरुष मुख्य श्रमिकों (Male Main Workers) का कम से कम **75% भाग गैर-कृषि कार्यों** (Non-agricultural pursuits) में संलग्न हो; तथा (3) जनसंख्या का घनत्व कम से कम **400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर** (1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील) हो।

(B) न्यूनतम जनसंख्या 1,00,000 हो और वहाँ नगर निगम कार्यरत हो।

(C) केवल 50% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हो और घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो।

(D) जहाँ कम से कम एक विश्वविद्यालय और एक हवाई अड्डा स्थित हो।

सही उत्तर: (A) (1) न्यूनतम जनसंख्या **5,000** हो; (2) कामकाजी पुरुष मुख्य श्रमिकों (Male Main Workers) का कम से कम **75% भाग गैर-कृषि कार्यों** (Non-agricultural pursuits) में संलग्न हो; तथा (3) जनसंख्या का घनत्व कम से कम **400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर** (1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील) हो।

विस्तृत व्याख्या:

- एनसीईआरटी भूगोल एवं समाजशास्त्र (ncert.nic.in) के अनुसार भारत की जनगणना (1961 के मानक से अद्यतन) में नगरीय क्षेत्रों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है: प्रथम, **'वैधानिक नगर' (Statutory Towns)**—वे सभी स्थान जहाँ नगरपालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड (Cantonment Board) या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति मौजूद हो; द्वितीय, **'जनगणना नगर' (Census Towns)**—वे ग्रामीण प्रशासनिक इकाइयां जो तीन जनसांख्यिकीय शर्तें एक साथ पूरी करती हों: (1) न्यूनतम जनसंख्या 5,000, (2) न्यूनतम 75% पुरुष मुख्य कार्यशील जनसंख्या गैर-कृषि व्यवसायों में संलग्न, और (3) जनसंख्या घनत्व न्यूनतम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी।
- (1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर को 'प्रथम श्रेणी का नगर' या 'शहर' - City और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी संकुल को 'दस लाखी नगर' या 'महानगर' - Metropolitan City कहा जाता है)।

अभ्यास प्रश्न #18 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 18. भारत में सामाजिक आंदोलनों के समाजशास्त्र के अंतर्गत 1970 के दशक के 'चिपको आंदोलन' (उत्तराखंड), 1980 के दशक के 'अप्पिको आंदोलन' (कर्नाटक) और केरल की 'साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन' को समाजशास्त्रीय वर्गीकरण में किस प्रकार के आंदोलन की श्रेणी में रखा जाता है?

(A) पारिस्थितिक आंदोलन (Ecological Movements) — जो एक ही समय में 'पुराने सामाजिक आंदोलन' (आजीविका और संसाधनों के आर्थिक वितरण का संघर्ष) और 'नए सामाजिक आंदोलन' (पहचान, पर्यावरण संरक्षण और जीवन की गुणवत्ता का प्रश्न) दोनों की विशेषताओं को समाहित करते हैं

(B) केवल सैन्य तख्तापलट आंदोलन

(C) केवल धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन

(D) शेयर बाजार सुधार आंदोलन

सही उत्तर: (A) पारिस्थितिक आंदोलन (Ecological Movements) — जो एक ही समय में 'पुराने सामाजिक आंदोलन' (आजीविका और संसाधनों के आर्थिक वितरण का संघर्ष) और 'नए सामाजिक आंदोलन' (पहचान, पर्यावरण संरक्षण और जीवन की गुणवत्ता का प्रश्न) दोनों की विशेषताओं को समाहित करते हैं

विस्तृत व्याख्या:

- एनसीईआरटी समाजशास्त्र ('सामाजिक आंदोलन' - ncert.nic.in) में प्रसिद्ध इतिहासकार व समाजशास्त्री रामचंद्र गुहा की पुस्तक 'द अनक्वाइट वुड्स' (*The Unquiet Woods*) के हवाले से स्पष्ट किया गया है कि चमोली जिले (उत्तराखंड) के रैणी गांव में चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी के नेतृत्व में चला **चिपको आंदोलन (1973)** केवल 'पेड़ बचाने का पर्यावरण आंदोलन' मात्र नहीं था, बल्कि यह पहाड़ी ग्रामीणों व महिलाओं की वन-आधारित आजीविका ('निर्वाह की अर्थव्यवस्था') और बाहरी ठेकेदारों की 'मुनाफे की अर्थव्यवस्था' के बीच का आर्थिक व पारिस्थितिक संघर्ष भी था।
- इसलिए भारत के पारिस्थितिक आंदोलन पश्चिमी देशों के शुद्ध मध्यमवर्गीय पर्यावरण आंदोलनों से भिन्न हैं क्योंकि इनमें गरीब किसानों, आदिवासियों और महिलाओं के अस्तित्व व सामाजिक न्याय का प्रश्न सीधे जुड़ा होता है।

अभ्यास प्रश्न #19 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 19. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, **1994 (PCPNDT Act)** तथा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) अधिनियम, **2021 (MTP Amendment Act, 2021)** के प्रमुख प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(A) PCPNDT अधिनियम 1994 भ्रूण के लिंग परीक्षण और लिंग-चयनात्मक गर्भपात को पूर्णतः दंडनीय अपराध घोषित करता है; जबकि MTP (संशोधन) अधिनियम 2021 ने विशेष श्रेणियों की महिलाओं (दुष्कर्म पीड़िता, दिव्यांग महिलाएं, नाबालिग, वैवाहिक स्थिति में बदलाव या गंभीर भ्रूणीय असामान्यता) के लिए सुरक्षित और वैध गर्भपात की ऊपरी गर्भावधि सीमा को पुराने कानून (1971) के 20 सप्ताह से बढ़ाकर **24 सप्ताह** कर दिया है (तथा गंभीर भ्रूणीय विकृति की स्थिति में मेडिकल बोर्ड की राय पर 24 सप्ताह के बाद भी अनुमति दी जा सकती है)।

(B) PCPNDT अधिनियम लिंग परीक्षण के विज्ञापनों को वैध मानता है।

(C) MTP संशोधन अधिनियम 2021 ने भारत में सभी प्रकार के चिकित्सीय गर्भपात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

(D) दोनों अधिनियम वर्ष 1950 में पारित किए गए थे।

सही उत्तर: (A) PCPNDT अधिनियम 1994 भ्रूण के लिंग परीक्षण और लिंग-चयनात्मक गर्भपात को पूर्णतः दंडनीय अपराध घोषित करता है; जबकि MTP (संशोधन) अधिनियम 2021 ने विशेष श्रेणियों की महिलाओं (दुष्कर्म पीड़िता, दिव्यांग महिलाएं, नाबालिग, वैवाहिक स्थिति में बदलाव या गंभीर भ्रूणीय असामान्यता) के लिए सुरक्षित और वैध गर्भपात की ऊपरी गर्भावधि सीमा को पुराने कानून (1971) के 20 सप्ताह से बढ़ाकर **24 सप्ताह** कर दिया है (तथा गंभीर भ्रूणीय विकृति की स्थिति में मेडिकल बोर्ड की राय पर 24 सप्ताह के बाद भी अनुमति दी जा सकती है)।

विस्तृत व्याख्या:

- गिरते बाल लिंगानुपात और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए संसद ने 1994 में PNDT अधिनियम पारित किया जिसे 2003 में संशोधित कर **PCPNDT अधिनियम (गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक अधिनियम)** बनाया गया (ncert.nic.in, www.iucacademy.com)।
- वहीं, महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत शारीरिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करते हुए **MTP (संशोधन) अधिनियम, 2021** ने गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 में संशोधन किया: अब 20 सप्ताह तक केवल एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी (RMP) की राय पर और 20 से 24 सप्ताह तक दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय पर विशेष श्रेणियों की महिलाओं का वैध गर्भपात किया जा सकता है।

• सर्वोच्च न्यायालय ने भी सितंबर 2022 (*X* बनाम प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग) के ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया कि MTP कानून के तहत विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाओं को 24 सप्ताह तक सुरक्षित गर्भपात का समान अधिकार है।

अभ्यास प्रश्न #20 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 20. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई **'पीएम-दक्ष' (PM-DAKSH)** योजना तथा **'नमस्ते' (NAMASTE — National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem)** योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(A) 'पीएम-दक्ष' (प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्न हितग्राही) योजना अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विमुक्त जनजातियों और सफाई कर्मचारियों को निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है; जबकि 'नमस्ते' योजना (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय एवं सामाजिक न्याय मंत्रालय की संयुक्त पहल) का उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में 'शून्य मृत्यु' हासिल करना, मानवीय मल के प्रत्यक्ष संपर्क को रोककर शत-प्रतिशत मशीनीकृत सफाई सुनिश्चित करना और सफाई मित्रों को वैकल्पिक आजीविका व सुरक्षा उपकरण प्रदान करना है।

(B) दोनों योजनाएं केवल अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण से संबंधित हैं।

(C) नमस्ते योजना विदेशी पर्यटकों को होटल बुकिंग में छूट देने के लिए है।

(D) पीएम-दक्ष योजना केवल शेयर बाजार के दलालों के लिए है।

सही उत्तर: (A) 'पीएम-दक्ष' (प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्न हितग्राही) योजना अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विमुक्त जनजातियों और सफाई कर्मचारियों को निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है; जबकि 'नमस्ते' योजना (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय एवं सामाजिक न्याय मंत्रालय की संयुक्त पहल) का उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में 'शून्य मृत्यु' हासिल करना, मानवीय मल के प्रत्यक्ष संपर्क को रोककर शत-प्रतिशत मशीनीकृत सफाई सुनिश्चित करना और सफाई मित्रों को वैकल्पिक आजीविका व सुरक्षा उपकरण प्रदान करना है।

विस्तृत व्याख्या:

• हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के उद्देश्यों को धरातल पर पूर्ण करने के लिए केंद्र सरकार ने पुरानी SRMS योजना के स्थान पर **'नमस्ते' (NAMASTE)** योजना लागू की है (www.iucacademy.com)।

• इसके तहत सीवर और सेप्टिक टैंक के खतरनाक कार्यों में किसी भी सफाई कर्मचारी को बिना सुरक्षात्मक मशीनीकरण के उतारने पर रोक है, सफाई मित्रों की प्रोफाइलिंग कर उन्हें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा से जोड़ा जाता है और स्वच्छता उद्यमियों को मशीनें खरीदने हेतु पूंजीगत सब्सिडी दी जाती है।

• इसी प्रकार **पीएम-दक्ष** योजना वंचित वर्गों के युवाओं को अल्पकालिक व दीर्घकालिक कौशल प्रशिक्षण और स्टाइपेंड देकर उन्हें स्वरोजगार व वेतनभोगी रोजगार योग्य बनाती है।

क्वालिटी ऑडिट, त्रुटि-निवारण एवं 2024–2026 भारतीय समाज एवं शासन बूस्टर (Society & Governance Audit)

1. भारतीय समाज, सामाजिक न्याय एवं गवर्नेंस के उच्च-प्राथमिकता संवैधानिक व विधिक प्रावधान

विषय / वर्ग	संवैधानिक अनुच्छेद / संशोधन	प्रमुख अधिनियम एवं नवीनतम सरकारी पहल (2024–2026)	आधिकारिक स्रोत
महिला सशक्तिकरण एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व	अनुच्छेद 14, 15(3), 39(d), 42, 243D; **106वाँ संशोधन (2023)**	नारी शक्ति वंदन अधिनियम (लोकसभा व विधानसभाओं में 33% आरक्षण - अनुच्छेद 330A, 332A), मिशन शक्ति, लखपति दीदी (3 करोड़ लक्ष्य)	भारत का संविधान
अनुसूचित जाति (SC) एवं जनजाति (ST) कल्याण	अनुच्छेद 17, 46, 244, 330, 332, **338 (NCSC), 338A (NCST)**	अस्पृश्यता अपराध/सिविल अधिकार संरक्षण 1955, SC/ST अत्याचार निवारण 1989, **पीएम-जनमन (PM-JANMAN — 75 PVTG समूह)**, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	नीति आयोग SDG रिपोर्ट
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं EWS आरक्षण	**102वाँ संशोधन (अनुच्छेद 338B - NCBC), 103वाँ संशोधन (10% EWS)**	इंद्रा साहनी वाद 1992 (50% सीमा व क्रीमी लेयर), जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022 (EWS वैधता), पीएम-यशस्वी व श्रेष्ठा योजना	IUC Academy GS-II
दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं ट्रांसजेंडर अधिकार	अनुच्छेद 41 (काम, शिक्षा व लोक सहायता का अधिकार)	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD Act 2016 — 21 श्रेणियाँ, 4% आरक्षण), वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम 2007, SMILE योजना	Census of India
पारदर्शिता, ई-गवर्नेंस एवं जवाबदेही	अनुच्छेद 19(1)(a); लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013	सूचना का अधिकार (RTI 2005), **सेवोत्तम मॉडल** (सिटीजन चार्टर + लोक शिकायत + सेवा वितरण), डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP Act 2023)	UPSC Mains Portal

2. समाजशास्त्रीय अवधारणाओं की परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alerts)

• **संस्कृतिकरण (Sanskritization) बनाम पश्चिमीकरण (Westernization):** दोनों अवधारणाएँ प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री **एम.एन. श्रीनिवास (M.N. Srinivas)** ने दीं। संस्कृतिकरण में निम्न जाति उच्च/द्विज जाति की जीवनशैली अपनाती है (यह पदमूलक/Positional परिवर्तन है, संरचनात्मक/Structural परिवर्तन नहीं)।

• **सर्वोदय एवं अंत्योदय:** 'सर्वोदय' शब्द महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन की पुस्तक '*Unto This Last*' के गुजराती अनुवाद में दिया, जबकि 'अंत्योदय' व 'एकात्म मानववाद' को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने विकसित किया।